

मूल वाद सं। 1 1997

कर्नाटक राज्य

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य

और

मूल वाद सं। 2 1997 का आंध्र प्रदेश राज्य कर्नाटक राज्य और अन्य

अप्रैल 25, 2000

[न्यायमूर्तिगण एस. बी. मजूमदार, जी. बी. पटनायक, वी. एन. खरे, आर. पी. सेठी और उमेश सी. बनर्जी]

भारत का संविधान, अनुच्छेद 131, 262 आर/डब्ल्यू अंतर-राज्य जल विवाद

अधिनियम 1956, एस. एस. 4, 5 (2) और (3), 6, 6-ए-अंतर-राज्य जल विवाद-कृष्णा नदी बेसिन कर्नाटक और आंध्र के तटवर्ती राज्यों के बीच जल का बंटवारा

प्रदेश और महाराष्ट्र-न्यायाधिकरण को भेजे गए विवाद-न्यायाधिकरण ने दिसंबर, 1973 में रिपोर्ट देते हुए अंतिम आदेश को शामिल करते हुए मई, 1976 में धारा 5 (3) न्यायाधिकरण के तहत राज्यों द्वारा दिए गए संदर्भों पर आगे की रिपोर्ट दी।

संशोधित अंतिम आदेश-दोनों रिपोर्टों में दो योजनाएं विकसित हुईं

योजना ए-तीन विश्वसनीय प्रवाह वाले राज्यों के पक्ष में 75 प्रतिशत पर बड़े पैमाने पर आवंटन करना जो कि 2060 टी. एम. सी. था-योजना 'बी' का विकास अतिरिक्त और कम प्रवाह वाले वर्षों में प्रतिशत के आधार पर आवंटन को प्रभावी बनाने के लिए किया गया-आंध्र प्रदेश योजना 'बी' के कार्यान्वयन के लिए कृष्णा घाटी प्राधिकरण (के. वी. ए.) के गठन के लिए सहमत नहीं है-इसलिए न्यायाधिकरण योजना 'बी' को अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं बना रहा है-कर्नाटक ने नदी तटीय राज्यों और भारत संघ के खिलाफ एक डिक्री के लिए मुकदमा दायर किया है कि 2060 टी. एम. सी. से अधिक अतिरिक्त पानी को योजना 'बी' के अनुसार साझा किया जाए; योजना 'बी' को अधिसूचित करने और 'के. वी. ए.' की स्थापना करने के लिए भारत संघ को एक अनिवार्य निषेधाज्ञा और आंध्र प्रदेश को योजना 'बी' तक परियोजनाओं को जारी रखने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा।

प्रभावी ढंग से लागू किया गया-आयोजित, योजना 'बी' न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं था और सर्वोच्च न्यायालय के अनिवार्य निषेधाज्ञा द्वारा लागू करने में सक्षम नहीं था।

आंध्र प्रदेश ने यह दावा करते हुए मुकदमा दायर किया कि परियोजना-वार आवंटन को न्यायाधिकरण द्वारा किए गए भरोसेमंद प्रवाह के बड़े पैमाने पर आवंटन में पढ़ा जाना चाहिए और एक घोषणा के लिए कि कर्नाटक द्वारा अलमट्टी बांध का निर्माण की ऊंचाई तक

524.256 मीटरों ने न्यायाधिकरण के फैसले का उल्लंघन किया-आंध्र प्रदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, कर्नाटक को 524.256 मीटर की ऊंचाई तक अलमट्टी बांध के निर्माण से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का अनुरोध करते हुए-आयोजित, ट्रिब्यूल

नाल के निर्णय ने केवल बड़े पैमाने पर आवंटन किया, न कि परियोजना-वार आवंटन, आगे कहा गया, जब तक कि कर्नाटक द्वारा पानी का कुल उपयोगकर्ता बड़े पैमाने से अधिक न हो।

आवंटन, न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन नहीं किया गया और कोई अनिवार्य निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकी; अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर कोई रोक नहीं थी केंद्र सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मंजूरी के अधीन 519.6 मीटर तक।

भारत का संविधान, अनुच्छेद 131, 262 (2) आर/डब्ल्यू अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम 1956, एस. एस. 2 (ग) और 11-मुकदमे की रखरखाव-कर्नाटक ने उस आदेश के लिए मुकदमा दायर किया जो योजना 'बी' कृष्णा के अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं थी।

जल विवाद न्यायाधिकरण को अधिसूचित किया जाना चाहिए और-- प्रतिवादियों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश और भारत संघ ने तर्क दिया कि यह अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर एक ताजे पानी का विवाद था जो अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध को आकर्षित करता है।

एस के तहत एक विवाद का गठन करें। 2 (ग) अधिनियम और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता अनुच्छेद 131 के तहत अदालत को बर्खास्त नहीं किया गया था। भारत का संविधान, अनुच्छेद 131, 142 और 262 (2) आर/डब्ल्यू अंतर-राज्य जल

विवाद अधिनियम, 1956। 2 (ग), 3 (क) और 11-वादी के खिलाफ निषेधाज्ञा में राहततिवादी द्वारा मांगा गया-अतिरिक्त लिखित में महाराष्ट्र की रखरखाव क्षमता महाराष्ट्र में भूमि के डूबने की आशंका व्यक्त करने वाला बयान कर्नाटक द्वारा अलमट्टी बांध की ऊंचाई को 524.256 तक बढ़ाने का लेखा-जोखा और इसके खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना-आयोजित, उठाया गया विवाद एक कॉम होगा एस के अर्थ के भीतर शिकायत। 3 (ए) और एस के तहत एक जल विवाद। 2 (ग) अधिनियम के; उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 131 या 142 के तहत इसे स्वीकार नहीं कर सका।

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956। 6 - न्यायाधिकरण रिपोर्ट दे रहा है और

1973 में निर्णय और 1976 में आगे की रिपोर्ट और निर्णय-आंध्र प्रदेश ने यह घोषणा करने के लिए प्रार्थना के साथ मुकदमा दायर किया कि रिपोर्ट और निर्णय दोनों अपनी संपूर्णता में तीन नदी तटीय राज्यों पर बाध्यकारी थे-राज्य उक्त प्रार्थना के संदर्भ में आंशिक डिक्री के लिए सहमत थे-कर्नाटक ने उस योजना 'बी' के गठन का तर्क दिया रिपोर्ट के हिस्से के रूप में, योजना 'बी' को लागू करने की मांग करने वाले उसके मुकदमे का विरोध नहीं किया जा सका आंशिक आदेश को देखते हुए आंध्र प्रदेश द्वारा-आंध्र प्रदेश ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण की रिपोर्ट एक फैसले की तरह थी और इसका निर्णय एक मुकदमे में एक डिक्री की तरह था जिसे रिपोर्ट के अनुरूप पढ़ा जाना था-आयोजित, न्यायाधिकरण का निर्णय था एक डिक्री नहीं है और इसकी रिपोर्ट एक दीवानी मुकदमे में निर्णय नहीं है; आगे आयोजित, प्रार्थना कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्यआंध्र प्रदेश की शिकायत को अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में उसके दावे के आलोक में समझना था; आंशिक डिक्री पूरी रिपोर्ट नहीं बना सकी और आगे की रिपोर्ट पक्षों पर बाध्यकारी नहीं हो सकी-दलीलों का कानून।

मूल सूट 1/97 उपयोग, वितरण और वितरण के संबंध में तीन नदी तटीय राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद। अंतर-राज्यीय नदी कृष्णा के पानी के नियंत्रण का समाधान कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ('न्यायाधिकरण') के निर्णयों द्वारा किया गया, जिसका गठन एस. 4 अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 ('अधिनियम')। न्यायाधिकरण की 24 दिसंबर, 1973 को प्रस्तुत की गई पहली रिपोर्ट के साथ-साथ 27 मई, 1976 की अगली रिपोर्ट में दो योजनाएं विकसित की गईं। योजना "ए" ने तीन नदी तटीय राज्यों के पक्ष में 75 प्रतिशत पर बड़े पैमाने पर आवंटन किया, जो 2060 टी. एम. सी. पर आया था, यह दर्शाता है कि किसी भी जल वर्ष में महाराष्ट्र 560 टी. एम. सी. से अधिक, कर्नाटक 700 टी. एम. सी. से अधिक और आंध्र प्रदेश 800 टी. एम. सी. से अधिक का उपयोग नहीं करेगा। इसने यह भी संकेत दिया है कि आंध्र प्रदेश जो अंतिम नदी तटीय स्वामी था, वह कृष्णा नदी में बहने वाले शेष पानी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन ऐसे उपयोगकर्ता द्वारा राज्य अतिरिक्त मात्रा के संबंध में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं करेगा, जिसका उपयोग वह 800 टी. एम. सी. की आवंटित मात्रा से अधिक करेगा।

अधिशेष के साथ-साथ प्रवाह के घाटे वाले वर्षों में प्रतिशत के आधार पर आवंटन को प्रभावी बनाने के लिए न्यायाधिकरण ने योजना "बी" और "इंडी" विकसित की।

इसकी मूल रिपोर्ट के साथ-साथ इसकी अगली रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया है। योजना "बी" के उचित कार्यान्वयन के लिए, कृष्णा घाटी प्राधिकरण (के. वी. ए.) का गठन नितांत आवश्यक था, आंध्र प्रदेश के. वी. ए. के गठन के लिए सहमत नहीं होने के कारण, न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम आदेश के हिस्से के रूप में योजना "बी" नहीं बनाई और इस मामले

को या तो प्रतिद्वंद्वी राज्यों के अच्छे ज्ञान पर छोड़ने या संसद के लिए संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 56 सूची I के तहत उस प्रभाव के लिए एक कानून बनाने के लिए उचित समझा।

कर्नाटक योजना के अनुसार "बी" न्यायाधिकरण के निर्णय का एक हिस्सा होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा भी अधिसूचित किया जाना आवश्यक था।

एस के तहत। 6 अधिनियम, इसे पक्षों के लिए बाध्यकारी बनाता है। आंध्र प्रदेश सहमत नहीं था। कर्नाटक ने तब अनुच्छेद के तहत इस अदालत में यह मुकदमा दायर किया।

एक आदेश की मांग करते हुए कि कृष्णा नदी में अधिशेष जल यानी 2060 टी. एम. सी. से अधिक 75 प्रतिशत निर्भरता पर साझा किया जाए न्यायाधिकरण के निर्धारण और निर्देश; एक घोषणा कि आंध्र प्रदेश 75 प्रतिशत निर्भरता पर अधिशेष जल अर्थात् 2060 टी. एम. सी. से अधिक के उपयोग के अपने अधिकार पर जोर देने का हकदार नहीं था, जब तक कि न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई योजना "बी" पूरी तरह से लागू नहीं की गई थी और भारत संघ को न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई योजना "बी" को अधिसूचित करने और न्यायाधिकरण के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए के. वी. ए. की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को कई परियोजनाओं को निष्पादित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के आदेश के लिए भी अनुरोध किया, जब तक कि न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई योजना "बी" को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता।

आंध्र प्रदेश ने अपने लिखित बयान में एक प्रारंभिक ओबीजेईसी लिया यह कि कर्नाटक द्वारा मांगा गया निर्णय स्वयं एक जल था विवाद और इसलिए, अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे को संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत जनादेश को देखते हुए वर्जित कर दिया गया था। 11 अधिनियम से। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि केवल योजना "ए" को न्यायाधिकरण का निर्णय माना जा सकता है। न्यायाधिकरण ने जो भी टिप्पणी की थी

योजना "बी" के निर्माण का संबंध अस्पष्ट था और इसका हिस्सा नहीं था। इस तरह का निर्णय अप्रवर्तनीय था। यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों द्वारा योजना 'ए' पर दो दशकों से अधिक समय से काम किया जा रहा है और उक्त योजना समीक्षा के तहत 31 मई, 2000 के बाद योजना 'बी' के कार्यान्वयन का सवाल न केवल असमान था, बल्कि अनावश्यक भी था।

महाराष्ट्र ने यह भी रुख अपनाया कि मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था चूंकि योजना "बी" का कार्यान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यों को भेजा गया और न्यायालय राज्यों को सहमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था और न ही संसद को इसके लिए कोई कानून बनाने का निर्देश दे सकता था। भारत संघ ने अपने लिखित बयान में यह रुख अपनाया कि तैयार किया गया मुकदमा एस के आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं था। 11 संविधान के अनुच्छेद 262 के

साथ पठित अधिनियम। जहां तक आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा पानी के उपयोगकर्ता का संबंध है, इसने तर्क दिया कि पुरस्कार में पानी की कुल मात्रा निर्धारित की गई है जिसका उपयोग महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश द्वारा किसी दिए गए जल वर्ष में आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त पानी का उपयोग करने की स्वतंत्रता के साथ किया जा सकता है, उक्त स्वतंत्रता आंध्र प्रदेश में कोई अधिकार प्रदान या सृजित नहीं करती है और ऐसा उपयोगकर्ता ऊपरी नदी तट के अधिकार के अधीन होगा।

महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य। इसने आगे जोर देकर कहा कि पुरस्कार कर्नाटक और ओआरएस का राज्य है।

एक परियोजना-वार आवंटन नहीं दिया, लेकिन सकल आवंटन करता है और प्रत्येक राज्य न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य था।

दलीलों के आधार पर इस अदालत ने 13 मुद्दे तैयार किए जिनमें शामिल हैं - निम्नलिखित:

(क) क्या मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 262 (2) द्वारा वर्जित था। एस के साथ पढ़ें। 11 अधिनियम का?

(ख) क्या योजना "ख" न्यायाधिकरण के "निर्णय" का हिस्सा थी। एस के तहत। 6 अधिनियम और क्या यह सक्षम था या न्यायसंगत और न्यायसंगत था इस स्तर पर योजना "बी" को लागू करें?

मूल सूट 2/97 आंध्र प्रदेश ने इसके खिलाफ अनुच्छेद 131 के तहत इस अदालत में मुकदमा दायर किया।

कर्नाटक, महाराष्ट्र और भारत संघ इस आधार पर कि हालांकि न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश में, 2060 टी. एम. सी. के तहत पानी के तीन तटवर्ती राज्यों के पक्ष में बड़े पैमाने पर पानी का आवंटन किया गया था।

75 % रिपोर्ट की गहन जांच से पता चला कि विभिन्न उप-बेसिनों के संबंध में आवंटन उन उप-बेसिनों में शुरू की गई परियोजनाओं के आधार पर किया गया था और इसके परिणामस्वरूप, कोई भी राज्य अपने क्षेत्र में आवंटित पानी की पूरी मात्रा का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

किसी विशेष उप-बेसिन में अनुकूलता। इन परिस्थितियों में कर्नाटक द्वारा किए गए पोस्ट पुरस्कार निर्माण, जिसमें इसे बढ़ाने का इरादा भी शामिल है

अलमट्टी बांध की ऊँचाई 524.256 मीटर तक, न्यायाधिकरण के निर्णय का घोर उल्लंघन था। तदनुसार, आंध्र प्रदेश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करने की मांग की कि न्यायाधिकरण की 24 दिसंबर, 1973 की रिपोर्ट और निर्णय और 27 मई, 1976 की आगे की

रिपोर्ट और निर्णय पूरी तरह से तीन नदी तटीय राज्यों पर बाध्यकारी थे; कर्नाटक के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा जिसमें उसे पुरस्कार के बाद के चरण में अलमट्टी बांध सहित अपनी परियोजनाओं के साथ किसी भी और संविधान को शुरू करने या जारी रखने से रोक दिया गया था।

कर्नाटक ने अपने लिखित बयान में यह रुख अपनाया कि न्यायाधिकरण ने

उन्होंने कोई परियोजना-वार आवंटन नहीं किया था और दूसरी ओर, आवंटन एनब्लॉक था। इस प्रकार न्यायाधिकरण के निर्णय की व्याख्या करने का प्रश्न इस प्रभाव से कि पानी के उपयोग में प्रतिबंध था

कोई विशेष बेसिन सही नहीं था। कर्नाटक ने [2000] 3 एस. सी. आर. पर विचार किया था।

1970 की परियोजना रिपोर्ट में ही अलमट्टी में बांध की ऊँचाई 524.256 मीटर है। वह रिपोर्ट न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई थी और दस्तावेज एम. वाई. पी. के.-3 के रूप में चिह्नित की गई थी। न तो आंध्र प्रदेश और न ही किसी अन्य राज्य ने उक्त परियोजना रिपोर्ट पर कोई आपत्ति जताई थी और इस संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था। वास्तव में अलमट्टी बांध की ऊँचाई न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय का विषय नहीं था। इसलिए न्यायाधिकरण के फैसले के किसी भी उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं था। इसके अलावा

अलमट्टी में एक करोड़ रुपये से अधिक की भारी लागत से परियोजना शुरू की गई थी। 6000 और इस अग्रिम चरण में परियोजना को रोकना राष्ट्रीय हित में नहीं था। यह दोहराया गया कि पानी का उपयोग पूरी तरह से न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित मात्रा के भीतर होगा।

भारत संघ का रुख यह था कि कर्नाटक का अधिकार था

ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पानी की सकल राशि का उपयोग करें और जब तक यह ऊपरी कृष्णा परियोजना में 173 एम. सी. के भीतर था, तब तक न्यायाधिकरण के फैसले का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

अपने पहले लिखित बयान में महाराष्ट्र ने कर्नाटक का समर्थन किया और

उन्होंने तर्क दिया कि आंध्र प्रदेश द्वारा शिकायत में मांगी गई राहत न्यायाधिकरण के निर्णय के पूर्ण पुनर्लेखन के समान होगी जो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के दायरे से बाहर होगी।

हालांकि बाद में दायर एक अतिरिक्त लिखित बयान में

महाराष्ट्र ने एफआरएल 524.56 एम के साथ अलमट्टी बांध के कथित निर्माण के संबंध में एक नया रुख अपनाया। कर्नाटक से। अब यह अनुमान लगाया गया कि अलमट्टी में बांध की

ऊँचाई बढ़ाने से निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान होने की संभावना है। अपने क्षेत्र के भीतर भूमि के डूबने की आशंका को देखते हुए, महाराष्ट्र ने अब बांध की ऊँचाई बढ़ाने से कर्नाटक के खिलाफ निषेधाज्ञा की प्रार्थना करने में आंध्र प्रदेश का समर्थन किया।

इस न्यायालय ने 33 मुद्दे तैयार किए जिनमें निम्नलिखित शामिल थे:

(क) क्या कर्नाटक ने न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन किया था

पुरस्कार के बाद के चरण में परियोजनाएं?

(ख) क्या आंध्र प्रदेश ने यह साबित किया कि राज्य द्वारा जल का आवंटन

न्यायाधिकरण परियोजनाओं के लिए विशिष्ट था न कि सामूहिक रूप से?

307

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य

(ग) क्या आंध्र प्रदेश इस घोषणा का हकदार था कि सभी का अर्थ है

कर्नाटक द्वारा न्यायाधिकरण के फैसले के अनुरूप नहीं होने के कारण

अवैध?

(घ) कर्नाटक द्वारा अलमट्टी बांध का निर्माण किया जाएगा।

524.256 एम उसे अपने आवंटित हिस्से से अधिक पानी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और क्या उसे अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति या भारत संघ की मंजूरी के बिना निर्माण के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए?

(ङ) क्या कर्नाटक को भंडारण स्तर बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।

संभावित जलमग्नता को देखते हुए आरएल 5090.16 मीटर के ऊपर अलमट्टी बांध पर

महाराष्ट्र में क्षेत्र?

30 सितंबर, 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज किया।

तीन तटवर्ती राज्यों में से कहते हैं कि उन्हें प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं थी (ए) में

आंध्र प्रदेश का दावा है कि न्यायाधिकरण की दो रिपोर्टों और उनकी संपूर्णता में निर्णयों को उन पर बाध्यकारी घोषित किया जाए। तदनुसार, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि उस हद तक एक आंशिक आदेश पारित किया जा सकता है। अंतिम सुनवाई में कर्नाटक ने तर्क दिया कि चूंकि योजना 'बी' रिपोर्ट का एक हिस्सा थी, इसलिए आंशिक आदेश को देखते हुए योजना 'बी' को लागू करने की मांग करने वाले उसके मुकदमे का आंध्र प्रदेश द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता था। आंध्र प्रदेश ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण की रिपोर्ट एक दीवानी मुकदमे में एक फैसले की तरह थी और इसका निर्णय एक डिक्री की तरह था जिसे रिपोर्ट के अनुरूप पढ़ा जाना था।

मूल वाद सं. 1/97 को खारिज करना और मूल वाद सं.

2/97, यह न्यायालय

आयोजित किया गया: पर पटनायक, जे। (अपने और पीठ के अन्य न्यायाधीशों के लिए,

मजमुदार, सेठी और उमेश सी. बनर्जी, जे. जे. द्वारा अलग-अलग सहमति/पूरक निर्णयों के साथ) :

1.1 . न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई योजना "बी" का निर्णय नहीं था

न्यायाधिकरण और इस प्रकार, एस के तहत अधिसूचित होने की आवश्यकता नहीं थी। 6 अधिनियम और इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक के इशारे पर लागू नहीं किया जा सका।

[332 - डी-ई]

1.2 . न्यायाधिकरण ने कभी भी योजना "बी" को अपना हिस्सा नहीं माना।

लागू करने का निर्णय भले ही विचाराधीन योजना की प्रभावशीलता के बारे में कोई संदेह न हो। जल विवाद खड़ा हो गया है

नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में तीन नदी तटीय राज्यों के बीच 3 एस. सी. आर.

कृष्ण और उक्त विवाद को न्यायाधिकरण को उसके निर्णय के लिए भेजा गया था और न्यायाधिकरण ने उसे संदर्भित मामलों की जांच करने के बाद पाया गया तथ्यों के साथ-साथ अपने निर्णय वाली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यह वह निर्णय था जिसने निर्णायक रूप से विवादों को फिर से तय किया और लागू करने में सक्षम था जिसे कहा जा सकता है एस के तहत न्यायाधिकरण का निर्णय। 5 (2) . [331 - एफ-एच]

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण [1993] पूरक 1 एस. सी. सी. 96, का अनुसरण किया गया। 1.3 . योजना "बी" पूर्ण

और बेहतर उपयोग के लिए प्रदान की गई

कृष्णा नदी में जल संसाधन और भविष्य में यदि किसी प्राधिकरण द्वारा कृष्णा नदी के आवंटन के प्रश्न पर विचार किया जाता है तो उक्त प्राधिकरण निश्चित रूप से योजना "बी" पर विचार करेगा जो उस समय उपलब्ध तिथि पर विकसित की गई थी और उसी की स्वीकार्यता पर विधिवत विचार किया जाएगा। [333 - बी-सी)

2.1 . शिकायत में किए गए दावे और मांगी गई राहत

यह एक न्यायनिर्णित विवाद के आधार पर एक दावा के रूप में दिखाया गया था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर करके लागू करने की मांग की गई थी। यह एस के अर्थ में कोई विवाद नहीं था। 2 (ग) अधिनियम। इसलिए इस तरह के मुकदमे को संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया था। 11 अधिनियम से। [339 - एफ-जी]

राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ, [1978] 1 एस. सी. आर. 1 और राज्य

कर्नाटक बनाम. भारत संघ, [1978] 2 एस. सी. आर. 1, संदर्भित।

एच. एम. सीरवई द्वारा निर्दिष्ट भारत का संवैधानिक कानून।

2.2 इस तरह का मुकदमा भी इस आधार पर अपरिपक्व नहीं था कि एक समीक्षा

31 मई, 2000 के बाद के लिए प्रावधान किया गया था। न्यायाधिकरण के आदेश में इंगित समीक्षा योजना 'ए' के तहत किए गए आवंटन के संबंध में थी और इसका योजना 'बी' से कोई लेना-देना नहीं था, जिसे मुकदमे के माध्यम से लागू करने की मांग की गई थी। [348 - ए-बी]

3. यह केंद्र सरकार पर था कि वह विवेक का प्रयोग करे

सबसे निचले नदी तटीय राज्य की किसी भी योजना या परियोजना को मंजूरी देते हुए ताकि बाद वाले को आवंटित मात्रा से अधिक अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर जल परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने की अनुमति न दी जाए, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं था।

ऊपरी राज्यों के मन में किसी भी आशंका को दूर करने के लिए विवेक का इस तरह से प्रयोग किया जाना था कि आने वाले सभी समय के लिए, अतिरिक्त पानी को साझा करने का उनका अधिकार किसी भी तरह से कर्नाटक और ओआरएस का राज्य होगा।

वी. ए. पी. राज्य

309

खतरे में है। [345 - ए-सी]

4.1 . स्थायी अनिवार्य निषेधाज्ञा से अब तक की राहत

अलमट्टी में बांध के निर्माण का संबंध था और साथ ही आंध्र प्रदेश की शिकायत के पैराग्राफ (बी) से (के) में मांगी गई राहत को मंजूरी नहीं दी जा सकी। [403 - डी]

4.2 . न्यायाधिकरण के निर्णय के तहत बड़े पैमाने पर आवंटन था और

खंड IX में उल्लिखित उन विशिष्ट परियोजनाओं को छोड़कर परियोजना-वार नहीं

और निर्णय का एक्स। वादी आंध्र प्रदेश यह स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहा था कि ऊपरी कृष्णा परियोजना या अलमट्टी जलाशय के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा कोई विशिष्ट आवंटन किया गया था। [381 - डी; 396-जी-एच]

4.3 . ऊपरी क्षेत्र में पानी के उपयोगकर्ता की मात्रा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था।

कर्नाटक द्वारा कृष्णा परियोजना और जब तक कुल उपयोगकर्ता बड़े पैमाने पर आवंटन से अधिक नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता था कि न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन किया जा रहा था जो आंध्र प्रदेश के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था जिसे कोई अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करके प्रतिबंधित किया जा सकता था। तथ्य यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा कई उप-बेसिनों में फिर से सख्ती की गई थी और नहीं उप-बेसिन के-2 तक प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसमें कर्नाटक की ऊपरी कृष्णा परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा था। [380 - डी-ई]

4.4 . यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि कर्नाटक ने कोई कार्रवाई की थी

संसद द्वारा बनाए गए किसी विशेष कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में या भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश के उल्लंघन में परियोजना। [399 - बी]

4.5 . ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं थी जिसके आधार पर यह संभव था

ताकि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि कर्नाटक के भीतर अलमट्टी बांध के निर्माण के कारण वादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना थी। [399 - एफ-जी]

5.1 . अलमट्टी में बांध की ऊँचाई बढ़ाने पर कोई रोक नहीं थी।

केंद्र सरकार और किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के उपयुक्त लेखक से मंजूरी प्राप्त करने के अधीन, 519.6 मीटर तक,

कानून के तहत पूछताछ की। [403 - ई]

5.2 . हालाँकि कर्नाटक में अलमट्टी में बांध हो सकता था, लेकिन

उक्त बांध की ऊँचाई 519.6 मीटर से अधिक नहीं हो सकती थी, विशेष रूप से जब कर्नाटक यह इंगित करने में सक्षम नहीं था कि 542.256 मीटर पर बांध की ऊँचाई की आवश्यकता क्या थी जब योजना 'आर' [2000] 3 एस. सी. आर. नहीं होने वाली थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

310

तुरंत ऑपरेशन किया। इसकी ऊँचाई को और बढ़ाने का सवाल

524.256 न्यायाधिकरण द्वारा मीटर में प्रवेश किया जाना चाहिए। [385 - एफ; 386-एच]

5.3 . केंद्र सरकार धोखाधड़ी करने के लिए बाध्य नहीं थी

किसी भी नदी तटीय राज्य की किसी भी परियोजना को मंजूरी देते समय अन्य राज्यों को भेजा गया। प्रत्येक राज्य की परियोजना को केंद्र सरकार के साथ-साथ अन्य वैधानिक प्राधिकरणों और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना था, लेकिन जिसके लिए कोई राज्य ऐसी परियोजना के निर्माण के साथ आगे नहीं बढ़ सकता था। [382 - बी-सी; 387-सी]

5.4 . अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति प्राप्त करने का सवाल उठाया गया

आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से गलत समझा गया था। न ही कानून द्वारा ऐसा अस्तित्व था जो किसी भी राज्य को अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए मजबूर करता था।

जब भी उसने अंतर-राज्यीय नदी के संबंध में पानी का उपयोग किया और न ही न्यायाधिकरण के निर्णय ने इस संबंध में कोई शर्त लगाई। [397 - ई]

6.1 . के उपयोगकर्ता के अनुसार भूमि के जलमग्न होने का प्रश्न

किसी विशेष राज्य के पक्ष में आबंटित अंतर-राज्यीय नदी के संबंध में पानी को पानी के आवंटन के साथ अटूट रूप से जोड़ा गया था और महाराष्ट्र की वर्तमान शिकायत धारा 3 (ए) के अर्थ के भीतर कर्नाटक राज्य की एक कार्यकारी कार्रवाई के कारण एक शिकायत होगी और धारा 3 (ए) के दायरे में एक जल विवाद भी होगा। 2 (ग)

और, इसलिए, इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह किसी न्यायाधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में अनुच्छेद 131 के तहत दायर मुकदमे में उसी पर विचार करे और उसकी जांच करे और जवाब दे। [393 - ए-बी; जी]

6.2 . यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्ति व्यापक है।

संविधान हो सकता है, महाराष्ट्र द्वारा अपने अतिरिक्त लिखित बयान में उठाए गए जलमग्न होने के सवाल पर विचार करना और उस आधार पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई के संबंध में निषेधाज्ञा के सवाल का फैसला करना उचित नहीं होगा। [394 - ए-बी]

दिल्ली न्यायिक सेवा संघ। वी. गुजरात राज्य, [1991] 4 एस. सी. सी. 406 और राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ, [1978] 1 एस. सी. आर. 1, संदर्भित।

7.1 . न्यायाधिकरण का निर्णय एक आदेश नहीं था जिसे होना चाहिए

मुकदमे में निर्णय के आलोक में समझा गया। न्यायाधिकरण की रिपोर्ट भी कोई निर्णय नहीं थी और इसे अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं थी ताकि इसे पक्षों के लिए बाध्यकारी बनाया जा सके। यह केवल न्यायाधिकरण का निर्णय था जिसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक था और इस तरह के प्रकाशन पर 311

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य

यह निर्णय अंतिम हो गया और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी था। [370 - ई-जी]

कालीकृष्ण टैगोर बनाम। राज्य सचिव, एल. आर. 15 इंडियन अपीलस

186 ; 107-08 और 1913 खंड में लॉ रिपोर्ट 25 इंडियन अपीलस। 25 पागल। एलजे 24, संदर्भित किया गया।

7.2 . इस न्यायालय के 30 सितंबर, 1997 के आदेश का मतलब यह नहीं था कि

कि एक डिक्री पारित की जानी चाहिए जिससे पूरी रिपोर्ट के साथ-साथ न्यायाधिकरण की आगे की रिपोर्ट पक्षों पर बाध्यकारी हो। जब एक शिकायत में एक प्रार्थना की गई थी, तो उक्त प्रार्थना को दावे के आलोक में समझा जाना चाहिए। [371 - बी; 370-जी]

एस. बी. मजमुदार, जे. (पूरक):

1. उपलब्ध जल के किसी भी परियोजना-वार आवंटन पर निर्णय नहीं लिया गया था

न्यायाधिकरण ने जहां तक ऊपरी कृष्णा परियोजना (यू. के. पी.) का संबंध है, योजना "ए" तैयार करते समय। [410 - एच]

2. अलमट्टी बांध की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, यह नहीं था।

न्यायाधिकरण की जांच का आदेश और न ही न्यायाधिकरण द्वारा उस संबंध में कोई निर्णय दिया गया था जिसे आंध्र प्रदेश के वर्तमान वाद में इस आधार पर चुनौती का विषय बनाया जा सकता था कि इस संबंध में न्यायाधिकरण के किसी भी स्पष्ट निर्देश का कर्नाटक द्वारा उल्लंघन किया गया था। [410 - एच; 411-ए-बी]

3. यदि अलमट्टी बांध की ऊँचाई एफ. आर. एल. 519.6 मीटर पर तय की जाती तो

न केवल आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि यह भी कम नहीं होगा

विशेषज्ञ समिति की राय के साथ-साथ केंद्रीय जल आयोग द्वारा यू. के. पी. के दूसरे चरण को दी गई मंजूरी की अवहेलना। एफ. आर. एल. 519 मीटर से अधिक ऊंचाई में कोई वृद्धि।

न्यायाधिकरण के किसी भी बाद के निर्णय द्वारा कर्नाटक को पानी के आगे के आवंटन पर निर्भर करता है, क्योंकि यह प्रावधान के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा।

प्रस्तावित योजना "बी" जिसे अभी तक किसी भी जल विवाद न्यायाधिकरण के बाध्यकारी निर्णय का दर्जा नहीं दिया गया था। [419 - ई; 420-सी]

4. एक एफ. आर. एल. 524.256 के साथ अलमट्टी बांध का गठन

कर्नाटक द्वारा निष्पादित और प्रगति पर और विचार की गई अन्य सभी परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा सकती थी और न ही कर्नाटक को अन्य सभी नदी तटीय राज्यों की सहमति के साथ-साथ केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना उस ऊंचाई तक निर्माण करने की अनुमति दी जा सकती थी। हालाँकि, यह सवार के अधीन होगा कि [2000] 3 एस. सी. आर. की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

312

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर्नाटक 519 मीटर की ऊँचाई तक अलमट्टी बांध का निर्माण करेगा। यह आगे विभिन्न कानूनों के तहत काम करने वाले अन्य सभी सक्षम अधिकारियों द्वारा मंजूरी के अधीन था। आवश्यक मंजूरी की आवश्यकता होगी

बांध की ऊँचाई 519 मीटर तक बढ़ाने के लिए कर्नाटक। [427 - डी-ई]

5. एस के संयुक्त पठन पर। 2 (ग) अधिनियम के (i) और 3 (क), शिकायत

कर्नाटक के खिलाफ महाराष्ट्र द्वारा उठाई गई आवाज अनुच्छेद 262 के तहत विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अधिनियम के अग्र कोणों में आएगी और अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। [425 - डी-ई]

प्रति बनर्जी, जे. (सहमत)

1. योजना बी न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं था जिसमें प्रकाशन की आवश्यकता थी

या अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना। कृष्णा घाटी प्राधिकरण योजना का केंद्र होने के कारण, जो अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है, न्यायाधिकरण के निर्णय के रूप में योजना बी के कार्यान्वयन का सवाल न तो उठा और न ही उठ सकता है।

[451 - ई; 453-बी]

विस्कॉन्सिन राज्य बनाम। इलिनोइस राज्य, 74 एल. एड। 799 , संदर्भित किया गया।

2. योजना बी के मुद्दे पर न्यायाधिकरण की टिप्पणियां थीं

पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना। एक न्यायाधिकरण परिकल्पना का फैसला नहीं कर सका

एक निर्णय जो इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, एक कानून जिसे संसद द्वारा या दलों की सहमति से अधिनियमित किया जाना है। केंद्र सरकार नहीं करेगी ऐसे किसी भी निर्देश को लागू करने के लिए सहमत होने का कोई दायित्व है। [452 - बी-सी; जी]

3. कर्नाटक का सूट बनाए रखने योग्य था। यह आवेग से संबंधित था

परामर्श, लेकिन एस के अर्थ के भीतर राज्यों के बीच जल विवाद के किसी और निर्णय की आवश्यकता नहीं थी। 2 ((ग) अधिनियम। [445 - एच; 446-डी]

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ए. आई. आर. (1992) एस. सी. 522; एन. पी.

पोन्नुस्वामी बनाम। निर्वाचन अधिकारी; नामक्कल संविधान, [1952] एस. सी. आर. 218 और मोहिंदर सिंह गिल बनाम। मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली, [1978] 2 एस. सी. आर. 272 का उल्लेख किया गया है।

4. निषेधाज्ञा देने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी क्योंकि

आंध्र प्रदेश द्वारा प्रार्थना की गई थी और न ही इस समय इस तरह के निषेधाज्ञा की आवश्यकता थी। [465 - बी]

कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड बनाम हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, [1999] 7 एस. सी. सी. 313

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य

और कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ, [1978] 2 एस. सी. आर. 1, संदर्भित।

विशेषज्ञों को दी गई रिपोर्ट के कारण, अलमट्टी बांध और इसके ऊपरी हिस्से

हालांकि, कानून के तहत आवश्यक उचित प्राधिकरण या अधिकारियों से मंजूरी के लिए सीमा को एफआरएल 519 विषय पर रखा जा सकता है। सवाल नदी तटीय राज्यों द्वारा रखी गई स्थिति का आकलन करने और जलमग्न होने की आशंका और खरिफ फसल के नुकसान की आशंका का आकलन करने पर न्यायाधिकरण द्वारा अलमट्टी बांध की अंतिम ऊंचाई बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। [468 - बी-सी]

5. न्यायाधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि यदि और कब इस मामले को देखा जाए

कृष्णा नदी बेसिन में पानी के आवंटन के संबंध में अवसर उत्पन्न हुआ, जो समय के लंबे अंतराल और आधुनिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण पहले के न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण द्वारा की गई टिप्पणियों से पूरी तरह से अप्रभावित था। [468 - डी]

प्रति सेठी, जे. (सहमत)

1

पानी का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जल से संबंधित विवाद

प्रबंधन पर कठोर तकनीकी या कानूनी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। (470 - ई-जी)

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: मूल सूट संख्या 1.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत।

अशोक एच. देसाई, सोली जे. सोराबजी, एटनर्नी जनरल्स, हरीश एन. साल्वे,

सॉलिसिटर जनरल, एम. एस. उसगांवकर, आर. एन. त्रिवेदी, के. एन. रावल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एफ. एस. नरीमन, एस. एस. जवाली, ए. के. गांगुली, के. परासरन, टी. आर. अंधारुजिना, एम. एस. नारगोलकर, जी. रघूराम, एन. एन. गोस्वामी, ए. एन. जयराम, (एन. वी. रमना), अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। ए. पी. राज्य के महाधिवक्ता (ए. एन. जयराम) कर्नाटक राज्य के महाधिवक्ता एस. पी. सिंह, सुभाष शर्मा, मोहन

कटारकी, सुश्री पूनम कुमार, संजय आर. हेगड़े, जी. उमापति, जी. प्रभाकर,

सुब्रत बिड़ला, डी. एम. नरगोलकर, एस. वसीम, ए. कादरी, एस. के. द्विवेदी, ए. के. शर्मा, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री सुषमा सूरी, के. के. त्यागी, सुश्री शालिनी भल्ला, विनीत कुमार, के. आर. नागराजा, सी. वी. सुब्बा राव, शंभू पी. सिंह, एस.

ए. पी. राज्य के लिए विजयशंकर, ए. राम नारायण, राजीव शर्मा, (निखिल नय्यर), ध्रुव मेहता, आर. एन. वर्मा, डॉ. एस. सी. जैन और पराग त्रिपाठी उपस्थित पक्षों के लिए।

[

2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

पटनायक जे. कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में होता है।

यह कर्नाटक राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। इसे कई सहायक नदियाँ मिली हैं और स्वतंत्रता पूर्व युग में, तब के बीच बहुत अधिक विवाद नहीं था।

किसी भी अंतर-राज्यीय नदी के पानी के बंटवारे के लिए राज्य। तब भी, जब एक राज्य में बड़े पैमाने पर परियोजनाएं शुरू की गई थीं, तो अन्य तटवर्ती राज्य नदी से अपने हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे और इस संदर्भ में, कृष्णा बेसिन में दूसरी नदी तुंगभद्रा के पानी को साझा करने के लिए, 1944 में एक समझौता हुआ था, जिसमें उक्त नदी तुंगभद्रा के पानी के हिस्से से संबंधित विवाद का निपटारा किया गया था। भारत का संविधान लागू होने के बाद, कृष्णा बेसिन बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद और मद्रास राज्यों के क्षेत्रों में आ गया। राज्यों ने कृष्णा बेसिन के पानी के उचित उपयोग के लिए बड़ी परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनाई और जुलाई, 1951 में चार तटवर्ती राज्यों के बीच कृष्णा नदी प्रणाली की उपलब्ध आपूर्ति के विभाजन के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया था

अर्थात्, बॉम्बे, हैदराबाद, मद्रास और मैसूर राज्य। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त समझौता ज्ञापन एक के लिए वैध रहने के लिए तैयार किया गया था

25 साल की अवधि और उस समय भी, मैसूर राज्य ने समझौते की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। सिफारिशों को लागू करने के बाद

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, वर्ष 1956 में, कृष्णा बेसिन को बॉम्बे, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों द्वारा नियंत्रित किया गया।

नदी तटीय राज्य बन गए। इनमें से प्रत्येक राज्य कृष्णा घाटी के पानी पर अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए सक्रिय हो गया और केंद्रीय जल और विद्युत आयोग ने कृष्णा जल के पुनः आवंटन के लिए एक योजना तैयार की थी। हालाँकि यह राज्यों को स्वीकार्य नहीं था और राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। जब भी कोई नदी तटीय राज्य बड़ी परियोजनाओं के साथ आएगा, तो अन्य राज्य उसी पर आपत्ति करेंगे। विभिन्न राज्यों द्वारा बड़ी परियोजनाओं का निर्माण करने से, उपलब्ध आपूर्ति पर अधिक दबाव पड़ गया और नदी तटीय राज्यों के बीच विवाद

अधिक से अधिक कड़वे हो गए। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर और श्रीशैलम परियोजनाओं के साथ-साथ महाराष्ट्र में कोयना परियोजना के संबंध में कई आपत्तियां उठाई गईं। केंद्र सरकार ने 1963 में इस आधार पर लंबित नई परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय लिया था कि महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों द्वारा पानी की निकासी क्रमशः 400,600 और 800 टी. एम. सी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार का यह निर्णय महाराष्ट्र राज्य को स्वीकार्य नहीं था और जून, 1963 में महाराष्ट्र सरकार ने सरकार से अनुरोध किया था। भारत की ओर से '315 बनाने के लिए

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे।

न्यायाधिकरण को विवादों का निर्देश। 1963 से 1969 की अवधि के बीच, केंद्र सरकार ने नदी तटीय राज्यों के बीच विवादों को बातचीत और कई अंतर-राज्य सम्मेलनों के माध्यम से हल करने की पूरी कोशिश की।

लेकिन इसे वर्ष 1968 और 1969 में विवाद के संदर्भ के लिए अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। फिर, राज्यों के पुनर्गठन और मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच तुंगभद्रा घाटी के पुनः वितरण के कारण, पहले के तुंगभद्रा समझौते की वैधता और तुंगभद्रा के नियंत्रण और वितरण के बारे में भी विवाद उत्पन्न हुए।

पानी। कर्नाटक राज्य मैसूर राज्य का उत्तराधिकारी राज्य है। अंत में 10 अप्रैल, 1969 को भारत सरकार ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया और अंतर-राज्यीय नदी कृष्णा और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवादों के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण का आह्वान किया। न्यायाधिकरण का गठन अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 4 के तहत किया गया था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। सामग्री पर विचार करने पर उक्त न्यायाधिकरण

उसके समक्ष रखे गए, उसे भेजे गए मामलों की जांच की और केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्यों को प्रस्तुत किया गया और अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत 24 दिसंबर, 1973 को उसे भेजे गए मामलों के अपने निर्णय दिए गए। उक्त रिपोर्ट और निर्णय की प्राप्ति पर, भारत सरकार के साथ-साथ तीन नदी तटीय राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत आगे के विचार के लिए न्यायाधिकरण को

निर्देश दिए और उन संदर्भों पर विचार करने पर न्यायाधिकरण ने अपनी आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि

स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन, जैसा कि न्यायाधिकरण 27 मई, 1976 को धारा 5 (3) के तहत उसे निर्दिष्ट मामलों पर उचित समझता है। यह कहा जा सकता है कि 24 दिसंबर, 1973 की मूल रिपोर्ट में न्यायाधिकरण का अंतिम आदेश था और 27 मई, 1976 की अगली रिपोर्ट में संशोधित अंतिम आदेश भी था, जो दिए गए स्पष्टीकरणों के कारण संशोधन आवश्यक था। अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा दिए गए संदर्भ। केंद्र सरकार ने उपरोक्त अंतिम आदेश को न्यायाधिकरण का निर्णय माना और तदनुसार, इसे 31 मई, 1976 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया और इस तरह के प्रकाशन पर, उक्त अंतिम आदेश वैधानिक रूप से अंतिम हो गया है और विवाद के पक्षों पर बाध्यकारी हो गया है।

न्यायाधिकरण की रिपोर्ट के साथ-साथ आगे की रिपोर्ट में, प्रस्तुत किया गया

न्यायाधिकरण द्वारा दो योजनाएं विकसित की गई हैं-योजना "ए" और योजना "बी"। सभी राज्यों के बीच समझौते के आधार पर पानी की उपलब्धता

2060 टी. एम. सी. में कृष्णा बेसिन में 75 प्रतिशत निर्भरता का पता चला था।

[2000] 3 एस. सी. आर.

316

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण ने योजना "ए" के तहत तीन नदी तटीय राज्यों के पक्ष में 75 प्रतिशत का सामूहिक आवंटन किया, जो 2060 टी. एम. सी. पर आया था, यह दर्शाता है कि महाराष्ट्र राज्य 560 टी. एम. सी. से अधिक किसी भी जल वर्ष में उपयोग नहीं करेगा, कर्नाटक राज्य 700 टी. एम. सी. से अधिक किसी भी जल वर्ष में उपयोग नहीं करेगा और आंध्र प्रदेश राज्य किसी भी जल वर्ष में 800 टी. एम. सी. से अधिक का उपयोग नहीं करेगा। इसने यह भी संकेत दिया था कि आंध्र प्रदेश राज्य जो कि अंतिम नदी तट मालिक है, शेष का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। जल जो कृष्णा नदी में बह रहा हो, लेकिन ऐसे उपयोगकर्ता द्वारा राज्य अतिरिक्त मात्रा के संबंध में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं करेगा, जिसका उपयोग वह 800 टी. एम. सी. की आवंटित मात्रा से अधिक करता है। यह कहा जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान, राज्यों द्वारा न्यायाधिकरण की जांच के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत की

गई थीं और न्यायाधिकरण ने ऐसी सभी योजनाओं पर विचार किया और अंत में योजना "ए" विकसित की थी। 4 मई, 1973 को तीनों राज्यों ने न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए जाने वाले आवंटन के तरीके पर अपने-अपने वकीलों के हस्ताक्षर के तहत अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष प्रदर्शनी एमआरके-340 के रूप में चिह्नित किया गया था और उस दस्तावेज के तहत पक्षों ने न्यायाधिकरण से न केवल 75 प्रतिशत पर उपयोग करने योग्य भरोसेमंद प्रवाह का बड़े पैमाने पर आवंटन करने का आह्वान किया था, बल्कि अधिशेष के प्रतिशत के आधार पर आवंटन के साथ-साथ प्रवाह के घाटे वाले वर्षों और उपयोग के संबंध में प्रतिबंधों और ऐसे प्रतिबंधों की प्रकृति का निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना था। इसने न्यायाधिकरण से अधिशेष के साथ-साथ प्रवाह के घाटे वाले वर्षों में प्रतिशत के आधार पर उक्त आवंटन की निगरानी के लिए एक संयुक्त नियंत्रण निकाय बनाने का भी आह्वान किया। अधिशेष के साथ-साथ प्रवाह के घाटे वाले वर्षों में प्रतिशत के आधार पर आवंटन को प्रभावी बनाने के लिए, न्यायाधिकरण ने योजना "बी" विकसित की और अपनी मूल रिपोर्ट के साथ-साथ अपनी अगली रिपोर्ट में भी इसका संकेत दिया। लेकिन योजना "बी" के उचित कार्यान्वयन के लिए, कृष्णा घाटी प्राधिकरण का गठन बहुत आवश्यक था और आंध्र प्रदेश राज्य नियंत्रण प्राधिकरण के गठन के लिए सहमत नहीं होने के कारण, न्यायाधिकरण ने योजना "बी" को अपने अंतिम आदेश के हिस्से के रूप में नहीं बनाया, हालांकि उक्त योजना "बी" अपनी मूल रिपोर्ट के साथ-साथ आगे की रिपोर्ट का एक हिस्सा थी और इस मामले को प्रतिद्वंद्वी राज्यों के अच्छे ज्ञान पर छोड़ना उचित समझा या संसद के लिए सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत उस प्रभाव के लिए एक कानून बनाना उचित समझा।

संविधान। कर्नाटक राज्य की हालांकि यह राय है कि

न्यायाधिकरण के निर्णय का एक हिस्सा बनने के कारण योजना "बी" को केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचित करने की भी आवश्यकता थी, जिससे इसे पक्षों के लिए बाध्यकारी बनाया गया और ऐसा नहीं किया गया, इसलिए 1 मार्च, 1997 को वर्तमान मुकदमा दायर किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र राज्य और भारत संघ को पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. की मांग की गई।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 317

भारत न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई योजना "बी" को अधिसूचित करेगा और इसके कार्यान्वयन के लिए कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करेगा। न्यायाधिकरण के निर्देश अपनी रिपोर्ट और आगे की रिपोर्ट में। कर्नाटक राज्य ने भी निषेधाज्ञा के आदेश के लिए

प्रार्थना की है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 को तेलगु गंगा जैसी कई अन्य परियोजनाओं को निष्पादित करने से रोक दिया गया है।

न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई योजना "बी" के प्रभावी ढंग से लागू होने तक श्रीशैलम दाहिने किनारे की नहर, श्रीशैलम बाएं किनारे की नहर, भीमा लिफ्ट सिंचाई और पुलीचिंतला परियोजनाएं। वादमे दर्शायल गेल कार्रवाईक कारण प्रतिवादी सं। 1 और 2 2060 टी. एम. सी. से अधिक अतिरिक्त जल के बंटवारे और योजना "बी" के कार्यान्वयन के लिए सहमति देना।

वादपत्र में किए गए दावों के अनुसार, विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय की व्याख्या के दायरे और विस्तार पर केंद्रित है, और विशेष रूप से खंड 5 (ग) "के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना" बी "के कार्यान्वयन के लिए पहले प्रतिवादी का इनकार और आंध्र प्रदेश राज्य का 2060 टी. एम. सी. से अधिक अतिरिक्त पानी का उपयोग बड़े पैमाने पर स्थायी परियोजनाओं का निर्माण करके करने का दावा। वादी, कर्नाटक राज्य ने अपनी शिकायत में न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निर्णय का व्यापक रूप से उल्लेख किया, जिसमें संकेत दिया गया कि न्यायाधिकरण ने 2060 टी. एम. सी. के आवंटन के प्रश्न पर विचार किया, जो बदले में विजयवाड़ा तक कृष्णा नदी के 75 प्रतिशत भरोसेमंद प्रवाह के आधार पर निर्धारित किया गया था और खंड VI में प्रदान की गई सीमा तक उनके लाभकारी उपयोग के लिए तीन राज्यों, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को आवंटित किया गया था। क्रमशः 560 टी. एम. सी., 700 टी. एम. सी. और 800 टी. एम. सी. से अधिक नहीं। शिकायत में यह भी कहा गया था कि न्यायाधिकरण की राय थी कि कृष्णा नदी के पानी के पूर्ण उपयोग के लिए,

अतिरिक्त और घाटे वाले दोनों वर्षों के लिए प्रावधान किए जाएंगे और तदनुसार, योजना "बी" विकसित की जाएगी, लेकिन कृष्णा घाटी प्राधिकरण के गठन के बाद से यदि उपरोक्त योजना "बी" की आधारशिला थी और आंध्र प्रदेश राज्य उक्त कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के लिए सहमत नहीं था, तो न्यायाधिकरण ने ऐसी योजना को लागू करने का सवाल दलों की अच्छी समझ या संसद के विवेक पर छोड़ दिया। कर्नाटक राज्य ने यह भी कहा है कि न्यायाधिकरण के समक्ष [2000] 3 एस. सी. आर. के तहत स्पष्टीकरणात्मक आवेदन दायर किए गए थे।

योजना "बी" के संबंध में अधिनियम की धारा 5 (3) और न्यायाधिकरण ने इस पर विचार किया और स्पष्टीकरण देकर मांगे गए स्पष्टीकरणों का जवाब दिया।

और/या मूल योजना में संशोधन और इसलिए, न्यायाधिकरण ने स्वयं इस स्थिति को स्वीकार किया कि मूल रिपोर्ट में निहित योजना "बी" भी न्यायाधिकरण का एक निर्णय है जिसे स्पष्ट या समझाया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत आवेदन दायर किया जा रहा है। तब शिकायत में बताया गया है कि कैसे 27 मई, 1976 की अगली रिपोर्ट में न्यायाधिकरण ने

2060 टी. एम. सी. से अधिक के अधिशेष प्रवाह में संबंधित राज्यों के शेयरों की जांच और निर्धारण किया गया और कैसे अंततः प्रत्येक जल वर्ष में सभी जल के पूर्ण और बेहतर उपयोग के लिए एक व्यापक योजना "बी" तैयार की गई और फिर भी इसे प्रभावी नहीं बनाया जा सका क्योंकि न्यायाधिकरण ने सभी नदी तटीय राज्यों के बीच समझौते के अभाव में एक प्राधिकरण का गठन करना अनुचित समझा। इस संदर्भ में न्यायाधिकरण ने कहा था कि पक्षों की सर्वसम्मति सहमति और अनुमोदन के बिना न्यायिक डिक्री द्वारा प्रशासनिक प्राधिकरण लागू करना मूल्यपूर्ण और अव्यावहारिक है। वादी के अनुसार, चूंकि योजना "बी" में कृष्णा नदी के पानी के पूर्ण और बेहतर उपयोग का प्रावधान किया गया है, जिसे न्यायाधिकरण ने इस मामले पर गहराई से विचार करने के बाद स्वयं विकसित किया है, इसलिए इसे न्यायाधिकरण का निर्णय माना जाना चाहिए, जिसे अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाना आवश्यक है और चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा अपनी आगे की रिपोर्ट देने पर पक्षकार किसी प्राधिकरण के गठन के लिए सहमत नहीं हुए थे, इसलिए इसे अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं बनाया जा सका। लेकिन वादी के अनुसार, धारा 6 (ए) को अधिनियम में शामिल किया गया है, जिससे केंद्र सरकार को प्राधिकरण की स्थापना सहित न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए योजना या योजनाएं बनाने में सक्षम बनाया गया है, उक्त योजना "बी" को लागू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है और न्यायालय द्वारा केंद्र को उचित निर्देश दिए जा सकते हैं।

प्राधिकरण के गठन और योजना "बी" को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए सरकार। वादी ने शिकायत में यह भी कहा कि कैसे कर्नाटक राज्य समय-समय पर आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार से योजना 'बी' के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध करता रहा है और कैसे उक्त राज्य ने योजना 'बी' को लागू किया है।

आंध्र प्रदेश के प्रतिवादी नंबर 1 ने कार्यान्वयन के लिए सहमत होने से इनकार कर दिया है योजना "बी"।

प्रतिवादी नं. 1, आंध्र प्रदेश राज्य ने लिखित बयान में

दायर किए गए, प्रारंभिक आपत्ति ली कि वादी द्वारा मांगा गया निर्णय स्वयं एक जल विवाद है और इसलिए, अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत जनादेश को देखते हुए अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा वर्जित है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आगे लिया गया रुख यह है कि यह केवल योजना "ए" है जिसे कर्नाटक और ओ. आर. एस. का राज्य माना जा सकता है।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 319

न्यायाधिकरण का निर्णय जो अधिनियम की धारा 6 के तहत उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होता है और न्यायाधिकरण ने योजना "बी" के निर्माण के संबंध में जो कुछ भी अवलोकन किया है, वह केवल अस्थायी और आज्ञाकारी अवलोकन है और इसे न्यायाधिकरण के निर्णय का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और इस तरह यह अप्रवर्तनीय है। यह भी कहा गया है कि न्यायाधिकरण ने स्वयं संकेत दिया है कि योजना "बी" को या तो पक्षों की सहमति से या संसद और दलों द्वारा कानून द्वारा लागू किया जा सकता है।

सहमत नहीं होने पर, न्यायालय निर्देश देने में सक्षम नहीं होगा

संसद के पास एक कानून होना चाहिए और इसलिए, मुकदमे में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती है। यह भी कहा गया है कि अंतिम आदेश के खंड 5 (सी) को ध्यान में रखते हुए, जिसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य को कृष्णा नदी में बहने वाले किसी भी पानी का उपयोग करने का अधिकार है, ताकि वह समुद्र में प्रवेश करके बर्बाद न हो और इसलिए, आंध्र प्रदेश राज्य को कई परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने से रोकने की प्रार्थना मनोरंजक नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 आगे दावा करता है कि योजना "ए" पर पक्षों द्वारा दो दशकों से अधिक समय से कार्य किया जा रहा है और उक्त योजना समीक्षा के तहत 31 मई, 2000 के बाद प्रदान की गई है, इस अवधि में योजना "बी" के कार्यान्वयन का प्रश्न न केवल असमान है, बल्कि पूरी तरह से अनावश्यक भी है। वादपत्र के विभिन्न पैराग्राफ में किए गए दावे का खंडन करते हुए, यह दोहराया गया है कि योजना "बी" कभी भी निर्णय का हिस्सा नहीं थी और इस तरह से इसके प्रभाव का सवाल नहीं उठता है और आगे अधिनियम की धारा 6 (ए) न्यायाधिकरण की रिपोर्ट प्रकाशित होने की तारीख को कानून की पुस्तक में नहीं है, यह संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, वादी ने इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के प्रयास में एक काल्पनिक विवाद को उठाने का प्रयास किया है ताकि सभी संबंधित लोगों का ध्यान उन अवैध परियोजनाओं से हटा दिया जाए जो न्यायाधिकरण के निर्णय के विपरीत उसके द्वारा निष्पादित की जा रही हैं और मुकदमे में ईमानदारी

का अभाव है। यह भी कहा गया है कि तथाकथित योजना "बी" केवल एक अस्थायी योजना थी और इसके बिना कृष्णा घाटी नामक निगरानी प्राधिकरण का गठन किया गया था।

प्राधिकरण, इसे किसी भी बाध्यकारी प्रभाव वाले न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता है। जहां तक आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का संबंध है, यह बताया गया है कि न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय से पहले ही त्रिपक्षीय समझौते के तहत वादी स्वेच्छा से 15 की आपूर्ति के लिए सहमत हो गया था।

मद्रास को पीने के पानी का टी. एम. सी., जो कि तेलगु गंगा परियोजना है और इसलिए, इस मुद्दे पर वादी की आपत्ति निराधार और तुच्छ है। वादी द्वारा आपत्ति की गई अन्य परियोजनाओं के संबंध में, यह कहा गया है कि न्यायाधिकरण ने स्वयं आंध्र प्रदेश राज्य को कृष्णा नदी में बहने वाले अतिरिक्त पानी का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान की है और इसलिए, [2000] 3 एस. सी. आर. किया गया है।

320

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण द्वारा दी गई उक्त स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं। यह भी कहा गया है कि न्यायाधिकरण ने अपनी अगली रिपोर्ट में योजना "ए" को अपने अंतिम निर्णय के रूप में अपनाया है, यह केवल वही योजना है जो पक्षों के लिए बाध्यकारी है और जो भी योजना "बी" के रूप में कहा गया है वह न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य, प्रतिवादी संख्या 2 ने भी यह रुख अपनाया था कि

योजना 'ख' के कार्यान्वयन का निर्देश देने के लिए वाद बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि इसका कार्यान्वयन राज्यों की सहमति पर निर्भर करता है और न्यायालय राज्यों को अपनी सहमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है और न ही न्यायालय संसद को इसके लिए कोई कानून बनाने का निर्देश दे सकता है। हालाँकि प्रतिवादी संख्या 2 ने आंध्र प्रदेश राज्य, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तेलगु गंगा, श्रीशैलम आरबीसी, श्रीशैलम एलबीसी, भीमा लिफ्ट और पुलीचिंतला जैसी परियोजनाओं का निर्माण करके कृष्णा नदी के शेष पानी को स्थायी रूप से विनियोजित करने के कर्नाटक राज्य के आरोप से सहमति व्यक्त की। महाराष्ट्र राज्य का सकारात्मक रुख यह है कि जब तक पूरे कृष्णा बेसिन में कैरी ओवर जलाशयों की एक श्रृंखला नहीं बनाई जाती, तब तक

योजना "बी" के कार्यान्वयन का सवाल ही नहीं उठेगा और चूंकि उक्त कैरी ओवर जलाशय का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए इसे लागू करने की प्रार्थना की जाती है।

योजना "बी" अपरिपक्व है। कथित प्रतिवादी ने यह भी कहा कि मांगी गई राहत अनिवार्य रूप से अंतिम आदेश की समीक्षा है और योजना "बी" के कार्यान्वयन के लिए प्रार्थना को उचित ठहराने वाली कोई परिस्थितियां नहीं थीं, विशेष रूप से, जब 31 मई, 2000 के बाद समीक्षा प्रदान की जाती है, जो काफी निकट है। महाराष्ट्र राज्य प्रतिवादी संख्या 2 आंध्र प्रदेश, प्रतिवादी संख्या 1 के रुख को दोहराता है कि यह योजना "ए" के संदर्भ में न्यायाधिकरण का निर्णय है, जो सभी राज्यों पर अंतिम और बाध्यकारी आदेश है न कि उक्त न्यायाधिकरण की रिपोर्ट में निहित योजना "बी" का निर्माण।

भारत संघ, प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने लिखित बयान में यह रुख अपनाया

कि संविधान के अनुच्छेद 262 के साथ पठित अधिनियम की धारा 11 के आधार पर वाद बनाए जाने योग्य नहीं है। जहां तक आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा पानी के उपयोगकर्ता का संबंध है, केंद्र सरकार का तर्क है कि इस पुरस्कार में पानी की कुल मात्रा निर्धारित की गई है जिसका उपयोग महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश द्वारा किसी दिए गए जल वर्ष में किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश को अधिशेष जल का उपयोग करने की स्वतंत्रता, उक्त स्वतंत्रता आंध्र प्रदेश राज्य में कोई अधिकार प्रदान या सृजित नहीं करती है और ऐसा उपयोगकर्ता ऊपरी नदी तटीय राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकार के अधीन होगा। केंद्र सरकार आगे इस बात पर जोर देती है कि पुरस्कार एक परियोजना-वार आवंटन नहीं देता है, बल्कि सकल आवंटन करता है और प्रत्येक राज्य न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य है।

कर्नाटक और ओ. आर. एस. के कथन पर। वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 321

अभियोग के पैराग्राफ में, केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि ई सभी रिकॉर्ड का विषय है और आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

पक्षों की दलीलों पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए हैं:

2. क्या मुकदमा कारण का खुलासा नहीं करने के कारण खारिज किया जा सकता है कार्रवाई? (ए. पी)

3. क्या मुकदमा राहत की मांग के रूप में खारिज होने योग्य है जो

के. डब्ल्यू. डी. टी. की रिपोर्ट और निर्णय के विपरीत हैं? (ए. पी)

4. पक्षकारों पर बाध्यकारी के. डब्ल्यू. डी. टी. का "निर्णय" क्या है?

अधिनियम की धारा 6 के तहत:

(क) योजना 'ख' (ख) खंड (वी) (सी) में विचार के अनुसार अतिरिक्त पानी का उपयोग

पुरस्कार का खंड XIV (A)।

5. क्या के. डब्ल्यू. डी. टी. की पहली और अगली रिपोर्ट में योजना 'बी' का संदर्भ, एक पूरी योजना का खुलासा करता है, और क्या ऐसी योजना प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 11 में निर्दिष्ट परिस्थितियों और आंध्र प्रदेश के लिखित बयान में विरोधाभासी जवाब के पैरा 1 को देखते हुए इस स्तर पर कार्यान्वयन करने में सक्षम है? (ए. पी)

6. क्या इस पर योजना 'बी' को लागू करना उचित, उचित और न्यायसंगत है?

स्टेज? (एमएएच)।

7. क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि योजना 'बी' इसका हिस्सा नहीं है

धारा के तहत मूल रिपोर्ट में के. डब्ल्यू. डी. टी. के "अंतिम आदेश" 5 (2) और अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत आगे की रिपोर्ट, योजना 'बी' के कार्यान्वयन की मांग करने वाला मुकदमा बनाए रखने योग्य है? (ए. पी)

8. क्या 1980 में आई. एस. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 1956 में Sec.6A का समावेशन, इप्सो फैक्टो कामटक को योजना 'बी' के कार्यान्वयन की मांग करने का अधिकार देता है

जैसा कि एक योजना तैयार करके न्यायाधिकरण की रिपोर्टों में संदर्भित किया गया है?

(के. ए. आर.-ए. पी. द्वारा संशोधित)

[

2000] 3 एस सी आर।

322

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. क्या अतिरिक्त जल का उपयोग करने का आंध्र प्रदेश का अधिकार है

न्यायाधिकरण के निर्णयों द्वारा दी गई स्वतंत्रता की शर्तें हैं -

वर्तमान कार्यवाहियों में पुनरीक्षण योग्य? (ए. पी)

10. क्या के निर्णय के तहत अतिरिक्त पानी का उपयोग करने की स्वतंत्रता के. डब्ल्यू. डी. टी. ए. पी. द्वारा अतिरिक्त पानी के उपयोग को रोकता है।

स्थायी प्रकृति की परियोजनाएं? (ए. पी. द्वारा संशोधित के. ए. आर.)

11. क्या के. डब्ल्यू. डी. टी. का निर्णय आंध्र राज्य को अधिकार देता है प्रदेश निम्नलिखित परियोजनाओं को निष्पादित करेगा: - (के. ए. आर. के द्वारा संशोधित

(क) तेलुगु गंगा परियोजना

(ख) श्रीशैलम दाहिने किनारे की नहर

(ग) श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल

(घ) भीम लिफ्ट सिंचाई

(ई) पुलीचिंतला डायवर्जन

12. क्या वादी का मुकदमा अनावश्यक और अपरिपक्व नहीं है

2000 ईस्वी के बाद न्यायाधिकरण के आदेशों की समीक्षा की जा सकती है? (एमएएच)

13. वादी किन राहतों, यदि कोई हो, का हकदार है? (ए. पी.) "

मुद्दे 4,5 और 7।

इन तीनों मुद्दों को एक साथ उठाया जाता है क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं।

तथ्य यह है कि मुकदमे का भाग्य काफी हद तक उपरोक्त मुद्दों के जवाब पर निर्भर करता है। वादी-कर्नाटक राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरीमन ने तर्क दिया कि जल विवाद के संदर्भ में जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत न्यायाधिकरण को भेजा गया था और उक्त न्यायाधिकरण ने उसे संदर्भित मामलों की जांच की थी और लोगों के बीच कृष्णा नदी में पानी के वितरण के लिए दो योजनाएं तैयार की थीं। तीन नदी तटीय राज्य, योजना "ए" को तत्काल प्रभाव देते हुए और योजना "बी" के संबंध में प्रभाव देने की तारीख को स्थगित करते हुए, क्योंकि निगरानी प्राधिकरण के गठन के लिए नदी तटीय राज्यों के बीच कोई

समझौता नहीं था, उक्त योजना-"बी" को न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं माना जा सकता है और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना आवश्यक था।

अधिनियम की धारा 6 के तहत, तीनों राज्यों पर सारने को बाध्यकारी बनाना।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 323

श्री नरीमन के अनुसार, अधिनियम में न्यायाधिकरण द्वारा दी जाने वाली एक रिपोर्ट की परिकल्पना की गई है जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्यों को प्रस्तुत किया जाएगा और उसे निर्दिष्ट मामलों पर अपना निर्णय दिया जाएगा और योजना "बी" को अतिरिक्त जल वर्ष और कमी वाले जल वर्ष दोनों के संबंध में कृष्णा नदी के जल में राज्यों के संबंधित हिस्से का निर्णय माना जाएगा।

न्यायाधिकरण का निर्णय माना जाता है और केवल योजना "ए" वाले अंतिम आदेश को न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं माना जा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार केवल अंतिम आदेश को प्रकाशित करने में धारा 6 के तहत अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही, जो केवल 75 प्रतिशत निर्भरता पर तीन राज्यों के पक्ष में एक सामूहिक आवंटन है, न कि पूरे विवाद का निर्णय, जिसे न्यायाधिकरण को भेजा गया था। श्री नरीमन ने आगे कहा कि न्यायाधिकरण अपनी रिपोर्ट दिनांक 1 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है-"इस मामले पर गहराई से विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बेहतर होगा कि हम महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी के विभाजन के लिए दो योजनाएं तैयार करें। इन योजनाओं को योजना "ए" और "बी" कहा जाएगा। योजना "ए" अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम की धारा 6 के तहत आधिकारिक राजपत्र में इस न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। योजना "बी" को उस स्थिति में लागू किया जा सकता है जब महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्य एक अंतर-राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन करते हैं जिसे उनके बीच समझौते द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ऐसे प्राधिकरण का गठन किए जाने की स्थिति में कृष्णा घाटी प्राधिकरण कहा जा सकता है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि योजना "बी" न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं था। वास्तव में न्यायाधिकरण स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि योजना "बी" अधिक व्यापक है और कृष्णा नदी के पानी के उपयोग के अधिक न्यायसंगत तरीके का प्रावधान करती है और फिर भी इसे अंतिम आदेश का हिस्सा बनाने से परहेज किया क्योंकि नदी तटीय राज्यों के बीच समझौते की कमी के कारण एक निगरानी प्राधिकरण का गठन नहीं किया जा सका और न ही पक्षों की सहमति के बिना एक निगरानी प्राधिकरण लागू करना बुद्धिमानी और व्यावहारिक था और इस मामले के दृष्टिकोण में योजना "बी" को न्यायाधिकरण का निर्णय माना जाना चाहिए जो कृष्णा नदी के पानी में प्रत्येक राज्य के शेयरों का निर्णय करता

है, जिससे अधिशेष और साथ ही साथ कमी दोनों के संबंध में विभाजन होता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरीमन ने यह भी आग्रह किया कि तीन राज्य महाराष्ट्र, तत्कालीन मैसूर (वर्तमान में कर्नाटक) और आंध्र प्रदेश ने खुद सहमति दी और न्यायाधिकरण द्वारा आवंटन की विधि को अपनाने के लिए अनुरोध किया: (i) 75 प्रतिशत पर उपयोग करने योग्य भरोसेमंद प्रवाह का सामूहिक आवंटन, (ii) प्रतिशत पर आवंटन।

(3) उपयोग के संबंध में प्रतिबंध और न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले प्रतिबंधों की प्रकृति और [2000] 3 एस. सी. आर.

324

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iv) के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए एक संयुक्त नियंत्रण निकाय का गठन

न्यायाधिकरण, और योजना "ए" उपरोक्त मद (i) का निर्णय और योजना "बी" उपरोक्त मद (ii), (iii) और (iv) का निर्णय होने के कारण, यह अकल्पनीय है कि योजना "बी" न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं है। श्री नरीमन ने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय पर विचार करने के बाद यदि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की राय है कि स्पष्टीकरण या आगे विचार की आवश्यकता है, फिर एक और संदर्भ दिया जा सकता है और इस तरह का एक संदर्भ/स्पष्टीकरण, कर्नाटक राज्य द्वारा योजना "बी" के संबंध में किया गया है और स्वयं न्यायाधिकरण ने उसी पर विचार और उत्तर दिया है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए खुला नहीं है कि योजना "बी" न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं है। इस संबंध में श्री नरीमन ने यह भी तर्क दिया कि हालांकि महाराष्ट्र राज्य और कर्नाटक राज्य को भी न्यायाधिकरण द्वारा राज्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर सुना गया था।

कर्नाटक ने किसी भी समय यह रुख नहीं अपनाया था कि योजना "बी" एक निर्णय नहीं है और इस तरह के संबंध में धारा 5 (3) के तहत स्पष्टीकरण

वही मनोरंजक नहीं था। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि योजना "बी" भी न्यायाधिकरण का निर्णय है, बशर्ते कि कृष्णा नदी में पानी के बेहतर और पूर्ण न्यायसंगत वितरण के लिए और विचाराधीन मुद्दे का जवाब कर्नाटक राज्य के पक्ष में दिया जाना चाहिए। श्री नरीमन ने यह भी आग्रह किया कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, [1993] में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि

न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश को भी अधिनियम की धारा 5 (2) के अर्थ के भीतर एक रिपोर्ट और निर्णय माना जाना चाहिए और मामले के इस दृष्टिकोण में अंतिम निर्णय विकसित करने वाली योजना "बी" को न्यायाधिकरण का निर्णय माना जाना चाहिए और इसलिए अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इसे प्रकाशित करने की आवश्यकता है।

श्री परासरन, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादी नं।

1, दूसरी ओर आंध्र प्रदेश राज्य का तर्क है कि वादी ने अपने

वादी ने यह भी नहीं कहा है कि योजना "बी" न्यायाधिकरण का निर्णय है। विद्वान वकील के अनुसार समग्र रूप से पढ़ा गया वाद इंगित करता है कि वादी योजना "ए" और योजना "बी" दोनों को लागू करना चाहता था और इस प्रकार मांगी गई राहत इन दोनों योजनाओं का समामेलन है जो वादी-राज्य के लिए अनुकूल है और जरूरी नहीं कि योजना "बी" का कार्यान्वयन हो और यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि वादी इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था कि उक्त योजना "बी" निर्णय का हिस्सा नहीं है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने वाद के पैराग्राफ 2 (बी) में किए गए दावों पर भरोसा किया, जो वास्तव में योजना "ए" से संबंधित है न कि योजना "बी" से। उन्होंने पैराग्राफ 6 (1) में किए गए दावों पर भी भरोसा किया, जिसमें वादी ने स्वयं कर्नाटक और ओ. आर. एस. के राज्य का उल्लेख किया है।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 325

कि न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम निर्णय के हिस्से के रूप में योजना "ए" बनाई और योजना "बी" को दलों के अच्छे ज्ञान या संसद के विवेक पर छोड़ दिया। श्री परासरन ने शिकायत के पैराग्राफ 21 में किए गए दावे के संदर्भ में भी तर्क दिया कि वादी के अनुसार न्यायाधिकरण ने केवल योजना "बी" को अपनाने के लिए सभी राज्यों की सहमति प्राप्त करने की उम्मीद व्यक्त की और इसलिए, यह न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं था। श्री परासरन ने पैराग्राफ 23 में किए गए दावों पर भी दृढ़ता से भरोसा किया "जैसा कि पहले प्रस्तुत किया गया था, न्यायाधिकरण ने दावों पर निर्णय लेते हुए योजना "बी" के तहत अधिशेष जल में बेसिन राज्यों के अधिकारों को घोषित किया है, हालांकि ऐसी योजना को निर्णय का हिस्सा नहीं बनाया गया था" और तर्क दिया कि उपरोक्त स्वीकारोक्ति

वादी का भाग मामले को स्वीकार करता है और योजना "बी" को न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं माना जा सकता है। वास्तव में श्री परासरन ने कहा कि वाद में उपरोक्त कथन को देखते हुए और आदेश 12 नियम 6 में निहित प्रावधान को देखते हुए, वाद को तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। श्री परासरन ने यह भी आग्रह किया कि शिकायत केवल अतिरिक्त पानी को साझा

करने के लिए है जैसा कि योजना "बी" में इंगित किया गया है, जिसने योजना "ए" के तहत बड़े पैमाने पर आवंटन का लाभ प्राप्त किया है और इस प्रकार यह योजना "बी" के कार्यान्वयन के लिए मुकदमा नहीं है जैसा कि वादी राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री नरीमन ने तर्क दिया है। श्री परासरन के अनुसार, कृष्णा घाटी प्राधिकरण जैसे निगरानी प्राधिकरण का गठन योजना "बी" का आधार है और न्यायाधिकरण इस तरह के प्राधिकरण का गठन करने के लिए पक्षों की सहमति प्राप्त करने में विफल रहा है और सातवीं की सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत संसद द्वारा कोई कानून नहीं है।

अनुसूची, अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण ने योजना "बी" जैसी अधिक न्यायसंगत योजना की कल्पना की थी और अपना खाका दिया था, लेकिन यह अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय के चरित्र को भाग नहीं ले सकता है, ताकि इसे सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी बनाया जा सके। विद्वान वकील श्री परासरन के अनुसार, यह न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय या आदेश है जिसे किसी भी समझौते या कानून से स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सकता है।

संसद द्वारा बनाया गया, जैसा कि इस मामले में अंतिम आदेश, जिसमें योजना "ए" शामिल है, जिसे न्यायाधिकरण का निर्णय माना जा सकता है, न कि कार्यवाही के दौरान रिपोर्ट में किया गया कोई अवलोकन या आदेश। श्री परासरन ने आग्रह किया कि न्यायाधिकरण अपनी आगे की रिपोर्ट में पीके2 को प्रदर्शित करे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "हम यह उचित नहीं समझते हैं कि योजना "बी" को हमारे द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

आदेश "। यह तर्क देना व्यर्थ है कि उक्त योजना "बी" न्यायाधिकरण का निर्णय है। श्री परासरन ने आगे तर्क दिया कि रिपोर्ट में ही न्यायाधिकरण ने दो योजनाओं-योजना "ए" और योजना "बी" पर विचार करने के बाद और योजना "बी" के तहत, जिस क्षण योजना को लागू किया जाता है, योजना "ए" चालू और प्रभावी नहीं होती है और न्यायाधिकरण ने अंततः इस पर विचार करने का विकल्प चुना है।

योजना "ए" अंतिम आदेश के रूप में, जिसे लागू किया जा सकता है, यह संभव नहीं है 326

[

2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह तर्क देना कि न्यायाधिकरण द्वारा विकसित योजना "बी" भी न्यायाधिकरण का निर्णय है।

श्री अंधारुजिना, विद्वान वरिष्ठ वकील, राज्य की ओर से उपस्थित हुए

महाराष्ट्र, प्रतिवादी संख्या 2 ने आंध्र प्रदेश राज्य के रुख का समर्थन किया और तर्क दिया कि योजना "बी" को न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं माना जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, जिसे न्यायाधिकरण का निर्णय माना जा सकता है, वह वह है जिसे न्यायाधिकरण ने स्वयं बाध्यकारी प्रभाव माना और मामले के इस दृष्टिकोण में, न्यायाधिकरण ने खुद कहा कि यह योजना "ए" है जो अंतिम आदेश का हिस्सा है और जिसे अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद लागू किया जा सकता है, यह बहुत स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण ने योजना "बी" को अपना "निर्णय" नहीं माना, हालांकि पाठ्यक्रम में

कार्यवाही में, इसने ऐसी योजना की व्यवहार्यता और इसकी प्रभावकारिता के बारे में चर्चा की होगी। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अंधारुजिना ने अंततः आग्रह किया कि यह केवल न्यायाधिकरण का अंतिम आदेश है, जिसमें योजना "ए" शामिल है, जिसे न्यायाधिकरण का निर्णय माना जा सकता है।

संघ की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री साल्वे

सरकार ने दो अन्य प्रतिवादी राज्यों द्वारा लिए गए रुख को दोहराया और प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने स्वयं कभी भी योजना "बी" को अपना निर्णय नहीं माना है और अभिव्यक्ति "निर्णय" की व्याख्या धारा 2 (सी) में परिभाषित जल विवाद, धारा 3 के तहत की गई शिकायतों और संदर्भ और धारा 5 में दिए गए निर्णय के संदर्भ में की जानी चाहिए। श्री साल्वे के अनुसार अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का एक संयुक्त अध्ययन,

यह इंगित करता है कि यह न्यायाधिकरण का वह निर्णय है जो होने में सक्षम है

अपने दम पर लागू किया गया, जिसे न्यायाधिकरण का निर्णय माना जा सकता है, जो पक्षों के लिए बाध्यकारी है और कार्यवाही के दौरान स्वयं न्यायाधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों या कई प्रस्तावित योजनाओं पर विचार नहीं किया गया है। श्री साल्वे के अनुसार, न्यायाधिकरण इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत था कि योजना "बी" को तब तक लागू करना संभव नहीं है जब तक कि इसके लिए एक निगरानी लेखक प्रदान नहीं किया जा सकता है और इस तरह के अधिकार को दोनों पक्षों की सहमति से या संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है और चूंकि दोनों की कमी थी, इसलिए न्यायाधिकरण ने सलाह दी कि उसने इसे अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं बनाया और मामले के इस दृष्टिकोण में, न्यायाधिकरण द्वारा विकसित योजना "बी" को निर्णय नहीं माना जा सकता है।

इस विवादास्पद मुद्दे पर पक्षों के प्रतिद्वंद्वी रुख की जांच करने से पहले

अभिवचनों के साथ-साथ निर्दिष्ट दस्तावेजों के आलोक में, अधिनियम की योजना को इंगित करना आवश्यक हो सकता है। कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. के अंतर-राज्यीय जल विवाद।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 327

अधिनियम, 1956, जिसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है, संसद द्वारा गणराज्य के सातवें वर्ष में किसी भी देश के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान करने वाले कानून के रूप में अधिनियमित किया गया है।

जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत

केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट, जो उसके द्वारा पाए गए तथ्यों को निर्धारित करती है और उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में अपना निर्णय देती है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत जांच के बाद न्यायाधिकरण द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट में उसके द्वारा पाए गए तथ्यों के साथ-साथ न्यायाधिकरण को भेजे गए मामलों का निर्णय भी होना चाहिए। इसलिए, विधायिका द्वारा एक अंतर निकाला गया है - अधिनियम की धारा 5 (2) में उपयोग की गई दो

अभिव्यक्तियाँ, अर्थात् 'पाए गए तथ्य' और 'निर्दिष्ट मामलों का निर्णय'। उपरोक्त तीन मुद्दों में जिन महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, जिन्हें एक साथ लिया गया है, वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा विचार की गई और विकसित की गई योजना "बी" आएगी।

'तथ्यों के रूप में पाए गए' या 'निर्दिष्ट मामले पर न्यायाधिकरण के निर्णय' अभिव्यक्ति के भीतर। यह इस संदर्भ में है कि 'न्यायाधिकरण को भेजा गया मामला' बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने 10 तारीख को अपने पत्र में

अप्रैल, 1969 ने अंतर-राज्यीय नदी कृष्णा और उसकी नदी घाटी के संबंध में 29 जनवरी, 1962 और 8 जुलाई, 1968 के मैसूर सरकार के पत्रों, 11 जून, 1963 और 26 अगस्त, 1968 के महाराष्ट्र सरकार के पत्रों और 21 अप्रैल, 1968 और 21 जनवरी, 1969 के आंध्र प्रदेश सरकार के पत्रों से उत्पन्न जल विवाद के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को एक संदर्भ दिया। न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 2 में प्रत्येक सरकार की शिकायतों का सारांश दिया और इस आशय के निर्णय के लिए विवाद का बिंदु तैयार किया कि "पक्ष अपने लाभकारी उपयोग के लिए कृष्णा के पानी का न्यायसंगत विभाजन चाहते हैं, ताकि वे उन सीमाओं को जान सकें जिनके भीतर प्रत्येक कार्य कर सकता है और तदनुसार अपने जल संसाधनों के विकास की योजना बना सकता है" और इसने आगे कहा कि कैसे और किस आधार पर न्यायसंगत विभाजन किया जाना चाहिए। पक्षों के प्रतिद्वंद्वी रुख के आधार पर न्यायाधिकरण ने व्यवस्था तैयार की 14 अप्रैल, 1971 के मुद्दों और उप-मुद्दों और वर्तमान चर्चा के लिए, हम

वे मुद्दा नं. II, जैसा कि मुद्दा संख्या 1 इस सवाल से संबंधित है कि क्या नदी के पानी के आवंटन के संबंध में कोई समझौता हुआ था

कृष्ण और क्या ऐसा समझौता लागू करने योग्य था और अभी भी अस्तित्व में था [2000] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

328

और संबंधित राज्यों पर कार्यात्मक। मुद्दा नं. न्यायाधिकरण द्वारा इस आशय का प्रावधान किया गया है कि न्यायसंगत न्याय के लिए क्या निर्देश दिए जाने चाहिए।

कृष्णा नदी और नदी घाटी के पानी के लाभकारी उपयोग का विभाजन। उक्त मुद्दे के तहत, आठ उप-मुद्दे हैं और उप-मुद्दा 8 इस आशय का था कि "संबंधित राज्यों को पानी के आवंटन, यदि कोई हो, को उपलब्ध कराने और विनियमित करने के लिए या अन्यथा न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए कौन सी मशीनरी स्थापित की जानी चाहिए"। यह मुद्दा नं. 24 दिसंबर, 1973 की रिपोर्ट के अध्याय IX में II पर चर्चा की गई है, जिसे प्रदर्शनी पी. के. 1 के रूप में चिह्नित किया गया है और उप-मुद्दों में से एक है, अर्थात् उपलब्ध जल का निर्धारण किस आधार पर किया जाना चाहिए? , न्यायाधिकरण ने कई आंकड़ों पर विस्तार से विचार किया और अंत में पक्षों के बीच एक समझौता हुआ कि विजयवाड़ा तक कृष्णा नदी की 75 प्रतिशत भरोसेमंद उपज 2060 टी. एम. सी. है, जिसका संकेत अध्याय IX में ही दिया गया है। इसके बाद न्यायाधिकरण कृष्णा नदी के पानी के विभाजन के कठिन और नाजुक कार्य को शुरू करने के साथ आगे बढ़ता है और कृष्णा नदी और नदी घाटी के पानी के लाभकारी उपयोग के न्यायसंगत विभाजन के लिए अंततः क्या निर्देश दिए जा सकते हैं। 24 दिसंबर, 1973 की रिपोर्ट के अध्याय XIV में, न्यायाधिकरण ने अंततः संक्षेप में बताया कि कैसे प्रत्येक राज्य ने भरोसेमंद प्रवाह में और भरोसेमंद प्रवाह से अधिक पानी में भी न्यायसंगत हिस्सेदारी का दावा किया। इसने पक्षों द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ गवाहों के साक्ष्य पर भी विचार किया, जो कृष्णा बेसिन में किए गए भंडारण से होने वाले लाभ का संकेत देता है। न्यायाधिकरण ने इस मामले पर भी विचार किया कि क्या जल विभाजन की योजना हमेशा के लिए बनी रहना चाहिए या समीक्षा के लिए एक जगह होनी चाहिए और अंततः यह राय थी कि बदलती स्थितियों के साथ तालमेल रखने के लिए आवंटन की समीक्षा और संशोधन आवश्यक हो सकता है। इसने 31 मई, 2000 के बाद किसी भी समय न्यायाधिकरण के आदेश की समीक्षा का भी प्रावधान किया। इस तरह की सामान्य

टिप्पणियां करने के बाद, यह जल विभाजन की योजना पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और इसने 4 मई, 1973 को प्रस्तुत किए गए तीनों राज्यों के सहमत विचारों पर ध्यान दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि 75 प्रतिशत पर उपयोग करने योग्य भरोसेमंद प्रवाह का बड़े पैमाने पर आवंटन होना चाहिए और न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले उपयोग के संबंध में कुछ प्रतिबंधों के साथ अधिशेष और कमी वाले वर्षों में पानी के प्रतिशत के आधार पर आवंटन होना चाहिए और न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए एक संयुक्त नियंत्रण निकाय होना चाहिए। न्यायाधिकरण ने संकेत दिया कि प्रत्येक राज्य द्वारा दी गई योजनाओं के गुण और अवगुणों में दो भाग और भाग II शामिल हैं जो निगरानी प्राधिकरण के गठन और शक्तियों से संबंधित हैं, जिसे कृष्णा घाटी प्राधिकरण कहा जाता है और हालांकि शुरू में, पक्षों के वकील कृष्णा घाटी प्राधिकरण के गठन पर सहमत थे, लेकिन मामले की फिर से सुनवाई के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य स्पष्ट रूप से कर्नाटक और ओआरएस का राज्य था।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 329

संकेत दिया कि कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के लिए कोई सहमति नहीं दी जा सकती है। एक प्राधिकरण के गठन के सवाल पर दलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों और सबसे अच्छी परंपरा पर ध्यान देने के बाद कि संघीय संरचना कैसे काम करती है और राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन करने के लिए कैसे बाध्य हैं, यह भी निष्कर्ष निकला कि एक प्राधिकरण की स्थापना का मामला बन जाता है

निर्णय के पीछे की हड्डी और इसका एक अभिन्न हिस्सा और जब तक कि इसे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, तब तक तीन नदी तटीय राज्यों के बीच पानी के समान आवंटन के लिए योजना "बी" के तहत परिकल्पित निर्णय लेने का कोई फायदा नहीं होगा। न्यायाधिकरण बिना किसी अनिश्चित शर्त के इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पक्षों की सहमति के बिना कोई प्राधिकरण स्थापित करना उचित नहीं होगा, और इसलिए, तथाकथित दस्तावेज़ Exh.MRK-340 ने इस तथ्य के बावजूद कोई सहायता प्रदान नहीं की कि 4 मई, 1973 को तीनों राज्यों के वकील द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई थी। सहमत दस्तावेज़ एक्सएच के तहत परिकल्पित आवंटन के सिद्धांत वाले निर्णय तक पहुंचने के अपने प्रयास में विफल होने के कारण। एम. आर. के. 340, न्यायाधिकरण ने योजना "ए" और योजना "बी" नामक दो योजनाओं को और एक्स. एच. के पृष्ठ 166 पर विकसित करना उचित समझा। पी. के. 1, न्यायाधिकरण ने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया कि योजना "ए" अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत आधिकारिक राजपत्र में न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख से लागू होगी और योजना "बी" को उस स्थिति में लागू किया जा सकता है जब राज्य स्वयं एक अंतर-राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण

का गठन करते हैं, जिसे उनके बीच समझौते द्वारा कृष्णा घाटी प्राधिकरण कहा जा सकता है या यदि ऐसा प्राधिकरण संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा गठित किया जाता है। न्यायाधिकरण का उपरोक्त निष्कर्ष, स्पष्ट रूप से यह बताता है कि यह केवल योजना "ए" है जिसे न्यायाधिकरण का निर्णय बनाया गया है और न्यायाधिकरण ने इसे अंतिम आदेश के रूप में नामित किया है, जो आदेश केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। रिपोर्ट एक्सएच के पृष्ठ 182 पर। पी. के. 1, न्यायाधिकरण ने स्वयं अंतिम आदेश के विभिन्न खंडों को निर्धारित करके आगे की चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पूरी तस्वीर दी है जो न्यायाधिकरण के अनुसार विभाजन के विषय पर सभी प्रावधानों को शामिल करता है। महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी का पानी और फिर यह कहा जाता है कि "अंतिम आदेश के इन प्रावधानों में अंक संख्या में उल्लिखित सभी मामले शामिल हैं। II और इसके उप-मुद्दे और अंक सं. II, इसलिए, अंतिम आदेश के इन खंडों में दिए गए प्रावधान के अनुसार निर्णय लिया जाता है "सं. II, जैसा कि ऊपर कहा गया है, और उसके बाद अगले पैराग्राफ में मुद्दा IV (बी) का निर्णय लेते हुए, न्यायाधिकरण योजना "बी" की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजना 'बी' अधिक फायदेमंद है और कृष्णा नदी के पानी का अधिक लाभकारी और पूर्ण उपयोग प्रदान करती है, लेकिन न्यायाधिकरण ने स्वयं इसे अपने निर्णय का हिस्सा नहीं माना है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट हो सकती है।

[2000] 3 एस सी आर।

330

अधिनियम की धारा 6 के तहत एक अधिसूचना द्वारा लागू किया गया। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि कावेरी जल विवाद मामले (1993 (पूरक) 1 एस. सी. सी. 96) में इस सवाल पर विचार करते हुए कि न्यायाधिकरण का निर्णय क्या था। अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत इस न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि आदेश है

प्रकृति में केवल घोषणात्मक होने के लिए नहीं, बल्कि पक्षों द्वारा लागू और प्रभावी होने के लिए है, तो यह धारा 5 (2) के अर्थ के भीतर एक निर्णय का गठन करेगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। हाथ में मामले के लिए उपरोक्त अनुपात को लागू करना और इस आशय के मुद्दे No.II का निर्णय करते समय

न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए स्पष्ट बयान को ध्यान में रखते हुए कि सं. II और इसके उप-मुद्दों का निर्णय अंतिम आदेश के खंडों के अनुसार किया जाता है जिसमें योजना 'ए' शामिल है, वादी की ओर से पेश श्री नरीमन के तर्क को बनाए रखना मुश्किल है।

बता दें कि योजना 'बी' भी न्यायाधिकरण का निर्णय है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है कि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान सभी पक्ष राज्यों ने, निस्संदेह, प्रदर्शनी एमआरके 340 के अनुसार न्यायाधिकरण द्वारा हल किए जाने वाले विवाद के बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की है। लेकिन न्यायाधिकरण स्वयं इस निष्कर्ष को दर्ज करता है कि पक्षों के बीच गैर-समझौते के कारण एमआरके 340 के तहत सहमत आवंटन के सिद्धांत पर निर्णय तक पहुंचना संभव नहीं है और इसलिए, न्यायाधिकरण ने योजना 'ए' विकसित करना उचित समझा जिसे स्वयं लागू किया जा सकता है, जिसे अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचित किया जा रहा है। कावेरी जल विवाद मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, योजना 'बी' को विवाद के पक्षों द्वारा लागू और प्रभावी नहीं किया जाना था और इस तरह अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं हो सकता है। इसे रिपोर्ट में पाए गए तथ्यों के रूप में माना जा सकता है। प्रस्तुत किया। न्यायाधिकरण ने राज्यों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करते हुए कहा कि जब तक एक संयुक्त नियंत्रण निकाय या अंतर-राज्य प्राधिकरण की स्थापना नहीं की जाती, तब तक हर जल वर्ष में पक्षों द्वारा सुझाए गए आधार पर कृष्णा नदी के पानी को विभाजित करना मुश्किल होगा। (पृष्ठ 161 Ex.PK-1) पर।

न्यायाधिकरण ने एक निष्कर्ष भी दर्ज किया:

" हमारे लिए यह दृष्टिकोण रखना संभव नहीं है कि हम सहमति का अनुमान लगा सकते हैं।

4 मई, 1973 को दायर किए गए Ex.MRK-340 के पक्षों में से। "

निम्नलिखित संदर्भों का उत्तर देने के बाद अपनी आगे की रिपोर्ट में

अधिनियम की धारा 5 (3), प्रदर्शनी पी. के.-2 में न्यायाधिकरण ने कर्नाटक राज्य की इस दलील को नकार दिया कि योजना "ए" के तहत पानी का आवंटन कर्नाटक और ओ. आर. एस. का राज्य नहीं है।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 331

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जल विभाजन की योजना। पृष्ठ 24 पर उक्त पी. के.-2 में न्यायाधिकरण ने कहा:

" अंतर-राज्यीय नदी कृष्णा के पानी के विभाजन को नदी प्रणाली की विशिष्ट विशेषताओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। हम यह भी बता सकते हैं कि जब तक पूरे कृष्णा बेसिन में 1000 टी. एम. सी. से कम का उपयोग नहीं किया गया था, और जब तक 2060 टी. एम. सी. की पूरी भरोसेमंद आपूर्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक शेष पानी के बंटवारे के बारे में शिकायत अवास्तविक है।

कर्नाटक राज्य द्वारा दायर स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए, जिसमें न्यायाधिकरण से योजना "बी" के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की आवश्यकता होती है, न्यायाधिकरण ने निस्संदेह एक पूरी योजना "बी" तैयार की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि योजना "बी" में कृष्णा नदी के पानी के पूर्ण और बेहतर उपयोग का प्रावधान है, लेकिन यह जोड़ने में जल्दबाजी की कि "हम योजना" बी "को अपने अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं बना सकते हैं जैसा कि भारत सरकार के विद्वान वकील द्वारा अनुरोध किया गया है क्योंकि अंतिम आदेश में केवल ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिन्हें संसद द्वारा किए गए किसी भी समझौते या कानून से स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सकता है।"

(पृष्ठ 26 पर Ex.PK 2 देखें)

तुंगभद्रा बोर्ड के उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने के बाद न्यायाधिकरण ने अपनी अगली रिपोर्ट एक्स. पी. के.-2 में कहा:

" इन परिस्थितियों में हम यह उचित नहीं समझते हैं कि योजना 'बी'

इसे हमारे आदेश द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

मूल रिपोर्ट में भी न्यायाधिकरण के उपरोक्त निष्कर्ष

क्योंकि आगे की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि न्यायाधिकरण ने कभी भी योजना 'बी' को लागू करने के लिए अपने निर्णय का एक हिस्सा बनाने पर विचार नहीं किया, भले ही

विचाराधीन योजना की प्रभावशीलता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में तीन नदी तटीय राज्यों के बीच एक जल विवाद उत्पन्न हो गया है और उक्त विवाद को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को भेजा गया है और न्यायाधिकरण ने इसकी जांच की है।

इसे निर्दिष्ट किए गए मामले और पाए गए तथ्यों के साथ-साथ इसके निर्णय वाली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, यह वह निर्णय है जो निर्दिष्ट विवाद का निर्णायक रूप से निर्णय करता है और अपने दम पर लागू करने में सक्षम है, जिसे धारा 5 (2) के तहत न्यायाधिकरण का निर्णय कहा जा सकता है। इस मामले में न्यायाधिकरण की स्वयं यह राय है कि वह अपने आदेश से

योजना 'बी' को लागू करने में असमर्थ है और उसने 332 के अनुसार कृष्णा नदी के पानी का बंटवारा किया है।

[2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

योजना 'ए', उक्त योजना 'बी' को न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं माना जा सकता है।

यह भी सच है, जैसा कि श्री नरीमन ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने किया था

कर्नाटक राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत योजना 'बी' के कुछ खंडों के लिए मांगे गए स्पष्टीकरण पर विचार करें और एक पक्ष केवल एक निर्णय के संबंध में धारा 5 (3) के तहत न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार है, लेकिन यह कि हमारी राय में, स्वयं ही योजना 'बी' को न्यायाधिकरण के निर्णय के चरित्र के साथ नहीं जोड़ेगा। श्री नरीमन अपनी इस दलील में सही हो सकते हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा योजना 'बी' विकसित करने में एक निर्णय लिया गया है जो दर्शाता है कि किस तरह से उक्त नदी कृष्णा के पानी को तीन राज्यों द्वारा अधिशेष और कमी वाले जल वर्ष में साझा किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निर्णय को धारा 5 (2) के अर्थ के भीतर एक निर्णय नहीं माना जा सकता है जब तक कि ऐसा निर्णय अपने आप लागू करने और उपरोक्त परीक्षण योजना 'बी' को लागू करने में सक्षम नहीं है, जब तक कि योजना के पिछले हिस्से, अर्थात् निगरानी प्राधिकरण के गठन पर सहमति नहीं होती है, उक्त योजना को धारा 5 (2) के अर्थ के भीतर एक निर्णय नहीं माना जा सकता है।

5 (2) अधिनियम से। उपरोक्त परिसर में, हम यह अभिनिर्धारित करते हुए उपरोक्त तीन मुद्दों का उत्तर देते हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई योजना 'बी' न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं है और इसलिए, धारा 6 के तहत अधिसूचित होने की आवश्यकता नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप वादी के कहने पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तदनुसार वादी के खिलाफ मुद्दों का जवाब दिया जाता है।

हम उपरोक्त निष्कर्ष पर आ गए हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि

यह ध्यान देना उचित है कि अंतर-राज्यीय नदी के जल बंटवारे के विवादों को हल करना आसान नहीं है। इस न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण को अपना निष्कर्ष

तैयार करने में कई साल लग गए। अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायाधिकरण ने प्रतिद्वंद्वी राज्यों के बीच कई वार्ताओं का प्रयास किया है और पक्षों द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञों के साक्ष्य को भी ध्यान में रखा है। दो योजनाओं-योजना 'ए' और योजना 'बी' को विकसित करने में इसने प्रत्येक राज्य द्वारा तैयार की गई कई योजनाओं को भी ध्यान में रखा है। न्यायाधिकरण ने योजना 'बी' विकसित करते समय यह भी सोचा कि हालांकि इसे लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पक्षों के बीच सहमति की कमी के कारण निगरानी प्राधिकरण का गठन करने में असमर्थ था, फिर भी उसने उक्त योजना 'बी' को रिकॉर्ड पर रखा जो न्यायाधिकरण के अनुसार तीन राज्यों के बीच कृष्णा बेसिन के जल संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए बेहतर है। योजना 'बी' को अपनी रिपोर्ट में रखते समय विचार यह था कि योजना को विकसित करने में न्यायाधिकरण का श्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा और इसलिए उसे उम्मीद थी कि पक्ष सहमत हो सकते हैं।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे।]

एक प्राधिकरण के गठन के लिए या यदि वे सहमत होने में विफल रहते हैं तो संसद भी एक कानून बना सकती है लेकिन दुर्भाग्य से, दोनों में से कोई भी आकस्मिकता नहीं हुई है। यद्यपि हमारे द्वारा योजना 'बी' को न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं माना गया है और इस तरह, इस न्यायालय से एक अनिवार्य निषेधाज्ञा द्वारा लागू करने में सक्षम नहीं है, फिर भी हमें स्वयं न्यायाधिकरण के निष्कर्षों से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है कि योजना 'बी' कृष्णा नदी में जल संसाधनों के पूर्ण और बेहतर उपयोग का प्रावधान करती है और भविष्य में यदि किसी भी प्राधिकरण द्वारा कृष्णा नदी के आवंटन का सवाल उठाया जाता है तो

उक्त प्राधिकरण निश्चित रूप से उस योजना 'बी' को देखेगा जो उस समय उपलब्ध आंकड़ों पर विकसित की गई थी और इसकी स्वीकार्यता विधिवत होगी।

विचार किया।

हालांकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यह उचित के लिए होगा।

तीन नदी तटीय राज्यों के बीच कृष्णा बेसिन में लंबे समय से चल रहे जल विवाद को हल करने का कार्य सौंपा जाएगा ताकि प्रतिस्पर्धा करने वाले राज्यों द्वारा उसके सामने रखे गए आंकड़ों के आधार पर अपना निर्णय लिया जा सके। पूर्ववर्ती न्यायाधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना-बी केवल इस प्राधिकरण के लिए एक उपयोगी खाका के रूप में काम कर सकती है, हालांकि यह उस पर सख्ती से बाध्यकारी नहीं हो सकती है। योजना-बी पर हमारी उपरोक्त टिप्पणियों को उसी

संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान न केवल तीन नदी तटीय राज्यों ने एक दस्तावेज़ पूर्व प्रस्तुत करके न्यायाधिकरण से अनुरोध किया था। 4 मई, 1973 को एम. आर. के.-340, तीन राज्यों की ओर से पेश होने वाले तीन वकीलों द्वारा हस्ताक्षरित आवंटन के सिद्धांतों का संकेत देता है, जो हालांकि बाद में सहमत नहीं थे, लेकिन भारत संघ की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील ने भी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया जब न्यायाधिकरण 8 मई, 1975 को विभिन्न राज्यों द्वारा दायर स्पष्टीकरणात्मक आवेदनों पर विचार कर रहा था।

" भारत सरकार ने 'बी' और 'ए' दोनों योजनाओं की जांच की है।

उन्हें लगता है कि योजना 'बी' बेहतर और लागू करने में आसान है।

योजना 'ए'। यदि योजना 'बी' इसके अंतिम क्रम के हिस्से के रूप में आती है माननीय न्यायाधिकरण, भारत सरकार आवश्यक कदम उठाएगी

इसे चालू करने के लिए। योजना 'बी' को इसके हिस्से के रूप में रखा जा सकता है

जिस तरह से माननीय न्यायाधिकरण उचित समझता है, उस तरीके से अंतिम आदेश। हम करेंगे।

इस माननीय न्यायाधिकरण द्वारा एक पूरी योजना तैयार करना पसंद करते हैं।

यह वास्तव में इंगित करता है कि कैसे केंद्र सरकार योजना 'बी' को अपने निर्णय का एक हिस्सा बनाने के लिए न्यायाधिकरण के आदेश के लिए उत्सुक थी, हालांकि अंततः जिन कारणों से पहले ही संकेत दिया जा चुका है, ट्रिब्यूनल ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।

[2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

334

अंक संख्या 1.

अगला महत्वपूर्ण मुद्दा अंक संख्या 1 है जो सवाल उठाता है -

अनुच्छेद 262 के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए मुकदमे की रखरखाव क्षमता

(2) अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम की धारा 11 के साथ पढ़ा गया संविधान। भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री साल्वे ने वास्तव में इस मुद्दे का संचालन किया, जिसका निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए श्री परासरन ने समर्थन किया। श्री साल्वे के अनुसार वादी द्वारा मांगी गई राहत-राज्य स्वयं अधिनियम के तहत एक जल विवाद है, और इसलिए, अधिनियम की धारा 11 को देखते हुए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। वादपत्र में किए गए विभिन्न कथनों का उल्लेख करते हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि वादपत्र के तहत वादी वास्तव में 2060 टी. एम. सी. के संबंध में योजना 'ए' के तहत पहले से किए गए आवंटन को 75 प्रतिशत निर्भरता और योजना 'बी' के तहत विकसित अधिशेष के बंटवारे पर लागू करने के लिए कहता है और इस तरह प्रार्थना एक नई योजना के समान है जो पूरी तरह से न्यायाधिकरण द्वारा विकसित नहीं की गई है और इसके परिणामस्वरूप, एक ताजा जल विवाद है और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस तरह के विवाद पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसे अधिनियम की धारा 11 के तहत वर्जित किया गया है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने संवैधानिक योजना के संदर्भ में अपने तर्क को विस्तार से बताया और यहां तक कि यह तर्क भी दिया कि किसी मामले में न्यायाधिकरण के पुरस्कार को लागू करने का अनुरोध भी अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत जल विवाद बन सकता है और जिस क्षण यह जल विवाद बन जाता है, इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत किसी मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

संविधान। विद्वान महान्यायवादी ने मुद्दे 4 और 5 का भी उल्लेख किया इस कार्यवाही में तैयार किया गया और तर्क दिया गया कि मुद्दे ही इंगित करते हैं कि एक जल विवाद उत्पन्न हुआ है और परिणामस्वरूप मुकदमा नहीं होगा। श्री साल्वे के अनुसार, किसी न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के मुकदमे में भी, यदि कोई मुद्दा उत्पन्न होता है, जो अधिनियम की धारा 2 (सी) (आई) के तहत जल विवाद होगा या अधिनियम की धारा 3 (बी) या 3 (सी) के तहत आता है, तो अनुच्छेद 131 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को वर्जित माना जाना चाहिए और मामले में, वास्तव में, वादी द्वारा मांगी गई राहत-राज्य ताजे पानी के विवाद के समान है। विद्वान महान्यायवादी का तर्क है कि धारा 3 के साथ पठित धारा 2 (सी) की भाषा किसी भी नदी तटीय राज्य को अंतर-राज्यीय नदी के पानी के उपयोग, नियंत्रण या वितरण के संबंध में विवाद उठाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त व्यापक है और इस तरह के विवाद के समाधान के लिए तंत्र संविधान के अनुच्छेद 262 के लिए संदर्भित है, जो प्रावधान न्यायालयों को उन विवादों से अलग करने के इरादे को प्रकट करता है जो राजनीतिक निहितार्थ मान सकते हैं और मामले को हाथ में लेते हुए परीक्षण को लागू करते हैं, यह निष्कर्ष अप्रतिरोध्य है कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमे पर विचार करने का हकदार नहीं होगा।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य (पटनायक, जे.) 335

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए श्री परासरन ने विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री साल्वे द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन किया और तर्क दिया,

यह कि मुकदमा केवल योजना 'बी' के कार्यान्वयन के लिए नहीं है, जैसा कि वादी द्वारा तर्क दिया गया है, बल्कि दोनों योजनाओं का एक समामेलन है, योजना 'ए' के तहत 2060 टी. एम. सी. का बंटवारा और योजना 'बी' के अनुसार 2060 टी. एम. सी. से अधिक अधिशेष का बंटवारा, यह स्पष्ट रूप से एक नवाचार है जिसके बारे में न्यायाधिकरण ने स्वयं नहीं सोचा है और अधिक उचित रूप से अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर एक ताजे पानी का विवाद है और इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमा नहीं होगा। दूसरी ओर वादी-राज्य की ओर से पेश श्री नरीमन ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया मुकदमा वास्तव में सामान्य दीवानी न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा नहीं है। पक्षकारों की दलीलों का पांडित्यपूर्ण तरीके से अर्थ नहीं लगाया जा सकता है और वाद को समग्र रूप से पढ़ने पर यह निष्कर्ष अटूट है कि वादी ने इस आशय का मामला बनाया है कि न्यायाधिकरण द्वारा विकसित योजना 'बी' भी न्यायाधिकरण का निर्णय है, हालांकि इसे निगरानी प्राधिकरण के गठन के अभाव में लागू नहीं किया जा सका और कृष्णा नदी के जल संसाधनों के बेहतर और पूर्ण उपयोग के लिए ऐसी लाभकारी योजना विकसित करने में न्यायाधिकरण द्वारा खर्च किए गए समय और शक्ति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को उक्त योजना 'बी' को लागू करने के लिए उचित निर्देश जारी करना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित विवाद का न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है और उस उद्देश्य के लिए दो योजनाएं विकसित की गई हैं और राहत योजना 'बी' के कार्यान्वयन के लिए है, यह अनिवार्य रूप से एक न्यायिक विवाद को लागू करने के लिए एक मुकदमा है और अब अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत विवाद नहीं बनाता है, जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है। मामले के इस दृष्टिकोण में अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रतिबंध को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी रुख की जांच करने से पहले शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि रखरखाव के सवाल का फैसला वादी द्वारा किए गए कथनों और मांगी गई राहत और उसकी समग्रता पर किया जाना चाहिए, न कि एक पैराग्राफ को काटकर और फिर मामले का फैसला करके। संविधान के अनुच्छेद 131 के दायरे की व्याख्या करते हुए, राजस्थान राज्य के मामले में v. भारत संघ, [1978] 1 एस. सी. आर. 1 चंद्रचूड़, जे., जैसा कि वे उस समय थे, ने अभिनिर्धारित किया कि आवश्यकता यह है कि विवाद में एक प्रश्न शामिल होना चाहिए, चाहे वह कानून का हो या तथ्य का, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार हो।

निर्भर करता है। यह वह योग्यता है जो यह निर्धारित करने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करती है कि क्या किसी विशेष विवाद को अनुच्छेद 131 के भीतर समझा जाता है। मकसद.

अनुच्छेद 131 उन विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है जो कानूनी अधिकार के अस्तित्व या सीमा पर उनके निर्णय के लिए निर्भर करते हैं। उसी में न्यायमूर्ति भगवती, जैसा कि वे उस समय संविधान के अनुच्छेद 131 के प्रावधानों का विश्लेषण कर रहे थे, ने निर्णय दिया कि संविधान के संबंध में दो सीमाएँ हैं।

:

[2000] 3 एस सी आर।

336

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 6 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित और इस तरह, वादी और प्रतिवादी के बीच विवाद सं। 3 - भारत संघ और इसके अलावा यह अनुच्छेद 131 के खंड (सी) के तहत कर्नाटक राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच एक विवाद है क्योंकि उक्त आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक निगरानी प्राधिकरण के गठन के लिए सहमत नहीं था योजना * बी 'विकसित करके न्यायाधिकरण के निर्णय का कार्यान्वयन। उसी निर्णय में न्यायमूर्ति भगवती ने यह भी संकेत दिया कि यदि ऐसा कानूनी अधिकार स्थापित हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास मुकदमे में दावा किए गए कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए जो भी राहत आवश्यक होगी, उसे देने की शक्ति होगी। कर्नाटक राज्य में v. भारत संघ और ए. एन. आर. , [1978] 2 एस. सी. आर. 1 इस न्यायालय ने फिर से संविधान के अनुच्छेद 131 के दायरे पर विचार किया।

चन्द्रचूड़, जे., जैसा कि वे उस समय थे, इस प्रकार माने जाते थे:

" उच्चतम न्यायालय को एरीटल 131 द्वारा प्रदत्त अधिकारिता

संविधान का परीक्षण साधारण नियमों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए जो

निर्धारित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लागू किए जाते हैं

क्या सूट रखरखाव योग्य है। अनुच्छेद 131 निस्संदेह प्रदान करता है

' उच्चतम न्यायालय पर 'मूल अधिकारिता' और सबसे सामान्य रूप

एक कानूनी कार्यवाही जिसका परीक्षण एक अदालत द्वारा किया जाता है

दीवानी अदालत को मनोरंजन करने का अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधान के बराबर एक आम मुकदमा ताकि अनुच्छेद के तहत एक मूल कार्यवाही पर लागू हो

131 एक मुकदमे के नियम जो धारा 15 के तहत आम तौर पर विचारण योग्य हैं

निम्नतम श्रेणी के न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता

कोशिश करने में सक्षम। सलाह दी जाती है कि संविधान इसका वर्णन नहीं करता है कार्यवाही जिसे अनुच्छेद 131 के तहत 'वाद' के रूप में लाया जा सकता है और

उल्लेखनीय रूप से, अनुच्छेद 131 में ऐसे शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग किया गया है जो सामान्य रूप से नहीं हैं।

पहली बार के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए नियोजित मनोरंजन करने और एक सूट आजमाने के लिए। यह 'कार्रवाई के कारण' की बात नहीं करता है,

दुनिया में ज्ञात और निश्चित कानूनी महत्व की अभिव्यक्ति

गवाह कार्रवाई। इसके बजाय, यह 'विवाद' शब्द का उपयोग करता है, जो नहीं है।

कानून के अण्डाकार शब्दजाल का हिस्सा। लेकिन सबसे बढ़कर, अनुच्छेद 131 जो कर्नाटक और ओ. आर. एस. का उल्लेख करता है।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 337

बोलने के तरीके में इसके दायरे में आने वाले मामलों पर एक स्व-निहित कोड है, जो उस स्थिति के लिए स्पष्ट रूप से प्रदान करता है जिसके अधीन कोई कार्रवाई हो सकती है। यह शर्त व्यक्त की जाती है कि खंड: " यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न (चाहे वह कानून या तथ्य का हो) शामिल है जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार है।

निर्भर करता है "। इसलिए, अनुच्छेद की शर्तों के अनुसार, इस न्यायालय की मूल अधिकारिता को लागू करने के लिए एकमात्र शर्त जो संतुष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट पक्षों के बीच विवाद में एक ऐसा प्रश्न शामिल होना चाहिए जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है।

अनुच्छेद 131 का सार यह है कि किसी ऐसे प्रश्न के संबंध में पक्षकारों के बीच विवाद होना चाहिए जिस पर अस्तित्व या

कानूनी अधिकार की सीमा निर्भर करती है। राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकार को चुनौती देने में स्पष्ट रूप से एक ऐसा प्रश्न शामिल होता है जिस पर जांच आयोग नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है और यह संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य द्वारा लाई गई कार्यवाही को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। यह "स्पष्ट की चूक" का मामला नहीं है। अनुच्छेद 131 में शब्दों को पढ़ने को उचित ठहराते हुए, जो वहां नहीं हैं, मैं मानता हूं कि संविधान ने उद्देश्यपूर्ण रूप से इस न्यायालय को एक ऐसा न्यायशास्त्र प्रदान किया है जो उन विचारों से अनियंत्रित है जो पहली बार के न्यायालय के न्यायशास्त्र को बाधित करते हैं, जो नागरिक प्रकृति के मुकदमों को स्वीकार करता है और उनका परीक्षण करता है। अनुच्छेद 131 के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों की प्रकृति, रूप और सार दोनों में, दावों की प्रकृति से अलग है जिन पर साधारण मुकदमों में निर्णय की आवश्यकता होती है।

न्यायाधीश ने आगे यह भी कहा था:

" अनुच्छेद 131 के तहत एक कार्यवाही एक साधारण दीवानी मुकदमे के बिल्कुल विपरीत है। इस तरह की कार्यवाही में प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक सरकारों के बीच होती है-या तो एक या दूसरे के पास

कार्य करने की संविधान की शक्ति "।

जे. चंद्रचूड़ से सहमत होते हुए जे. भगवती ने भी इस प्रकार टिप्पणी की थी:

" की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए एकमात्र आवश्यक आवश्यकता

अनुच्छेद 131 यह है कि विवाद किसी भी प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए "जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है", भले ही [2000] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

338

क्या कानूनी अधिकार का दावा एक पक्ष या दूसरे द्वारा किया जाता है और यह है

यह आवश्यक नहीं है कि वादी के कुछ कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाए

इससे पहले कि किसी मुकदमे को उस अनुच्छेद के तहत लाया जा सके।

कैलासम, जे. और बेग, जे. ने इन निष्कर्षों पर पहुंचने पर सहमति व्यक्त की

चंद्रचूड़, जे. और भगवती, जे.

प्रख्यात न्यायविद श्री एच. एम. सीरवई ने "संवैधानिक" विषय पर अपनी पुस्तक में कहा,

संविधान के अनुच्छेद 131 के दायरे से संबंधित भारत का कानून कहता है: जब किसी न्यायालय को पक्षों के बीच किसी विवाद के संबंध में अनन्य अधिकार क्षेत्र दिया जाता है, तो यह अभिनिर्धारित करना उचित होता है कि न्यायालय के पास अपने फरमानों या आदेशों के प्रवर्तन सहित पूरे विवाद को हल करने की शक्ति है, विशेष रूप से जब ऐसे प्रवर्तन के लिए प्रावधान किया गया हो। 'यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न (कानून या तथ्य का) शामिल है, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है' शब्दों का अर्थ इस तथ्य पर जोर देना है कि विवाद कानूनी अधिकारों से संबंधित होना चाहिए, न कि राजनीतिक स्तर पर विवाद जो कानूनी अधिकार पर आधारित नहीं है।

संविधान का अनुच्छेद 131 अन्य प्रावधानों के अधीन

संविधान किसी विवाद पर उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्रदान करता है।

केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच इस शर्त के अधीन कि विवाद में कोई भी प्रश्न शामिल है, चाहे वह कानून या तथ्य का हो, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। संविधान का अनुच्छेद 262 (1) संसद को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के समर्थन के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। उप-अनुच्छेद 262 का अनुच्छेद 2 संसद को कानून द्वारा प्रावधान करने के लिए भी अधिकृत करता है।

खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद या शिकायत के संबंध में उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता। इस प्रकार अनुच्छेद 131 अनुच्छेद 262 सहित संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन होने के कारण, यदि संसद ने किसी जल विवाद या किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवाद के निर्णय के लिए कोई कानून बनाया है, तो ऐसा विवाद अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है, भले ही विवाद केंद्र या राज्य के बीच या दोनों राज्यों के बीच का हो। अनुच्छेद 262

(1) के तहत संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने वास्तव में अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 नामक कानून अधिनियमित किया है और उक्त अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को किसी भी जल विवाद के संबंध में अधिकार क्षेत्र होगा जिसे अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण, यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या कर्नाटक और ओआरएस के वादी राज्य में किए गए दावे हैं।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 339

कर्नाटक राज्य द्वारा दायर और किसी भी तरह की कल्पना से मांगी गई राहत को जल विवाद माना जा सकता है, जिसे न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है, ताकि अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को हटाया जा सके।

वादपत्र में किए गए कथनों और वादी-राज्य द्वारा मांगी गई राहत की जांच करने पर, हमारी यह सुविचारित राय है कि कर्नाटक राज्य वास्तव में जो चाहता है वह सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र को निर्देश है।

सरकार न्यायाधिकरण द्वारा विकसित योजना "बी" को अधिसूचित करे और केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 6 ए के तहत एक प्राधिकरण का गठन करने के निर्देश के लिए, जिसे संशोधन द्वारा अधिनियम में जोड़ा गया था, हालांकि उक्त प्रावधान उस तारीख को नहीं था, न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया। वादी शिकायत में दावा करता है कि कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में तीनों नदी तटीय राज्यों के बीच विवाद पर अंततः न्यायाधिकरण द्वारा दो योजनाओं को विकसित करके निर्णय लिया गया था और

योजना "ए" के तहत, नदी बेसिन में 75 प्रतिशत निर्भरता पर पानी की उपलब्धता के संबंध में तीन राज्यों के पक्ष में बड़े पैमाने पर आवंटन किया जा रहा है, योजना "बी" के तहत पानी की कमी वाले वर्ष में अतिरिक्त और पानी दोनों के संबंध में आवंटन किया गया है और वादी के अनुसार, संपूर्ण जल विवाद जिसे न्यायाधिकरण को भेजा गया था, कहा जा सकता है

योजना "बी" के लागू होने पर ही इसका समाधान किया जाता है। उक्त योजना "बी" को संघ द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय के रूप में नहीं माना गया है सरकार, और इसलिए, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचित नहीं किया जा रहा है, उक्त योजना "बी" के कार्यान्वयन से बहने वाले कर्नाटक राज्य के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और राज्य नदी बेसिन में किसी भी अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए अपनी भविष्य की योजना बनाने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए, उपयुक्त अधिकारियों को उक्त योजना को अधिसूचित करने और

निगरानी प्राधिकरण के गठन के लिए अनिवार्य रूप से बुलाया जाना चाहिए। वाद में किए गए दावों और मांगी गई राहत की प्रकृति होने के कारण, हमारे लिए यह मानना मुश्किल है कि यह अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर एक विवाद है, और इसलिए, इस न्यायालय की अधिकारिता अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित अनुच्छेद 262 के तहत वर्जित हो जाती है। वास्तव में, वाद में किए गए दावे और मांगी गई राहत को एक न्यायिक विवाद के आधार पर दावा माना जा सकता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर करके लागू करने की मांग की जाती है। अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत इस तरह के मुकदमे को वर्जित नहीं माना जा सकता है। यह सच है, हमने 4,5 और 7 मुद्दों पर निर्णय लेते समय कहा है कि न्यायाधिकरण द्वारा विकसित योजना "बी" अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं है, लेकिन हमारे इस तरह के निष्कर्ष से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि मुकदमा स्वयं अधिनियम की धारा 11 के तहत वर्जित हो जाता है, जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है। सवाल यह है कि क्या न्यायशास्त्र [2000] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

340

अधिनियम की धारा 11 को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का गठन वर्जित हो जाता है, जिसका जवाब वाद में किए गए दावों और मांगी गई राहत की जांच करके दिया जाना चाहिए।

और ऐसा करके, हम यह अभिनिर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं कि वाद में किए गए दावे, मांगी गई राहत के साथ, अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत एक विवाद का गठन करते हैं, जिससे धारा 11 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाती है। इसलिए हम इस मुद्दे को वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ रखते हैं।

इश्यू नं। 6

उपरोक्त मुद्दा महाराष्ट्र राज्य के लिखित बयान में किए गए दावों पर आधारित है। यह लिखित में कहा गया है महाराष्ट्र राज्य का यह कथन कि योजना "ए" धारा 6 के तहत आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू की गई है और 21 वर्षों से चल रही है और पक्षकारों ने कृष्णा नदी में पानी के बड़े पैमाने पर आवंटन पर उक्त योजना के आधार पर अपने शेषों पर काम किया है, इस स्तर पर योजना "बी" को लागू करने का सवाल यह मानते हुए भी नहीं उठता है कि योजना "बी" को न्यायाधिकरण का निर्णय माना जाता है। महाराष्ट्र

राज्य के अनुसार योजना "बी" को प्रभावी बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी राज्यों के बेसिन में अपने जलाशय तथाकथित निगरानी प्राधिकरण द्वारा इंगित किए जाने वाले स्थानों पर होने चाहिए, जिनके बारे में माना जाता है कि उसी योजना के तहत उनका नियंत्रण होना चाहिए। 21 वर्षों के अंतराल के बाद योजना "बी" को लागू करने के लिए कोई भी निर्देश महाराष्ट्र राज्य के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल होगा। लिखित कथन में आगे यह रुख अपनाया गया है कि योजना "ए" को सभी वर्षों से लागू किया गया है और 31 मई, 2000 के बाद समीक्षा के लिए प्रावधान किया गया है, जो तेजी से आ रहा है और कर्नाटक राज्य ने भी एक समय पर यह रुख अपनाया है कि योजना "बी" को लागू नहीं किया जाना चाहिए, इस न्यायालय के लिए उक्त योजना "बी" के कार्यान्वयन के लिए कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा। तर्कों के दौरान, महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री अंधारुजिना ने इस तथ्य पर जोर दिया कि 30 अगस्त, 1993 के अंत तक, सरकार के सचिव, सिंचाई विभाग, कामटक ने जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को सूचित किया था। पी. के.-94 में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार की दृढ़ राय है कि कृष्णा की स्थापना

घाटी प्राधिकरण को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि योजना "बी" के संदर्भ के बिना भी, अतिरिक्त पानी को पक्षों द्वारा आपसी समझौते से साझा किया जा सकता है। यह न्यायाधिकरण द्वारा विकसित तथाकथित योजना "बी" को लागू करने के संबंध में कर्नाटक सरकार के रुख को दर्शाता है।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 341

दूसरी ओर वादी की ओर से पेश श्री नरीमन ने तर्क दिया कि कर्नाटक राज्य हमेशा से अनुरोध करने के लिए उत्सुक रहा है।

मुहम्मद ने स्वयं न्यायाधिकरण से योजना "बी" को चालू करने का अनुरोध किया था, लेकिन बाद में प्रत्येक राज्य ने अपनी जल प्रबंधन परियोजनाएं शुरू कीं। योजना "ए" के तहत किए गए सामूहिक आवंटन का आधार। श्री नरीमन ने अपनी दलील में सही कहा कि राज्यों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि यह केवल योजना "ए" थी जिसे अधिसूचित किया गया था और पक्षों के बीच बाध्यकारी बनाया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर आवंटन के आधार पर अपनी-अपनी परियोजनाओं की योजना बनाने के बाद, कर्नाटक राज्य ने वर्ष 1993 में कृष्णा घाटी प्राधिकरण के गठन के लिए केंद्र सरकार के पत्र के जवाब में सोचा था कि राज्य को उस समय प्राधिकरण होना उचित नहीं लगता है। इस प्रकार तीनों राज्यों ने योजना "ए" के तहत न्यायाधिकरण द्वारा अपने-अपने हिस्से में आवंटित पानी के उपयोग के लिए अपनी-अपनी योजना बनाई है, जो आज तक प्रभावी है, लेकिन आंध्र प्रदेश

और कर्नाटक राज्य के बीच आशंका और विवाद के कारण, जब कर्नाटक ने अलमट्टी में बांध का निर्माण शुरू किया और आंध्र प्रदेश ने तेलुगु जैसी बड़ी परियोजनाओं के साथ काम किया।

गंगा, नागार्जुनसागर और अन्य। अंतर-राज्यीय नदी के पानी के बंटवारे के मामले में जब अंतर-राज्यीय जल विवादों के तहत न्यायाधिकरण का गठन किया गया था

अधिनियम, योजना "ए" के तहत बड़े पैमाने पर आवंटन की एक योजना विकसित की और वह योजना इन सभी वर्षों से चालू है और इसकी समीक्षा की जा सकती है

31 मई, 2000 के बाद किसी भी समय, भले ही स्वयं न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य का यह तर्क कि इस अवधि में योजना "बी" को लागू करने के निर्देश को प्रभावी नहीं बनाया जाना चाहिए, काफी सारवान है। वर्तमान प्रकृति के विवाद में जब न्यायालय कोई निर्देश जारी करने से पहले मामले को सौंप रहा है, तो न्यायालय केवल न्यायाधिकरण के किसी भी पूर्व आदेश से आने वाले पक्षों के अधिकारों, यदि कोई हो, की जांच नहीं कर रहा है, बल्कि समानता और ऐसे किसी निर्देश की प्रभावशीलता के सवाल की भी जांच कर रहा है। यह इस संदर्भ में श्री परासरन, [2000] 3 एस. सी. आर. की प्रस्तुति है।

342

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि योजना "ए" जैसी एक परीक्षित योजना, जो इन सभी वर्षों से चालू है, को योजना "बी" के सीधे कार्यान्वयन द्वारा अचानक मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, विशेष रूप से, जब यह एक स्वीकृत तथ्य है कि न केवल उक्त योजना "बी", कृष्णा घाटी प्राधिकरण की रीढ़ नहीं है। राज्य स्वयं भी अतिरिक्त जल के भंडारण के लिए अपने जलाशयों का निर्माण नहीं कर पाए हैं, जो स्वयं भी योजना "बी" का एक हिस्सा है। हालाँकि, हमें इस मामले में और अधिक गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है।

पहले यह निष्कर्ष निकालना कि योजना "बी" न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं है और इस प्रकार न्यायालय उक्त योजना के कार्यान्वयन में कोई निर्देश जारी करने में उचित नहीं होगा। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

आईएसयूई एन. ओ. एस. 10 और 11.

ये दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए इन्हें एक साथ उठाया जाता है।

विचार करें। इस संबंध में वादी का रुख यह है कि कृष्णा नदी के 2060 टी. एम. सी. के संबंध में तीन राज्यों के पक्ष में सामूहिक आवंटन करते हुए, जो निर्भरता का 75 प्रतिशत पाया गया था और तीनों राज्यों के संबंध में एक जल वर्ष में पानी की निर्दिष्ट मात्रा आवंटित करते हुए, न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि आंध्र प्रदेश किसी भी जल वर्ष में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा, शेष पानी जो कृष्णा नदी में बह रहा हो सकता है, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता किसी भी तरह का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और न ही राज्य निर्दिष्ट मात्रा से अधिक किसी भी पानी के संबंध में किसी भी अधिकार का दावा कर सकता है, अर्थात् 800 टी. एम. सी.। भारत सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अंतिम आदेश का प्रासंगिक खंड यहां निकाला गया है:

" (ग) आंध्र प्रदेश राज्य किसी भी क्षेत्र में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

जल वर्ष शेष जल जो नदी में बह सकता है

कृष्णा लेकिन इस प्रकार यह उपयोग करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं करेगा।

किसी भी जल वर्ष में और न ही किसी जल में आवंटित किया गया माना जाएगा। वर्ष, कृष्णा नदी का पानी निर्दिष्ट मात्रा से अधिक

इसके नीचे:

(11) के बाद 1 जून को शुरू होने वाले जल वर्ष के रूप में

आधिकारिक में न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख

जल वर्ष 1982-83 तक राजपत्र।

800 टी. एम. सी

((ii) जल वर्ष 1983-84 से जल वर्ष 1989-90 तक।

800 टी. एम. सी. प्लस कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य
[पटनायक, जे.] 343

पानी की मात्रा अतिरिक्त पानी के 10 प्रतिशत के बराबर है।

कृष्णा नदी में सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग का औसत
जल वर्षों के दौरान बेसिन 1990-91, 1991-92 और 1992-93

उपयोग पर सालाना 3 टी. एम. सी. या उससे अधिक का उपयोग करने वाली
अपनी परियोजनाएं

ऐसी परियोजनाओं से जल वर्ष 1968-69 में इस तरह की शुरुआत के लिए।

(iii) जल वर्ष 990-91 से जल वर्ष 1997-98 तक

800

टी. एम. सी. प्लस

पानी की मात्रा अतिरिक्त पानी के 10 प्रतिशत के बराबर है।

कृष्णा नदी में सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग का औसत

जल वर्षों के दौरान बेसिन 1982-83, 1983-84 और 1984-85
उपयोग पर सालाना 3 टी. एम. सी. या उससे अधिक का उपयोग करने वाली अपनी परियोजनाएं

ऐसी परियोजनाओं से पानी में ऐसी सिंचाई 1968-69 की जाती है।

(iv) जल वर्ष 1998-99 के बाद से

800 टी. एम. सी. प्लस

पानी की मात्रा अतिरिक्त पानी के 10 प्रतिशत के बराबर है।

कृष्णा नदी में सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग का औसत

जल वर्षों के दौरान बेसिन 1990-91, 1991-92 और 1992-93 i 'से;
के लिए उपयोग पर 3 टी. एम. सी. या अधिक वार्षिक उपयोग करने वाली अपनी परियोजनाएं

ऐसी परियोजनाओं से जल वर्ष 1968-69 में ऐसी सिंचाई।

लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद,

नदी बेसिन में बहने वाले सभी अतिरिक्त पानी का उपयोग ऊपरी हिस्से को पहले से खाली करने के लिए करना। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे नदी तटीय राज्यों को योजना "ए" के तहत आवंटित 2060 टी. एम. सी. से अधिक अतिरिक्त पानी में अपने हिस्से का दावा करने से रोक दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार भी समर्थन करती है

कर्नाटक राज्य का लेकिन दूसरी ओर आंध्र प्रदेश राज्य का उपरोक्त रुख यह है कि आंध्र प्रदेश नदी बेसिन में सबसे कम नदी तटीय राज्य है और न्यायाधिकरण ने इसका उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

शेष जल जो कृष्णा नदी में बह रहा हो, राज्य द्वारा उस स्वतंत्रता के प्रयोग में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और कर्नाटक राज्य के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य की आशंका निराधार है। पक्षों के प्रतिद्वंद्वी रुख के संदर्भ में, विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा सबसे निचले नदी तटीय राज्य, अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के पक्ष में अतिरिक्त पानी का उपयोग करने की स्वतंत्रता निर्बाध है और राज्य इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, या वहाँ [2000] 3 एस. सी. आर. है।

344

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह के उपयोग में कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उसी खंड में, आंध्र प्रदेश राज्य को शेष जल का उपयोग करने की स्वतंत्रता देते हुए, न्यायाधिकरण ने स्वयं यह निर्णय लेने में जल्दबाजी की है-"लेकिन इस प्रकार वह किसी भी जल वर्ष में उपयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करेगा और न ही किसी भी जल वर्ष में आवंटित किया गया माना जाएगा, कृष्णा नदी का जल निर्दिष्ट मात्रा से अधिक है।" न्यायाधिकरण का उपरोक्त निर्देश स्वयं ही कम हो जाता है

आंध्र प्रदेश राज्य को दी गई तथाकथित स्वतंत्रता, लेकिन चूंकि न्यायाधिकरण तीन राज्यों के संबंध में बड़े पैमाने पर आवंटन दे रहा था और जब तक कि ऐसी स्वतंत्रता सबसे निचले नदी तटीय राज्य के पक्ष में नहीं दी जाती, तब तक पानी अन्यथा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाता और इसलिए, यह उचित समझा गया कि सबसे निचला नदी तटीय राज्य इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन अतिरिक्त पानी का उपयोग करके कभी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ऐसी बड़ी परियोजनाओं के लिए होने वाले खर्च और राष्ट्रीय नुकसान के संदर्भ में, जिसे देश हमारे देश की तरह संघीय ढांचे में बनाए नहीं रख सकता है, यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह

आंध्र प्रदेश जैसे सबसे निचले नदी तटीय राज्य की ऐसी किसी भी बड़ी परियोजना को मंजूरी देते समय इसे ध्यान में रखे। न्यायाधिकरण की रिपोर्ट और उसके निर्णय को अंतिम आदेश के रूप में पढ़ना, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सबसे निचले नदी तटीय राज्य को दी गई तथाकथित स्वतंत्रता आवंटित हिस्से से परे कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है, दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण के निर्णय के तहत सबसे निचले नदी तटीय राज्य को जो दिया गया है, वह संबंधित राज्य के पक्ष में कोई अधिकार पैदा किए बिना बहने वाले अतिरिक्त पानी का उपयोग करने की स्वतंत्रता है। इसलिए इस तरह की स्वतंत्रता का मतलब यह होगा कि जब तक बड़े पैमाने पर आवंटन लागू है, सबसे कम नदी तटीय राज्य निश्चित रूप से नदी बेसिन में बहने वाले किसी भी अतिरिक्त पानी का उपयोग समुद्र में विलय होने से पहले कर सकता है, लेकिन इस तरह के उपयोगकर्ता को बड़े पैमाने पर परियोजनाओं और जलाशयों के स्थायी निर्माण के रूप में नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से, जब योजना "ए" के तहत तथाकथित बड़े पैमाने पर आवंटन की समीक्षा 31 मई, 2000 के बाद की जानी चाहिए, जो तेजी से आ रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से श्री परासरन का यह तर्क कि अतिरिक्त जल के उपयोग के तरीके में कोई बाधा नहीं है, इतने व्यापक आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब तक योजना "ए" चालू है और जब तक दो ऊपरी नदी तटीय राज्यों को पानी के आवंटन का अपना हिस्सा मिलता है, तब तक सबसे निचला नदी तटीय राज्य आंध्र प्रदेश नदी बेसिन में बहने वाले अतिरिक्त पानी का उपयोग कर सकता है। यह सच है कि इस तरह की स्वतंत्रता देते समय न्यायाधिकरण ने अपने उपयोगकर्ता के तरीके के बारे में संकेत नहीं दिया है, लेकिन इसे पढ़ा जाना चाहिए।

जिस क्षण आदेश के दूसरे भाग को पढ़ा जाता है, अर्थात् ऐसा उपयोगकर्ता न तो पढ़ेंगे।

अधिकार प्रदान करना और न ही उक्त के पक्ष में आवंटित किया गया माना जा सकता है सबसे निचला नदी तटीय राज्य। न्यायाधिकरण के निर्देश की प्रकृति होने के कारण, यह कर्नाटक और ओ. आर. एस. का राज्य है।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 345

केंद्र सरकार के लिए सबसे निचले नदी तटीय राज्य की किसी भी योजना या परियोजना को मंजूर करते समय विवेक का प्रयोग करना और यह ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में दी गई स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, ताकि सबसे निचले नदी तटीय राज्य को आवंटित मात्रा से अधिक अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर जल परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने की

अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है। यह केंद्र सरकार है जिसे सबसे निचले नदी तटीय राज्य की परियोजनाओं को मंजूरी देते समय इस विवेकाधिकार का प्रयोग करना है और इसका इस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए कि नदी तट पर किसी भी तरह की आशंका न हो। उच्च राज्यों का मानना है कि आने वाले सभी समय के लिए, अधिशेष जल को साझा करने का उनका अधिकार किसी भी तरह से खतरे में पड़ जाएगा। इन दोनों मुद्दों का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

इश्यू नं। 9

मुद्दे 10 और 11 का जवाब देते समय हमारे द्वारा जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, यह मुद्दा अब किसी भी आगे के विचार के लिए जीवित नहीं है और इस मुद्दे का जवाब तदनुसार प्रतिवादी राज्य आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिया जाता है।

इश्यू नं। 2 इस मुद्दे का जवाब शिकायत में किए गए दावों के साथ-साथ मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई के कारण के आधार पर दिया जाना चाहिए। जैसा कि कहा गया है।

उक्त राज्य ने वर्तमान मुकदमा दायर किया। यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्राधिकरण के गठन के लिए सहमत होने से इनकार है, जिससे योजना को लागू नहीं किया जा सकता है, जिसने वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण दिया है जिसके आधार पर मुकदमा दायर किया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आंध्र प्रदेश राज्य कभी भी कृष्णा घाटी प्राधिकरण के गठन के लिए सहमत नहीं हुआ है, जिसे योजना "बी" का आधार माना जाता था, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी-राज्य के पास मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। इस मुद्दे का जवाब वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ दिया जाता है।

इश्यू नं। 3

उपरोक्त मुद्दा वास्तव में आगे किसी स्पष्टीकरण और चर्चा के लिए उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि हमारे द्वारा यह माना गया है कि योजना "बी" नहीं है न्यायाधिकरण का निर्णय, हालांकि उसी का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। राहत 346

[

2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, शिकायत में मांगी गई रिपोर्ट को रिपोर्ट के विपरीत नहीं माना जा सकता है क्योंकि न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दोनों योजनाएं-योजना "ए" और योजना "बी" शामिल थीं, लेकिन यह निश्चित रूप से न्यायाधिकरण के फैसले के विपरीत है क्योंकि न्यायाधिकरण ने स्वयं बड़े पैमाने पर आवंटन के आधार पर पानी के वितरण के लिए योजना "ए" तैयार करके इसे संदर्भित विवाद का समाधान किया और जो न्यायाधिकरण के अनुसार स्वयं न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश में निहित है। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

इश्यू नं। 8

उपरोक्त मुद्दा शिकायत की प्रार्थना (ग) को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न होता है, जहाँ

अधिनियम की धारा 6 (ए) को शामिल करने पर, उस शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा नहीं है और इसलिए, इस न्यायालय को उस संबंध में उचित निर्देश जारी करने चाहिए। श्री नरीमन के अनुसार, अधिनियम की धारा 6 (ए) को शामिल करने का उद्देश्य, अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय का कार्यान्वयन है, जिसमें निर्णय में इस उद्देश्य के लिए एक तंत्र की स्थापना शामिल हो सकती है, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इंगित किया गया है और हाथ में ऐसे प्राधिकरण की स्थापना के मामले में, पार्टियों द्वारा सहमति नहीं होने पर, और न ही संसद सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत कोई कानून लेकर आई है और साथ ही उक्त योजना "बी" सभी नदी तटीय राज्यों द्वारा कृष्णा नदी के पानी के बेहतर और पूर्ण उपयोग के लिए विकसित की गई है, इस न्यायालय को केंद्र सरकार से प्राधिकरण का गठन करने का आह्वान करते हुए आवश्यक अनिवार्य आदेश जारी करने चाहिए। श्री नरीमन के अनुसार, कर्नाटक राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील, धारा 6 (ए) केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है और तदनुसार, उक्त सरकार पर एक कर्तव्य डालती है और यदि कानून कर्तव्य के साथ एक शक्ति प्रदान करता है, तो न्यायालय हमेशा संबंधित प्राधिकारी को उक्त कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है, यदि इसका पालन बिल्कुल नहीं किया जाता है। श्री नरीमन का तर्क है कि हालांकि न्यायाधिकरण ने अपना काफी समय कर्नाटक और ओ. आर. एस. के बेहतर राज्य के लिए योजना "बी" विकसित करने में लगाया।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 347

और तीन तटवर्ती नदियों के बीच कृष्णा नदी के पानी का पूर्ण उपयोग राज्य, लेकिन इसे अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं बना सके क्योंकि राज्यों में से एक ने निगरानी प्राधिकरण के गठन के लिए न्यायाधिकरण को सहमति नहीं दी थी।

जिसे वास्तव में योजना की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जब संसद स्वयं आगे आई है, संविधि पुस्तक पर धारा 6 (ए) को अंकित करना, जो केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए प्राधिकरण बनाने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि योजना "बी" निर्णय है और इसे लागू किया जाना चाहिए, तो निगरानी प्राधिकरण के गठन के लिए केंद्र सरकार को उचित निर्देश जारी कर सकता है। के अनुसार

श्री नरीमन, धारा 6 (ए) (1) विशुद्ध रूप से एक कार्यकारी कार्य है और इसमें अधीनस्थ विधान का कोई स्वाद नहीं है और इसलिए, न्यायालय को अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए श्री परासरन ने तर्क दिया कि धारा 6 (ए) के तहत शक्ति कार्यकारी नहीं है, बल्कि विधायी प्रकृति की है और इसलिए, न्यायालय किसी विधायी कार्य के प्रदर्शन के लिए अनिवार्य या अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने में उसी तरह उचित नहीं होगा जैसे न्यायालय विधायिका को कानून बनाने के लिए नहीं कह सकता है। श्री परासरन ने यह भी तर्क दिया कि धारा 6 (ए) की उप-धारा (7) में विचार किया गया है कि धारा 6 (ए) के तहत बनाई गई योजना को प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।

संसद और यह केवल संसद द्वारा योजना की पुष्टि करने के बाद ही प्रभावी होगा और यदि संसद योजना के निर्माण के लिए सहमत नहीं होती है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यह स्थिति होने के कारण, न्यायालय एक डिक्री पारित नहीं करेगा जो अंततः द्वारा रद्द किए जाने में सक्षम है संसद। श्री परासरन ने आगे तर्क दिया कि धारा 6 (ए) न्यायाधिकरण के निर्णय के लंबे समय बाद 1980 में अस्तित्व में आई थी, भले ही यह माना जाता है कि योजना "बी" न्यायाधिकरण का निर्णय है और धारा 6 (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा कर्तव्य का पालन कार्यकारी प्रकृति का है, फिर भी शक्ति

न्यायाधिकरण के निर्णय के संबंध में उन विषयों को छोड़कर प्रयोग नहीं किया जा सकता है जो सूची I की प्रविष्टि 56 से संबंधित शक्ति के भीतर आते हैं। अभियुक्त वकील के अनुसार, केंद्र सरकार एक प्राधिकरण तभी स्थापित कर सकती है जब संसद सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत कानून बनाती है और आवश्यकतानुसार आगे की घोषणा भी करती है। महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अंधारुजिना ने भी श्री परासरन के तर्क का समर्थन किया और कहा कि धारा 6 (ए) के तहत शक्ति अनिवार्य रूप से एक प्रत्यायोजित है।

विधायी शक्ति और इसलिए, कोई भी अदालत जारी करने में उचित नहीं होगी।

इस तरह की शक्ति के प्रयोग के लिए परमादेश। इस मुद्दे का वास्तव में जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कृष्णा घाटी प्राधिकरण जैसे प्राधिकरण के गठन के लिए निर्देश का

सवाल अभी सामने आएगा जब यह माना जाए कि योजना "बी" विकसित हुई [2000] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण द्वारा न्यायाधिकरण का निर्णय होता है और इसके कार्यान्वयन के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने की आवश्यकता होती है। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि योजना "बी" को न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं माना जा सकता है। 4, 5 और 7 और मामले के उस दृष्टिकोण में, हम विवादास्पद मुद्दों की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि क्या केंद्र द्वारा शक्ति का प्रयोग धारा 6 (ए) के तहत सरकार एक कार्यकारी है, जैसा कि श्री नरीमन ने तर्क दिया है या विधायी प्रकृति की है, जैसा कि श्री परासरन ने तर्क दिया है। इसलिए, हम इस मुद्दे को खुला छोड़ते हैं, न कि उसी पर निर्णय लेते हैं।

इश्यू नं। 12

यह मुद्दा महाराष्ट्र राज्य के कहने पर तैयार किया गया है।

उक्त राज्य द्वारा लिए गए इस रुख को ध्यान में रखते हुए कि 2000 ईस्वी में पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है, वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा पूर्व-परिपक्व है। 2060 टी. एम. सी. के आधार पर 75 प्रतिशत विश्वसनीय प्रवाह पर तीन नदी तटीय राज्यों के पक्ष में बड़े पैमाने पर आवंटन प्रदान करते हुए, न्यायाधिकरण ने स्वयं अपनी मूल रिपोर्ट में कहा है, जिसे प्रदर्शनी पी. के. 1 के रूप में चिह्नित किया गया है कि न्यायाधिकरण के आदेश की समीक्षा 31 मई, 2000 और इस अवधि के बाद किसी भी समय की जा सकती है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित माना जाता है कि इस बीच की अवधि के दौरान कृष्णा बेसिन में सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की बढ़ती मांग होगी, जिसकी जांच ताजा आंकड़ों के आलोक में की जानी चाहिए जो उपलब्ध हो सकते हैं और आगे जल संरक्षण और इसके उपयोग के मामले में और अन्य कारणों से भी प्रौद्योगिकी में अद्भुत प्रगति को देखते हुए। लेकिन न्यायाधिकरण के आदेश में इंगित की गई उपरोक्त समीक्षा योजना "ए" के तहत किए गए आवंटन के संबंध में है और इसका योजना "बी" से कोई लेना-देना नहीं है। चूंकि वादी-राज्य ने इस धारणा पर मुकदमा दायर किया है कि योजना "बी" न्यायाधिकरण का निर्णय है और इसे न्यायालय के अनिवार्य आदेश द्वारा लागू किया जाना चाहिए, इसलिए इस तरह के मुकदमे को इस आधार पर पूर्व-परिपक्व नहीं माना जा सकता है कि समीक्षा का प्रावधान 2000A.D के बाद किया गया है। इसलिए इस मुद्दे का जवाब वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ दिया जाता है।

इश्यू नं। 13

वाद में की गई प्रार्थना के साथ-साथ आधार के संदर्भ में

उक्त प्रार्थना और मुद्दे 3,4 और 7 पर हमारे निष्कर्षों को देखते हुए, वादी राज्य द्वारा मांगी गई राहत देने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमा है, और पक्षों द्वारा उठाए गए विवादों की प्रकृति को देखते हुए और कर्नाटक और ओआरएस राज्य में हमारी चर्चा को देखते हुए।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 349

न्यायाधिकरण द्वारा विकसित योजना 'बी' से संबंधित निर्णय, हमें लगता है कि यह

यह अवलोकन करना उचित होगा कि यदि तटवर्ती राज्यों में से कोई भी केंद्र सरकार से संपर्क करता है, तो केंद्र सरकार एक न्यायाधिकरण का गठन करने में अच्छा करेगी, जो न्यायाधिकरण विवादों के पूरे सरगम में जा सकता है और उक्त कार्यवाही में पक्ष निश्चित रूप से डेटा और सामग्री रख सकते हैं।

जिसके आधार पर बच्चावत न्यायाधिकरण ने कृष्णा नदी में पानी के प्रभावी आवंटन के लिए दो योजनाएं विकसित की थीं। कृष्णा बेसिन में पानी की उपलब्धता का पता लगाने के लिए भी पार्टियों के लिए यह खुला रहेगा कि वे मापन की बेहतर विधि के आधार पर नए आंकड़े दे सकें। वास्तव में विद्वान साँलिसिटर जनरल ने निष्पक्ष रूप से कहा कि यदि तटवर्ती राज्यों में से कोई भी केंद्र सरकार से संपर्क करता है, तो वह न्यायाधिकरण के गठन के लिए अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में संकोच नहीं करेगा और यही एकमात्र समाधान है

इस समय में।

पटनायक, जे. आंध्र प्रदेश राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर किया है, जिसमें कर्नाटक राज्य, भारत संघ और महाराष्ट्र राज्य को पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है, इस आरोप पर घोषणा की राहत और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की गई है कि कर्नाटक राज्य ने विशेष रूप से कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले का घोर उल्लंघन किया है और इस तरह के उल्लंघनों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। आंध्र प्रदेश राज्य के निवासी। मुकदमे में मांगी गई राहत इस प्रकार है:

" (क) घोषणा करें कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (के. डब्ल्यू. डी. टी.) की दिनांकित 24.12.1973 की रिपोर्ट/निर्णय और अगली रिपोर्ट/निर्णय उनकी संपूर्णता में तीन नदी तटीय राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और भारत संघ पर भी बाध्यकारी हैं; (ख) घोषणा करें कि नदी तटीय राज्य एक-दूसरे को और भारत संघ को भी पूरी तरह से खुलासा करने के लिए बाध्य हैं।

दिसंबर, 1973 और मई, 1976 के बाद शुरू की गई या प्रस्तावित सभी परियोजनाओं का विवरण और प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि उनका निष्पादन के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णयों के अनुरूप है और उनके साथ टकराव या उल्लंघन नहीं करता है और वे अन्य नदी तटीय राज्यों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं; (सी) घोषणा करें कि पार्टी राज्यों को पानी की मात्रा से अधिक उपयोग करने का अधिकार नहीं है जो

[2000] 3 एस. सी. आर. के लिए के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णयों द्वारा आवंटित या अनुमति दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण के समक्ष संबंधित पक्ष राज्यों की संबंधित परियोजनाएं; और यह कि ऐसी प्रत्येक परियोजना के संबंध में ऐसे प्रत्येक राज्य द्वारा पानी के भंडारण या उपयोग में कोई बदलाव केवल अन्य नदी तटीय राज्यों की पूर्व सहमति या सहमति से हो सकता है; (घ) घोषणा करें कि सभी परियोजनाएं निष्पादित हैं और/या जो प्रक्रिया में हैं।

कर्नाटक राज्य द्वारा निष्पादन जो के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णयों के अनुरूप नहीं हैं और उनके साथ टकराव या उल्लंघन करते हैं, अवैध के रूप में

(च) घोषणा करें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के संबंध में किसी भी अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णय द्वारा अधिकृत नहीं की गई योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में अंतर-राज्यीय नदी कृष्णा के पानी का भंडारण, नियंत्रण और उपयोग; (छ) यह घोषणा करना कि केंद्र सरकार किसी भी प्रस्तावित/शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं के लिए किसी भी अनुमोदन/मंजूरी/सैद्धांतिक मंजूरी के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सभी नदी तटीय राज्यों से परामर्श करने के लिए बाध्य है।

अंतर-राज्यीय नदी कृष्णा पर किसी भी नदी तटीय राज्य द्वारा और केंद्र सरकार को उक्त घोषणा के संदर्भ में कार्य करने का निर्देश देना; (ज) कर्नाटक राज्य को सभी को पूर्ववत करने का निर्देश देते हुए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा देना। परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में इसके अवैध, अनधिकृत कार्यों और विशेष रूप से के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णयों के विपरीत इसके द्वारा निष्पादित निम्नलिखित परियोजनाओं को, ताकि उन्हें उक्त निर्णयों के अनुरूप बनाया जा सके:

यू. के. पी. के तहत अलमट्टी बांध अलमट्टी जलाशय पर नहरों/लिफ्ट योजनाओं का निर्माण।

के-2 उप-बेसिन में ऊपरी कृष्णा परियोजनाएं।

हिप्परगी वियर/सिंचाई योजनाएं।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.) 351

नारायणपुर रिसर पर इंडी और रामपुर लिफ्ट योजनाओं का निर्माण

वाँयर और नहरें।

(i) कर्नाटक राज्य को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करना।

किसी भी आगे के कार्य को करने, जारी रखने या आगे बढ़ने से

निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में निर्माण: के तहत अलमट्टी बांध

यू. के. पी. अलमट्टी जलाशय पर नहरों/लिफ्ट योजनाओं का निर्माण के-2 उप-
बेसिन में ऊपरी कृष्णा परियोजनाएं।

हिप्परगी वियर/सिंचाई योजनाएं।

नारायणपुर रिसर पर इंडी और रामपुर लिफ्ट योजनाओं का निर्माण

वाँयर और नहरें।

(जे) एक व्यापक तकनीकी बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त करें।

विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट, निषेधाज्ञा का आदेश दें प्रतिवादी संख्या 1-कर्नाटक राज्य
को कार्यवाही से रोकना

निम्नलिखित में से किसी भी परियोजना में किसी भी आगे के निर्माण के साथ /

योजनाएं: यू. के. पी. नहरों/लिफ्टों के निर्माण के तहत अलमट्टी बांध अलमट्टी जलाशय पर योजनाएं।

के-2 उप-बेसिन में ऊपरी कृष्णा परियोजनाएं।

एल. वाई.

हिप्परगी वियर/सिंचाई योजना। नारायणपुर रिसेर पर इंडी और रामपुर लिफ्ट शर्न का निर्माण

वॉयर और नहरें।

(के) प्रतिवादी संख्या 1 को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना।
कर्नाटक राज्य गन्ना उगाने या उगाने की अनुमति देने से या

अधीन आने वाले कमान क्षेत्रों में अन्य गीली फसलें उगाना ऊपरी कृष्णा परियोजना के भीतर परियोजनाएं/योजनाएं; (1) प्रार्थना (ए) से (के) के संदर्भ में एक डिक्री पारित करें; और (एम) वर्तमान की पुरस्कार लागत

वादी के पक्ष में कार्यवाही; (एन) ऐसी आगे की डिक्री या डिक्री या अन्य आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

हालांकि ऊपर बताए गए अनुसार 14 राहतों की मांग की गई है, लेकिन [2000] 3 एस. सी. आर.

352

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनिवार्य रूप से राहत कर्नाटक राज्य द्वारा ऊपरी कृष्णा परियोजना के तहत अलमट्टी बांध के निर्माण से संबंधित है जिसकी ऊंचाई 524.256 M है। हालांकि शिकायत में तथ्यों के कथन 71 पैराग्राफ में किए गए हैं, जो सूक्ष्म विवरणों से छोटे हैं, उन्हें नीचे दिया जा सकता है:

कि तीन नदी तटीय राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र के बीच विवाद,

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने अंतर-राज्यीय नदी कृष्णा के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में 1973 में दिए गए निर्णय और 1976 में दिए गए आगे के निर्णय द्वारा अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 4 के तहत गठित न्यायाधिकरण के निर्णयों द्वारा समाधान किया। केंद्र सरकार द्वारा धारा 6 के तहत अधिसूचित किए जाने के बाद उक्त निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी हो गया। सभी पक्षकार-राज्य जो भारतीय गणराज्य संघ के घटक हैं, वादी को उम्मीद थी कि प्रत्येक राज्य, न्यायाधिकरण द्वारा अपने पक्ष में आवंटित पानी की मात्रा के उपयोग के लिए अपनी परियोजनाएं शुरू करते समय अन्य संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करेगा और इस तरह उपयोग करेगा, जो किसी भी तरह से न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन कर्नाटक राज्य न्यायाधिकरण के निर्णय के अक्षर और भावना के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है और दूसरी ओर न्यायाधिकरण के व्यक्त नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसने आंध्र प्रदेश राज्य को अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए मजबूर किया है।

संविधान। नदी के साथ-साथ तीन नदी तटीय राज्यों की स्थलाकृति और उन राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का संकेत देने के बाद जो केंद्र सरकार को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए प्रेरित करते हैं, वादी ने कहा है कि न्यायाधिकरण ने सात मुख्य मुद्दे तैयार किए हैं और सं. II ने अपने आठ उप-मुद्दों के साथ, योजना "ए" विकसित करके और अपने अंतिम आदेश या निर्णय के समान बनाकर कृष्णा नदी और नदी घाटी के पानी के लाभकारी उपयोग के न्यायसंगत विभाजन के प्रश्न का निर्णय लिया, जो अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी हो गया। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम उन सभी तथ्यों को दोहराएँ जो विवादों को उठाने और न्यायाधिकरण के गठन की ओर ले जाते हैं, जिन्हें हम कर्नाटक राज्य द्वारा दायर 1997 की धारा 1 के फैसले में पहले ही बता चुके हैं। वादी ने तब कहा कि कैसे पक्षों के बीच समझौते के आधार पर, विजयवाड़ा में 75 प्रतिशत भरोसेमंद प्रवाह 2060 टी. एम. सी. पाया गया और उपरोक्त 75 प्रतिशत भरोसेमंद प्रवाह के संबंध में अपने-अपने हिस्से के पानी के आवंटन के लिए प्रत्येक राज्य के मामले पर विचार करते हुए, नदी बेसिन में कई परियोजनाएं, जो पहले से ही राज्यों द्वारा शुरू की गई थीं और साथ ही परियोजनाओं के लिए आवश्यक पानी की मात्रा पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया था, जिसके आधार पर कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. के अंतिम आंकड़े पर विचार किया गया था।

आवंटन किया गया। शिकायत के अनुसार, न्यायाधिकरण ने महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों को उनके पक्ष में आवंटित पानी से अधिक पानी का उपयोग करने से रोकते हुए, वादी-आंध्र प्रदेश राज्य को शेष पानी का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

प्रदेश को आवंटित सीमा के अलावा इस तरह के पानी के उपयोगकर्ता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। वादी ने यह भी कहा कि तीनों राज्यों को आवंटन करते समय किसी भी कमी को साझा करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था और आगे न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 100 वर्षों में से 25 वर्षों में कमी हो सकती है। यह भी माना गया कि आंध्र राज्य को राहत देने के लिए

प्रदेश ने उपरोक्त कठिनाई से, न्यायाधिकरण ने आंध्र प्रदेश राज्य को नागार्जुनसागर बांध और श्रीशैलम बांध में पानी संग्रहीत करने की अनुमति दी और कहा कि इस तरह के भंडारण के लिए, इस आधार पर भरोसेमंद प्रवाह से उसके हिस्से से कोई कटौती नहीं की जाएगी कि यदि वादी-राज्य द्वारा पानी को संग्रहीत करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वह नीचे बह जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा। शिकायत के अनुसार, न्यायाधिकरण ने अपर कृष्णा परियोजना के संबंध में उसके समक्ष प्रस्तुत की गई विभिन्न परियोजना रिपोर्टों पर विचार किया और 103 टी. एम. सी. के संरक्षित उपयोग की अनुमति देते हुए, यह निष्कर्ष निकाला कि कर्नाटक राज्य की नारायणपुर राइट बैंक नहर द्वारा उपयोग की जाने वाली 52 टी. एम. सी. की मांग सार्थक है।

विचार करें। 1973 की अपनी मूल रिपोर्ट में न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के विभिन्न खंडों को गिनाने के बाद, वादी ने प्रतिवाद किया है कि हालांकि न्यायाधिकरण ने आवंटन को नकारात्मक रूप में निहित किया है, अर्थात् राज्य किसी भी जल वर्ष में अपने हिस्से में पानी की आवंटित मात्रा से अधिक का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन उक्त आवंटन को न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षों के प्रासंगिक रुख, न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों और आंकड़ों और अंतिम आधार के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया था। वादी के अनुसार, उपरोक्त विधि का सहारा लेने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पक्ष-राज्यों को अपने-अपने क्षेत्र के भीतर, उससे आगे कृष्णा नदी के विभिन्न उप-बेसिनों में उपयोग करने से रोक दिया गया था

जिसे सुरक्षात्मक उपयोग और उनके हिस्से के लिए आवंटित अतिरिक्त मात्रा के रूप में माना जाता था। शिकायत में यह कहा गया है कि जहां तक कर्नाटक राज्य के भीतर ऊपरी कृष्णा परियोजना का संबंध है, न्यायाधिकरण ने उपयोग के लिए केवल 160 टी. एम. सी. पानी आवंटित किया है और 524 मीटर की ऊंचाई तक अलमट्टी बांध का निर्माण, जैसा कि कर्नाटक राज्य द्वारा संकेत दिया गया है, इसलिए न्यायाधिकरण के फैसले का उल्लंघन होगा। अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न आवेदनों

और उसी पर न्यायाधिकरण के जवाब का उल्लेख करने के बाद, वादी ने यह भी बताया है कि न्यायाधिकरण ने दलीलों से कैसे निपटा

52 [2000] 3 एस. सी. आर. के आवंटन के संबंध में महाराष्ट्र राज्य द्वारा उठाया गया।

354

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नारायणपुर दाहिने किनारे की नहर से टी. एम. सी. पानी। हालाँकि, वादी के अनुसार, न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश में कोई संदेह नहीं है कि 2060 टी. एम. सी. में से तीन नदी तटीय राज्यों के पक्ष में बड़े पैमाने पर पानी का आवंटन किया गया है, जो कि विजयवाड़ा में निर्भरता के 75 प्रतिशत से कम है, जो कि पक्षों की सहमति से आया था, लेकिन रिपोर्ट की पूरी तरह से जांच की जा रही है, यह स्पष्ट होगा कि विभिन्न उप-बेसिनों के संबंध में आवंटन उन उप-बेसिनों में शुरू की गई परियोजनाओं के आधार पर किया गया था और इसके परिणामस्वरूप, कोई भी राज्य किसी विशेष उप-बेसिन में अपने पक्ष में आवंटित पानी की पूरी मात्रा का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। वादी ने तब कहा है कि कर्नाटक राज्य द्वारा अलमट्टी बांध की ऊंचाई को 524 मीटर तक बढ़ाने के इरादे से किए गए निर्णय के बाद के विकास न्यायाधिकरण के फैसले का घोर उल्लंघन है और इसलिए, इस न्यायालय को कर्नाटक राज्य को 524 मीटर की ऊंचाई तक अलमट्टी बांध के साथ आगे बढ़ने पर रोक लगा देनी चाहिए, जैसा कि उसकी परियोजना में संकेत दिया गया है। इसके बाद वादी ने कर्नाटक राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच हुए कई पत्राचारों के साथ-साथ इन राज्यों और केंद्र सरकार और केंद्रीय जल आयोग के बीच हुए पत्राचार का उल्लेख किया। यह भी अनुमान लगाया गया है कि कर्नाटक राज्य को अलमट्टी में 524 मीटर की ऊंचाई तक बांध बनाने की अनुमति देना निचले नदी तटीय राज्य आंध्र प्रदेश के लिए बहुत हानिकारक होगा क्योंकि जुलाई से सितंबर तक साल में तीन महीने तक आंध्र प्रदेश राज्य सूख सकता है और पानी की कमी के कारण राज्य में पूरी फसल क्षतिग्रस्त हो सकती है। वादी ने वाद के कई अनुच्छेदों में यह भी कहा है कि कैसे वादी-राज्य कर्नाटक राज्य से अलमट्टी में बांध के निर्माण के संबंध में उपयुक्त जानकारी की मांग कर रहा है और कैसे वादी-राज्य को ऐसी किसी भी जानकारी के साथ पक्ष लेने से रोका गया है। शिकायत के पैराग्राफ 34 में, वादी ने तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र का उल्लेख किया है, जिसमें कृष्णा बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया गया है।

ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण-II पर चर्चा करते हुए और उक्त पत्र के साथ, केंद्रीय जल आयोग का अवलोकन, यह दर्शाता है कि कैसे परियोजना

अलमट्टी 173 टी. एम. सी. से अधिक पानी के उपयोग की भौतिक क्षमता पैदा करता है, जो 173 टी. एम. सी. पानी के उपयोग के लिए आवश्यक स्तर 518.7 मीटर के मुकाबले एफ. आर. एल. 521 मीटर पर रेडियल गेट के प्रस्तावित शीर्ष को देखते हुए संभव होगा। वाद के बाद के पैराग्राफ में, यह भी संकेत दिया गया है कि कैसे आंध्र प्रदेश राज्य बाढ़ सुरक्षा उपाय की आड़ में अलमट्टी बांध की ऊंचाई 524 मीटर रखने के कर्नाटक राज्य के प्रस्तावों पर आपत्ति जता रहा है और फिर कैसे वादी राज्य ने भारत के प्रधान मंत्री से कर्नाटक राज्य और ओआरएस से बचने के लिए मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 355

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन। पैराग्राफ में 39 शिकायत में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ केंद्रीय जल आयोग जो अंतर-राज्यीय परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है, आंध्र प्रदेश राज्य से परामर्श किए बिना 524 मीटर की ऊंचाई तक अलमट्टी परियोजना को मंजूरी देने पर आमादा है, हालांकि, सरकार के संघीय ढांचे में वादी के अनुसार, प्रत्येक घटक राज्य अंतर-राज्यीय नदी के संबंध में किसी भी परियोजना की प्रगति जानने का हकदार होगा, क्योंकि इसका अन्य राज्यों पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वादी ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य के कहने पर, संयुक्त मोर्चा सरकार, जो केंद्र में थी, ने अलमट्टी बांध के निर्माण से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए चार मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया, जिसने बदले में, केंद्रीय जल आयोग और योजना आयोग के एक प्रतिनिधि के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया, जिन्होंने अंततः कार्यवाही में भाग नहीं लिया। उक्त विशेषज्ञ समिति ने पाया है कि अलमट्टी बांध के लिए 524.256 मीटर के एफआरएल के साथ ऊपरी कृष्णा परियोजना का प्रस्ताव विचाराधीन है और भारत सरकार द्वारा इसे मंजूरी नहीं दी गई है, हालांकि कई नहरों को भविष्य के उपयोग के लिए बड़ी क्षमता के लिए डिजाइन और निर्माण किया गया है और अलमट्टी बांध में 227 टीएमसी का बड़ा भंडारण बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें 524.256 मीटर पर शटर का शीर्ष हो। उक्त समिति ने यह भी कहा था कि शटर के शीर्ष पर एफ. आर. एल. को वर्तमान के लिए 519.6 मीटर पर तय किया जाना चाहिए और फाटकों का निर्माण और निर्माण तदनुसार किया जाना चाहिए और यह ऊपरी कृष्णा परियोजना के तहत वर्तमान में परिकल्पित 173 टी. एम. सी. की वार्षिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त होगा। उक्त समिति,

इसके बाद 18 दिसंबर, 1996 के अपने पत्र में सचिव से अनुरोध किया गया, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा कृष्णा जल विवाद [2000] 3 एस. सी. आर. के निर्णय को भारत के राजपत्र में तुरंत सार्वजनिक करना सुनिश्चित करना।

356

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण अर्थात् रिपोर्ट दिनांकित 24.12.1973 और अगली रिपोर्ट दिनांकित 27.5.1976 पूरी तरह से। लेकिन जब से यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिवादी संख्या 1 कर्नाटक राज्य किसी भी सौहार्दपूर्ण चर्चा द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था और न ही वह मध्यस्थता के लिए कोई प्रयास करना चाहता था।

जो भी हो, वादी के पास वादी राज्य के अधिकारों के साथ-साथ कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय से आने वाले उसके निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ घोषणाओं और निषेधाज्ञा के लिए संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। पैराग्राफ 65 के बाद से, वादी ने कर्नाटक राज्य द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन करने वाले कई तथ्यों का वर्णन किया है और पैराग्राफ 69 के बाद से, वादी ने कर्नाटक राज्य को बांध की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति देने के मामले में केंद्र सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका का संकेत दिया है, जो अंततः नियमों और शर्तों के साथ-साथ न्यायाधिकरण के निर्णय में प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा और जो आंध्र प्रदेश राज्य और उसके निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। मुकदमे को दायर करने के लिए कार्यवाई का कारण शिकायत के पैराग्राफ 73 में इंगित किया गया है, अर्थात् कर्नाटक राज्य द्वारा ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण I और II के साथ अल्मट्टी बांध के निर्माण के साथ आगे बढ़ने में संलिप्तता जो अक्षर और भावना में न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन है।

प्रतिवादी संख्या 1-कर्नाटक राज्य ने अपने लिखित बयान में,

यह स्थिति है कि न्यायाधिकरण ने कोई परियोजना-वार आवंटन नहीं किया था और दूसरी ओर, आवंटन निहित है और इस प्रकार न्यायाधिकरण के निर्णय की व्याख्या करने का प्रश्न कि किसी विशेष बेसिन में पानी के उपयोग पर प्रतिबंध है, सही नहीं है। यह भी कहा गया है कि कर्नाटक राज्य ने 1970 की परियोजना रिपोर्ट में ही अल्मट्टी में बांध की ऊंचाई को 524.256 m माना था और यह रिपोर्ट न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई थी और इसे दस्तावेज़ MYPK-3 के रूप में चिह्नित किया गया था। न तो आंध्र प्रदेश राज्य और न ही किसी अन्य राज्य ने उक्त

परियोजना रिपोर्ट पर कोई आपत्ति जताई थी और उस मुद्दे पर न्यायाधिकरण के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था और वास्तव में अलमट्टी बांध की ऊंचाई न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय का विषय नहीं थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, वादी-राज्य को इस कथित आरोप पर उस मुद्दे को उठाने का अधिकार नहीं है कि यह न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन है। यह भी संतोषजनक है कि एक व्यक्ति द्वारा आंध्र प्रदेश में एक रिट याचिका दायर करके एक समान मुद्दा उठाया गया है और उसे खारिज करने के बाद, मामला इस न्यायालय में लाया गया है और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई है, उसी प्रश्न को कर्नाटक और ओआरएस के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य द्वारा मुकदमा दायर करके फिर से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 357

भारत का संविधान। समिति के निर्णय के संबंध में, जिसमें एफ. आर. एल. 519.6 एम. के बारे में कहा गया है, लिखित बयान में यह कहा गया है कि उक्त समिति ने बांध की भंडारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए 519.6 मीटर की ऊंचाई को पर्याप्त माना, जो एक जल वर्ष में 173 टी. एम. सी. की वार्षिक आवश्यकता का ध्यान रखेगी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया।

बिजली उत्पादन के लिए और अलमट्टी में बांध की ऊंचाई 519.6 मीटर से अधिक और 524.256 मीटर तक की परियोजना के लिए केवल बिजली उत्पादन के लिए और इस प्रकार बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के गैर-उपभोगी होने के कारण, इसके उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं है।

न्यायाधिकरण का कोई भी निर्देश जब कर्नाटक राज्य ने अलमट्टी में बांध की ऊंचाई 524.256 मीटर रखने का निर्णय लिया हो। लिखित वक्तव्य में विशेष रूप से यह कहा गया है कि न्यायाधिकरण के निर्णय, जिसे अधिनियम की धारा 6 के तहत राजपत्रित किया गया है, ने किसी भी परियोजना के निर्माण के लिए किसी भी राज्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और दूसरी ओर खंड XV में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि: न्यायाधिकरण के आदेश की कोई भी बात किसी भी राज्य के अपनी सीमाओं के भीतर विनियमन के अधिकार या शक्ति या अधिकार को बाधित नहीं करेगी। पानी का उपयोग, या उस राज्य के भीतर पानी का लाभ इस तरह से लेना जो इस न्यायाधिकरण के आदेश से असंगत न हो और ऐसे विशिष्ट प्रावधान को देखते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए यह तर्क देना व्यर्थ है कि अलमट्टी में बांध की ऊंचाई को 524.256 मीटर तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि अलमट्टी में परियोजना को करोड़ रुपये से अधिक की भारी लागत से शुरू किया गया है और इस अग्रिम चरण में परियोजना को रोकना राष्ट्रीय हित में नहीं है और कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा करने में देरी करने के लिए डिजाइन के साथ मुकदमा दायर किया गया है।

यह दोहराया गया है कि पानी का उपयोग पूरी तरह से न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित मात्रा के भीतर होगा। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, वादी ने अपने कानूनी अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनाया है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। द.

प्रतिवादी ने उस पृष्ठभूमि का भी वर्णन किया जिसके तहत केंद्र सरकार ने नदी तटीय राज्यों के बीच विवादों के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया और कैसे अंततः न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उसमें पाए गए तथ्यों के साथ-साथ उस पर निर्णय भी दिया गया। प्रतिवादी राज्य ने लिखित बयान में यह भी कहा है कि अलमट्टी बांध को ऊपरी कृष्णा परियोजना के लिए दो चरणों में 173 टी. एम. सी. के उपयोग के लिए तैयार किया गया है और राज्य ने न्यायाधिकरण के समक्ष शुरुआत से ही यह संकेत दिया था कि ऊंचाई, हालांकि न तो किसी पक्ष ने कोई आपत्ति जताई है और न ही कोई मुद्दा उठाया गया है, न ही न्यायाधिकरण द्वारा स्वयं कोई निर्णय दिया गया है और इस मामले को देखते हुए अलमट्टी में बांध की ऊंचाई के संबंध में कोई भी शिकायत ताजा जल विवाद होगी और यह न्यायनिर्णित विवाद और निर्णय [2000] 3 एस. सी. आर. के भीतर नहीं आएगी।

358

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस पर स्वयं न्यायाधिकरण द्वारा और इसलिए, अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया मुकदमा विचारणीय नहीं है। यह विशेष रूप से अनुमान लगाया गया है कि भंडारण स्तर

अलमट्टी बांध 519.6 मीटर से 524.256 मीटर तक बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, विशेष रूप से, जब न्यायाधिकरण ने स्वयं स्पष्ट रूप से अलमट्टी बांध की पूर्ण ऊंचाई पर विचार किया है जो कि प्रदर्शनी एम. वाई. पी. के. 3 में ऊंचाई है। प्रतिवादी ने 30 जनवरी, 1994 की केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसके तहत यह संकेत दिया गया है कि चूंकि अलमट्टी में परियोजना के तहत 519.60 मीटर और 521 मीटर के बीच पानी के अतिरिक्त भंडारण का उपयोग करके बिजली उत्पादन पर विचार किया जा रहा है, इसलिए परियोजना को एक बहुउद्देश्यीय परियोजना के रूप में माना जा सकता है (सिंचाई के लिए 173 टी. एम. सी. पानी का उपयोग करने के लिए आवश्यक स्तर 519.60 मीटर है)। प्रतिवादी-कर्नाटक राज्य ने स्पष्ट किया है कि भले ही बांध की ऊंचाई इस अंतिम स्तर तक बढ़ा दी गई हो

पुरस्कार में किए गए आवंटन और किसी भी अतिरिक्त राशि के अनुसार सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा केवल 173 टी. एम. सी. है।

173 टी. एम. सी. से अधिक की मात्रा को बिजली पैदा करने के बाद नदी में छोड़ा जाएगा। यह भी तर्क दिया गया है कि अंतर-राज्यीय नदी के संबंध में जल विवाद होने के कारण उठाया गया विवाद अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 11 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 262 द्वारा शासित है, और इसलिए, अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। पद के दुरुपयोग के बारे में वादी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया गया है। इस बात से भी इनकार किया गया है कि न तो न्यायाधिकरण के निर्णय की कोई आवश्यकता है और न ही कोई दायित्व जो किसी भी राज्य को अपने जल संसाधनों के उपयोग के लिए परियोजनाओं की योजना बनाने के मामले में किसी अन्य राज्य से परामर्श करने के लिए मजबूर करता है और इस संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा उठाया गया तर्क पूरी तरह से गलत है। प्रतिवादी आगे तर्क देता है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने अलमट्टी बांध की ऊंचाई या किसी अन्य विनिर्देश के संबंध में अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत स्पष्टीकरण मांगने के अवसर का उपयोग नहीं किया है, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर करके इस न्यायालय में इस विवाद को उठाने का हकदार नहीं है। प्रतिवादी-कर्नाटक राज्य ने दोहराया कि यू. के. पी. के तहत पानी का उपयोग पहले अलमट्टी में और बाद में नारायणपुर डाउनस्ट्रीम में, पूरी तरह से 173 टी. एम. सी. के दायरे में है और किसी भी स्थिति में प्रतिवादी कर्नाटक को आवंटित 734 टी. एम. सी. के कुल हिस्से के भीतर है और अलमट्टी और नारायणपुर में अपर कृष्णा परियोजना का निर्माण सभी मामलों में विशेषज्ञ तकनीकी निकायों द्वारा निर्धारित कार्य विनिर्देशों के अनुरूप है, जिसमें नदी जलमार्ग का प्रावधान भी शामिल है। न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के खंड XV के संबंध में, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि ऊपरी कृष्णा परियोजना के संबंध में विचार की गई 155 टी. एम. सी. की मात्रा प्रतिवादी कर्नाटक को 34 टी. एम. सी. पुनर्जनन, 23 टी. एम. सी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उपयोग बढ़ाने की योजना बनाने से प्रतिबंधित नहीं करती है।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 359

न्यायाधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना "बी" को अपनाने के बाद उपलब्ध होना। यह तर्क दिया जाता है कि न्यायाधिकरण ने आवंटन के लिए प्रावधान नहीं किया है या उपयोग परियोजना-जब तक सामूहिक आवंटन का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तब तक वादी को कोई शिकायत नहीं है और वह मुकदमा दायर करने का हकदार नहीं है। लिखित बयान में कहा गया है कि 21 अप्रैल, 1996 को अपर कृष्णा परियोजना चरण-II के लिए बहुउद्देशीय परियोजना के

रूप में पुनः प्रस्तुत किए गए संशोधित प्रस्ताव में सी. डब्ल्यू. सी. की विभिन्न टिप्पणियों के अनुपालन को शामिल किया गया है और फिर से 524.256 मीटर के एफ. आर. एल. का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भले ही बांध को इसके अंतिम स्तर 524.256 तक उठाया जाना था।

एम, पुनः समायोजन के अनुसार सिंचाई के लिए उपयोग केवल 173 टी. एम. सी होगा

लिखित बयान में, प्रतिवादी संख्या 1 ने यह भी कहा कि उक्त विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष गलत हैं। अलमट्टी बांध के निर्माण से भारी मात्रा में पानी के भंडारण से आंध्र प्रदेश और उसके निवासियों के हित प्रभावित होने के शिकायत में आरोपों के संबंध में, प्रतिवादी कर्नाटक ने इसका खंडन किया और यह भी कहा कि बांध का उद्देश्य सिंचाई के लिए लगभग 173 टी. एम. सी. पानी का उपयोग करना है और शेष भंडारण जल का उपयोग करना है। गैर-उपभोगी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए अर्थात् बिजली का उत्पादन और इसलिए, [2000] 3 एस. सी. आर.

360

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पानी आंध्र प्रदेश में बह जाएगा और उक्त राज्य किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। चामुंडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कर्नाटक राज्य के निगमन के संबंध में शिकायत में आरोपों के संबंध में

उसने कहा है कि राज्य कानून के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष मामले को आगे बढ़ा रहा है और वादी की सहमति प्राप्त करने का सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ तक पर्यावरण पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव के बारे में शिकायत में किए गए दावों का संबंध है, कर्नाटक राज्य इसका खंडन करता है। कथित जलमग्नता के सवाल पर यह कहा गया है कि कर्नाटक राज्य सभी पर्याप्त कदम उठाएगा। कानून के अनुसार मुआवजा प्रदान करना और विस्थापित आबादी, यदि कोई हो, का पुनर्वास करना। इस दावे का खंडन किया गया है कि अलमट्टी बांध आंध्र प्रदेश में प्रमुख परियोजनाओं को अनावश्यक बना देगा। जहाँ तक पर्यावरण कानून के उल्लंघन के आरोप का संबंध है, लिखित बयान में यह कहा गया है कि पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा प्रक्रिया में हैं और कर्नाटक राज्य ने ऐसा नहीं किया है।

उपयुक्त प्राधिकरणों से उचित मंजूरी के बिना कुछ भी किया। प्रतिवादी-कर्नाटक राज्य के अनुसार, शिकायत में किए गए कथन गलत हैं और उनमें ईमानदारी और सभी आरोपों का अभाव है और

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्षेपों का खंडन किया जाता है। बाकी सब।

कर्नाटक राज्य द्वारा अवैध रूप से बनाए जाने के आरोपों का खंडन किया गया है। जहाँ तक ऊपरी कृष्णा परियोजना के प्रभावी निष्पादन के लिए जल निगम के निर्माण का संबंध है, कर्नाटक राज्य का तर्क है कि उक्त निगम पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है और इसकी सभी गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं -

सिंचाई विभाग, सरकार द्वारा नियंत्रित। कर्नाटक सरकार और इसलिए, वादी का यह आरोप कि राज्य परियोजना के निष्पादन के लिए अपनी जिम्मेदारी का त्याग कर रहा है, गलत है और इससे इनकार किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर अलमट्टी में काम बंद कर दिया जाता है और आंध्र प्रदेश राज्य फसल काटना चाहता है तो कर्नाटक राज्य को अपूरणीय नुकसान होगा।

तीनों राज्यों के पक्ष में किए गए बड़े पैमाने पर आवंटन को देखते हुए नदी में बहने वाले अतिरिक्त पानी का उपयोग करने की स्वतंत्रता का लाभ। यह हो चुका है

विशेष रूप से कहा गया है कि 519.6 से 524.256 मीटर की ऊंचाई के बीच अतिरिक्त पानी के भंडारण का उपयोग केवल बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा न कि सिंचाई के लिए जब तक कि गोदावरी मोड़ और योजना "बी" के तहत अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं हो जाता है। यह विशेष रूप से बताया गया है कि कैसे कर्नाटक सरकार ने ऊपरी कृष्णा परियोजना में पनबिजली परियोजनाओं के समूह को चरणों में शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी है और कैसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने "सैद्धांतिक" मंजूरी दी है। दोहराव की कीमत पर, कर्नाटक राज्य ने कहा है कि कोई

न्यायाधिकरण और अलमट्टी बांध के निर्णय के विचलन की योजना कर्नाटक और ओ. आर. एस. राज्य में बनाई गई है।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 361

कर्नाटक राज्य के पक्ष में न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित जल के उपयोग के लिए। इस प्रतिवादी के अनुसार, अंतिम नदी तटीय राज्य होने के नाते आंध्र प्रदेश को प्रचुर मात्रा में पानी प्राप्त है, जिसमें अपने स्वयं के आवंटन के अलावा ऊपरी नदी तटीय राज्यों का अप्रयुक्त हिस्सा भी शामिल है।

पक्ष लिया और इसलिए, कोई भी हानिकारक कठिनाइयों को स्थापित करने का मामला नहीं बनाया गया है ताकि राज्य को निषेधाज्ञा की विवेकाधीन राहत प्राप्त करने का अधिकार हो। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि वादी ने पीने के पानी, खाद्यान्न या बेरोजगारी के कथित नुकसान को स्थापित करने वाली किसी भी स्वीकार्य सामग्री के आधार पर साक्ष्य का एक टुकड़ा नहीं रखा है और ऐसे सभी आरोप गलत हैं। कर्नाटक राज्य के अनुसार, सभी प्रासंगिक समय पर सभी संशोधित योजनाओं को केंद्र सरकार के उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और सक्षम अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है। अंत में यह कहा गया है कि मुकदमे का आधार यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा किया गया आवंटन परियोजना-वार है और उक्त आधार सही होने के कारण, वादी संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर करके मांगी गई राहत का हकदार नहीं है।

भारत संघ-प्रतिवादी सं। 2 अपने लिखित बयान में मुकदमे की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर उठाई गई कि बनाया गया मुकदमा अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 11 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 को देखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं है। आम तौर पर शिकायत में लगाए गए आरोपों को नकारते हुए भारत संघ ने सकारात्मक रूप अपनाया कि कर्नाटक बहुउद्देशीय परियोजना चरण II, जिसमें पनबिजली के युगों के उत्पादन की परिकल्पना की गई है, अभी भी जांच के दायरे में है और परियोजना रिपोर्ट में 519.6 M से 524.256 M तक भंडारण स्थान के अतिरिक्त पानी का भंडारण करके पनबिजली उत्पादन का प्रावधान है और यह संकेत दिया गया है कि इसके बाद

बिजली उत्पादन के बाद पनबिजली का उत्पादन कृष्णा नदी में किया जाएगा और यू. के. पी. के तहत कृष्णा नदी के पानी का उपयोग 173 टी. एम. सी. के भीतर किया जाएगा। शिकायत के आरोप के संबंध में कि पुरस्कार न्यायाधिकरण के तहत जल परियोजना के अनुसार आवंटित किया गया है, भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि पानी का आवंटन सकल आवंटन है न कि परियोजना के अनुसार आवंटन। यह भी कहा गया है कि राज्य सकल राशि का उपयोग करने का हकदार है।

ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पानी की मात्रा और जब तक कामटक द्वारा उपयोग ऊपरी कृष्णा परियोजना में 173 टी. एम. सी. के भीतर है, तब तक कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण पुरस्कार का कोई उल्लंघन नहीं है। यह भी संकेत दिया गया है कि यू. के. पी. के पहले चरण को मंजूरी दे दी गई है और दूसरे चरण की विभिन्न जांच की जा रही है और अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है। जहाँ तक शिकायत का मामला है कि केंद्र सरकार को एक राज्य की परियोजनाओं को मंजूरी देते समय अन्य राज्यों से परामर्श करने की आवश्यकता है, यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार पर उक्त पक्ष [2000] 3 एस. सी. आर. से परामर्श करने का कोई दायित्व नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य पक्षीय राज्य कृष्णा बेसिन की परियोजनाओं को मंजूरी देते समय राज्य जब वे के. डब्ल्यू. डी. टी. पुरस्कार के ढांचे के भीतर हों। द्वारा वित्तीय सहायता केंद्र सरकार राज्य को अनुदान के रूप में दे रही है और

ऋण। जहाँ तक विशेष रूप से अलमट्टी परियोजना का संबंध है, केंद्र सरकार का अपने लिखित बयान में यह रुख है कि यू. के. पी. चरण I पहले ही हो चुका है।

इसे मंजूरी दी गई और इसे योजना आयोग द्वारा 22 अप्रैल, 1978 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत ईएल 500 मीटर पर ठोस स्पिलवे क्रैस्ट स्तर और 12.2 मीटर ऊंचे फाटकों के साथ एफआरएल 512.2 मीटर के अनुरूप आंशिक ऊंचाई तक अलमट्टी बांध का निर्माण किया गया। लेकिन द्वितीय चरण में इतनी ऊंचाई के रेडियल गेटों को विच्छेदन और पुनर्निर्धारण करने की तकनीकी कठिनाई को देखते हुए, कर्नाटक सरकार यू. के. पी. चरण I में ही अंतिम चरण और 512 मीटर तक के ठोस शिखर के लिए आवश्यक पूर्ण खंड के साथ अलमट्टी डार्न का निर्माण करना चाहती थी। कर्नाटक सरकार के संशोधित प्रस्ताव की केंद्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई और तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपनी 20 वीं बैठक में विचार किया गया। टी. ए. सी. ने सिफारिश की कि ई. एल. 500 मीटर तक पूरी चौड़ाई में अलमट्टी बांध को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की मंजूरी इस अवलोकन के अधीन दी जा सकती है कि राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद, राज्य सरकार ने परियोजना के पहले चरण के तहत जलमग्नता को कम करने के उद्देश्य से ई. एल. 509 मीटर पर अलमट्टी स्पिलवे क्रैस्ट और 15.2 उच्च रेडियल गेट के साथ संशोधित प्रस्ताव पेश किए। इस संशोधित चरण I अनुमान को 24.4.1990 पर योजना आयोग की मंजूरी मिल गई। केंद्र सरकार के लिखित बयान के अनुसार, यू. के. पी. के पहले चरण को केंद्रीय जल आयोग के साथ-साथ योजना आयोग द्वारा कुछ संशोधनों के साथ विधिवत मंजूरी दी गई थी

कृष्णा परियोजना चरण II (1993) UKP.Stage II बहुउद्देशीय परियोजना (1996) के रूप में और उस परियोजना की जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश राज्य ने उक्त परियोजना को अपनी टिप्पणियां भेजी हैं और विभिन्न मूल्यांकन एजेंसियां हैं संरचनात्मक पहलू से फाटकों के डिजाइन की जांच करना। लेकिन कोई अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है। आंध्र प्रदेश राज्य के इस आरोप का खंडन किया गया है कि केंद्र सरकार ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और दूसरी ओर

कहा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य यह साबित करने में सक्षम नहीं है

कि अलमट्टी बांध के निर्माण से कर्नाटक राज्य के. डब्ल्यू. डी. टी. द्वारा आवंटित पानी से अधिक पानी का उपयोग करेगा। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य तेलुगु गंगा का निर्माण कर रहा है।

परियोजना जो एक अप्रमाणित परियोजना है। जहाँ तक शिकायत में आरोप है कि पर्यावरण और वन विभाग द्वारा ऊपरी कृष्णा परियोजना को मंजूरी देने से पहले आंध्र प्रदेश राज्य से परामर्श नहीं किया गया था, यह 363 रहा है।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे।]

उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वन विभाग, भारत सरकार की ओर से कर्नाटक राज्य की ऊपरी कृष्णा परियोजना को मंजूरी देते समय आंध्र प्रदेश राज्य के विचार प्राप्त करने का कोई दायित्व नहीं है। केंद्र सरकार के अनुसार न्यायाधिकरण का निर्णय पक्षों के लिए बाध्यकारी है और वादी इसका कोई उल्लंघन नहीं दिखा पाया है।

न्यायाधिकरण का निर्णय।

विद्युत मंत्रालय की ओर से जो प्रतिवादी संख्या 2 (सी) है एक अलग

अभियोग के पैराग्राफ 56 और 57 में किए गए कथनों का जवाब देते हुए लिखित बयान दायर किया गया है और यह संकेत दिया गया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा ऊपरी अदालत को "सिद्धांत रूप में" मंजूरी दी गई है।

अलमट्टी में कृष्णा परियोजना परियोजना की मंजूरी के समान नहीं है।

सक्षम प्राधिकारी। कथित प्रतिवादी के अनुसार मूल्यांकन करते समय राज्यों से प्राप्त बिजली परियोजना के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर उचित ध्यान दिया जाता है।

उचित मूल्यांकन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा।

महाराष्ट्र राज्य-प्रतिवादी संख्या 3 ने एक लिखित बयान दायर किया।

कर्नाटक राज्य द्वारा लिए गए रुख का पूरी तरह से समर्थन करते हुए लिखित बयान में कहा गया है कि ए. पी. राज्य की शिकायत आगे बढ़ती है।

कुछ धारणाओं पर जो सही नहीं हैं। मुख्य के बारे में

प्रश्न, अर्थात्, क्या एनब्लॉक आवंटन था या परियोजनावार आवंटन था प्रतिवादी राज्य महाराष्ट्र का स्पष्ट रूप से कहना है कि न्यायाधिकरण

मात्राएँ आवंटित करके कृष्णा नदी के पानी को समान रूप से आवंटित किया गया एनब्लॉक या भारी मात्रा में। यद्यपि इसने अलग-अलग परियोजनाओं पर चर्चा की है

प्रत्येक राज्य केवल प्रत्येक राज्य की जरूरतों का आकलन करने के सीमित उद्देश्य के लिए न्यायसंगत वितरण के सिद्धांतों के अनुसार। यह आगे कहा गया है

उक्त लिखित बयान में कहा गया है कि प्रतिबंधों के अलावा स्पष्ट रूप से

न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश में कहा गया है जिसे केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है सरकार द्वारा उपयोग की विधि पर कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया गया है

संबंधित राज्य और न्यायाधिकरण के आवंटित हिस्से के भीतर प्रत्येक राज्य ने प्रत्येक राज्य द्वारा और खंड के अनुसार भंडारण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है

अंतिम आदेश का VII प्रत्येक राज्य द्वारा जल का भंडारण नहीं होगा

न्यायाधिकरण की रिपोर्ट के कई पैराग्राफ उद्धृत किए गए हैं यह इंगित करने के लिए कि अंतिम आवंटन परियोजना के अनुसार नहीं था और

इसके अलावा न्यायाधिकरण द्वारा कोई प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है

कृष्णा बेसिन में बांधों के भंडारण, आकार और ऊंचाई के संबंध में। राज्य ने

बाद के आचरण का भी उल्लेख किया गया है, कि मूल प्रस्तुत करने के बाद

रिपोर्ट और न्यायाधिकरण का निर्णय आंध्र प्रदेश राज्य ने वास्तव में दायर किया [2000] 3 एस. सी. आर.

364

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्टीकरण नोट 9 और 10 7.5.1975 और 8.5.1975 पर आपत्ति उठाते हुए

भंडारण लेकिन अंततः उन नोटों को वापस ले लिया और भंडारण के विषय पर कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहते थे जो महाराष्ट्र राज्य के रुख को मजबूत करता है कि कृष्णा बेसिन के भीतर पानी के भंडारण के संबंध में किसी भी राज्य पर तब तक कोई प्रतिबंध नहीं है जब तक कि यह राज्य द्वारा दिए गए एनब्लॉक आवंटन से अधिक न हो। न्यायाधिकरण। इस प्रतिवादी के अनुसार वाद में मांगी गई राहत न्यायाधिकरण के निर्णय के पूर्ण पुनर्लेखन के समान होगी जो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के दायरे से बाहर होगी। लिखित बयान के पैराग्राफ 16 में शिकायत में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लिए गए रुख का खंडन करने के बाद महाराष्ट्र राज्य ने प्रस्तुत किया, "कि वादी के लिए प्रार्थना की गई किसी भी प्रार्थना को स्वीकार करने के योग्य नहीं है।

अतिरिक्त लिखित बयान में कहा गया है कि अलमट्टी में बांध की ऊंचाई बढ़ाने से निजी और सार्वजनिक संपत्तियों और पुरातात्विक संरचनाओं सहित कार्यों और संरचनाओं को भारी नुकसान होने की संभावना है। महाराष्ट्र राज्य में तीर्थ स्थल। हर साल बाढ़ के दौरान संचार में व्यवधान, बढ़े हुए संकट और नुकसान भी होगा

अवसादन के कारण। यह आगे बताया गया है कि इसका विवरण

जलमग्नता का परिमाण, अवधि और विस्तार महाराष्ट्र राज्य के लिए स्पष्ट नहीं था क्योंकि उक्त जलमग्नता पर स्वयं न्यायाधिकरण द्वारा चर्चा नहीं की गई है, लेकिन कर्नाटक राज्य से बाढ़ के दस्तावेज प्राप्त करने और 524.256 m पर प्रस्तावित अलमट्टी बांध के प्रभाव का पता लगाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में बड़े पैमाने पर क्षेत्र जलमग्न होगा और किसी भी राज्य को अपनी परियोजना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसका दूसरे राज्य पर हानिकारक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में अतिरिक्त लिखित बयान में यह भी कहा गया है कि उक्त कर्नाटक राज्य ने विभिन्न पर्यावरण प्राधिकरणों और वन प्राधिकरणों से प्रासंगिक मंजूरी प्राप्त नहीं की है और यहां तक कि केंद्रीय जल आयोग ने भी मंजूरी नहीं दी है और इसलिए, कर्नाटक राज्य को बांध की ऊंचाई 519.00 m से बढ़ाने से रोक दिया जाना चाहिए। 524.256 m तक। जब तक कि जलमग्न होने की संभावना वाले वास्तविक क्षेत्र का उचित सर्वेक्षण के बाद पता नहीं चल जाता। लिखित कथन में जलमग्नता के प्रतिकूल प्रभाव का संकेत विभिन्न अनुच्छेदों में दिया गया है और अंततः यह प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना एच, आई और कर्नाटक राज्य और ओआरएस।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे।]

जहाँ तक यह यू. के. पी. के तहत अलमट्टी बांध से संबंधित है, वादी द्वारा जे. की मांग की गई

अनुमति दी जानी चाहिए, अर्थात्, कर्नाटक राज्य पर रोक लगाई जानी चाहिए। यद्यपि महाराष्ट्र राज्य ने पूर्व में लिए गए रुख के बिल्कुल विपरीत रुख लेते हुए उपरोक्त अतिरिक्त लिखित राज्य आदेश दायर किया, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया।

उसी पर पारित किया गया था और यह केवल तभी है जब इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई अदालत ने एक आदेश पारित किया कि राज्य के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

कर्नाटक के उक्त अतिरिक्त लिखित कथन पर विचार किया जाना चाहिए।

जिसके आधार पर एक अतिरिक्त मुद्दा भी तैयार करने की आवश्यकता है।

पक्षकारों की दलीलों पर 22 मुद्दे तैयार किए गए जो हैं -

यहाँ नीचे निकाला गया है:

1. क्या कर्नाटक राज्य ने बाध्यकारी निर्णयों का उल्लंघन किया है

दिनांकित 24.12.1973 और 27.05.1976 निष्पादन द्वारा KWDT द्वारा प्रस्तुत किया गया

अभियोग के पैरा 66,68 एन और 69 में उल्लिखित परियोजनाओं का उल्लेख करना? (ए. पी /

केएआर)

2. क्या यह माननीय न्यायालय इस मुकदमे पर विचार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है?

(एमएएच.)

3. क्या वादी यह साबित करता है कि कृष्णा जल का आवंटन के. डब्ल्यू. डी. टी. अपने अंतिम आदेश में परियोजनाओं के लिए विशिष्ट है न कि एनब्लॉक के लिए।

अन्य राज्यों के संदर्भ और सहमति के बिना परियोजना का निर्माण?
(एमएएच.)

5. क्या वादी इस घोषणा का हकदार है कि सभी परियोजनाएं राज्य द्वारा निष्पादित और/या जो निष्पादन की प्रक्रिया में हैं

कर्नाटक का, और इसके अनुरूप या इसके साथ संघर्ष में नहीं

के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णय अवैध और अनधिकृत हैं? (ए. पी)

इनमें से किसी द्वारा प्रस्तावित/शुरू की गई किसी भी योजना, परियोजना को मंजूरी अंतर-राज्यीय नदी कृष्णा पर तटवर्ती राज्य? (ए. पी)

7. क्या दूसरे द्वारा दिए गए प्रतिबंध और अनुमोदन [2000] 3 एस. सी. आर. में निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए कर्नाटक राज्य का प्रतिवादी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुद्दा I, आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्व सहमति के बिना वादी के लिए वैध और बाध्यकारी है? (ए. पी) 8. क्या दूसरे प्रतिवादी द्वारा दिए गए प्रतिबंधों और अनुमोदनों की समीक्षा की जा सकती है, अन्य नदी तटीय राज्यों के विचार प्राप्त करने के बाद नए सिरे से पुनर्विचार किया जा सकता है? (एपी)।

(क) क्या एफ. आर. एल. के साथ अलमट्टी बांध का निर्माण।

9 .

निष्पादित अन्य सभी परियोजनाओं के साथ 524.256 m का

कर्नाटक द्वारा विचार की गई प्रगति इसे सक्षम बनाएगी।

न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित पानी से अधिक पानी का उपयोग करना? (ए. पी)

(ख) क्या कर्नाटक को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है।

दूसरों की सहमति के बिना इस तरह के बांध का निर्माण

नदी तटीय राज्य, और केंद्र की मंजूरी के बिना

सरकार? (ए. पी)

10. क्या वादी यह साबित करता है कि शिकायत के पैराग्राफ 68 में कथित जलाशय और सिंचाई नहरें बड़ी हैं। यदि ऐसा है, तो क्या वे न्यायाधिकरण के निर्णय के विपरीत हैं? (ए. पी)

11. क्या आंध्र प्रदेश का वादी राज्य यू. के. पी. और नहरों के लिए विशिष्ट आवंटन/उपयोग को साबित करता है जैसा कि आरोप लगाया गया है? (ए. पी)

12. क्या कर्नाटक राज्य किसी भी सिंचाई के लिए प्रावधान करने का हकदार है

अलमट्टी नहरों और अन्य नई परियोजनाओं के तहत, जब के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णयों के तहत कोई आवंटन नहीं किया जाता है? (ए. पी)

13. क्या कर्नाटक का प्रतिवादी राज्य एकतरफा रूप से हकदार है

यू. के. पी. या किसी अन्य परियोजना के तहत आवंटन/उपयोग को फिर से आवंटित/पुनः समायोजित करना? क्या अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति आवश्यक है? (ए. पी)

14. क्या भारत संघ अनुमति दे सकता है और/या इसमें उचित है

कर्नाटक राज्य को विभिन्न परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देना जो के. डब्ल्यू. डी. टी. द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लंघन है? (ए. पी)

15. क्या ऊपरी कृष्णा चरण-II बहुउद्देशीय परियोजना हो सकती है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण मंजूरी और कर्नाटक और ओ. आर. एस. के केंद्रीय राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के बिना निष्पादित।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 367

सरकार ने 1994 में उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनिवार्य रूप से विभिन्न विश्लेषणों की आवश्यकता होती है

एस. आई. एस. जिसमें बांध टूटना विश्लेषण शामिल है? (ए. पी.) 16. क्या कर्नाटक राज्य के अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, और यदि ऐसा है, तो

इसके क्या परिणाम होते हैं? (केएआर)

17. क्या हिप्परगी हमेशा यू. के. पी. का हिस्सा था और उस आधार पर

के. डब्ल्यू. डी. टी. ने इसके तहत 5 टी. एम. सी. उपयोग प्रदान किया? (ए. पी)

18. क्या चिक्कापाड़ा सलागी, हेगगुर के तहत पानी का उपयोग

और 5 अन्य बैराज 33 टी. एम. सी. नहीं हैं जैसा कि वादी राज्य द्वारा मूल्यांकन किया गया है?

(ए. पी)

19. क्या के2 उप-बेसिन में संचयी उपयोग 173 टी. एम. सी. है जैसा कि कर्नाटक राज्य द्वारा दावा किया गया है या 428.75 टी. एम. सी. जैसा कि आकलन किया गया है

वादी राज्य द्वारा? (ए. पी)

20. क्या कर्नाटक राज्य ने उप-बेसिन जैसे के-6, के-8 और के-9 में कई नई परियोजनाओं के साथ आगे बढ़कर के. डब्ल्यू. डी. टी. निर्णय का उल्लंघन किया है, जिनके संबंध में न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय में उपयोग की मात्रा में प्रतिबंध लगाए गए हैं? (ए. पी)

21. क्या अलमट्टी के तहत उपयोग 91 के क्रम का होगा

टी. एम. सी. जैसा कि शिकायत के पैरा 66 (iii) में दावा किया गया है? (ए. पी)

22. यदि कोई राहत है तो वादी किस राहत का हकदार है? (ए. पी)

प्रतिवादी नं. 9 (सी) की ओर से दायर अतिरिक्त लिखित बयान के कारण अतिरिक्त मुद्दा बनाया गया। 3 प्रभाव यह है कि "क्या कर्नाटक को अलमट्टी बांध के जलमग्न होने की संभावना को देखते हुए आरएल 509.16 मीटर से ऊपर भंडारण स्तर बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। महाराष्ट्र में क्षेत्र "।

इसलिए हम न्यायालय द्वारा बनाए गए विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं और उठाए गए तर्कों के साथ-साथ उनके समर्थन में दायर किए गए तर्कों के संदर्भ में जवाब देते हैं, इसलिए हमारे लिए नोटिस देना उचित होगा।

इस न्यायालय की तारीख 30 सितंबर, 1997 और [2000] 3 एस. सी. आर. पर इसका प्रभाव।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमे का ही अंतिम निर्णय।

30 सितंबर, 1997 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" एस. एफ. एस. नरीमन, कर्नाटक राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रतिवादी नं. 1 और एस. विद्वान सॉलिसिटर जनरल टी. आर. अंध्यार्जुन
महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित-प्रतिवादी संख्या 3 को संदर्भित किया गया

ये राज्य अर्थात् कर्नाटक और महाराष्ट्र इस दावे को स्वीकार करते हैं -
आंध्र प्रदेश राज्य की शिकायत और अनुदान के लिए सहमत

खंड (क) में प्रार्थना के संदर्भ में वाद में राहत निम्नानुसार है:

" (क) घोषणा करें कि रिपोर्ट/निर्णय दिनांकित 24.12.1973 और आगे

कृष्णा जल विवाद जनजाति की रिपोर्ट/निर्णय दिनांक 27.5.1976

नाल (के. डब्ल्यू. डी. टी.) अपनी संपूर्णता में तीन नदी तटों पर बाध्यकारी हैं।
महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य और

भारत संघ।

दूसरे शब्दों में, के बीच सूट में कोई विवाद नहीं है

वादी और प्रतिवादी 1 और 3 अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और

महाराष्ट्र और रिपोर्ट/निर्णय दिनांक 24.12.1973 और

कृष्णा जल विवादों की अगली रिपोर्ट/निर्णय दिनांक 27.5.1976

महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य। इस प्रकार है
तीन नदी तटीय राज्यों के बीच इस हद तक कोई विवाद नहीं है। द.

कि वह आज इस संबंध में कोई बयान देने में असमर्थ है क्योंकि उसने
मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए। विद्वान द्वारा दिया गया यह कथन

तीन नदी तटीय राज्यों के वकील को संकेत देने के लिए रिकॉर्ड में रखा गया है
कि इस सीमा तक एक आंशिक डिक्री के प्रवेश के आधार पर

प्रतिवादियों (1 और 3, कर्नाटक और महाराष्ट्र) को पारित किया जा सकता है और

इसलिए, इस पहलू को शामिल करने के लिए किसी भी मुद्दे को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है सूट "।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान कर्नाटक राज्य की ओर से श्री नरीमन ने तर्क दिया कि उपरोक्त आंशिक आदेश के संदर्भ में

1

1997 के ओएस नंबर 2 की प्रार्थना 'ए' स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि पूरी रिपोर्ट यानी 24.12.1973 और पूरी तरह से 27.5.1976 की अगली रिपोर्ट को तीन नदी तटीय राज्यों पर बाध्यकारी माना जाना चाहिए, और यह कि स्थिति होने के कारण, कर्नाटक और ओआरएस का राज्य है।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 369

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से 1997 के ओएस नंबर 1 में वादी नंबर 1 की उस प्रार्थना का विरोध करने का कोई तर्क नहीं है जिसमें योजना 'बी' को पक्षकारों के लिए बाध्यकारी बनाया गया हो जो योजना स्पष्ट रूप से रिपोर्ट और आगे की रिपोर्ट का एक हिस्सा है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गंगुली ने तर्क दिया कि वादी द्वारा की गई प्रार्थना को वाद में किए गए कथनों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए न कि उससे रहित। श्री गंगुली की याचिका 'अ' के अनुसार, यदि वाद में किए गए कथनों के आलोक में पढ़ा जाए, तो इसका मतलब केवल यह होगा कि वादी ने वाद में कहा है कि न्यायाधिकरण ने परियोजनावार आवंटन किया था जिसे अंतिम निर्णय में पढ़ा जाना चाहिए।

न्यायाधिकरण, जिसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और इसलिए, कर्नाटक राज्य अलमट्टी में बांध की ऊंचाई को 524.256 मीटर तक बढ़ाने का हकदार नहीं है, जिससे वह लगभग 400 टी. एम. सी. की उपयोग क्षमता के साथ 200 टी. एम. सी. से अधिक पानी का भंडारण करने में सक्षम होगा। यह इस संदर्भ में है कि श्री गंगुली ने लिखित बयान के अनुच्छेद 3.1, 3 और 3.3 को हमारे सामने रखा है ताकि हमें यह संकेत दिया जा सके कि कथित प्रतिवादी कैसे

शिकायत में प्रार्थना 'ए' को समझा। श्री गांगुली ने अंततः आग्रह किया कि न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश को दीवानी मुकदमे में एक डिक्री के साथ जोड़ा जा सकता है और डिक्री निर्णय के अनुरूप होनी चाहिए और इसलिए, उक्त सादृश्य को लागू करते हुए अंतिम आदेश को न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम रिपोर्ट में किए गए निर्णय के आलोक में पढ़ने की आवश्यकता है। विद्वान वकील ने उपरोक्त दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा:

(i) कालीकृष्ण टैगोर बनाम। राज्य सचिव, एलआर 15

भारतीय अपील 186 192.3 पर

(ii) 107-08 पर 25 भारतीय अपीलों की विधि रिपोर्ट करें।

(iii) 1913 खंड। 25 मद्रास लॉ जर्नल 24.

शुरुआत में हम श्री गांगुली के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि न्यायाधिकरण के निर्णय को, जिसे अंततः अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचित किया जाता है, एक मुकदमे की डिक्री माना जा सकता है और रिपोर्ट निर्णय है और,

इसलिए, जिन निर्णयित मामले कानूनों पर निर्भरता रखी गई है, उनका कोई अनुप्रयोग नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद द्वारा बनाया गया अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण अधिनियम है और इसके तहत किए गए निर्णय की प्रकृति और चरित्र को अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में ही समझना होगा। दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न हुआ विवाद या मतभेद अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत जल विवाद और उस प्रभाव की शिकायत [2000] 3 एस. सी. आर.

370

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को केंद्र सरकार ने जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया है।

विचाराधीन विवाद, एक बार जब यह राय बन जाती है कि विवाद को बातचीत से हल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार गठित न्यायाधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे भेजे गए मामलों की जांच करे और फिर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजे जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्यों

को प्रस्तुत किया जाए और अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत उस पर अपना निर्णय दिया जाए। न्यायाधिकरण के ऐसे निर्णय पर विचार करने पर यदि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की राय है कि विचाराधीन निर्णय के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या किसी ऐसे बिंदु पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो मूल रूप से न्यायाधिकरण को संदर्भित नहीं किया गया है, तो निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर, आगे के विचार के लिए न्यायाधिकरण को निर्देश दिया जा सकता है और फिर उक्त न्यायाधिकरण को आगे भेजा जा सकता है -

निर्णय को अधिसूचित करने की भी आवश्यकता होती है ताकि इसे पक्षों के लिए बाध्यकारी बनाया जा सके। यह स्थिति होने के कारण, श्री गंगुली के इस तर्क की सराहना करना मुश्किल है कि न्यायाधिकरण का निर्णय, जैसा कि अधिसूचित किया गया है, वास्तव में एक दीवानी मुकदमे की डिक्री है और उस डिक्री को मुकदमे के फैसले के आलोक में समझा जाना चाहिए। तदनुसार हम श्री के निवेदन को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं। इस मुद्दे पर गंगुली, लेकिन साथ ही हम श्री नरीमन के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि याचिका 'ए' के संदर्भ में मुकदमे में पारित इस न्यायालय के 30 सितंबर, 1997 के आदेश का अर्थ यह होना चाहिए कि 1997 के ओएस 2 में एक डिक्री तैयार की जानी है, जिसमें पूरी रिपोर्ट और आगे की रिपोर्ट पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है। जब वाद में प्रार्थना की जाती है तो उक्त प्रार्थना को उन तथ्यों के दावे के आलोक में समझना चाहिए जिन पर प्रार्थना की गई है। कर्नाटक के प्रतिवादी राज्य ने उस आधार पर प्रार्थना को समझा जैसा कि प्रतिवादी नं. 1 पैराग्राफ 3.1, 3.2 और 3.3 में। उपरोक्त प्रार्थना इस राहत के लिए की गई थी कि अंतिम में किए गए एनब्लॉक आवंटन के बावजूद

न्यायाधिकरण का आदेश जो न्यायाधिकरण का निर्णय है लेकिन कर्नाटक और ओ. आर. एस. का आधार है।

» . ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 371

उस निर्णय पर पहुंचने के लिए कि रिपोर्ट में निहित परियोजनावार आवंटन होने के कारण उक्त परियोजनावार आवंटन को एनब्लॉक आवंटन में पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए, कर्नाटक राज्य की ओर से ऊपरी कृष्णा परियोजना में आवंटित मात्रा से अधिक पानी का उपयोग नहीं करने पर प्रतिबंध होना चाहिए।

160 टीएमसी। इस प्रकार 30 सितंबर, 1997 के इस न्यायालय के आदेश का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि एक डिक्री पारित की जानी चाहिए जो पूरी रिपोर्ट के साथ-साथ न्यायाधिकरण की आगे की रिपोर्ट को पक्षों पर बाध्यकारी बनाती है। तो।

जहाँ तक इस सवाल का सवाल है कि क्या आवंटन एनब्लॉक किया गया है या परियोजना के हिसाब से किया गया है, इसका जवाब मुद्दे संख्या पर चर्चा करते समय दिया गया है। 1, 3 और 5 और मामले के इस दृष्टिकोण में 30 सितंबर, 1997 के पूर्व आदेश का विचाराधीन वाद के निपटारे में कोई प्रभाव नहीं है।

आई. एस. यू. ई. नंबर। 1, 3 और 5:

हालाँकि, ऐसे 22 मुद्दे हैं, जिन्हें तैयार किया गया है और जिनका जवाब मुकदमे में दिया जाना आवश्यक है, लेकिन तर्कों के क्रम में आगे बढ़ें

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गंगुली ने कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तावित और विभिन्न परियोजना रिपोर्टों से पता चलता है कि अल्मट्टी बांध चरण-II की ऊँचाई 524.256 मीटर पर पूरी तरह से जोर दिया। पक्षों के वकील द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, ये तीन मुद्दे अनिवार्य रूप से विवाद का मूल हैं। यह कहना आवश्यक है कि तीन अलग-अलग राज्यों द्वारा बहुत सारे मुद्दे तैयार किए गए हैं और न्यायालय ने भी ऐसे मुद्दों को उठाने की अनुमति दी है और अधिकांश मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और वास्तव में वादी द्वारा की गई प्रार्थना के संबंध में कोई संबंध नहीं है। लेकिन मुद्दों को फिर से तैयार करने के बजाय, पक्षकारों के वकील द्वारा तर्क दिए जाने के बाद, हम उनमें से प्रत्येक से निपटेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष जोर देंगे। जहाँ तक हम इस समय जिन तीन मुद्दों से संबंधित हैं, जब शिकायत के पैराग्राफ के साथ पढ़ा जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वादी आंध्र प्रदेश ने शिकायत में एक मामला बनाया है कि योजना "ए" के तहत जो न्यायाधिकरण का निर्णय है और जिसे अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, हालाँकि जल का आवंटन किया गया है, लेकिन रिपोर्ट को देखने के बाद और उसी आधार पर जिसके आधार पर सामूहिक आवंटन की मात्रा निर्धारित की गई है, यह इंगित करेगा कि परियोजना-वार आवंटन को तथाकथित सामूहिक आवंटन में पढ़ा जाना चाहिए। यह स्थिति होने के कारण, ऊपरी कृष्णा परियोजना में, न्यायाधिकरण ने केवल 160 टी. एम. सी. पानी आवंटित किया है, अल्मट्टी बांध का निर्माण एक 524.256 मीटर की ऊँचाई स्वयं न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन है, और इसलिए, न्यायालय को कर्नाटक राज्य को [2000] 3 एस. सी. आर. से रोक देना चाहिए।

अलमट्टी में 524.256 मीटर की ऊँचाई तक एक बांध का निर्माण। दायर किए गए लिखित बयान में कर्नाटक राज्य का रुख और साथ ही केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य का अपने मूल लिखित बयान में यह रुख है कि न्यायाधिकरण द्वारा एक एनब्लॉक आवंटन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप, किसी भी राज्य पर अपनी किसी भी परियोजना में सीमित मात्रा तक पानी का उपयोग करने के लिए कोई बाधा नहीं आई है, सिवाय उन लोगों के जो स्वयं न्यायाधिकरण के आदेश में उल्लिखित हैं और यह स्थिति होने के कारण, वादी 524.256 मीटर की ऊँचाई तक अलमट्टी बांध के निर्माण के संबंध में निषेधाज्ञा के आदेश का हकदार नहीं होगा। इससे पहले कि हम इन तीन मुद्दों का जवाब देने में अभिलेख पर साक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें, पक्षकारों के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निषेधाज्ञा एक विवेकाधीन उपाय होने के नाते, एक न्यायालय निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दे सकता है, भले ही तीनों आवश्यक तत्व स्थापित हो जाएं और वे तत्व कानूनी अधिकारों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला हों, इस तरह के उल्लंघन से वादी को अपूरणीय नुकसान और चोट होती है और चोट ऐसी प्रकृति की होती है कि इसकी भरपाई नुकसान के रूप में नहीं की जा सकती है। हाथ में मामले में, जब वादी है

कर्नाटक राज्य को अलमट्टी में 524.256 मीटर की ऊँचाई तक बांध के निर्माण पर रोक लगाने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश के लिए प्रार्थना की और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय से प्रवाहित आंध्र प्रदेश राज्य के कानूनी अधिकारों के उल्लंघन का मामला बनाया, जो निर्णय अंतिम हो गया है और संघ द्वारा अधिसूचित किए जाने पर बाध्यकारी हो गया है। धारा 6 के तहत सरकार को जो स्थापित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि वास्तव में न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय में ऊपरी कृष्णा परियोजना के संबंध में एक परियोजना-वार आवंटन किया गया है और यदि यह स्थापित किया जाता है, तो आगे यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि क्या 524.256 मीटर की ऊँचाई तक अलमट्टी बांध के निर्माण से न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय का कोई उल्लंघन हुआ है जिससे निचले नदी तटीय राज्य आंध्र प्रदेश को अपूरणीय क्षति और क्षति हुई है और उक्त क्षति की भरपाई नुकसान के रूप में नहीं की जा सकती है। चूंकि वादी-राज्य को उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को स्थापित करना होता है, ताकि निषेधाज्ञा का आदेश, जैसा कि अनुरोध किया गया है, दिया जा सके, आइए हम पहले घटक की जांच करें कि क्या इसके निर्णय के तहत

न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश श्री गंगुली द्वारा तर्क दिए जाने के अनुसार एक परियोजना-वार आवंटन किया गया है या आवंटन किया गया था एनब्लॉक, जैसा कि श्री नरीमन ने तर्क दिया, कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए और महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री साल्वे और श्री अंधारुजिना ने दोहराया। कर्नाटक राज्य द्वारा दायर 1997 के मूल वाद संख्या 1 का निर्णय लेते समय, उक्त राज्य के इस तर्क को नकारते हुए

कि न्यायाधिकरण द्वारा योजना "बी" विकसित की गई है, चाहे वह कर्नाटक और ओ. आर. एस. का राज्य हो।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 373

न्यायाधिकरण का निर्णय हो या न हो, हमने पहले ही यह निष्कर्ष दर्ज कर लिया है कि योजना "बी" को न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह केवल न्यायाधिकरण का वह आदेश है जो निर्णायक रूप से विवाद का फैसला करता है।

निर्दिष्ट, और अपने दम पर लागू करने में सक्षम है, अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत न्यायाधिकरण का निर्णय माना जा सकता है। वास्तव में वर्तमान वाद में वादी भी अपने मामले को योजना "ए" पर आधारित करता है और तर्क देता है कि

प्रतिवादी द्वारा उक्त योजना "ए" का उल्लंघन किया गया है-राज्य

कर्नाटक से। यदि हम मूल रिपोर्ट के अध्याय XVI में निहित न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश की जांच करते हैं, तो विभिन्न राज्यों द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किए गए आवेदन का जवाब देने के बाद संशोधित आदेश को दिसंबर, 1976 की अगली रिपोर्ट में EXH के अध्याय VII में प्रदर्शित करें। पीके2, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचित किया गया है

31 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि किया गया आवंटन परियोजना के हिसाब से नहीं, बल्कि निगमित है और इसलिए किसी भी राज्य में किसी भी परियोजना में सीमित सीमा तक पानी का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है। निर्णय के खंड (IX) में निहित लोगों को छोड़कर। किया गया आवंटन

तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को उनके लाभकारी उपयोग के लिए खंड (V) में प्रावधान किया गया है और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है जो बाद के खंडों में उल्लिखित हैं। निर्णय का खंड (वी) जो वास्तव में आवंटन करता है, नीचे उद्धृत किया जा सकता है।

विस्तार से:

" खंड 5 (ए) महाराष्ट्र राज्य किसी भी जल का उपयोग नहीं करेगा।

वर्ष कृष्णा नदी के पानी की निर्दिष्ट मात्रा से अधिक

इसके नीचे: - (i) 1 जून को शुरू होने वाले जल वर्ष से
न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख के बाद
जल वर्ष 1982-83 तक आधिकारिक राजपत्र में

560 टीएमसी।

((ii) जल वर्ष 1983-84 से जल वर्ष 1989-90 तक

560 टी. एम. सी प्लस

पानी की मात्रा अतिरिक्त पानी के 10 प्रतिशत के बराबर है।
कृष्णा नदी में सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग का औसत

जल वर्षों के दौरान बेसिन 1975-76, 1976-77 और 1977-78

उपयोग पर सालाना 3 टी. एम. सी. या उससे अधिक का उपयोग करने वाली
अपनी परियोजनाएं

ऐसी परियोजनाओं से जल वर्ष 1968-69 में ऐसी सिंचाई।

(iii) जल वर्ष 1990-91 से जल वर्ष 1997-98 तक

560 टी. एम.

सी प्लस [2000] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसी परियोजनाओं से जल वर्ष में ऐसी सिंचाई के लिए उपयोग पर 3 टी. एम. सी. या उससे
अधिक वार्षिक उपयोग करने वाली अपनी परियोजनाओं से जल वर्षों के दौरान कृष्णा नदी बेसिन
में सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग के औसत के 10 प्रतिशत के बराबर पानी की मात्रा।

(iv) जल वर्ष 1998-99 के बाद से

560 टी. एम.

सी प्लस

ऐसी परियोजनाओं से जल वर्ष में ऐसी सिंचाई के लिए उपयोग पर 3 टी. एम. सी. या उससे अधिक वार्षिक उपयोग करने वाली अपनी परियोजनाओं से कृष्णा नदी बेसिन में सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग के औसत के 10 प्रतिशत के बराबर पानी की मात्रा। (ख) कर्नाटक राज्य किसी भी जल वर्ष में नीचे निर्दिष्ट कृष्णा नदी के पानी की मात्रा से अधिक का उपयोग नहीं करेगा:

(i) आधिकारिक रूप से न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख के बाद 1 जून को शुरू होने वाले जल वर्ष से

जल वर्ष तक राजपत्र 1982-83

700 टी. एम.

सी प्लस

(ii) जल वर्ष 1983-84 से जल वर्ष 1989-90 तक

700 टी. एम.

सी प्लस

ऐसी परियोजनाओं से जल वर्ष में ऐसी सिंचाई के लिए उपयोग पर 3 टी. एम. सी. या उससे अधिक वार्षिक उपयोग करने वाली अपनी परियोजनाओं से कृष्णा नदी बेसिन में सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग के औसत के 10 प्रतिशत के बराबर पानी की मात्रा।

(iii) जल वर्ष 1990-91 से जल वर्ष 1997-98 तक

700 टी. एम.

सी प्लस

ऐसी परियोजनाओं से जल वर्ष में ऐसी सिंचाई के लिए उपयोग पर 3 टी. एम. सी. या उससे अधिक वार्षिक उपयोग करने वाली अपनी परियोजनाओं से जल वर्षों के दौरान कृष्णा नदी बेसिन में सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग के औसत के 10 प्रतिशत के बराबर पानी की मात्रा।

कर्नाटक और ओआरएस की तिथि। वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 375

(iv) जल वर्ष 1998-99 के बाद से 700 टी. एम. सी. और एक मात्रा

औसत से 10 प्रतिशत अधिक पानी के बराबर

कृष्णा नदी बेसिन में सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग अपनी परियोजनाओं से जल वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93

ऐसी सिंचाई के लिए सालाना 3 टी. एम. सी. या उससे अधिक का उपयोग करना।

ऐसी परियोजनाओं से जल वर्ष 1968-69 में।

((c) आंध्र प्रदेश राज्य किसी भी जल में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

वर्ष शेष जल जो कृष्णा नदी में बह रहा हो लेकिन

इस प्रकार यह किसी भी जल में उपयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करेगा। वर्ष और न ही किसी भी जल वर्ष में पानी आवंटित किया गया माना जाएगा

((i) अगले 1 जून को शुरू होने वाले जल वर्ष के रूप में आधिकारिक में न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख

जल वर्ष 1982-83 तक राजपत्र।

800

टीएमसी

((ii) जल वर्ष 1983-84 से जल वर्ष 1989-90 तक।

800 टी.

एम. सी प्लस

पानी की मात्रा अतिरिक्त पानी के 10 प्रतिशत के बराबर है।

कृष्णा नदी में सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग का औसत

जल वर्षों के दौरान बेसिन 1990-91, 1991-92 और 1992-93

ऐसी परियोजनाओं से जल वर्ष 1968-69 में ऐसी सिंचाई। ((iii) जल वर्ष 1990-91 से जल वर्ष 1997-98 तक

800 टी. एम.

सी प्लस

जल वर्षों के दौरान बेसिन 1982-83, 1983-84 और 1984-85 उपयोग पर सालाना 3 टी. एम. सी. या उससे अधिक का उपयोग करने वाली अपनी परियोजनाएं

ऐसी परियोजनाओं से जल वर्ष 1968-69 में ऐसी सिंचाई।

(iv) जल वर्ष 1998-99 के बाद से

800 टी.

एम. सी प्लस

पानी की मात्रा अतिरिक्त पानी के 10 प्रतिशत के बराबर है।
के लिए वार्षिक उपयोग का औसत [2000] 3 एस. सी. आर.

कृष्णा नदी में सिंचाई

376

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जल वर्षों के दौरान बेसिन 1990-91, 1991-92 और 1992-93

((घ) इस खंड के सीमित उद्देश्य के लिए, यह घोषित किया जाता है कि:

(i) पानी में कृष्णा नदी बेसिन में सिंचाई के लिए उपयोग

वार्षिक रूप से 3 टी. एम. सी. या उससे अधिक का उपयोग करने वाली
परियोजनाओं से वर्ष <आई. डी. 1.

निम्नलिखित है:

महाराष्ट्र राज्य की परियोजनाओं से

61.45 टीएमसी

कर्नाटक राज्य की परियोजनाओं से

176.05 टीएमसी

आंध्र प्रदेश राज्य की परियोजनाओं से

170.00 टीएमसी

इस आदेश के बाद के जल वर्ष की परियोजना से संचालन में आता है
वार्षिक रूप से 3 टी. एम. सी. या उससे अधिक का उपयोग करने वाले किसी भी राज्य की गणना

उस राज्य द्वारा तैयार और बनाए गए अभिलेखों का आधार

खंड XIII।

(iii) 3 टी. एम. सी. का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के जलाशयों से वाष्पीकरण नुकसान
या

10 प्रतिशत की गणना में वार्षिक रूप से अधिक को बाहर रखा जाएगा।

उपखंडों में उल्लिखित औसत वार्षिक उपयोग का आंकड़ा

इसके ए (ii), ए (iii), ए (iv), बी (ii), बी (iii), बी (iv), सी (ii), सी (iii) और
सी (iv)

खंड "।

उपरोक्त खंड V, निस्संदेह एक नकारात्मक रूप में है, जो निषेध करता है

महाराष्ट्र राज्य और कर्नाटक राज्य किसी भी जल वर्ष में उपयोग करने से

यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त खंड 5 में किसी भी राज्य को क्रमशः उनके पक्ष में आवंटित
किए गए पानी से अधिक, लेकिन किसी भी तरह की कल्पना के बिना, कोई प्रतिबंध लगाया गया
है, जब तक कि वे किसी भी जल वर्ष में अपने पक्ष में आवंटित मात्रा से अधिक का उपयोग नहीं
करते हैं। दूसरे शब्दों में निर्णय के खंड 5 के तहत, महाराष्ट्र राज्य किसी भी जल वर्ष में 560 टी.
एम. सी. तक का उपयोग करने का हकदार है और इसी तरह कर्नाटक राज्य किसी भी जल वर्ष में
700 टी. एम. सी. तक का उपयोग करने का हकदार है। न्यायाधिकरण द्वारा उपयोग की जाने
वाली भाषा

निर्णय के खंड 5 को तैयार करना स्पष्ट और स्पष्ट है और इस प्रकार न्यायालय के लिए आंध्र
प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी
प्रतिबंध को इसमें पढ़ना मुश्किल है।

हम कर्नाटक और ओ. आर. एस. के बारे में बता सकते हैं। वी. ए. पी. राज्य
[पटनायक, जे.] 377

इस स्तर पर उल्लेख करें कि मूल रिपोर्ट और 1973 के निर्णय को ओएस 1/97 में प्रदर्शनी पीके-1 के रूप में चिह्नित किया गया था और आगे की रिपोर्ट और 1976 के निर्णय को ओएस 1/97 में प्रदर्शनी पीके-2 के रूप में चिह्नित किया गया था, और उन दो दस्तावेजों को तर्कों के दौरान पक्षों द्वारा पीके-1 और पीके-2 के रूप में संदर्भित किया गया था। हमने निर्णय में पी. के.-1 और पी. के.-2 के रूप में भी संदर्भित किया है जिन्हें ओएस 1/97 में प्रदर्शित किया गया था।

पी. के. आई. को स्वयं प्रदर्शित करने और फिर न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के बाद के चरण में, सभी पक्षीय राज्य इस बात पर सहमत हुए कि कृष्णा नदी में विजयवाड़ा तक 75 प्रतिशत निर्भर प्रवाह 2060 टी. एम. सी. है, जो कि प्रत्येक राज्य द्वारा की गई कुल मांग से बहुत कम है, जो 4269.33 टी. एम. सी. है। विद्वान वकील ने आगे आग्रह किया कि तीनों राज्यों ने 7.5.1971 पर एक समझौता किया, जिसमें संकेत दिया गया कि महाराष्ट्र में 20 परियोजनाओं, कर्नाटक में 13 परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश में 17 परियोजनाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए और पक्षकार प्रत्येक परियोजना के संबंध में पानी के उपयोग की निर्दिष्ट मात्रा पर भी सहमत हुए, जिसे संरक्षित उपयोग के रूप में माना जा सकता है और इस तरह के संरक्षित उपयोग का कुल 751.20 TMC पर आया, जैसा कि मूल रिपोर्ट से स्पष्ट है। पी. के. आई. प्रदर्शित करें। यह आगे का तर्क है कि चूंकि महाराष्ट्र में एक परियोजना, कर्नाटक में पांच परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश में पांच परियोजनाओं के संबंध में, पक्षकार उपयोग की मात्रा पर सहमत नहीं हो सके, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए और सभी राज्यों ने न्यायाधिकरण को उन 11 परियोजनाओं के संबंध में उपयोग की सीमा तय करने के लिए आमंत्रित किया और न्यायाधिकरण ने 11 परियोजनाओं में से 9 के संबंध में अतिरिक्त उपयोग का निर्णय लिया और इस प्रकार कुल सुरक्षित उपयोग पर निर्भर प्रवाह से कुल 75 प्रतिशत निर्भरता पर काम किया, जिसमें निश्चित रूप से छोटी सिंचाई पर कुल सुरक्षित उपयोग शामिल है। इस प्रकार संरक्षित उपयोग के लिए 1693.36 टी. एम. सी. के आंकड़े पर पहुंचने के बाद, 366.64 टी. एम. सी. की सीमा तक भरोसेमंद प्रवाह से शेष मात्रा को न्यायाधिकरण द्वारा श्रीशैलम जलाशय और जुराला परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश को 50.84 टी. एम. सी. की सीमा तक वितरित किया गया। शेष 315.80 टी. एम. सी. में से,

सभी जर्मन कारकों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने महाराष्ट्र को 125.35 और कर्नाटक को 190.45 टी. एम. सी. आवंटित किया। श्री गंगुली का तर्क है कि जहां तक कर्नाटक राज्य में ऊपरी कृष्णा परियोजना का संबंध है, यह आवंटन करते समय न्यायाधिकरण ने संरक्षित 378 टी. एम. सी. के अलावा नारायणपुर की दाहिने किनारे की नहर में केवल 52 टी. एम. सी. के उपयोग की अनुमति दी।

[

2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नारायणपुर नहर के तहत लेफ्ट बैंक नहर के संबंध में पहले से ही 103 टी. एम. सी. का उपयोग और इसलिए, कुल 155 टी. एम. सी. पर काम किया गया और जहाँ तक अलमट्टी बांध का संबंध है, न्यायाधिकरण द्वारा कोई आवंटन नहीं किया गया था। बाद के चरण में जब अपनी आगे की रिपोर्ट प्रदर्शनी पीके2 में, न्यायाधिकरण ने हिप्परगी परियोजना के तहत उपयोग के लिए अतिरिक्त 5 टी. एम. सी. आवंटित किया,

निष्कर्ष यह अटूट है कि हिप्परगी, अलमट्टी और नारायणपुर में ऊपरी कृष्णा परियोजनाओं में कुल 160 टी. एम. सी. आवंटित किया गया था और इसे खंड (वी) में अंतिम आदेश में पढ़ा जाना चाहिए, हालांकि इसमें विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यह इस संबंध में है, श्री गांगुली ने हमें अलग-अलग माध्यमों से ले जाया

पी. के. आई. के पृष्ठों के साथ-साथ कर्नाटक राज्य की शिकायत और लिखित बयान को प्रदर्शित करें। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है, यदि न्यायाधिकरण का निर्णय उसका मूल आदेश है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है, तो हम वास्तव में यह समझने में विफल हैं कि उपरोक्त सीमाओं को उक्त निर्णय में कैसे पढ़ा जा सकता है, विशेष रूप से, जब निर्णय का खंड (V) स्पष्ट है और उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। यह निस्संदेह सच है कि 2060 में से तीन नदी तटीय राज्यों को 75 प्रतिशत निर्भरता पर पानी के आवंटन की सीमा के सवाल पर विचार करते हुए न्यायाधिकरण ने विभिन्न राज्यों द्वारा पहले से ही शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को ध्यान में रखा, लेकिन उन परियोजनाओं पर विचार केवल इस उद्देश्य के लिए किया गया है कि 2060 में से तीन नदी तटीय राज्यों को 75 प्रतिशत निर्भरता पर पानी का आवंटन किया जाए।

आवंटित किया जाए और किसी भी परियोजना-वार आवंटन के लिए नहीं, जैसा कि श्री गांगुली ने तर्क दिया है। स्वयं प्रदर्शनी पी. के. आई. में, न्यायाधिकरण निम्नलिखित प्रभाव को दर्ज करता है:

" परियोजना रिपोर्टों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की हमारी जांच

इसका एक बहुत ही सीमित उद्देश्य है और यह निर्धारित करना है कि क्या हैं दोनों राज्यों की उचित आवश्यकताएँ ताकि एक न्यायसंगत तरीका हो सके

दोनों राज्यों के बीच शेष पानी के वितरण के लिए पता लगाया। यह निश्चित रूप से हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जल का आवंटन

हालांकि कुछ परियोजनाओं पर विचार के आधार पर पाया जा रहा है
 विचार करने योग्य इस कारण से प्रतिबंधित नहीं हैं और
 केवल उन परियोजनाओं तक ही सीमित। वास्तव में राज्य (और यह लागू होता है)
 सभी राज्यों को) सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने का अधिकार होगा।
 इस तरह से कि वे हमेशा प्रतिबंधों के लिए उचित विषय पाते हैं और
 जो शर्तें उन पर रखी गई हैं।

यह स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को इंगित करता है जिसके लिए परियोजनाएं

विभिन्न राज्यों की जांच की जा रही थी और यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यों को सिंचाई के
 लिए पानी का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए, जैसा कि वे कर्नाटक और ओ. आर. एस.
 के बारे में कहते हैं।

» . ए. पी. राज्य (पटनायक, जे.) 379

हमेशा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन, उचित पाएँ। इसलिए, जब तक उच्च
 कृष्णा परियोजना में कुल आवंटित हिस्से में से पानी की एक विशिष्ट मात्रा के उपयोग के लिए
 न्यायाधिकरण के निर्णय में कोई प्रतिबंध या शर्तों का पता नहीं लगाया जा सकता है, तब तक
 ऐसा उपयोगकर्ता बनाने के लिए कर्नाटक राज्य की ओर से कोई बाधा नहीं हो सकती है। फैसले में

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की रिपोर्ट में कृष्णा बेसिन में पानी के आवंटन के उद्देश्य से
 पीके-1 को प्रदर्शित किया गया है। तीनों राज्यों में से प्रत्येक की प्रत्येक परियोजना
 की जांच की और फिर अपने निष्कर्ष को दर्ज किया कि क्या परियोजना विचार के योग्य है।
 न्यायाधिकरण ने "विचार करने योग्य" अभिव्यक्ति का अर्थ यह कहते हुए व्यक्त किया कि
 अभिव्यक्ति का उपयोग इस अर्थ में किया जाता है कि इसका अर्थ संबंधित राज्य में किसी क्षेत्र
 की आवश्यकताओं से है। इस स्तर पर इस संबंध में न्यायाधिकरण के सटीक निष्कर्षों को उद्धृत
 करना उचित होगा:

" यह कहते हुए कि परियोजना विचार के योग्य है, हम यह कहना नहीं चाहते कि
 परियोजना, यदि संभव हो, तो अपनाई जानी चाहिए। इसी तरह जब हम कहते हैं कि परियोजना
 विचार के योग्य नहीं है तो हम यह नहीं कहते कि इसके लिए कभी भी पानी की अनुमति नहीं दी
 जानी चाहिए। यदि भविष्य में और अधिक पानी उपलब्ध हो जाता है तो यह संभव है कि और
 अधिक परियोजनाएं विचार करने योग्य मानक तक आ सकें। यह आकलन करते हुए कि क्या

परियोजना विचार करने योग्य है या नहीं, हमने क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं जैसे वर्षा आदि, जलग्रहण क्षेत्र, नियंत्रित क्षेत्र, परियोजना के आयकट, इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि क्या परियोजना कमी वाले क्षेत्र की सिंचाई के लिए है।

या नहीं और ऐसे अन्य तथ्य। दूसरे शब्दों में हम व्यावहारिक रूप से तय करते हैं कि महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों की क्या आवश्यकताएँ हैं।

राज्यों। यह उन परियोजनाओं से संबंधित हमारी टिप्पणियों को नहीं लिया जाना चाहिए जिन्हें हमने ध्यान में रखा है कि किसी भी मामले में स्वीकार किया जाना चाहिए। योजना आयोग या किसी अन्य द्वारा अंतिम और बाध्यकारी तरीका

प्राधिकार "।

उपरोक्त निष्कर्ष श्री गांगुली के तर्क को पूरी तरह से नकारता है।

ए. पी. राज्य के लिए, कि आवंटन परियोजना के अनुसार था जिसे 380 में पढ़ा जा सकता है

[

2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतिम आदेश। अंतिम आदेश के खंड IX ने तीनों राज्यों द्वारा कृष्णा बेसिन में पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कारण यह प्रतीत होता है कि मुख्य धारा पर केवल

भीमा नदी पर प्रतिबंध जबकि किनारे की धाराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

तुंगभद्रा और वेदावती उप-बेसिन के मामले में प्रतिबंध। उप-बेसिन के-3 के मामले में भी महाराष्ट्र राज्य पर घटप्रभा से किसी भी जल वर्ष में 7 टी. एम. सी. से अधिक का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है और इस तरह के प्रतिबंध का कारण मैसूर राज्य की आवश्यकताएँ हैं। उस उप-बेसिन में परियोजनाओं को नुकसान हो सकता है। इसी तरह आंध्र प्रदेश राज्य पर कोयना नदी के जलग्रहण क्षेत्र से 6 टी. एम. सी. से अधिक का उपयोग नहीं करने का प्रतिबंध लगा दिया गया है, विचार यह है कि उस नदी का पानी भीमा नदी की मुख्य धाराओं तक पहुंच जाएगा। इस तरह का प्रतिबंध लगाते समय भी न्यायाधिकरण ने ऊपरी सीमा को उस राज्य की कुल आवश्यकताओं से थोड़ा अधिक रखा है, जैसा कि की गई मांगों से

मूल्यांकन किया गया था, जिन्हें या तो संरक्षित किया गया था या जिन्हें विचार के योग्य माना गया था। तथ्य यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा कई उप-बेसिनों में प्रतिबंध लगाए गए हैं और उप-बेसिन के-2 तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जिसमें कर्नाटक राज्य की ऊपरी कृष्णा परियोजना को आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चलाया जा रहा है और इन तीन मुद्दों पर चर्चा की गई है, अर्थात्, कर्नाटक राज्य द्वारा ऊपरी कृष्णा परियोजना में पानी के उपयोगकर्ता की मात्रा के लिए किसी भी प्रतिबंध को पढ़ना संभव नहीं है और जब तक कुल उपयोगकर्ता सामूहिक आवंटन से अधिक नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन किया जा रहा है जो आंध्र प्रदेश राज्य के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है जिसे कोई अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करके प्रतिबंधित किया जा सकता है। रिपोर्ट की प्रति और प्रदर्शनी पी. के.-1 के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय को प्राप्त करने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य ने स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दायर किया, अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत स्पष्टीकरण संख्या 4 होने के नाते, महाराष्ट्र राज्य की कोयना परियोजना से टी. एम. सी. को कम करने का अनुरोध किया। 5 मार्च, 1976 को इस तरह का आवेदन दायर करने के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने इस आधार पर उक्त स्पष्टीकरण संख्या 4 पर जोर नहीं दिया कि आवंटन एनब्लॉक हैं जो स्पष्टीकरण संख्या के साथ संबंधित प्रदर्शनी पी. के.-2 से स्पष्ट है। 4 .

न्यायाधिकरण के समक्ष ही एक स्पष्ट बयान देने के बाद कि आवंटन अनिवार्य हैं, हम यह समझने में विफल हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य ने कैसे एक मामला बनाते हुए मुकदमा दायर किया है कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा कोई परियोजना-वार आवंटन किया गया है। न्यायाधिकरण के समक्ष विद्वत महाधिवक्ता के उपरोक्त बयान को न तो राज्य द्वारा दायर शिकायत में और न ही मुकदमे की सुनवाई के दौरान भी समझाया गया है, और हमारे विचार में, आंध्र प्रदेश राज्य भी पूरी तरह से समझ गया है कि योजना 'ए' के तहत किया गया आवंटन अंतर्निहित था। यह प्रदर्शनी पी. के.-2 से आगे दिखाई देता है कि कर्नाटक और ओ. आर. एस. का राज्य।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 381

आंध्र प्रदेश राज्य ने स्पष्टीकरण सं. 5 अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत यह अनुरोध किया गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के के-5 और के-6 उप-बेसिन में उपयोग की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अंततः 23 अगस्त, 1974 को, नामित महाधिवक्ता

क्योंकि उक्त राज्य ने स्पष्टीकरण के लिए दबाव नहीं डाला क्योंकि उसके पास अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर वह इसकी पुष्टि कर सके। तथ्य यह है कि राज्य ने अब तक के-2 उप-बेसिन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण आवेदन दायर नहीं किया था, हालांकि उसने उप-

बेसिन के-5 और के-6 के साथ-साथ क्वाना कृष्णा लिफ्ट सिंचाई योजना के मामले में भी ऐसा आवेदन दायर किया था।

जहाँ तक न्यायाधिकरण द्वारा किए गए आवंटन की कोई शिकायत नहीं थी और के-2 उप-बेसिन में उपयोगकर्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था जिसमें ऊपरी कृष्णा परियोजना शामिल है। हमारे विचार में यह मामले को पूरी तरह से पकड़ता है और यह निष्कर्ष अटूट है कि न्यायाधिकरण के निर्णय के तहत बड़े पैमाने पर आवंटन किया गया है और कोई परियोजना-वार आवंटन नहीं किया गया है जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य ने मुकदमे में तर्क दिया है। उपरोक्त परिसर में, हम वादी के खिलाफ और प्रतिवादियों के पक्ष में तीन मुद्दों का जवाब देते हैं और मानते हैं कि न्यायाधिकरण के निर्णय के तहत कृष्णा नदी में पानी का आवंटन निगमित था और निर्णय के खंड IX और X में उल्लिखित उन विशिष्ट परियोजनाओं को छोड़कर परियोजना-वार नहीं था।

इश्यू नं. 2

हालाँकि यह मुद्दा महाराष्ट्र राज्य के कहने पर उठाया गया है, लेकिन अतिरिक्त लिखित बयान में उक्त राज्य द्वारा लिए गए रुख और उस पर बनाए गए अतिरिक्त मुद्दों को देखते हुए, महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने न्यायशास्त्र के सवाल पर बहस नहीं की, और दूसरी ओर तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमे में इस न्यायालय की अधिकारिता को प्रतिबंधित या संकुचित नहीं किया जाना चाहिए और दूसरी ओर न्यायालय को सभी मामलों को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। उठाए गए विवाद के न्यायनिर्णयन में आवश्यक राहत। इसके अलावा कि जिस आधार पर वादी राज्य ने मुकदमा दायर किया और इसके लिए मांगी गई राहत को यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। इसलिए हम इस मुद्दे का जवाब वादी के पक्ष में देते हैं।

आईएसयूई एन. ओ. एस. 4 , 6 , 7 और 8

ये चार मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लिए गए सकारात्मक रुख को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

राज्य नदी जब एक राज्य की किसी भी परियोजना पर [2000] 3 एस. सी. आर. की सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

भारत या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकरण के बारे में दूसरे राज्य को भी जागरूक किया जाना चाहिए और उनकी सहमति भी ली जानी चाहिए। हालाँकि यह रुख वादी-आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लिया गया था, लेकिन तीनों प्रतिवादियों ने इसका खंडन किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विद्वान वकील श्री गंगुली ने हमारे सामने कोई ऐसी सामग्री या कोई कानून नहीं रखा है जो संबंधित प्राधिकारी को एक राज्य की परियोजना को मंजूरी देने से पहले सभी नदी तटीय राज्यों से परामर्श करने के लिए मजबूर करता हो। इस तरह के रुख के लिए किसी भी कानूनी आधार के अभाव में हम आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लिए गए इस रुख से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि केंद्र सरकार किसी भी नदी तटीय राज्य की किसी भी परियोजना को मंजूरी देते समय अन्य राज्यों की सहमति लेने के लिए कर्तव्यबद्ध थी। इसके अलावा, ये मुद्दे कर्नाटक राज्य की ऊपरी कृष्णा परियोजना और विशेष रूप से, अलमट्टी बांध के निर्माण के संदर्भ में अकादमिक हैं। न्यायाधिकरण के समक्ष कर्नाटक राज्य ने जुलाई 1970 की ऊपरी कृष्णा परियोजना की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष एम. वाई. पी. के.-3 के रूप में प्रदर्शित किया गया था और उक्त दस्तावेज़ को वर्तमान मुकदमे में प्रदर्शनी पी. ए. पी.-42 के रूप में चिह्नित किया गया है। द. जहाँ तक अलमट्टी बांध की ऊँचाई का संबंध है, उक्त परियोजना की मुख्य विशेषताओं को एफआरएल 524.256 मीटर और बांध के शीर्ष को 528.786 मीटर के रूप में दिखाया गया था। पूरी परियोजना स्वयं न्यायाधिकरण के समक्ष होने के कारण, हालाँकि न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से अपने द्वारा किए गए एनब्लॉक आवंटन को देखते हुए परियोजना पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझा, आंध्र प्रदेश राज्य की शिकायत है कि परियोजना का निर्माण गुप्त रूप से किया जा रहा था, जिसमें कोई सार नहीं है। इसलिए हम वादी के खिलाफ उपरोक्त मुद्दों का जवाब देते हैं।

इश्यू नं। 9 (ए) (बी)

यह मुद्दा वर्तमान मुकदमे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और राहत मांगी गई है

क्योंकि यह अनिवार्य रूप से इस मुद्दे पर आए निष्कर्षों पर निर्भर करता है। पूरा मामला इस मुद्दे का निर्णय इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या न्यायाधिकरण के फैसले में अलमट्टी में 524.256 मीटर तक बांध बनाने या उसमें किसी विशेष मात्रा में पानी के भंडारण पर कोई प्रतिबंध है। और यदि उत्तर नकारात्मक है तो बांध की ऊँचाई 524.256 तक बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य को प्रतिबंधित करने की प्रार्थना को अस्वीकार करना होगा। यदि न्यायाधिकरण के निर्णय की जांच उपरोक्त दृष्टिकोण से और हमारे दृष्टिकोण से की जाती है

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह वह अंतिम आदेश है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जो कि न्यायाधिकरण का निर्णय है, हमें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिसे कर्नाटक राज्य की एक विशेष ऊँचाई तक

बांध की ऊंचाई रखने की शक्ति पर निषेध या प्रतिबंध भी माना जा सके। मामले के इस दृष्टिकोण में वादी की कर्नाटक राज्य को बांध के निर्माण से रोकने की प्रार्थना

§ 1

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. » . ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 383

अलमट्टी में 524.256 मीटर तक की ऊंचाई नहीं दी जा सकती है। इस मुद्दे के दो उप-मुद्दे हैं- उप-मुद्दा 'ए' अलमट्टी बांध की ऊंचाई से संबंधित है और उप-मुद्दा 'बी' इस सवाल पर है कि क्या कर्नाटक राज्य को इसकी अनुमति दी जा सकती है।

अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति के बिना और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना निर्माण के साथ आगे बढ़ना? शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि हालांकि कर्नाटक राज्य ने अपनी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी

प्रदर्शनी पी. ए. पी.-42 के अनुसार अलमट्टी बांध के निर्माण के संबंध में लेकिन न तो न्यायाधिकरण ने इस पर विचार किया था और न ही उक्त बांध की ऊंचाई के सवाल पर कोई निर्णय लिया गया है। मूल रिपोर्ट और अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत किए गए निर्णय के बाद भी आंध्र प्रदेश राज्य ने भी कोई विवाद या स्पष्टीकरण नहीं दिया अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत अलमट्टी बांध के निर्माण या यहां तक कि ऐसे बांध की ऊंचाई पर आपत्ति जताने वाला आवेदन। अलमट्टी में बांध के निर्माण या इसकी ऊंचाई और बड़े पैमाने पर आवंटन के सवाल पर न्यायाधिकरण के निर्णय के अभाव में, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचित होने के बाद सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होने के कारण, अलमट्टी में बांध के निर्माण या इसकी ऊंचाई से संबंधित शिकायत जल विवाद का मामला होगा।

धारा 2 (सी) का अर्थ, जितना यह कृष्णा नदी के पानी के उपयोग से संबंधित मामला होगा और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत किसी मुकदमे में निर्णय का विषय नहीं हो सकता है। यदि आंध्र प्रदेश राज्य की शिकायत है कि अलमट्टी बांध के निर्माण से, जो कर्नाटक राज्य की एक कार्यकारी कार्रवाई है, आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, तो धारा 3 (ए) के तहत केंद्र सरकार को ऐसी शिकायत किए जाने पर भी मामले को निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। लेकिन, हम यह समझने में विफल हैं कि यह न्यायालय कैसे उपरोक्त पर विचार कर सकता है और उसी पर निर्णय ले सकता है, विशेष

रूप से जब न्यायाधिकरण ने उसी पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया है और न ही इसमें कोई निर्णय लिया है।

अलमट्टी में बांध के निर्माण या उसकी ऊँचाई के संबंध में। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्णा नदी में पानी के आवंटन को शामिल किए जाने के बावजूद कोई भी राज्य राज्य के भीतर पानी के उपयोग के लिए किसी भी परियोजना का निर्माण तब तक नहीं कर सकता जब तक कि ऐसी परियोजना को योजना आयोग, केंद्रीय जल आयोग और अन्य सभी सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, जिनकी विभिन्न विशिष्ट कानूनों के तहत अलग-अलग भूमिकाएँ हो सकती हैं। संघीय ढांचे के तहत, हमारी तरह, केंद्र सरकार के पास भारी शक्ति और अधिकार हैं और कोई भी राज्य अपने क्षेत्र के भीतर मामलों को अपने दम पर नहीं चला सकता है, विशेष रूप से जब ऐसी परियोजनाओं का अन्य राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से एक अंतर-राज्यीय नदी के संबंध में जहां प्रत्येक नदी तटीय राज्य और उसके निवासियों का अपना अधिकार है, जिससे नदी बहती है। शिकायत में किए गए कथनों से यह स्पष्ट है कि आंध्र प्रदेश राज्य [2000] 3 एस. सी. आर. के प्रस्ताव से व्यथित है।

384

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर्नाटक राज्य में बांध की ऊँचाई अलमट्टी एफआरएल 524.256 मीटर होगी। पैराग्राफ 51 में वाद में ही वादी ने समिति के अवलोकन को इस प्रभाव के लिए संदर्भित किया है:

" यू. के. पी. पर बांध की ऊँचाई तक 173 टी. एम. सी. के आवश्यक उपयोग के लिए

एफआरएल पर 519.6 एम पर्याप्त होगा।

उक्त पैराग्राफ में संदर्भित समिति विशेषज्ञ समिति है।

भारत के प्रधान मंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने और एफआरएल 524.256 मीटर की ऊँचाई तक अलमट्टी बांध बनाने के लिए कर्नाटक के रुख की प्रभावकारिता या अन्यथा का पता लगाने का अनुरोध किया गया। उक्त विशेषज्ञ समिति ने पाया था कि कर्नाटक राज्य के अलमट्टी में द्वितीय चरण में एफ. आर. एल. 524.256 एम के साथ ऊपरी कृष्णा परियोजना के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। और यह भी देखा गया है कि राष्ट्र के व्यापक हित में अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना वांछनीय होगा ताकि अलमट्टी बांध में बड़े भंडारण

का निर्माण शुरू करने से पहले ऊपर और नीचे की धारा में विभिन्न कृष्णा प्रणाली के संचालन की प्रतीक्षा की जा सके। प्रचलित स्थितियाँ। हम विशेषज्ञ समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए की गई टिप्पणियों पर ध्यान दे रहे हैं कि वादी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है, क्या इस न्यायालय के लिए कर्नाटक राज्य को अलमट्टी में बांध की ऊँचाई 524.256 m पर रखने की अनुमति देना उचित होगा या यह स्पष्ट रूप से देश और सभी संबंधित राज्यों के व्यापक हित में होगा कि बांध को 519.6 m की ऊँचाई तक अनुमति दी जाए और फिर संबंधित राज्यों को कृष्णा नदी में पानी के बंटवारे से संबंधित विवादों को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी शिकायतें रखने के लिए खुला छोड़ दिया जाए। समग्र रूप से शिकायत को पढ़ने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वादी राज्य ने अलमट्टी में एफ. आर. एल. 519.6 मीटर की ऊँचाई तक बांध होने के लिए कोई शिकायत नहीं की थी और दूसरी ओर, पूरी शिकायत केंद्र कर्नाटक राज्य के प्रस्ताव के आसपास है कि ऊँचाई 524.256 मीटर हो। मैं निर्दिष्ट विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। शिकायत को प्रदर्शनी पी. ए. पी.-212 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और यहां तक कि वह रिपोर्ट भी इंगित करती है कि आंध्र प्रदेश की शिकायत थी कि एफ. आर. एल. 524.256m पर अलमट्टी बांध की ऊँचाई, जिसे भारत सरकार द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है, सिंचाई के साथ-साथ बिजली उत्पादन के मामले में निचले नदी तटीय राज्य आंध्र प्रदेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। उक्त रिपोर्ट

आगे यह पता चलता है कि कर्नाटक राज्य बांध की ऊँचाई रखना चाहता है।

वाई कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 385

एफ. आर. एल. 524.256 एम. पर ताकि यह योजना 'बी' के तहत उपलब्ध पानी के अपने हिस्से का भंडारण कर सके। यह केवल योजना 'बी' के फलीभूत होने पर ही अलमट्टी में एक बड़े भंडारण की आवश्यकता उत्पन्न होगी, और इसलिए, राज्य बांध की ऊँचाई 524.256m पर रखने की योजना बना रहा है। उक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भले ही ऊँचाई की अनुमति 524.256 m तक न हो, लेकिन बाद में आवश्यकता पड़ने पर ही इसकी अनुमति दी जा सकती है और तकनीकी रूप से यह संभव है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि अलमट्टी और नारायणपुर में 173 टी. एम. सी. के उपयोग के लिए बांध की ऊँचाई 519 मीटर होगी, न कि 524.256 मीटर। इस प्रकार 4 अलग-अलग मुख्यमंत्रियों द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ निकाय

जो राज्य किसी भी तरह से अंतर-राज्यीय नदी कृष्णा से नहीं जुड़े हैं, वे ऊपरी कृष्णा परियोजना में 173 टी. एम. सी. के उपयोग के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा परिकल्पित वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष दर्ज किया कि अलमट्टी में शटर के शीर्ष को 519.6 एम. पर तय किया जाना चाहिए जो लगभग 173 टी. एम. सी. का भंडारण प्रदान करेगा जो ऊपरी कृष्णा परियोजना के तहत परिकल्पित 173 टी. एम. सी. की वार्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नारायणपुर में 37.8 टी. एम. सी. के भंडारण के साथ पर्याप्त होगा। हमारे निष्कर्ष को देखते हुए

1997 के ओ. एस. 1 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि योजना 'बी' न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं है, और इस प्रकार, इस न्यायालय के अनिवार्य आदेश और तथाकथित विशेषज्ञ समिति के समक्ष कर्नाटक राज्य के रुख द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

इस तथ्य के बावजूद कि वादी कर्नाटक राज्य द्वारा अलमट्टी बांध के निर्माण के संबंध में निषेधाज्ञा से राहत पाने के लिए अपने दम पर एक मामला स्थापित करने में विफल रहा है, यह कहना उचित होगा कि हालांकि राज्य में अलमट्टी बांध हो सकता है, लेकिन उक्त बांध की ऊंचाई 519.6 m से अधिक नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से जब कर्नाटक राज्य यह इंगित करने में सक्षम नहीं है कि बांध की ऊंचाई < ID2 होने की आवश्यकता क्या है। अपर कृष्णा परियोजना चरण II, अक्टूबर 1993 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसे वर्तमान मामले में पी. ए. पी. 45 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, यह भी इंगित करता है कि 173 टी. एम. सी. उपयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम एफ. आर. एल. 518.7 एम. पाया गया है। उस रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि यह 31000 क्यू. एम. एक्स. की संभावित अधिकतम बाढ़ के कारण है।, जल स्तर के 521 मीटर तक जाने की उम्मीद है।

इसलिए, प्रस्ताव है कि द्वार की ऊंचाई शिखर स्तर से 2 मीटर के साथ 521 रखी जाए। द्वार की ऊंचाई के रूप में। इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अलमट्टी की ऊंचाई शिखर स्तर 509 मीटर है।

और यह इस संदर्भ में है कि एफआरएल 524.256 मीटर पर ऊंचाई 386 की स्थिति है।

[

2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर्नाटक ने द्वार की ऊँचाई 15 मीटर रखने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, चूंकि कर्नाटक राज्य का बांध की ऊँचाई 524.256 मीटर रखने का पूरा आधार न्यायाधिकरण की योजना 'बी' के कार्यान्वयन पर निर्भर है, जिससे कर्नाटक राज्य को अतिरिक्त पानी में अपना हिस्सा प्राप्त करने और अलमट्टी बांध को कैरी ओवर जलाशय के रूप में जारी रखने का अधिकार है और चूंकि हमने 1997 की ओ. एस. 1 में कर्नाटक राज्य के खिलाफ निर्णय लिया है, जिसे राज्य ने योजना 'बी' के कार्यान्वयन के लिए दायर किया था, इसलिए उक्त राज्य के लिए अलमट्टी में बांध की ऊँचाई 524.256 मीटर रखने का कोई औचित्य नहीं है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि अलमट्टी में बांध की ऊँचाई 519.6m तक रखने के लिए उक्त कर्नाटक राज्य पर कोई निषेधाज्ञा या निषेध नहीं हो सकता है जो सभी संबंधित लोगों के हित में होगा।

श्री गंगुली, विद्वान वरिष्ठ वकील, राज्य की ओर से पेश हुए

आंध्र प्रदेश ने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक राज्य ने यू. के. पी. चरण II के संबंध में केंद्रीय जल आयोग के समक्ष दायर परियोजना रिपोर्ट में, स्वयं

इंगित किया कि प्रदर्शनी पी. ए. पी. 46 के अनुसार अलमट्टी जलाशय में आवश्यक न्यूनतम एफ. आर. एल. 519.60 एम है। लिखित बयान में कर्नाटक राज्य ने यह भी संकेत दिया कि 524.256 मीटर पर बांध की अनुमानित ऊँचाई अतिरिक्त भंडारण के लिए है, हालांकि बिजली उत्पादन के उद्देश्य से जो गैर-उपभोग्य उपयोग है और 524.256 मीटर की ऊँचाई पर, यह 302 का उपयोग करेगा।

टी. एम. सी., जो 734 टी. एम. सी. के एनब्लॉक आवंटन से अधिक होगा। श्री गांगुली ने यह भी तर्क दिया कि 1996 की ऊपरी कृष्णा बहुउद्देशीय चरण II परियोजना रिपोर्ट के अनुसार। पी. ए. पी. 48, इंगित करता है कि राज्य ने अलमट्टी में पानी से सिंचाई की योजना बनाई है जो राज्य को इसके तहत प्राप्त होगी।

योजना "बी" लागू की जा रही है। यह स्थिति होने के कारण, एफआरएल 526.256 पर अलमट्टी में बांध की ऊँचाई रखने का विचार, योजना "ए" के तहत इसके पक्ष में किए गए बड़े पैमाने पर आवंटन के विपरीत है और इसलिए, राज्य को आदेश दिया जाना चाहिए। हम आंध्र प्रदेश राज्य के इस तर्क की सराहना करने में असमर्थ हैं क्योंकि आज केंद्र सरकार के साथ-साथ उपयुक्त प्राधिकरण ने बांध की ऊँचाई 524.256 मीटर के साथ ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण II को मंजूरी नहीं दी है। इस न्यायालय के लिए यह निर्णय देना संभव नहीं होगा कि यदि कर्नाटक राज्य को अलमट्टी में बांध की ऊँचाई 524.256 मीटर रखने की अनुमति दी जाती है, तो बड़े पैमाने पर आवंटन का उल्लंघन होगा, हालांकि जैसा कि पहले कहा गया है, कर्नाटक राज्य के अनुसार 173 टी. एम. सी. के उपयोग से बांध की आवश्यक ऊँचाई 519.6 मीटर है।

इन परिस्थितियों में, हमारी यह सुविचारित राय है कि अलमट्टी में बांध के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य के खिलाफ कोई रोक नहीं होनी चाहिए और इसकी ऊंचाई को 2 मीटर तक बढ़ाने के सवाल पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जिसने कर्नाटक और ओआरएस के सॉलिसिटर स्टेट को सीखा।

» . ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 387

जनरल ने सरकार की ओर से सहमति व्यक्त की। इन दोनों मुकदमों के निर्णय के तुरंत बाद भारत सरकार का गठन किया जाएगा, ताकि किसी भी राज्य द्वारा की जा रही शिकायत पर नदी तटीय राज्यों में से प्रत्येक की शिकायत को कम किया जा सके। जहां तक उप-मुद्दा (बी) का संबंध है, हम वास्तव में आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री गंगुली के तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं। हालांकि सभी राज्यों के लिए अन्य राज्यों के विकास के बारे में जानना पूरी तरह से वांछनीय हो सकता है, लेकिन इस विषय पर किसी भी कानून में यह आवश्यक नहीं है कि कोई राज्य अपने स्वयं के जल संसाधनों के उपयोग के लिए भी अंतर-राज्यीय नदी के मामले में अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति लेगा। जहाँ तक अंक 'ख' के दूसरे भाग का संबंध है, इसका उत्तर अप्रतिरोध्य है कि प्रत्येक राज्य की परियोजना को केंद्र सरकार के साथ-साथ अन्य वैधानिक प्राधिकरणों और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है, लेकिन जिसके लिए किसी राज्य को ऐसी परियोजना के निर्माण के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 9 (ए) और (बी) मुद्दों का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

अंक 9 (सी) को महाराष्ट्र राज्य के अतिरिक्त लिखित बयान की अनुमति देते हुए तैयार किया गया था, जो इस प्रश्न से संबंधित है - जलमग्नता। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर मूल लिखित बयान में एक सकारात्मक रुख अपनाया गया था कि

न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार, तीन नदी तटीय राज्यों में से प्रत्येक के पक्ष में पानी का एक एनब्लॉक आवंटन किया गया है और इस तरह कर्नाटक राज्य पर अलमट्टी में किसी भी ऊंचाई तक बांध बनाने पर कोई रोक नहीं थी और इसलिए, यह प्रार्थना की गई थी कि आंध्र प्रदेश द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अतिरिक्त लिखित बयान में, हालांकि यह कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य के भीतर क्षेत्र के अंतिम जलमग्न होने का पहले पता नहीं चला था और इसलिए, न तो न्यायाधिकरण के समक्ष और न ही दायर किए गए मूल लिखित बयान में, कोई शिकायत की गई थी।

अलमट्टी में 524.256 मीटर की ऊंचाई पर बांध के निर्माण के संबंध में बनाया गया था, लेकिन चूंकि दोनों राज्यों के अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन से पता चला है कि महाराष्ट्र राज्य के भीतर एक बड़ा क्षेत्र होगा

यदि कर्नाटक को अलमट्टी में बांध की ऊंचाई 524.256 मीटर तक रखने की अनुमति दी जाती है, तो महाराष्ट्र राज्य ने अतिरिक्त लिखित बयान में इन तथ्यों को इस न्यायालय के संज्ञान में लाया है और अतिरिक्त मुद्दा तैयार किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के विरुद्ध वादी द्वारा वाद में किसी भी राहत की मांग के अभाव में, क्या प्रतिवादी राज्य

महाराष्ट्र सह-प्रतिवादी के खिलाफ किसी भी राहत का दावा कर सकता है जो अपने आप में एक बहस का विषय है।

मुद्दा। राज्य [2000] 3 एस. सी. आर. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अंधारुजिना।

388

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा बहुत ही विशिष्ट प्रकृति का है और एक साधारण दीवानी न्यायालय में दायर किए गए मुकदमे का सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए।

श्री अंधारुजिना के अनुसार, यदि दोनों राज्यों के बीच एक राज्य के कानूनी अधिकार के अस्तित्व या विस्तार से जुड़े विवाद का उल्लंघन किया जा रहा है

संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत अधिकारिता का आह्वान करते हुए किसी अन्य राज्य की कार्रवाई या कार्रवाई को इस न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, यह न्यायालय उक्त विवाद पर विचार करने और निर्णय लेने में पूरी तरह से उचित होगा, चाहे विवाद अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही में वादी या प्रतिवादी के रूप में उठाया गया हो। यह इस संदर्भ में विद्वान वकील ने कर्नाटक राज्य बनाम के मामले में न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की टिप्पणियों का उल्लेख किया है। भारत संघ, [1978] 2 एस. सी. आर. 1, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति भगवती ने संकेत दिया था कि एक मुकदमा दायर करने के माध्यम से लागू किए जाने पर अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता, न्यायालय को सावधान रहना चाहिए कि वह 'कार्रवाई के कारण' के विचारों से प्रभावित न हो जो मुकदमे में स्पष्ट हैं और उक्त अधिकार क्षेत्र

का दायरा और परिधि किसी भी प्राथमिक विचार द्वारा बाधित किए बिना अनुच्छेद की स्पष्ट शर्तों पर निर्धारित की जानी चाहिए। उसी निर्णय में विद्वान न्यायाधीश ने यह भी संकेत दिया था कि अनुच्छेद 131 का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि एक ऐसा मंच होना चाहिए, जो दो राज्यों या राज्य और संघ के बीच ऐसे विवादों का समाधान कर सके और वह मंच देश का सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए ताकि किसी भी पक्ष को न्यायालयों के पदानुक्रम के माध्यम से लंबी कठिन और समय लेने वाली यात्रा शुरू किए बिना विवादों का अंतिम निर्णय तेजी से और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। श्री अंधारुजिना ने भी भगवती जे की टिप्पणियों पर भरोसा किया

प्रभाव के लिए उपरोक्त मामला:

" अनुच्छेद 131 की अपेक्षा यह है कि विवाद वह होना चाहिए जो एक प्रश्न शामिल है जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार है निर्भर करता है। लेख में यह नहीं कहा गया है कि कानूनी अधिकार का होना चाहिए

वादी। यह वादी या प्रतिवादी का हो सकता है। क्या है?

आवश्यक है कि कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार होना चाहिए पक्षों के बीच विवाद का मुद्दा। हम अनुच्छेद का अर्थ नहीं लगा सकते।

131 उन मामलों तक सीमित जहाँ विवाद अस्तित्व से संबंधित है या

वादी के कानूनी अधिकार की सीमा, ऐसा करने के लिए, पढ़ना होगा लेख में ऐसे शब्द जो नहीं हैं। ऐसा लगता है क्योंकि

उच्चतम न्यायालय के नियमों के भाग III में प्रदान की गई कार्यवाही का तरीका

अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवाद लाने के लिए

एक सूट है, कि हम अनजाने में धारणा को आयात करने के लिए प्रभावित हैं

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. की व्याख्या में 'कार्रवाई का कारण', जो एक सूट में स्पष्ट है।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 389

अनुच्छेद 131 और इस लेख को केवल उन मामलों तक सीमित के रूप में पढ़ने के लिए जहां वादी के कुछ कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी के खिलाफ 'कार्रवाई का कारण' है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 131 में किसी मुकदमे या 'कार्रवाई के कारण' का कोई संदर्भ नहीं है।

और वह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है

विवाद के स्वरूप का संदर्भ जिसे न्यायनिर्णयन के लिए उसके समक्ष लाया जा सकता है। 'कार्रवाई के कारण' की आवश्यकता, जो एक मुकदमे में इतनी आवश्यक है, इसलिए, कला के दायरे और दायरे का अर्थ लगाते हुए आयात नहीं किया जा सकता है। 131. "

विद्वान वकील श्री अंधारुजिना ने भी अवलोकन पर भरोसा किया

न्यायमूर्ति भगवती ने निम्नलिखित प्रभाव के उक्त निर्णय में कहा:

" क्या है, इसलिए, कला की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए देखा जाना चाहिए। 131 यह है कि क्या पक्षकारों के अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति या प्रतिरक्षा से जुड़ा कोई संबंधपरक कानूनी मामला है

विवाद। यदि ऐसा है, तो सूट बनाए रखने योग्य होगा, लेकिन अन्यथा नहीं। "

इसी मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की टिप्पणियों पर भी भरोसा रखा गया था, जिसे यहाँ नीचे निकाला जा सकता है:

" लेख की शर्तों के अनुसार, इसलिए, एकमात्र शर्त जो मूल अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए संतुष्ट करने की आवश्यकता है

इस न्यायालय का यह है कि खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट पक्षों के बीच विवाद में एक प्रश्न शामिल होना चाहिए जिस पर अस्तित्व या कानूनी अधिकार की सीमा निर्भर करती है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने भी स्पष्ट रूप से कहा था:

" मेरा मानना है कि संविधान ने उद्देश्यपूर्ण रूप से उन्हें प्रदान किया है

यह न्यायालय, एक अधिकारिता जो उन विचारों से अनियंत्रित है जो पहली बार के न्यायालय की अधिकारिता को बाधित करते हैं, जो

अनुच्छेद 131 के तहत उत्पन्न होने वाला विवाद अलग-अलग है, दोनों रूप में और दावे की प्रकृति से, जिसमें न्यायनिर्णयन की आवश्यकता होती है

साधारण सूट "।

श्री अंधारुजिना ने अपनी पुस्तक में श्री सीरवाई की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है, जिसमें लेखक ने कहा है कि यह अभिनिर्धारित करना उचित है कि न्यायालय [2000] 3 एस. सी. आर.

390

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसे पूरे विवाद को हल करने की शक्ति है, जब तक कि उसकी शक्ति स्पष्ट शब्दों या आवश्यक निहितार्थों द्वारा सीमित न हो और उच्चतम न्यायालय के पास मुकदमे में दावा किए गए कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए जो भी आवश्यक राहत देने की शक्ति होगी, यदि ऐसा कानूनी अधिकार स्थापित है। श्री अंधारुजिना उन्होंने तर्क दिया कि एक बार जब महाराष्ट्र राज्य की शिकायत संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक लंबित कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया है, न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पर्याप्त शक्ति है और पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, न्यायालय किसी भी प्रक्रिया के प्रावधानों से बाध्य नहीं होगा और उसी से अलग हो सकता है। यह इस संदर्भ में है कि दिल्ली न्यायिक सेवा बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था। गुजरात राज्य, [1991] 4 एस. सी. सी. 406, जिसके तहत इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"केंद्रीय या राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया कोई भी अधिनियम सीमित या सीमित नहीं कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति को सीमित करना, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए,

न्यायालय को वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए

विवादग्रस्त मामले को विनियमित करना। "पूर्ण" की क्या आवश्यकता होगी?

किसी कारण या मामले में न्याय तथ्यों पर निर्भर करेगा और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय एक मूल के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा

कानून। एक बार जब यह न्यायालय किसी मामले, कारण या मामले को अपने हाथ में ले लेता है, इसके पास कोई भी आदेश या निर्देश जारी करने की शक्ति है जो आवश्यक हो।

मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए। .

श्री अंधारुजिना ने प्रस्तुत किया कि जलमग्न होने की संभावना

अलमट्टी में बांध की ऊँचाई को 524.256 मीटर तक बढ़ाए जाने के कारण महाराष्ट्र राज्य का खुलासा केवल वर्तमान वाद के लंबित रहने के दौरान किया गया था और कर्नाटक राज्य ने स्वयं 10 अगस्त, 1998 को अपने पत्र में महाराष्ट्र राज्य को सूचित किया था कि राज्य को इस मुद्दे पर न्यायालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, कर्नाटक राज्य ने भी अपनी दिनांकित बैठक में केंद्रीय जल आयोग के निर्देशों के तहत जलमग्नता की सीमा निर्धारित करने के लिए वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण और गणना करने पर सहमति व्यक्त की और वे अध्ययन अभी भी प्रगति पर हैं और आगे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं दिनांकित आदेश द्वारा अलमट्टी बांध की ऊँचाई से संबंधित यथास्थिति का आदेश पारित किया था और इसके परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र राज्य ने कभी भी कर्नाटक राज्य और ओआरएस के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए एक स्वतंत्र मुकदमा दायर करना उचित नहीं समझा।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 391

अनुच्छेद 131। लेकिन कर्नाटक राज्य ने इस माननीय न्यायालय से दिनांक 1 के आदेश द्वारा फाटकों की असेंबली की स्थापना के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और उक्त कर्नाटक राज्य ने महाराष्ट्र राज्य को इसकी ऊँचाई नहीं बढ़ाने का वचन देने से इनकार कर दिया है।

509 मीटर के वर्तमान स्तर से परे अलमट्टी बांध, महाराष्ट्र राज्य

अपने क्षेत्र के संभावित जलमग्न होने के सवाल पर अपनी शिकायत रखने के लिए मजबूर किया गया था और बांध की ऊँचाई 524.256 मीटर तक बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य के खिलाफ निषेधाज्ञा की राहत के लिए प्रार्थना की है। श्री अंधारुजिना ने यह भी प्रस्तुत किया

कि अलमट्टी बांध को 524.256 मीटर तक बनाने की अनुमति देने की स्थिति में जलमग्न होने वाले क्षेत्र की सटीक सीमा अभी तक नहीं है!

पता लगा लिया गया है और सर्वेक्षण अभी भी जारी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य के भीतर एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। | कर्नाटक राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरीमन ने महाराष्ट्र राज्य जैसे सह-प्रतिवादी के शिकायतों को सामने रखने के अधिकार पर गंभीरता से विवाद नहीं किया ताकि किसी अन्य सह-प्रतिवादी के खिलाफ राहत मिल सके, हालांकि उन्होंने निस्संदेह प्रस्तुत किया कि इस घटना में, महाराष्ट्र राज्य को अतिरिक्त लिखित बयान और निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी।

अतिरिक्त मुद्दे बनाए जाने पर कर्नाटक राज्य को अपना मामला रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि अलमट्टी में बांध की ऊँचाई को 524.256 मीटर तक बढ़ाने के कारण महाराष्ट्र के क्षेत्र के जलमग्न होने से संबंधित विवाद अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमे में निर्णय का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य ने न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद नहीं उठाया था, भले ही न्यायाधिकरण के समक्ष कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट ने 524.256 मीटर पर बांध की ऊँचाई का संकेत दिया था। श्री नरीमन के अनुसार, इस तरह का विवाद एक ताजे पानी का विवाद होगा और यह न्यायिक विवाद का हिस्सा नहीं होगा और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस विवाद पर इस न्यायालय द्वारा विचार और निर्णय नहीं लिया जा सकता है। श्री नरीमन ने यह भी तर्क दिया कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री अदालत को इस सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद नहीं करती है कि यदि अलमट्टी बांध को 524.256 मीटर तक उठाया जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। जलमग्नता, यदि कोई हो और वापस प्रवाह, यदि कोई हो, नदी में ही होगा, न कि नदी से परे कोई क्षेत्र। श्री नरीमन ने आगे आग्रह किया कि महाराष्ट्र राज्य ने अपने क्षेत्र के उथल-पुथल का अनुमान लगाया था जैसा कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपने रुख से दिखाई देगा जो स्पष्ट है

अनुच्छेद 6.3। 1 (के) एक्सएच का। एमआरके-1. विद्वान वकील के अनुसार यह सच है कि न्यायाधिकरण ने उक्त प्रश्न पर विचार नहीं किया, बल्कि मूल रिपोर्ट के बाद किया।

1

प्रस्तुत किया गया था, महाराष्ट्र जलमग्नता के प्रश्न पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत एक आवेदन दायर कर सकता था, लेकिन वह 392 था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[

2000] 3 एस सी आर।

स्वीकार नहीं किया गया है, जो इंगित करता है कि इसे जलमग्न होने के सवाल पर कोई शिकायत नहीं थी। इस मुद्दे पर प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच करने के बाद, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इस मुद्दे का जवाब महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ दिया जाना चाहिए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद के तहत एक मुकदमे में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सही है।

131 संविधान की धारा काफी व्यापक है, जो उक्त अनुच्छेद में उपयोग की गई भाषा से स्पष्ट है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दोनों में व्याख्या की गई है। पहले से संदर्भित मामले (देखें [1978] 2 एससीआर 1 और [1978] 1 एससीआर 64)। यह भी सच है कि अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

पक्षकारों और न्यायालय के बीच कोई भी आदेश पारित किया जा सकता है या कोई भी निर्देश जारी किया जा सकता है जो आवश्यक हो सकता है, लेकिन साथ ही, अनुच्छेद 131 के अर्थ के भीतर, वर्तमान वाद में उठाया गया विवाद राज्य के बीच है।

इसलिए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य और सवाल यह होगा कि क्या इसमें इस तरह के विवाद के कानूनी अधिकार का कोई अस्तित्व या विस्तार शामिल है। इस तरह के विवाद का जवाब देने में, एक सह प्रतिवादी, महाराष्ट्र राज्य द्वारा उठाए गए जलमग्न होने के सवाल पर आगे के विवाद पर विचार करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन श्री नरीमन द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, मामले में आगे की जांच किए बिना और कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना, क्या महाराष्ट्र द्वारा लिए गए ऐसे रुख पर निर्णय लिया जाना संभव है, हम उक्त विवाद के गुण-दोष की जांच करेंगे। न्यायाधिकरण की रिपोर्ट का एक नंगे अवलोकन जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है और Exh.PK1 के अनुसार उसे संदर्भित मामलों पर अपना निर्णय देने के साथ-साथ उक्त न्यायाधिकरण की आगे की रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा दायर स्पष्टीकरण के लिए आवेदन को स्पष्टीकरण दिया गया है। पीके2, हम पाते हैं कि कर्नाटक राज्य में अलमट्टी बांध के कारण महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र के भीतर जलमग्न होने के सवाल पर न तो कोई चर्चा की गई है और न ही उस पर कोई राय व्यक्त की गई है। न्यायाधिकरण ने एनब्लॉक आवंटन के आधार पर कृष्णा नदी में पानी के बंटवारे के प्रश्न पर अपना निर्णय देने के बाद, यदि किसी विशेष तरीके से इस तरह के पानी का उपयोगकर्ता किसी अन्य राज्य के लिए हानिकारक हो जाता है, तो ऐसी शिकायत अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 2 (सी) के

अर्थ के भीतर एक नया विवाद होगा और इसे न्यायाधिकरण का न्यायिक विवाद नहीं माना जा सकता है। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यह केवल राज्यों के बीच एक न्यायिक विवाद है जिस पर सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिया गया है।

यदि न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के कार्यान्वयन में कोई उल्लंघन होता है, तो भारत अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे का विषय हो सकता है। लेकिन एक राज्य द्वारा पानी के उपयोगकर्ता से उत्पन्न होने वाली उक्त अंतर-राज्यीय नदी के संबंध में दोनों राज्यों के बीच विवाद एक ताजा जल विवाद होगा और इस तरह कर्नाटक और ओ. आर. एस. का राज्य होगा।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 393

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 11 के साथ पठित अनुच्छेद 262 के तहत वर्जित किया जाए। किसी विशेष राज्य के पक्ष में आवंटित अंतर-राज्यीय नदी के संबंध में पानी के उपयोगकर्ता के अनुसार भूमि के डूबने का सवाल पानी के आवंटन से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र राज्य की वर्तमान शिकायत एक शिकायत होगी।

धारा 3 (ए) के अर्थ के भीतर कर्नाटक राज्य की किसी कार्यकारी कार्रवाई की और यह भी धारा 2 (सी) के दायरे में एक जल विवाद होगा और इसलिए, इस न्यायालय के लिए इस पर विचार करना और जांच करना और इसका जवाब देना उचित नहीं होगा। हम महाराष्ट्र राज्य की चिंता की सराहना करते हैं, जब यह उसके संज्ञान में आता है कि अगर अलमट्टी बांध की ऊंचाई को कम करने की अनुमति दी जाती है तो उसके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ और जलमग्नता होगी।

कर्नाटक राज्य की नवीनतम परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसे 524.256 मीटर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन अकेले महाराष्ट्र राज्य की ऐसी चिंता इस न्यायालय के लिए मामले का फैसला करने और निषेधाज्ञा का कोई आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जैसा कि राज्य द्वारा दायर अतिरिक्त लिखित बयान में अनुरोध किया गया है।

महाराष्ट्र में संयुक्त सर्वेक्षण अभी भी जारी है। यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि कोई भी न्यायालय प्रतिकूल प्रभावों के बारे में सकारात्मक आंकड़ों के बिना और अपूरणीय क्षति और सुविधा के संतुलन के सवाल पर किसी निश्चित निष्कर्ष के बिना केवल आशंका पर अनिवार्य निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं कर सकता है। फिर, किसी विशेष राज्य को किसी अंतर-राज्यीय नदी के पानी का उपयोग करने की अनुमति देते समय, यदि इस तरह के उपयोगकर्ता का तरीका वास्तव में किसी अन्य राज्य में किसी भूमि को जलमग्न कर देता है, तो इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए कि मुआवजे की राशि क्या होगी और जलमग्न क्षेत्र के भीतर उन व्यक्तियों के पुनर्वास के सवाल से कैसे निपटा जा सकता है जो वास्तव में न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांत

का एक पहलू है और यदि कोई शिकायत हो तो इन सभी पर विचार किया जा सकता है। उसी के बारे में बनाया जाता है और भारत सरकार उक्त उद्देश्य के लिए एक न्यायाधिकरण नियुक्त करती है। लेकिन न्यायाधिकरण के न्यायिक विवाद के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में अनुच्छेद 131 के तहत दायर मुकदमे में इन चीजों को शामिल नहीं किया जा सकता है। यह भी आश्चर्य की बात है कि भले ही अलमट्टी बांध के संबंध में 1970 की मूल परियोजना रिपोर्ट न्यायाधिकरण के समक्ष पेश की गई थी, जो विभिन्न राज्यों द्वारा उठाए गए विवादों का निर्णय ले रहा था, फिर भी

महाराष्ट्र ने कभी जलमग्न होने के बारे में नहीं सोचा और न ही कभी 394 पर।

[2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए लालायित। उपरोक्त परिसर में, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्ति कितनी व्यापक हो सकती है

हम महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपने अतिरिक्त लिखित बयान में उठाए गए जलमग्न होने के प्रश्न पर विचार करना और उस आधार पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई के संबंध में निषेधाज्ञा के प्रश्न का निर्णय करना उचित नहीं समझते हैं।

तदनुसार अंक 9 (सी) का निर्णय महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ किया जाता है।

इस स्तर पर एक और तर्क पर ध्यान देना भी उचित होगा।

महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंधारुजिना ने इस आशय का प्रस्ताव रखा कि न्यायाधिकरण के निर्णय के खंड XV को देखते हुए प्रत्येक राज्य अपनी सीमा के भीतर अपने पक्ष में आवंटित पानी का उपयोग करने का हकदार है, जिस क्षण एक राज्य द्वारा ऐसे पानी का उपयोगकर्ता दूसरे राज्य का कोई भी क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, तो यह खंड XV में निहित न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन होगा, और इसलिए, उक्त राज्य को ऐसे उपयोगकर्ता से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। निर्णय का खंड XV इस प्रकार है:

" इस न्यायाधिकरण के आदेश में कुछ भी अधिकार को बाधित नहीं करेगा या

अपनी सीमाओं के भीतर विनियमित करने के लिए किसी भी राज्य की शक्ति या प्राधिकरण

जल का उपयोग, या उस राज्य के भीतर जल का लाभ उठाने के लिए इस न्यायाधिकरण के आदेश के अनुरूप नहीं है।

उपरोक्त खंड किसी भी तरह से न्यायाधिकरण द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर आवंटित पानी का उपयोग करने के राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही यह खंड यह समझने में सक्षम है कि यदि ऐसे उपयोगकर्ता द्वारा किसी अन्य राज्य में कोई जलमग्नता होती है, तो उपयोगकर्ता न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश के साथ असंगत हो जाता है। श्री अंधारुजिना का पूरा तर्क 'अपनी सीमा के भीतर विनियमन' अभिव्यक्ति पर आधारित है, लेकिन यह अभिव्यक्ति पानी के उपयोग पर लागू होती है या उस राज्य के भीतर पानी के लाभ प्राप्त करती है। चूंकि किसी अन्य राज्य द्वारा उसके पक्ष में आवंटित पानी के उपयोगकर्ता द्वारा किसी अन्य राज्य के जलमग्न होने का प्रश्न न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय का विषय नहीं है और वास्तव में न्यायाधिकरण ने उस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, इसलिए हमारे लिए यह अभिनिर्धारित करना मुश्किल होगा कि जलमग्नता वास्तव में महाराष्ट्र राज्य के भीतर कर्नाटक राज्य द्वारा अलमट्टी में पानी के उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी रूप में स्वीकार किए जाने पर भी न्यायाधिकरण के आदेश के साथ असंगत माना जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में हम महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अंधारुजिना की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि कर्नाटक राज्य द्वारा अलमट्टी में बांध का निर्माण करके पानी का उपयोग न्यायाधिकरण के निर्णय के खंड XV के अनुरूप है। इसलिए अंक 9 (सी) का जवाब महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ दिया गया है।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 395

इश्यू नं. 10

उपरोक्त मुद्दा शिकायत के पैराग्राफ 68 में किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। वाद के उपरोक्त पैराग्राफ में वादी ने विभिन्न परियोजनाओं द्वारा सिंचित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा किए गए आवंटन से परे पानी के अतिरिक्त उपयोग के संदर्भ में आंकड़े का संकेत दिया है। वादी स्पष्ट रूप से इस गलत धारणा में है कि न्यायाधिकरण के निर्णय में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में पानी का परियोजनावार आवंटन किया गया है।

राज्यों। हम पहले ही इस मामले पर विस्तार से विचार कर चुके हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि आवंटन परियोजना के हिसाब से नहीं बल्कि एनब्लॉक किया गया था और इस तरह, सवाल यह है कि अलमट्टी में बड़े जलाशय का निर्माण क्या है?

न्यायाधिकरण के निर्णय के विपरीत उत्पन्न नहीं होता है। इसके अलावा न्यायाधिकरण के निर्णय के खंड VII से संकेत मिलता है कि एक जल वर्ष में पानी के उपयोग को कैसे मापा जाएगा और यह निर्धारित करता है कि उपयोग को किसी भी तरह से कृष्णा नदी के पानी की कमी की सीमा से मापा जाएगा।

वाष्पीकरण से होने वाले जल के नुकसान और मानव निर्मित जलाशयों और अन्य कार्यों से अन्य प्राकृतिक कारणों से पानी की मात्रा में कटौती किए बिना जो नदी में इस तरह के उपयोग के बाद वापस आ सकती है, लेकिन जहां तक कृष्णा नदी प्रणाली की किसी भी धारा के पार किसी भी जलाशय में संग्रहीत पानी का संबंध है, भंडारण को स्वयं धारा के पानी की कमी के रूप में नहीं माना जाएगा, सिवाय वाष्पीकरण से होने वाले पानी के नुकसान और ऐसे जलाशय से अन्य प्राकृतिक कारणों के। हालाँकि, ऐसे जलाशय से अपने उपयोग के लिए डायवर्ट किए गए पानी को जल वर्ष में उस राज्य द्वारा उपयोग के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायाधिकरण के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह मानते हुए कि कर्नाटक राज्य ने अलमट्टी में पानी के भंडारण की संभावना, वादी द्वारा कर्नाटक राज्य द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए ऐसे जलाशय से किसी भी मोड़ के रूप में संकेत करने के लिए रखी गई किसी भी सामग्री के अभाव में, किसी भी स्थिति में आना संभव नहीं है।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि कर्नाटक राज्य द्वारा अलमट्टी में पानी के भंडारण की क्षमता होने के कारण न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन किया गया है,

जैसा कि वादी के वकील ने तर्क दिया है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि 1973 में प्रदर्शनी पी. के.-1 के अनुसार रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत करने के बाद भारत सरकार ने इसके लिए आवेदन दायर किया था।

न्यायाधिकरण और स्पष्टीकरण 1 (बी) द्वारा 1974 के संदर्भ संख्या 1 के रूप में दर्ज किया गया स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रभाव से था:

" जबकि न्यायाधिकरण ने कुछ उप-बेसिनों में पानी के उपयोग के साथ-साथ प्रत्येक राज्य द्वारा कुल उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है,

ऐसे स्थान हों जहाँ पनबिजली उत्पादन (बेसिन के भीतर) 396 हो सकता है।

[

2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संभव है। विशेष रूप से जल-स्थलों पर या बहु-उद्देश्य वाले स्थलों पर परियोजनाएं। ऐसे स्थलों पर, राज्यों को आवंटित जल का कुछ हिस्सा, जैसे -

अन्य राज्यों में बहने वाले पानी का भी उपयोग किया जा सकता है

बिजली उत्पादन या तो एक एकल बिजली स्टेशन पर या एक श्रृंखला में

बिजली स्टेशन। न्यायाधिकरण कृपया मार्गदर्शन दे सकता है कि क्या

कृष्णा बेसिन के भीतर बिजली उत्पादन के लिए पानी का ऐसा उपयोग है

अनुमति भले ही इस तरह के उपयोग उपभोग्य की सीमा से अधिक हो सकता है प्रत्येक राज्य या उप-बेसिन या पहुंच के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उपयोग,

और यदि हां, तो किन शर्तों और सुरक्षा उपायों के तहत।

आंध्र प्रदेश राज्य ने स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त आवेदन को

दो नोट प्रस्तुत किए। 9 और 10 न्यायाधिकरण के समक्ष 7 मई, 1975 और 8 मई, 1975 को। इस नोट में यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि न्यायाधिकरण को यह स्पष्ट करने में खुशी हो सकती है कि ऊपरी राज्य को उन्हें आवंटित हिस्से से अधिक पानी को इस तरह से संग्रहीत करने का कोई अधिकार नहीं है जो भरोसेमंद प्रवाह में आंध्र प्रदेश राज्य के अधिकार को प्रभावित करेगा। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा कई आधार दिए गए थे कि इस तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है, विशेष रूप से जब योजना 'ए' आवंटन के तहत कमी को साझा करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। न्यायाधिकरण ने उसी पर विचार किया और अंततः प्रदर्शनी पी. के.-2 के तहत अपनी आगे की रिपोर्ट में उल्लेख किया कि आंध्र प्रदेश राज्य ने उक्त नोट को वापस ले लिया और परिणामस्वरूप आगे किसी स्पष्टीकरण के लिए कोई आधार नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा एक नोट प्रस्तुत किया गया है जिसमें ऊपरी नदी तटीय राज्यों द्वारा पानी के भंडारण के मामले में एक सीमा निर्धारित करने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई है और फिर अंततः उसी वर्तमान शिकायत को वापस ले लिया गया है कि कर्नाटक राज्य द्वारा अलमट्टी में बड़े आकार के बांध के निर्माण से आंध्र प्रदेश राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसके अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। तदनुसार वादी के खिलाफ मुद्दे का जवाब दिया जाता है।

इश्यू नं। 11 & 12 :

ये दोनों मुद्दे समान प्रश्न के आसपास केंद्रित हैं कि क्या वहाँ था

ऊपरी कृष्णा परियोजना में कोई विशिष्ट आवंटन या उपयोग और क्या अलमट्टी नहर के तहत सिंचाई का प्रावधान करना न्यायाधिकरण के निर्णय के विपरीत है क्योंकि इसके तहत सिंचाई के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। हम पहले ही आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक सामग्रियों के साथ-साथ न्यायाधिकरण के निर्णय पर चर्चा कर चुके हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादी-आंध्र प्रदेश राज्य, यह स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि वास्तव में कर्नाटक और ओ. आर. एस. के उच्च राज्य के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा कोई विशिष्ट आवंटन किया गया था।

वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 397

कृष्णा परियोजना या अलमट्टी जलाशय और दूसरी ओर, आवंटन स्पष्ट और स्पष्ट था कि राज्य इसका उपयोग कर सकते हैं।

उनके क्षेत्र के भीतर उनके पक्ष में आवंटित पानी की मात्रा। यह स्थिति होने के कारण हमें वादी राज्य-आंध्र प्रदेश के खिलाफ इन दो मुद्दों का जवाब देने में कोई संकोच नहीं है और हमारा मानना है कि वादी उपरोक्त दो मुद्दों के समर्थन में कोई सामग्री पेश करने में विफल रहा है। ये दोनों मुद्दे तदनुसार

वादी के खिलाफ जवाब दिया जाता है।

ISSUE NO.13

जहाँ तक इस मुद्दे का संबंध है, कर्नाटक राज्य के यू. के. पी. या किसी अन्य के तहत उपयोग को फिर से आवंटित करने या फिर से समायोजित करने के अधिकार का सवाल है।

परियोजना एकतरफा रूप से उत्पन्न नहीं होती है। यदि न्यायाधिकरण ने कोई परियोजनावार आवंटन किया होता और यू. के. पी. के तहत पानी के उपयोगकर्ता को किसी विशेष मात्रा तक सीमित कर दिया होता तो राज्य द्वारा पुनः आवंटन का प्रश्न - कर्नाटक अपने दम पर उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन न्यायाधिकरण ने ऊपरी कृष्णा परियोजना के संबंध में कोई आवंटन नहीं किया है, जिसमें अलमट्टी शामिल है और एक एनब्लॉक आवंटन किया है, जब तक कि कर्नाटक राज्य द्वारा कुल उपयोगकर्ता इसके पक्ष में एनब्लॉक आवंटन से अधिक नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अलमट्टी में किसी विशेष मात्रा में पानी का उपयोग करने की योजना

बनाकर कर्नाटक राज्य द्वारा कोई उल्लंघन किया गया है। फिर से अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति प्राप्त करने का सवाल, जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा उठाया गया है, पूरी तरह से गलत है। न तो ऐसा कोई कानून मौजूद है जो किसी भी राज्य को अंतर-राज्यीय नदी के संबंध में जब भी पानी का उपयोग करता है तो अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है और न ही न्यायाधिकरण का निर्णय जो 75 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर कृष्णा बेसिन में पानी का आवंटन करता है, जो पक्षकारों के समझौते से प्राप्त हुआ था, अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति के लिए कोई शर्त रखता है। मामले के इस दृष्टिकोण में इस मुद्दे पर और विस्तार किए बिना, हम वादी के खिलाफ इसका जवाब देते हैं।

उपरोक्त मुद्दा इस परिकल्पना पर उठाया गया है कि भारत संघ कर्नाटक राज्य के भीतर विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देने जा रहा है। जो कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, जहाँ तक ऊपरी कृष्णा परियोजना का संबंध है,

भारत सरकार ने 509 मीटर के शिखर स्तर पर बांध की ऊंचाई को मंजूरी दी है। कर्नाटक राज्य द्वारा 1993 में प्रस्तुत और 1996 में फिर से प्रस्तुत की गई बाढ़ की संशोधित परियोजना अभी भी विचाराधीन है और कोई अंतिम नहीं है।

इस पर निर्णय लिया गया है। भारत संघ ने अपने जवाबी हलफनामे में 398

[

2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है और दूसरी ओर, यह कहा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य कुछ ऐसी परियोजना के साथ आगे बढ़ रहा है जिसे केंद्र द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। सरकार। सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गंगुली ने मुद्दा संख्या से संबंधित उपरोक्त रुख के समर्थन में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है। 14. इसलिए हम वादी के खिलाफ उक्त मुद्दे पर निर्णय लेते हैं।

इश्यू नं। 15

उपरोक्त मुद्दा वादी के इस आरोप पर तैयार किया गया है कि कर्नाटक राज्य द्वारा ऊपरी कृष्णा चरण II को निष्पादित करने की संभावना है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना बहुउद्देशीय परियोजना के साथ-साथ उसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों के लिए यह दायित्व है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें और यहां तक कि यह केंद्र सरकार को भी ऐसा करने में सक्षम बनाता है किसी राज्य को निर्देश देना जो उस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। हमारे जैसे संघीय ढांचे में, संविधान स्वयं शक्तियों का वितरण करके संतुलन बनाए रखता है

केंद्र और राज्यों के बीच और केंद्र सरकार को विनियमित करने और जब भी आवश्यक हो निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करके। पिछले 50 वर्षों में संविधान के कई प्रावधानों का परीक्षण किया गया है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कोई भी राज्य उपयुक्त प्राधिकरणों की मंजूरी/सहमति प्राप्त किए बिना और संसद द्वारा बनाए गए प्रासंगिक कानूनों या कानूनों का पालन किए बिना अंतर-राज्यीय जलाशय के संबंध में पानी के उपयोग से संबंधित अपनी परियोजना को आगे बढ़ाएगा। यह एक सामान्य ज्ञान है कि इनमें से प्रत्येक राज्य द्वारा नियोजित बड़े पैमाने की परियोजनाओं को योजना आयोग को इसकी मंजूरी के लिए और प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है

वित्तीय सहायता। इस तरह की परियोजनाओं की विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जांच की जाती है और योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही इसे भारत सरकार के उपयुक्त विभागों को प्रस्तुत किया जाता है जहां फिर से सभी औपचारिकताओं की जांच की जाती है और अंतिम मंजूरी या अनुमति दी जाती है। जहाँ तक अंतरराज्यीय जलाशय के संबंध में पानी का उपयोगकर्ता है

संबंधित, केंद्रीय जल आयोग द्वारा भी योजनाओं की जांच की जाती है, जो एक विशेषज्ञ निकाय है और ऐसे आयोग द्वारा दिए गए विचारों को भी लिया जाता है।

भारत सरकार द्वारा विचार। यह प्रक्रिया का पूरा सरगम होने के कारण हम वास्तव में यह समझने में विफल हैं कि आंध्र राज्य किस आधार पर है।

प्रदेश ने आरोप लगाया है और इस संबंध में मुद्दा उठाया गया है।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 399

अंतरराज्यीय नदी के संबंध में उनके लिए उपलब्ध पानी के उपयोगकर्ता से संबंधित विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं को उचित जांच के बाद भारत सरकार के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा विधिवत मंजूरी दी जानी चाहिए और यह केवल तब राज्य को ऐसा करने का अधिकार होगा। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

इश्यू नं। 16

यदि विचाराधीन मुद्दे की जांच अलमट्टी बांध के निर्माण के संबंध में की जाती है, जो वास्तव में मुकदमे में ही विवाद का विषय है, तो हम यह पता नहीं लगा पाए हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य कैसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है या होगा या इसके क्या प्रतिकूल परिणाम होंगे या इसके क्या परिणाम होंगे। जब कोई वादी इस आधार पर प्रतिवादी की कार्यवाई या निष्क्रियता द्वारा निषेधाज्ञा की राहत लेना चाहता है कि ऐसी कार्यवाई या निष्क्रियता वादी राज्य के हित के लिए अत्यधिक हानिकारक रही है और वादी राज्य के अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो ऐसे मामले में वादी के लिए सामग्री को रिकॉर्ड पर रखना और आवश्यक सामग्री स्थापित करना अनिवार्य है ताकि अदालत इस निष्कर्ष पर आ सके कि प्रतिवादी की ऐसी कार्यवाई या निष्क्रियता से वादी को अपूरणीय क्षति हुई है। जब हम वाद में किए गए कथनों की जांच करते हैं

साथ ही इस आधार पर वादी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा करने की मांग की गई थी, हम पाते हैं कि ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं है जिसके आधार पर यह संभव हो

एक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि निम्न नदी तटीय राज्य, कर्नाटक राज्य के भीतर अलमट्टी बांध के निर्माण के कारण-वादी ने

प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है। वादी राज्य की शिकायत और शिकायत वास्तविक की तुलना में काल्पनिक है और इस कार्यवाही के अभिलेखों पर ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई है जिससे न्यायालय अलमट्टी में बांध के निर्माण के कारण आंध्र प्रदेश राज्य पर तथाकथित प्रतिकूल प्रभाव के प्रश्न पर निष्कर्ष पर पहुंच सके। श्री गंगुली, आंध्र राज्य [2000] 3 एस. सी. आर. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील।

प्रदेश ने कर्नाटक राज्य द्वारा समिति को प्रस्तुत लिखित ज्ञापन का उल्लेख किया जिसमें उक्त राज्य ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि अलमट्टी में अतिरिक्त भंडारण से अगस्त से अक्टूबर के दौरान लगभग तीन महीने की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश में जाने वाले प्रवाह की मात्रा में अस्थायी कमी आएगी जो बाद में ठीक हो जाती है। विद्वानों के अनुसार

चूंकि वे तीन महीने आंध्र प्रदेश राज्य में फसलों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए राज्य को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा और इस तरह कर्नाटक राज्य की स्वीकृति पर एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सबसे पहले हमें यह बताना होगा कि राज्य द्वारा प्रस्तुत लिखित ज्ञापन

कर्नाटक को एक विशेष वाक्य को काटकर अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है और इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार हम कर्नाटक राज्य की ओर से आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवाह में कमी का कोई संकेत नहीं पाते हैं। श्री गांगुली ने योजना 'बी' के खंड XV की ओर भी इशारा किया, जिसके तहत न्यायाधिकरण स्वयं पानी की कमी की संभावना के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचा था और संबंधित प्राधिकरण को आवश्यक समायोजन करने का अधिकार दिया था। लेकिन इसके तहत जो कहा गया है वह इसके संबंध में है

योजना 'बी' को अपनाना जो आंध्र प्रदेश राज्य की ईमानदारी की कमी के कारण संभव नहीं हुआ है और यहां तक कि कृष्णा नदी के तहत भी।

घाटी प्राधिकरण को प्रत्येक राज्य के हिस्से में आने वाले पानी की मात्रा निर्धारित करने और अधिकारियों के उपयोग को इस तरह से समायोजित करने का अधिकार दिया गया है ताकि जल वर्ष के अंत तक प्रत्येक राज्य अपने हिस्से के अनुसार पानी का उपयोग कर सके। हमें इस पहलू की आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से तब जब योजना 'बी' अब तक चालू नहीं हुई है और यहां तक कि इस न्यायालय ने कर्नाटक राज्य द्वारा दायर 1997 के ओएस 1 में योजना 'बी' को अपनाने के लिए कोई अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार कर दिया है। उपरोक्त परिसर में, हमारे पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि कर्नाटक राज्य द्वारा अलमट्टी बांध के निर्माण ने किसी भी तरह से आंध्र प्रदेश राज्य को प्रभावित किया है या किसी भी तरह से प्रभावित करने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप उक्त मुद्दे का वादी के खिलाफ जवाब दिया जाना चाहिए।

इश्यू नं। 17

इस मुद्दे के तहत, विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार, हिप्परगी में उपयोग के लिए केवल 5 टी. एम. सी. का आदेश दिया गया था। अंक संख्या 3 का उत्तर देते समय, हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि न्यायाधिकरण ने केवल खण्ड (IX) और खंड (IX) में उल्लिखित,

जहां तक हिप्परगी का संबंध है, कर्नाटक और ओ. आर. एस. के. 2 उप-राज्य के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को छोड़कर, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया है।

» . ए. पी. राज्य [पटनायक, जे.] 401

बेसिन, उसी का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, वादी के खिलाफ उक्त मुद्दे का जवाब दिया जाता है।

इश्यू नं. 18

उपरोक्त मुद्दे को पैराग्राफ 66 (बी) और पैराग्राफ 68 (बी) आइटम नंबर 4 में किए गए कथनों के आधार पर तैयार किया गया है। पैराग्राफ 66 (बी) में कथन समाचार पत्र रिपोर्ट के आधार पर है और पैराग्राफ 68 (बी) आइटम नंबर 4 में किया गया कथन आंध्र प्रदेश राज्य का अपना अनुमान है। प्रतिवादी सं. 1-कर्नाटक राज्य पैराग्राफ सं. 12.88 और पैराग्राफ सं. 12.111 के माध्यम से शिकायत में किए गए कथनों की सामग्री से इनकार करता है। आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश वकील ने भी इसके समर्थन में कोई सामग्री नहीं रखी

उपरोक्त मुद्दे के तर्कों और वाद में किए गए अभिकथनों को लिखित बयान में अस्वीकार कर दिया गया है, इस मुद्दे का जवाब वादी के खिलाफ दिया जाना चाहिए। इश्यू नं. 19

हालाँकि, वादी-आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने स्वयं के अनुमान पर, पैराग्राफ 68 (बी) में इस आशय का अनुमान लगाया है कि कर्नाटक राज्य द्वारा के2 उप-बेसिन में योजना का उपयोग 428.75 टी. एम. सी. है जिसके आधार पर उपरोक्त मुद्दा तैयार किया गया है, लेकिन उपरोक्त निष्कर्ष पर आने के लिए हमारे सामने कोई सकारात्मक डेटा नहीं रखा गया है। दूसरी ओर, कर्नाटक राज्य ने अपने लिखित बयान में कहा है कि ऊपरी कृष्णा परियोजना के तहत 173 टी. एम. सी. का उपयोग किया जाएगा और यह न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए कई दस्तावेजों के साथ-साथ इस कार्यवाही से भी स्पष्ट है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम इस मुद्दे का जवाब यह मानते हुए देते हैं कि वादी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि कर्नाटक राज्य के के2 उप-बेसिन में संचयी उपयोग 428.75 टी. एम. सी. के बराबर होगा। कम से कम, क्योंकि हम पहले ही यह मान चुके हैं कि आवंटन अनिवार्य था और न्यायाधिकरण के निर्णय में के2 उप-बेसिन में उपयोग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यह मुद्दा वास्तव में विचार के लिए जीवित नहीं है। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

इश्यू नं। 20 यह मुद्दा खंड (IX) में न्यायाधिकरण के निर्णय से संबंधित है, जिसके तहत खंड, प्रतिबंधों को उसके तहत इंगित सीमा तक रखा गया है।

लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य इस संबंध में लगाए गए आरोप को स्थापित नहीं कर पाया है और न ही राज्य की ओर से पेश वकील ने कोई आरोप लगाया है।

उस पर समर्पण करें। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की गई थीं और [2000] 3 एस. सी. आर. के बाद भी।

402

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुनवाई के अंत में, आंध्र प्रदेश राज्य ने 15 मार्च, 2000 को एक लिखित निवेदन दायर किया है, जिसमें उप-बेसिन के-6, के-8 और के-9 में कथित उल्लंघन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए हम इस मुद्दे का जवाब यह मानते हुए देते हैं कि वादी इसे स्थापित करने में विफल रहा है।

और वादी के खिलाफ मुद्दे का जवाब तदनुसार दिया जाता है।

इश्यू नं। 21

यह

मुद्दा अलमट्टी के तहत पानी के उपयोग से संबंधित है। पैराग्राफ में

66 (iii), वादी ने दावा किया है, जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा अनुच्छेद 12.85 के माध्यम से लिखित बयान में अस्वीकार और समझाया गया है और कर्नाटक राज्य ने आगे कहा है कि अलमट्टी में पूरा उपयोग उसके आवंटित हिस्से के भीतर है और इसके तहत आंध्र प्रदेश राज्य को कोई नुकसान नहीं हुआ है। चूंकि, हम पहले ही यह मान चुके हैं कि न्यायाधिकरण के निर्णय के तहत, आवंटन परियोजना-वार नहीं बल्कि निगमित था, भले ही यह माना जाए कि अलमट्टी के तहत उपयोग 91 टी. एम. सी. के आदेश का होगा, जैसा कि दावा किया गया है, यह न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके अलावा, हमारे पास कोई सकारात्मक सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अलमट्टी के तहत उपयोग 91 टी. एम. सी. के क्रम का होगा। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

दलीलों के दौरान श्री गंगुली, विद्वान वरिष्ठ वकील

आंध्र प्रदेश राज्य ने एक तर्क उठाया था कि कर्नाटक राज्य इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले किसी भी आदेश को विफल करने के लिए प्रतिवादी नं. 1 आई. डी. 1 की ऊंचाई पर अलमट्टी में बांध के निर्माण से पहले ही एक स्वायत्त निकाय, जिसे कृष्ण भाग्य जल निगम लिमिटेड (के. बी. जे. एन. एल.) कहा जाता है, को शामिल कर लिया गया है और राज्य सरकार ने उपरोक्त निगम के साथ अलमट्टी में बांध के निर्माण से संबंधित सभी शक्तियों से खुद को अलग कर लिया है और यह योजनाबद्ध रूप से बनाया गया है ताकि निषेधाज्ञा के लिए कोई भी आदेश या डिक्री बाध्यकारी न हो। चूंकि यह तर्क सुनवाई के चरण की ओर बढ़ा दिया गया था और इस संबंध में वाद में कोई दावा नहीं था, और न ही न्यायालय द्वारा कोई मुद्दा उठाया गया था, इसलिए कर्नाटक राज्य को के. बी. जे. एन. एल. के गठन के संबंध में सही स्थिति का संकेत देते हुए एक हलफनामा दायर करने और वादी राज्य के मन में आशंका या आशंका को दूर करने की अनुमति दी गई थी। कर्नाटक सरकार के सिंचाई विभाग के सचिव, जिन्हें के. बी. जे. एन. एल. के निदेशक के रूप में भी नामित किया गया है, द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था, उक्त नामांकन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज के अनुच्छेद 147 (सी) के तहत किया गया था। इसे कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

बी. ए. पी. राज्य [मजमुदार, जे.] 403

उक्त शपथ पत्र कि धन जुटाने और प्रदान करने की सुविधा के लिए

2000 ईस्वी तक ऊपरी कृष्णा परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करने के एकमात्र विचार के साथ सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन के साथ के. बी. जे. एन. एल. का गठन किया गया है। यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना 6 मई, 1994 के अपने निर्णय द्वारा कर्नाटक राज्य में मंत्रिमंडल की मंजूरी से की गई है और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कंपनी के अध्यक्ष हैं जबकि उप मुख्यमंत्री निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष हैं। ज्ञापन के सभी अभिदाता सरकारी अधिकारी हैं और इसे एक सरकारी कंपनी घोषित किया गया है। एसोसिएशन के लेखों का ज्ञापन है

प्रदर्शित पी. ए. पी. 210 के रूप में प्रदर्शित किया गया। हलफनामे में विवरण दिया गया है कि कैसे राज्य सरकार के. बी. जे. एन. एल. पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और उक्त हलफनामे को पढ़ने पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि वादी राज्य की आशंका पूरी तरह से गलत है और इसमें कोई सार नहीं है। विभिन्न मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों को देखते हुए, अदालत के लिए स्थायी अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत देना संभव नहीं है, जहां तक अलमट्टी में बांध के निर्माण के साथ-साथ मांगी गई राहत का संबंध है।

पैराग्राफ (बी) से (के) के लिए। लेकिन साथ ही हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि केंद्रीय सरकार के उपयुक्त प्राधिकरण और कानून के तहत आवश्यक किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त करने के अधीन, अलमट्टी में बांध की ऊंचाई को 519.6 मीटर तक बढ़ाने के लिए कोई रोक नहीं है। अलमट्टी में ऊंचाई को 524.256 मीटर तक बढ़ाने के सवाल पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से विचार किया जा सकता है, जब तीन नदी तटीय राज्यों में से किसी एक द्वारा संपर्क किया जाता है और ऐसा न्यायाधिकरण भी कर सकता है।

महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र के भीतर जलमग्न होने की आशंका के प्रश्न पर जाएं और उस पर अपना निर्णय दें, यदि अलमट्टी में बांध की ऊंचाई को 524.256 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। न्यायाधिकरण को कृष्णा नदी बेसिन में पानी के पुनः आवंटन के सवाल पर भी विचार करने का अधिकार होगा, यदि राज्यों द्वारा देखने की बेहतर विधि के आधार पर नए आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं।

तदनुसार मुकदमे का निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एस. बी. मजमुदार, जे. आई. को मसौदे को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

भाई जी. बी. पटनायक, जे. द्वारा उपरोक्त मुकदमे में तैयार किया गया निर्णय, I

उसी के साथ सम्मानपूर्वक सहमत हैं। हालांकि, दो महत्वपूर्ण मुद्दों के महत्व को देखते हुए, मुद्दा संख्या 1 2 और 9 (ए), (बी) और (सी), मैंने इसे [2000] 3 एस. सी. आर. के लिए उपयुक्त माना है।

404

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त निर्णय में तर्क के पूरक के रूप में इन मुद्दों पर मेरी सहमति वाली टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

अंक संख्या 2:

क्या यह माननीय अदालत का अधिकार क्षेत्र इस मुकदमे पर विचार करने और मुकदमा चलाने के लिए है?

(एमएएच)। अनुच्छेद 131 निम्नानुसार प्रदान करता है:

" 131. के अधीन उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता

इस संविधान के प्रावधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय,

किसी अन्य न्यायालय का बहिष्करण, किसी भी मामले में मूल अधिकार क्षेत्र है

विवाद -

((a) XXX

XXX

XXX

(ख) XXX

XXX

XXX

(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच।

यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न शामिल है (क्या

कानून या तथ्य) जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार हो।

निर्भर करता है:

XXX

XXX

XXX

हम प्रोविसो से संबंधित नहीं हैं जो संधियों से संबंधित है और

संविधान के प्रारंभ से पहले किए गए या निष्पादित किए गए समझौते। चूंकि अनुच्छेद 131 स्वयं संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है, इसलिए हमें अनुच्छेद 262 का पालन करना होगा जो जल से संबंधित विवादों से संबंधित है। इसके उप-अनुच्छेद (1) में प्रावधान किया गया है कि:

" 262. अंतर-राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय

या नदी घाटियाँ। - (1) संसद कानून द्वारा प्रावधान कर सकती है -

उपयोग के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का निर्णय
किसी अंतर-राज्यीय नदी के जल का वितरण या नियंत्रण या
नदी घाटी "।

इसके उप-अनुच्छेद (2) में कहा गया है:

" (2) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, संसद

कानून द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही
कोई अन्य न्यायालय

ऐसे किसी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा।

खंड (1) में उल्लेख किया गया है। ”

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [मजमुदार, जे.] 405

यह दोनों पक्षों के बीच विवाद में नहीं है कि अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 (जिसे
इसके बाद 'विवाद अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) संविधान के अनुच्छेद 262 के
तहत पारित एक कानून है। यह समान रूप से विवाद में नहीं है कि इसकी धारा 11 जल विवादों के
संबंध में इस न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करती है।

न्यायाधिकरण को संदर्भित किया गया। इसलिए, यह देखना होगा कि क्या आंध्र प्रदेश राज्य
ने वादी के रूप में, इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 131 को लागू करने के बाद,
वास्तव में, 'जल विवाद' उठाया है जो विवाद अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस न्यायालय
के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर देगा।

अनुच्छेद 262 उप-अनुच्छेद, (2)। दूसरे शब्दों में, यदि वास्तव में, वादी अपने और अन्य
प्रतिस्पर्धी राज्यों, अर्थात् कर्नाटक राज्य या महाराष्ट्र राज्य के बीच किसी भी 'जल विवाद' का
न्यायनिर्णयन चाहता है, जो कृष्णा बेसिन में स्थित ऊपरी नदी तटीय राज्य हैं, जिसके माध्यम से
कृष्णा नदी, जो कि एक अंतर-राज्यीय नदी है, बहती है। विवाद अधिनियम द्वारा 'जल विवाद'
शब्द को धारा 2 (सी) के अनुसार निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" " जल विवाद का अर्थ है दोनों के बीच कोई विवाद या अंतर।

अधिक राज्य सरकारें -

(1) किसी भी क्षेत्र के जल का उपयोग, वितरण या नियंत्रण

राज्य नदी या नदी घाटी; या

((ख) ऐसे जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण या ऐसे समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी समझौते की शर्तों की व्याख्या; या

((ग) निषेध के उल्लंघन में किसी भी जल-दर का अधिरोपण।

धारा 7 में निहित है।

संवैधानिक योजना की उपरोक्त मुख्य विशेषताओं और विवाद अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान वाद में आंध्र प्रदेश राज्य के वाद की ओर रुख कर सकते हैं। इस न्यायालय की अधिकारिता के प्रश्न का निर्णय करते समय, वाद-प्रतिवाद करने वाले पर वाद में किए गए कथनों को ध्यान में रखना होगा। शिकायत के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि:

" कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा अपना निर्णय देने के बाद, पहले आई. डी. 2 पर और आई. डी. 1 पर एक और निर्णय देने के बाद, वादी समझ गया कि सभी नदी तटीय राज्य, जो भारतीय गणराज्य संघ की संवैधानिक इकाइयाँ हैं, न केवल उक्त निर्णयों को स्वीकार करेंगे, बल्कि उन्हें अक्षर और भावना में पूरा प्रभाव देंगे।

जैसा कि [2000] 3 एस. सी. आर. द्वारा और उसके तहत स्थापित संवैधानिक सरकारों से अपेक्षित है।

406

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का संविधान। वादी को सभी पक्षों से उम्मीद थी

राज्य उन परियोजनाओं के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे जो वे शुरू कर सकते हैं

न्यायाधिकरण और यह कि उनका कार्यान्वयन किसी भी तरह से नहीं होगा, अन्य नदी तटीय राज्यों के अधिकारों को प्रभावित करता है। लेकिन हाल ही में

अतीत में, वादी के पूर्ण आश्चर्य के लिए, यह पता चला है कि

कर्नाटक, अक्षर और भावना के अनुसार कार्य करने से बहुत दूर है

के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णयों में से, अंतर की शर्तों का घोर उल्लंघन किया है कई परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में वादी की जानकारी इसके द्वारा अनधिकृत रूप से किया गया, लेकिन महत्वपूर्ण सूचना को भी दबा दिया गया यहां तक कि प्रतिवादी संख्या 2 भारत संघ से भी इसकी मांग करते हुए इन परियोजनाओं को मंजूरी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादी नं. 1 मांग करते हुए केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को भी गुमराह किया इसकी परियोजनाओं के लिए वित्तीय और अन्य अनुमोदन। वादी, एक दृष्टिकोण के साथ

पक्ष राज्यों के बीच मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, अपील की गई, नहीं केवल प्रतिवादी संख्या 1 को इस तरह के अवैध निष्पादन से बचने के लिए

परियोजनाएँ, लेकिन केंद्र सरकार को भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्नाटक की शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णय और इसका अनुचित लाभ नहीं उठाते हैं

अंतर-राज्यीय नदी के संबंध में एक ऊपरी नदी तटीय राज्य के रूप में स्थापित कृष्णा। हालाँकि, इस तरह के सभी अनुनय और वार्ताएँ विफल रही। द.

इस प्रकार वादी इस माननीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए विवश है जनहित में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत अधिकार क्षेत्र

और वादी के निवासियों के हित में-राज्य की मांग

इस माननीय न्यायालय द्वारा उनके हितों की सुरक्षा के लिए तत्काल राहत।

नदी तटीय राज्यों के बीच पहले के जल विवाद के इतिहास का उल्लेख करने के बाद, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा विवाद अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (इसके बाद 'के. डब्ल्यू. डी. टी.' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्णय दिया गया था और उक्त न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के सार का पाठ करने के बाद, उस मुकदमे में व्यक्त की गई शिकायतें उच्च हैं-अभियोग के पैराग्राफ 65 से 68 में शीर्षक 'के. डब्ल्यू. डी. टी. के फैसले का उल्लंघन' के तहत प्रकाश डाला गया है।

कर्नाटक-प्रतिवादी संख्या 1, वाद में और इन शिकायतों के आलोक में ही वाद के पैराग्राफ 75 के बाद प्रार्थना और राहत दी गई है। जिन मुख्य प्रार्थनाओं के आधार पर राहत मांगी जाती है, वे हैं प्रार्थना (ए), (सी), (डी) और (एफ) जो नीचे दी गई हैं:

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [मजमुदार, जे.] 407

" (क) घोषणा करें कि कृष्णा जल विवाद जनजाति की रिपोर्ट/निर्णय दिनांक 24.12.1973 और अगली रिपोर्ट/निर्णय दिनांक 27.5.1976 एन. ए. एल. (के. डब्ल्यू. डी. टी.) अपनी संपूर्णता में तीन रिपेरियन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पर बाध्यकारी हैं और साथ ही

भारत संघ।

(ख) XXX

XXX

XXX

(ग) घोषणा करें कि पक्षकार राज्य न्यायाधिकरण के समक्ष संबंधित पक्षकार राज्यों की संबंधित परियोजनाओं के लिए के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णयों द्वारा आवंटित या अनुमत पानी की मात्रा से अधिक का उपयोग करने के हकदार नहीं हैं और ऐसी प्रत्येक परियोजना के संबंध में ऐसे प्रत्येक राज्य द्वारा पानी के भंडारण या उपयोग में कोई भी बदलाव केवल उनकी पूर्व सहमति या सहमति से ही हो सकता है।

अन्य नदी तटीय राज्य;

(घ) घोषणा करें कि कर्नाटक राज्य द्वारा निष्पादित और/या निष्पादन की प्रक्रिया में सभी परियोजनाएं जो कर्नाटक राज्य के निर्णयों के साथ पुष्टि और टकराव में नहीं हैं या उनका उल्लंघन नहीं करती हैं।
केडब्ल्यूडीटी, अवैध और अनधिकृत के रूप में।

(ई) XXX

XXX

XXX

(च) घोषणा करें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य अंतर-राज्यीय नदी कृष्णा के पानी के भंडारण, नियंत्रण और उपयोग के संबंध में उन योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में किसी भी अधिकार का दावा करने के हकदार नहीं होंगे जो कर्नाटक सरकार के निर्णय द्वारा अधिकृत नहीं हैं।

केडब्ल्यूडीटी।

XXX "।

XXX

XXX

वाद में उपरोक्त कथन-वादी की शिकायतों को उजागर करते हुए-आंध्र प्रदेश राज्य जब विचार के लिए रखी गई प्रार्थनाओं और इस प्रकार दावा की गई राहतों के आलोक में पढ़ा जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं रहता है कि पूरा मुकदमा इस आधार पर आधारित है कि प्रतिवादी संख्या 1-कर्नाटक राज्य ने न्यायाधिकरण के बाध्यकारी निर्णय का उल्लंघन किया है जो योजना "ए" से संबंधित है जिसे केंद्र सरकार द्वारा विवाद अधिनियम की धारा 6 के तहत विधिवत अधिसूचित किया गया था। यह वह वाद है जिसका पहले प्रतिवादी-कर्नाटक राज्य द्वारा अपना लिखित बयान दाखिल करके विरोध करने की मांग की गई है। रोशनी में।

मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज्यों की इन दलीलों के लिए, मुकदमे में मुद्दे तैयार किए जाते हैं।

[2000] 3

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वादी राज्य की शिकायतों पर प्रकाश डालते हुए मुद्दे संख्या।

9 (क), (ख) और (ग), 10 और 20, जो निम्नानुसार हैं:

" 1 . क्या कर्नाटक राज्य ने बाध्यकारी निर्णय का उल्लंघन किया है

अनुच्छेद 66, 68 और 69 में उल्लिखित परियोजनाओं को निष्पादित करके शिकायत? (A.P./KAR)।

क्या वादी यह साबित करता है कि कृष्णा जल का आवंटन

3 .

के. डब्ल्यू. डी. टी. द्वारा अपने अंतिम आदेश में परियोजनाओं के लिए विशिष्ट हैं और नहीं

एनब्लॉक जैसा कि प्रतिवादी द्वारा तर्क दिया गया है? (एमएएच)।

5 .

क्या वादी इस घोषणा का हकदार है कि सभी

निष्पादित परियोजनाएं और/या जो निष्पादन की प्रक्रिया में हैं

कर्नाटक राज्य द्वारा, और इसके साथ या इसके अनुरूप नहीं

के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णयों के साथ टकराव अवैध है और

अनाधिकृत? (एपी)।

(क) क्या एक एफ. आर. एल. के साथ अलमट्टी बांध का निर्माण

9 .

524.256 एम. निष्पादित अन्य सभी परियोजनाओं के साथ, जो प्रगति पर हैं

और कर्नाटक द्वारा विचार किए जाने से यह अधिक उपयोग करने में सक्षम होगा।

न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित पानी से अधिक? (एपी)।

(ख) क्या कर्नाटक को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है।

अन्य नदी तटों की सहमति के बिना इस तरह के बांध का निर्माण

राज्य, और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना?

(एपी)।

(ग) क्या कर्नाटक को भंडारण बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।

आर. एल. 509.16 मीटर से ऊपर अलमट्टी बांध का स्तर। संभावना को देखते हुए

महाराष्ट्र में क्षेत्रों का जलमग्न होना।

10. क्या वादी यह साबित करता है कि जलाशय और सिंचाई

वादी के पैराग्राफ 68 में कथित नहरों का आकार बड़ा है।

यदि ऐसा है, तो क्या वे न्यायाधिकरण के निर्णय के विपरीत हैं? (एपी)।

20. क्या कर्नाटक राज्य ने डेडव्यूडीटी पुरस्कार का उल्लंघन किया है

उप-बेसिन में कई नई परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए

के-6, के-8 और के-9 के रूप में जिसके संबंध में मात्रा में प्रतिबंध हैं

उपयोग के अंतिम निर्णय में लगाया गया है

न्यायाधिकरण? (एपी)। ”

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [मजमुदार, जे.] 409

राज्य की शिकायत की उपरोक्त मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए

आंध्र प्रदेश, उसमें उठाए गए विवादों की प्रकृति, दावा किए गए राहत और अदालत के विचार के लिए आने वाले मुद्दे, प्रतिवादियों, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य की इस दलील से सहमत होना मुश्किल है कि वादी का मामला संविधान के अनुच्छेद 131 के अग्र-कोण में नहीं आता है।

संविधान। यह स्पष्ट है कि वादी-आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा उठाए गए विवाद बाध्यकारी के कथित गैर-कार्यान्वयन से संबंधित हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा के. डब्ल्यू. डी. टी. का पुरस्कार। इसका ताजे पानी के विवाद को उठाने से कोई लेना-देना नहीं है। वादी राज्य के अनुसार, वादी और प्रतिवादी संख्या 1 राज्य या उस मामले के लिए प्रतिवादी संख्या 3 राज्य के बीच पहले जो भी जल विवाद था, उस पर पहले से ही विवाद अधिनियम की धारा 4 के तहत न्यायाधिकरण के संविधान द्वारा निर्णय लिया गया था और कौन सा निर्णय उसकी धारा 6 के तहत विधिवत प्रकाशित किया गया था। योजना "ए"। वादी-राज्य की शिकायत यह है कि हालांकि निर्णय ऊपरी नदी तटीय राज्यों पर बाध्यकारी है, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 और 3, संबंधित राज्यों की कार्यकारी कार्यवाई न्यायाधिकरण के बाध्यकारी निर्णयों का उल्लंघन और उल्लंघन है। यह स्पष्ट रूप से एक सवाल उठाता है कि

पहले से ही निर्णय लिए गए जल विवाद का निष्पादन और कार्यान्वयन। एक बार जब वह निष्कर्ष निकल जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 262 गलत होगा और केवल अनुच्छेद

131 प्रतिवादी राज्यों के खिलाफ विवादित राज्य द्वारा लागू किए जाने के लिए लागू रहेगा क्योंकि यह निश्चित रूप से न्यायाधिकरण के बाध्यकारी निर्णय के निष्पादन और कार्यान्वयन के संबंध में विवाद पैदा करेगा और इसलिए, इस मुद्दे पर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। तदनुसार, मुद्दा संख्या 2 का जवाब वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ देना होगा। मुद्दा संख्या 9 (ए), (बी) और (सी):

जहाँ तक इन मुद्दों का संबंध है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वादी राज्य आंध्र प्रदेश का मुख्य तर्क यह है कि

योजना "ए" से संबंधित के. डब्ल्यू. डी. टी. का निर्णय, न्यायाधिकरण ने कृष्णा नदी बेसिन में स्थित प्रतिस्पर्धी राज्यों की प्रत्येक परियोजना के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा के परियोजना-वार आवंटन के सवाल पर गौर किया है, जहां तक कि वे प्रत्येक प्रतिस्पर्धी नदी तटीय क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर हैं।

राज्यों। तथापि, जब हम न्यायाधिकरण (Exh.PK-1) के अधिनिर्णय और विवाद अधिनियम (Exh.PK-II) की धारा 5 (3) के तहत न्यायाधिकरण के आगे के अधिनिर्णय की ओर मुड़ते हैं, जो अंततः प्रदर्शनी पी. के.-2 के पृष्ठ 102 और 114 पर राजपत्रित हो गया, तो हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा कहीं भी यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया है कि पानी की कुल मात्रा में से, अर्थात्, 75 प्रतिशत निर्भरता [2000] 3 एस. सी. आर. के आधार पर प्रति जल वर्ष 2096 टी. एम. सी.।

410

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपयोग के लिए पानी का कोई भी निश्चित कोटा ऊपरी कृष्णा परियोजना (जिसे इसके बाद 'यू. के. पी.' के रूप में संदर्भित किया गया है) के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें तीन बांध शामिल थे, अर्थात् हिप्परगी वीर, अलमट्टी बांध और नारायणपुर बांध। विवाद अधिनियम की धारा 6 के तहत राजपत्रित न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के खंड 3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि "न्यायाधिकरण एतद्वारा निर्धारित करता है कि इस मामले के उद्देश्य के लिए, कृष्णा नदी का 75 प्रतिशत विश्वसनीय प्रवाह

विजयवाड़ा 2,060 टी. एम. सी. "है और यह पूरी मात्रा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार वितरण के लिए उपलब्ध कुल मात्रा में से, खंड V

के अनुसार महाराष्ट्र राज्य को जल वर्ष 1982-83 तक किसी भी जल वर्ष में 560 टी. एम. सी. से अधिक और भविष्य में उसमें निर्धारित अतिरिक्त मात्रा का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया गया है।

इसी तरह, कर्नाटक राज्य को आदेश दिया गया है कि वह किसी भी जल वर्ष में 700 टी. एम. सी. से अधिक का उपयोग शुरू करने के लिए, जल वर्ष 1982-83 तक नहीं करेगा और उसके बाद उसमें निर्धारित मात्रा की अनुमति दी जाएगी। जबकि वादी-आंध्र प्रदेश राज्य को किसी भी जल वर्ष में कृष्णा नदी में बहने वाले शेष पानी का उपयोग करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन इस तरह यह किसी भी जल वर्ष में उपयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करेगा और न ही यह माना जाएगा कि किसी भी जल वर्ष में कृष्णा नदी का 800 टी. एम. सी. से अधिक का पानी जल वर्ष 1982-83 तक आवंटित किया गया है और बाद के जल वर्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिशत प्रदान किया गया है। जब इस अंतिम आदेश को न्यायाधिकरण की रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाता है जिसमें खंड 1 और 2, Exh.PK-I और Exh.PK-II शामिल होते हैं, तो वादी द्वारा तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरण ने प्रत्येक परियोजना, विशेष रूप से यू. के. पी. के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की निश्चित मात्रा का निर्णय दिया है। यह

न्यायाधिकरण योजना "ए" से संबंधित है जिसमें प्रत्येक राज्य को आवंटित पानी में से कुछ परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है जिनके लिए पानी की दी गई मात्रा आवंटित की गई है। अब उन परियोजनाओं की पूरी सूची में जहां खंड IX में उल्लिखित पानी के आवंटन को परियोजना-वार बनाया गया है, यू. के. पी. स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि भले ही कर्नाटक राज्य के लिए प्रत्येक जल वर्ष के लिए पानी के भरोसेमंद प्रवाह का आवंटन एक सीमा के साथ किया गया है जैसा कि उपरोक्त निर्णय के खंड V में पाया गया है और भले ही न्यायाधिकरण ने इस संबंध में यू. के. पी. को संदर्भित कुल पानी की मात्रा के अंतिम आवंटन के परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर कृष्णा नदी बेसिन में स्थित यू. के. पी. में संग्रहीत और उपयोग किए जाने वाले पानी की किसी भी निर्धारित मात्रा का संकेत नहीं दिया है। इसलिए, वादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है-आंध्र राज्य यह दर्शाता है कि जहां तक यू. के. पी. का संबंध है, उपलब्ध जल के किसी भी परियोजना-वार आवंटन पर न्यायाधिकरण द्वारा योजना "ए" तैयार करते समय निर्णय लिया जाता है। एक बार जब यह निष्कर्ष निकल जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्नाटक और ओआरएस का अलमट्टी राज्य किस ऊंचाई पर है।

बांध का निर्माण किया जाना चाहिए, जो न्यायाधिकरण की जांच के दायरे में नहीं था और न ही न्यायाधिकरण द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय दिया गया था जिसे आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुकदमे में इस आधार पर चुनौती का विषय बनाया जा सकता है कि इस संबंध में न्यायाधिकरण के किसी भी स्पष्ट निर्देश का प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है।

भले ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, लेकिन एक विवादास्पद सवाल बना रहता है कि क्या 524.256 के एफआरएल के साथ अलमट्टी बांध का निर्माण अंततः परिणाम देगा। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित पानी से अधिक पानी के उपयोग में। यह शिकायत, जिसे वादी-आंध्र प्रदेश राज्य के कहने पर मुद्दा संख्या 9 (ए) का विषय बनाया गया है, का निर्णय के उल्लंघन के बारे में उक्त राज्य की शिकायत के साथ स्पष्ट संबंध है।

न्यायाधिकरण। इस प्रकार, भले ही यह अभिनिर्धारित किया गया हो कि योजना "ए" के संबंध में न्यायाधिकरण के निर्णय में स्पष्ट रूप से किसी भी अनुमेय ऊंचाई का उल्लेख नहीं किया गया है, जिस पर पानी की उचित भंडारण क्षमता के साथ अलमट्टी बांध का निर्माण किया जा सकता है, यदि यह साक्ष्य पर अभिनिर्धारित किया जाता है कि 524.256 एफआरएल की ऊंचाई का परिणाम होगा न्यायाधिकरण के निर्णय के खंड V के अनुसार प्रति वर्ष अनुमति से अधिक पानी का उपयोग, तब प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा खंड V के निषेधाज्ञा के उल्लंघन का प्रश्न स्पष्ट रूप से विचार के लिए आएगा। इसी दृष्टि से हमें वादी-राज्य की शिकायत पर विचार करना होगा।

इस प्रश्न का निर्णय लेने के लिए हम उपयोगी रूप से यू. के. पी. चरण-II बहुउद्देशीय परियोजना-प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हैं।

न्यायाधिकरण (Exh.PAP-46)। उक्त रिपोर्ट में, हम परियोजना की क्रम संख्या 2 मुख्य विशेषताओं को पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका उल्लेख यू. के. पी. चरण-II मल्टी के रूप में किया गया है।

परियोजना परियोजना, सिंचाई और बिजली। परिच्छेद 2.3 में। 1 हम पाते हैं कि चरण-II योजनाओं के लिए उल्लिखित सिंचाई और संवर्धित कमान क्षेत्र 1,97,120 हेक्टेयर दिखाया गया है। 2. 3 पर बिजली के साथ काम करते हुए। 2, हम पाते हैं कि कुल वार्षिक ऊर्जा 67.2 करोड़ यूनिट उत्पन्न होती है। उक्त रिपोर्ट पी. ए. पी. 46 का अध्याय IV जल विज्ञान से संबंधित है जिसमें अलमट्टी बांध पर जल बजट गेट की ऊंचाई और पश्च जल प्रभाव के लिए पी. एम. एफ. के लिए बाढ़ मार्ग अध्ययन शामिल हैं। पैरा 4.4 में। 3 आई. आई. एस. सी. द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार यह उल्लेख किया गया है।, अलमट्टी जलाशय में 173 टी. एम. सी. पानी का उपयोग करने के लिए न्यूनतम एफ. आर. एल. की आवश्यकता है।

अलमट्टी बांध, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, कर्नाटक सरकार ने ईएल 524.256 मीटर पर एफआरएल पर जल स्तर बनाए रखने का निर्णय लिया है। मानसून के महीनों के दौरान EL 519.60 m से ऊपर के भंडारण का उपयोग करने के लिए। केवल बिजली उत्पादन के लिए। यह पक्षकारों के बीच विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 [2000] 3 एस. सी. आर. के अनुसार।

412

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य, यह सिंचाई के उद्देश्य से अलमट्टी बांध पर 173 टी. एम. सी. पानी का भंडारण करना चाहता है। यदि ऐसा है तो उक्त जल अनुच्छेद 2.3 के अनुसार सांस्कृतिक कमान क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है। 1 जैसा कि पैराग्राफ 2.3 से देखा गया है, इसका उल्लेख पहले किया गया है और यह 67.2 करोड़ यूनिट बिजली भी पैदा कर सकता है। 2 . जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। हम प्रो. के एक शपथ पत्र का उल्लेख करते हैं। डी. के. सुब्रमण्यन ने वादी-आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर संकलन II पर पृष्ठ 109 पर आंध्र प्रदेश राज्य में शक्ति पर कर्नाटक में अलमट्टी बांध के एफ. आर. एल. को बढ़ाने के प्रभाव पर और प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा स्वयं अपने मामले के समर्थन में किस हलफनामे पर भरोसा किया गया है। उक्त शपथपत्र पढ़ने में दिलचस्प लगता है। पैरा 38 पर संकलन II के पृष्ठ 110 पर, प्रतिवादी संख्या 1 राज्य मामले के समर्थन में आश्रित द्वारा निम्नलिखित प्रासंगिक कथन किए गए हैं:

" यदि अलमट्टी बांध का एफआरएल 519.60 मीटर तक सीमित है।, तब सत्ता

उत्पादन केवल 250 मेगावाट होगा जिससे ऊर्जा उत्पादन होगा लगभग 672 मिलियन किलोवाट घंटे। यदि एफ. आर. एल. को 524.256 तक बढ़ाया जाता है।

एम. तब चार झरनों को स्थापित करना संभव और व्यवहार्य दोनों है बढ़ रहे बिजली संयंत्रों के अलावा नारायणपुर के निचले हिस्से में भी

अलमट्टी बिजली संयंत्र की क्षमता "।

एक बार प्रतिवादी संख्या 1 के मामले के समर्थन में इन कथनों को पढ़ा जाता है।

पहले उल्लिखित पी. ए. पी.-46 की रोशनी से यह स्पष्ट हो जाता है कि 67.2 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करने के लिए बांध की ऊंचाई 519.60 मीटर हो सकती है। यह प्रतिवादी नंबर 1 राज्य के उद्देश्य को पूरा करेगा, दोनों के लिए 1.97.120 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र की सिंचाई के साथ-साथ उत्पादन के लिए

बिजली की उपरोक्त इकाइयाँ और बहुत अच्छी तरह से अलमट्टी परियोजना को बहुउद्देश्यीय परियोजना के रूप में मानेगी।

हम इस संबंध में प्रो. के एक शपथ पत्र का भी उपयोग कर सकते हैं।

कर्नाटक राज्य की ओर से राम प्रसाद-प्रतिवादी संख्या 1। यह प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा अपने मामले के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है। उक्त शपथ पत्र आंध्र प्रदेश राज्य की संकलन II फाइल के पृष्ठ 103 पर है। उक्त शपथपत्र का पैराग्राफ 4 भी एक दिलचस्प पठन बनाता है। वही नीचे पढ़ा गया है:

" ऊपरी कृष्णा परियोजना (यू. के. पी.) में दो जलाशय हैं, जिनमें से एक में

नारायणपुर में अलमट्टी और दूसरे में 173 टी. एम. सी. पानी का उपयोग किया जाएगा।

सिंचाई (जलाशयों से वाष्पीकरण सहित)। मामले में

कर्नाटक सरकार, भारतीय विज्ञान संस्थान (आई. आई. एस. सी.)

1996 में एक अध्ययन किया गया (पैरा 12 में उल्लिखित) जिसमें I TATE OF KARNATAKA AND ORS।

वी. ए. पी. राज्य (जे. जे.) 413

उन्होंने दो तकनीकी सलाहकारों में से एक के रूप में भाग लिया, जिसने निष्कर्ष निकाला कि अलमट्टी में बांध का पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) 173 टी. एम. सी. का उपयोग करेगा। 50 साल के लिए अनुमति देने के बाद जलाशयों का अवसादन आर. एल. 519.6 मीटर होगा। कर्नाटक सरकार ने बांध के एफआरएल को आरएल 524.256 मीटर तक बढ़ाने की योजना बनाई है। आर. एल. 519.6 एम. से उपलब्ध अतिरिक्त भंडारण के साथ निकट भविष्य में बिजली उत्पन्न करने के लिए। आरएल 524.256 एम। परियोजना के तहत कुल उपयोग को 173 टी. एम. सी. तक सीमित करना। आई. आई. एस. सी. ने यू. के. पी. जलाशयों के संचालन के लिए 524.256 मीटर पर अलमट्टी एफ. आर. एल. के साथ एक "नियम वक्र" विकसित किया।

ताकि बिजली उत्पादन को अधिकतम किया जा सके, साथ ही उपयोग को 173 टी. एम. सी. तक सीमित किया जा सके। एफ. आर. एल. में वृद्धि और नियम वक्र के अनुसार जलाशय के संचालन से नीचे की ओर प्रवाह का स्वरूप बदल जाता है, यानी आंध्र प्रदेश (ए. पी.) में प्रवाह जो इन पानी का उपयोग सिंचाई के साथ-साथ जुराला, श्रीशैलम, नागार्जुनसागर और प्रकाशम बैराज में अपनी परियोजनाओं में बिजली उत्पादन के लिए करता है। मुख्य रूप से, यह परिवर्तन अगस्त के महीने में आंध्र प्रदेश में प्रवाह में कमी का रूप लेता है, जो अल्मट्टी में बड़े हुए अवरोध के कारण होता है, और बाद के महीनों में जब्त किए गए पानी को छोड़ने के कारण प्रवाह में वृद्धि होती है। यह परिवर्तन आंध्र प्रदेश में सिंचाई के प्रदर्शन में सुधार करता है, जैसा कि बाद में जलाशय के काम करने से स्पष्ट होगा।

मेज "।

वे श्री एम. कृष्णप्पा के एक अन्य हलफनामे का भी उल्लेख कर सकते हैं "अल्मट्टी में बांध और यू. के. पी. के तहत नहरों पर" जिस पर प्रतिवादी राज्य कर्नाटक ने भरोसा किया था। उक्त हलफनामा अल्मट्टी बांध से संबंधित उपरोक्त संधि II के पृष्ठ 106 पर है। प्रतिनिधि ने नीचे कहा है:

" यू. के. पी. के तहत अल्मट्टी बांध मुख्य भंडारण है। अल्मट्टी बांध का एफआरएल आरएल 1720 फीट पर तय किया गया है। (524.256 एम.)। यह योजना के शुरुआती दिनों के दौरान किया गया था, यानी के. डब्ल्यू. डी. टी. के गठन से पहले भी। सिंचाई के लिए 173 टी. एम. सी. पानी के उपयोग के लिए,

घरेलू उपयोग और बिजली उत्पादन, अल्मट्टी जलाशय में 123.25 टी. एम. सी. का भंडारण, 519.60 मीटर के एफ. आर. एल. के साथ। आवश्यक है। हालाँकि, 524.256 m का FRL। सिंचाई, घरेलू उद्देश्यों के लिए 227.10 टी. एम. सी. के सकल भंडारण के साथ, 302 टी. एम. सी. के अंतिम उपयोग की आवश्यकता है।

और बिजली उत्पादन। इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार, बांध के आकार की प्रासंगिकता, अंतिम उपयोग के लिए, 302 टी. एम. सी. है। यूकेपी के तहत। इस संबंध में, मैंने सिंचाई विभाग और परियोजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक तकनीकी अभिलेखों का अध्ययन किया है।

[

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेषज्ञों के इन हलफनामों पर प्रतिवादी संख्या 1 ने खुद भरोसा किया है

दिखाएँ कि सिंचाई और घरेलू उपयोग और बिजली उत्पादन के लिए 173 टी. एम. सी. पानी के उपयोग के लिए एफ. आर. एल. 519.60 पर्याप्त होगा। इस संबंध में यह ध्यान में रखा जा सकता है कि न्यायाधिकरण के निर्णय के तहत कर्नाटक राज्य द्वारा यू. के. पी. के लिए पानी की आवश्यकता का आकलन न्यायाधिकरण द्वारा किया गया था।

जहाँ तक हिप्परगी बांध परियोजना का संबंध है, गणना में त्रुटि के कारण यू. के. पी. में अलमट्टी बांध पर 155 टी. एम. सी. और 5 और टी. एम. सी. पानी जोड़ा गया था। वे कुल 160 टी. एम. सी. तक हैं और यहाँ तक कि इसके अलावा, के अनुसार

प्रतिवादी संख्या 1 राज्य को सिंचाई, घरेलू उपयोग और बिजली उत्पादन के लिए टी. एम. सी. पानी के लिए अलमट्टी बांध में भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी। हम न्यायाधिकरण के निर्णय को भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसा कि पी. के. I और II से देखा गया है, कि अलमट्टी बांध को अंततः नारायणपुर परियोजना की निचली धारा में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के लिए एक भंडारण जलाशय के रूप में माना जा रहा था। एफ. आर. एल. 519.60 पर अलमट्टी जलाशय की ऊँचाई भी विशेषज्ञों द्वारा वर्तमान उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गई है, जिनके हलफनामों पर प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा ही भरोसा किया गया है, जैसा कि पहले देखा गया है।

इस संबंध में हम किए गए प्रासंगिक कथनों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

पक्षकारों और केंद्रीय जल आयोग के बीच आदान-प्रदान किए गए संवाददाताओं के उद्धरण के आधार पर वाद में। अभियोग के पैरा 28 में

केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा वादी राज्य को संबोधित अपने 23 अक्टूबर, 1986 के पत्र द्वारा दिनांकित एक संचार का उल्लेख किया गया है। उक्त पत्राचार, अन्य बातों के अलावा, निम्नानुसार कहा गया है:

" (1) के. डब्ल्यू. डी. टी. ने कुल यू. के. पी. के तहत उपयोग की अनुमति दी है

160 परियोजना के पहले चरण प्लस 52 के तहत टी. एम. सी. उपयोग की अनुमति है।

दूसरे चरण के तहत टी. एम. सी. का उपयोग और हिप्परगी के तहत 5 टी. एम. सी. का उपयोग

परियोजना)।

(2) यू. के. पी. चरण-I अप्रैल में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया 1978 , जलाशय सहित 119 टी. एम. सी. के उपयोग पर विचार किया गया हानि होती है।

(3) फरवरी 1982 में सी. डब्ल्यू. सी. ने सरकार से प्राप्त किया

कर्नाटक ने अतिरिक्त सिंचाई के लिए यू. के. पी. चरण II पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की

218 मेगावाट का उत्पादन। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, कुल उपयोग यू. के. पी. चरण I और II के तहत 173 टी. एम. सी. पर विचार किया गया था। (119 अल।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. बी. ए. पी. राज्य [मजमुदार, जे.]

415

टी. एम. सी. चरण I + 31 टी. एम. सी. चरण II + पोलावरम से गोदावरी के पानी का मोड़ 21 टी. एम. सी., + 21 टी. एम. सी. के उपयोग से पुनर्जनन

गोदावरी जल, 2 टी. एम. सी.)।

(4) केंद्रीय जल आयोग को हिप्परगी परियोजना पर एक अलग रिपोर्ट मिली है जिसमें कृष्णा जल के 10 टी. एम. सी. के उपयोग की परिकल्पना की गई है जिसे योजना आयोग द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई थी, इस प्रकार कुल 183 टी. एम. सी. (यानी 160 टी. एम. सी.) के उपयोग पर विचार किया गया था।

एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, कृष्णा जल + गोदावरी जल का 21 टी. एम. सी. + पुनर्जनन का 2 टी. एम. सी.) और 200 टी. एम. सी. नहीं।

XXX "

XXX

XXX

अभियोग के पैराग्राफ 34 में 25.4.94 दिनांकित एक डी. ओ. पत्र जिसे संबोधित किया गया है

तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का उल्लेख किया जाता है। इस संबंध में उस संचार में निम्नलिखित प्रासंगिक कथन निकाले गए हैं:

" इसके बाद ही उनके डी. ओ. पत्र सं. 6.1.91 - p.1-1660, दिनांक 25.4.1994 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए, तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा

अन्य अंतर-राज्यीय परियोजनाओं के साथ-साथ ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण-II पर कृष्णा बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। उक्त पत्र के साथ भेजी गई परियोजनाओं की पृष्ठभूमि में यह कहा गया था कि केंद्रीय जल आयोग ने देखा था कि परिकल्पित परियोजना (यू. के. पी. चरण I और II) 173 टी. एम. सी. के परिकल्पित उपयोग से अधिक जल उपयोग की भौतिक क्षमता पैदा करती है। यह देखा गया कि "यह 173 टी. एम. सी. के उपयोग के लिए 518.7 मीटर के आवश्यक स्तर के मुकाबले एफ. आर. एल. + 521 मीटर पर रेडियल गेट के प्रस्तावित शीर्ष को देखते हुए संभव है।

पानी "।

खंड के पृष्ठ 60 पर शिकायत के पैरा 40 में। III का एक पत्र में उल्लेख किया गया है

11 जुलाई, 1996 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, सरकार द्वारा संबोधित

→

यू. के. पी. चरण II के संबंध में वादी राज्य के मुख्यमंत्री को भारत का पत्र। उक्त पत्र में यह खुलासा किया गया कि केंद्रीय जल आयोग ने राय दी है कि चूंकि कोई स्थायी बाढ़ पूल की परिकल्पना नहीं की गई है, इसलिए एफआरएल के ऊपर गेट टॉप है।

518.70 M स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब है कि गेट स्तर [2000] 3 एस. सी. आर. पर जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस ऊँचाई तक का अलमट्टी बांध और उससे आगे की कोई भी ऊँचाई केंद्रीय जल आयोग को स्वीकार्य नहीं होगी।

वाद के पैरा 48 में यह कहा गया है कि "के अनुरोध पर

आंध्र प्रदेश, केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चा सरकार की संचालन समिति ने अलमट्टी बांध के निर्माण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए चार मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया। द.

मुख्यमंत्रियों की समिति की बैठक 12 अगस्त, 1996 को हुई थी। केंद्रीय जल आयोग और योजना आयोग के एक प्रतिनिधि के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया, जिन्होंने, हालांकि, अंततः कार्यवाही में भाग नहीं लिया। यह आगे कहा गया है कि विशेषज्ञ समिति ने शिकायत के पैरा 51 में उल्लिखित स्थान पर जाने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी की:

" .

" 173 टी. एम. सी. के उपयोग के लिए आवश्यक भंडारण क्षमता के संबंध में यू. के. पी. में, जैसा कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया है, समिति ने देखा है

कि बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान के अनुसार भी एक एफएलआर

+ 518.7 m का। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा। समिति ने

हालांकि गाद के कारण भंडारण क्षमता में संभावित नुकसान की अनुमति दी गई

आदि और देखा कि शटर के शीर्ष पर एफ. आर. एल. के लिए तय किया जाना चाहिए

+ 519.6 m पर वर्तमान। और फाटकों का निर्माण और निर्माण किया जाए

तदनुसार। विशेषज्ञ समिति की राय में, अलमट्टी बांध

+ 519.6 m पर एफ. आर. एल. के साथ। लगभग 123 टी. एम. सी. का भंडारण प्रदान करेगा।

जो नारायणपुर में 37.8 टी. एम. सी. के भंडारण के साथ काफी अच्छा होगा। 173 टी. एम. सी. की वार्षिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त

वर्तमान में ऊपरी, कृष्णा परियोजना के तहत परिकल्पित। समिति ने

महसूस किया कि वर्तमान समस्या को हल करने के लिए पहला कदम उठाया जाना चाहिए

अलमट्टी बांध अपने सुझाव को लागू करने और ऊंचाई को सीमित करने के लिए है + 519.6 m पर बांध।'

अब यह निश्चित रूप से सच है कि वादी-राज्य ने स्वीकार नहीं किया था

यू. के. पी. के तहत 173 टी. एम. सी. का उपयोग करने के लिए पहले प्रतिवादी की पात्रता और एफ. आर. एल. 519.6 पर बांध की ऊंचाई। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा भरोसा किए गए विशेषज्ञों के उपरोक्त हलफनामों द्वारा समर्थित विशेषज्ञ समिति की राय से पता चलता है कि एफ. आर. एल. 519.6 पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई प्रतिवादी संख्या 1 राज्य की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करेगी, अगर योजना "ए" के खंड V के अनुसार आवंटित पानी से अधिक पानी उपलब्ध है, जो कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. के बीच बाध्यकारी योजना है, तो पानी के आगे के भंडारण की अपनी मांग को दरकिनार कर देगी।

वी. ए. पी. राज्य [मजमुदार, जे.] 417

और योजना "बी" के अभाव में फलीभूत हो रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 राज्य और उसके गवाहों द्वारा लिए गए उपरोक्त रुख के आलोक में और विशेषज्ञ समिति और पर्यवेक्षक की राय भी।

केंद्रीय जल आयोग की शर्तों के अनुसार, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि

प्रतिवादी संख्या 1 राज्य के अनुसार, एफ. आर. एल. 519 पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई सिंचाई और बिजली उत्पादन उद्देश्यों के लिए अलमट्टी बांध में पर्याप्त पानी के भंडारण की अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेगी। यह हो सकता है कि इसकी भविष्य की आवश्यकता निर्भर करे; योजना "बी" की आकस्मिकता को अंततः अंतिम रूप देने के लिए अलमट्टी बांध में अधिक ऊंचाई के लिए बड़ी भंडारण क्षमता की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जैसा कि रिकॉर्ड से देखा गया है, अलमट्टी बांध की ऊंचाई को एफआरएल 519 पर सीमित करके इसकी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। वास्तव में, जहां तक उपरोक्त ऊंचाई का संबंध है, यहां तक कि वादी-राज्य ने भी कर्नाटक राज्य द्वारा के. डब्ल्यू. डी. टी. निर्णयों के उल्लंघन को सूचीबद्ध करते हुए ऐसा किया है अपनी शिकायत के पृष्ठ 74 से 76 पर पैरा 66 (ii) और 66 (iii) में निम्नलिखित प्रासंगिक अभिकथन:

अलमट्टी जलाशय का निर्माण केवल नारायणपुर के पूरक के रूप में किया गया था, लेकिन अलमट्टी के तहत किसी भी सिंचाई की अनुमति नहीं दी गई थी। हालाँकि, कर्नाटक ने एकतरफा रूप से अलमट्टी जलाशय के डिजाइन को बदल दिया और इसे एक बहुउद्देशीय परियोजना में बदल दिया।

4. 13 लाख एकड़ तक सीधी सिंचाई और 297 मेगावाट पनबिजली के उत्पादन के लिए, जिसमें के. डब्ल्यू. डी. टी. द्वारा यू. के. पी. को दी गई अनुमति और आवंटन से अधिक कम से कम 91 टी. एम. सी. पानी का अतिरिक्त उपयोग शामिल है। संशोधित डिजाइन के अनुसार, ऊँचाई

अलमट्टी में बांध का क्षेत्रफल 518.7 m से बढ़ाने की मांग की गई है। 524.256 m तक। ताकि के. डब्ल्यू. डी. टी. द्वारा अनुमत सिंचाई के लिए अनुमेय भंडारण से परे 116 टी. एम. सी. का भंडारण बढ़ाया जा सके।

नारायणपुर।

(iii) अलमट्टी परियोजना एक कैरी ओवर जलाशय होने के अलावा

अब निम्नलिखित आगे के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए के. डब्ल्यू. डी. टी. आवंटन से परे 91 टी. एम. सी. अतिरिक्त पानी का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है:

[2000] 3

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. नहीं। विवरण और उपयोग

क्षेत्र

पानी।

(लाख एकड़ में)

अनिवार्यता

(टीएमसी में)

(a) बाएं हिस्से के तहत नहर सिंचाई

0.90

11

और अलमट्टी में दाहिने किनारे की नहरें

(ख) तटवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई

3.23

39

लिफ्ट योजना (मुलवाड़)

(ग) अतिरिक्त आवश्यकता

19

गन्ना और अन्य दूसरे
योजनाओं के तहत मौसमी फसलें

लिफ्ट

(घ) वृद्धिशील वाष्पीकरण हानि

22

अतिरिक्त भंडारण के कारण

बिजली उत्पादन (100 टी. एम. सी.)

कुल

91 टीएमसी

4.13 लाख।

एकड़।

यदि कर्नाटक को अलमट्टी में सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए 91 टी. एम. सी. की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो अलमट्टी और नारायणपुर के निचले हिस्से में नदी में विश्वसनीय प्रवाह कई गुना कम हो जाएगा, जिससे निचले तटवर्ती क्षेत्र के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- वादी राज्य।

इसके अलावा, कर्नाटक द्वारा अलमट्टी में सिंचाई उद्देश्यों के लिए 91 टी. एम. सी. के उक्त अतिरिक्त उपयोग से पारिस्थितिक संतुलन पर भारी प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण खराब होगा, नदी

के पानी में प्रदूषण बढ़ेगा और वादी राज्य में बड़े पैमाने पर सिंचित क्षेत्र सूख जाएंगे। यह प्रवाह स्वरूप को भी बदल देगा जो बदले में किसानों के नदी तटीय हितों को खतरे में डालने के लिए बाध्य है, जिनके पास निर्धारित अधिकार हैं, नदी के पानी के प्राथमिक उपयोग का अधिकार है।

वादी-राज्य। इस तरह के उपयोग से वादी-राज्य के भीतर बिजली उत्पादन प्रणाली पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रकार ये कथन स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. की वास्तविक शिकायत है।

वी. ए. पी. राज्य [मजमुदार, जे.] 419

वादी-राज्य 518.7 मीटर से परे अलमट्टी बांध की ऊंचाई से संबंधित है। और 524.256 m तक जा रहा है। दूसरे शब्दों में, वादी की कोई वास्तविक शिकायत नहीं है-कम से कम 518.7 m तक अलमट्टी बांध की ऊंचाई के रखरखाव के संबंध में राज्य। या 519 मीटर। इसके अलावा यह वादी-राज्य द्वारा विवाद की एक वास्तविक हड्डी होगी। वादी की उपरोक्त शिकायत-राज्य और अधिक है। जब हम पृष्ठ 82 पर शिकायत के पैरा 68 की ओर मुड़ते हैं। इसमें वादी का कहना है कि प्रथम प्रतिवादी कर्नाटक ने के. डब्ल्यू. डी. टी. के निर्णयों का घोर उल्लंघन किया है। अलमट्टी बांध से संबंधित उक्त पैरा में, मद 2 पर, यह था

जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

परियोजना का नाम

अनुमत क्षेत्र

" एस. एल.

योजनाबद्ध

नहीं।

क्षेत्र

(लाख एकड़)

(

लाख एकड़)

अलमट्टी

. 2 .

नील

4.13 "

पैरा 66 (ii) और (iii) और पैरा 68 (ए) (2) में उपरोक्त कथनों को एक साथ पढ़ने पर, यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि वादी राज्य की वास्तविक शिकायत अलमट्टी बांध में अतिरिक्त 11 टी. एम. सी. पानी के भंडारण और उपयोग की है।

ऊँचाई को 524.256 m तक बढ़ाकर। जिसके परिणामस्वरूप 4 लाख 13 हजार एकड़ के नियोजित क्षेत्र की सिंचाई होगी। इन परिस्थितियों में, इसलिए, हमारे विचार में, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी जाती है कि क्या अलमट्टी बांध की ऊँचाई एफआरएल 519 पर तय की गई है। एम. यह न केवल वादी-राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 राज्य की वर्तमान आवश्यकता को भी पूरा करेगा और विशेषज्ञ समिति की राय के साथ-साथ केंद्रीय जल आयोग द्वारा यू. के. पी. परियोजना के चरण 2 को दी गई मंजूरी पर भी गलत नहीं होगा, जैसा कि पहले देखा गया था।

इस संबंध में, यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि प्रतिवादी नंबर 1 क्या है

कर्नाटक राज्य को यू. के. पी. के संबंध में अपनी रिपोर्ट के संबंध में कहना है दूसरा चरण। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर प्रासंगिक दस्तावेज के संकलन II में, हमें उस रिपोर्ट की एक प्रति पृष्ठ 98 पर न्यूनतम आवश्यक अल्माटी एफआरएल के संबंध में मिलती है। रिपोर्ट इस प्रकार है:

" न्यूनतम अल्माटी एफ. आर. आई. 173 टी. एम. सी. उपयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है

518.7 m पाया गया। अलमट्टी के लिए जलाशय संचालन तालिकाएँ

एफ. आर. एल. 518.7 एम. के साथ 1950-51 से 1988-89 वर्षों के लिए जलाशय। और

नारायणपुर जलाशय के लिए संबंधित संचालन तालिकाएँ

39 वर्षों की अवधि में केवल 7 विफलता वर्ष हैं, जो इससे कम हैं
25 % वर्ष की कुल संख्या:

ऑपरेशन का। "[2000] 3 एस. सी. आर.

420

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, मुद्दा संख्या 9 (ए) का उत्तर देते समय यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच वास्तव में कोई विवाद नहीं है।

कम से कम एक एफ. आर. एल. 519.6 मीटर के साथ अलमट्टी बांध का निर्माण। एक ओर प्रतिवादी संख्या 1 राज्य की आवश्यकता को पूरा करेगा और दूसरी ओर वादी-राज्य की शिकायत को भी पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में, अलमट्टी बांध का निर्माण

न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए प्रत्येक जल वर्ष में पानी की 75 प्रतिशत भरोसेमंद उपलब्धता के आधार पर योजना "ए" के अनुसार कर्नाटक राज्य को पानी की सकल मात्रा के आवंटन को देखते हुए इस स्तर पर 524.256 के एफ. आर. एल. के साथ व्यवहार्य या अनुमेय नहीं हो सकता है। एफ. आर. एल. 519 मीटर से अधिक ऊंचाई में कोई वृद्धि। न्यायाधिकरण के किसी भी बाद के निर्णय द्वारा कर्नाटक राज्य को पानी के आगे के आवंटन पर निर्भर हो सकता है, जब भी और जब गठन किया जाता है यह प्रस्तावित योजना "बी" के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा जिसे अब तक किसी भी जल विवाद न्यायाधिकरण के बाध्यकारी निर्णय का दर्जा नहीं दिया गया है।

जब हम अंक संख्या 9 (बी) की ओर रुख करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह मानता है कि

कर्नाटक के क्षेत्र के भीतर एक बांध के निर्माण के लिए अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। इस धारणा को अपने आप में इस सरल कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि अपने क्षेत्र के भीतर प्रत्येक नदी तटीय राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार बांध का निर्माण कर सकता है। अन्य नदी तटीय राज्यों की शिकायत केवल तभी उत्पन्न होगी जब इस तरह के निर्माण से न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय द्वारा अंतर-राज्यीय नदी के उपलब्ध जल प्रवाह को प्रभावित करने की संभावना है या यदि यह इस संबंध में कोई विवाद उठाता है जिस पर भविष्य के किसी न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस मुद्दे में पूर्ण धारणा कि कर्नाटक राज्य को अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति के बिना बांध के निर्माण के साथ आगे बढ़ने की

अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे उपरोक्त राइडर के अधीन माना जाएगा।

जहाँ तक दूसरी धारणा का संबंध है, अनुमोदन

संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार की आवश्यकता होगी जब भी कोई

केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना। वास्तव में अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि यह पहले ही आवश्यक अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार से संपर्क कर चुका है। मुद्दा संख्या 9 (बी) का जवाब उसी के अनुसार दिया गया है। अंक संख्या 9 (ग):

हमारा उपरोक्त निष्कर्ष कर्नाटक राज्य और ओआरएस के बीच के मुद्दे संख्या 9 (ए) का जवाब देगा।

वी. ए. पी. राज्य [मजमुदार, जे.] 421

वादी-राज्य और प्रतिवादी संख्या 1 राज्य मुख्य प्रतियोगी राज्य हैं। हालाँकि, इस निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, वादी और प्रतिवादी संख्या 1, जैसा कि पहले कहा गया है, प्रतिवादी संख्या 3 कर्नाटक राज्य की शिकायत को भी अनुमेय ऊँचाई के संबंध में ध्यान में रखा जाना चाहिए। अलमट्टी बांध। महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंधारुजिना-प्रतिवादी संख्या 3 ने इसमें जोरदार तर्क दिया कि यदि कर्नाटक राज्य द्वारा बनाए जाने वाले अलमट्टी बांध की ऊँचाई को 519 मीटर से अधिक जाने की अनुमति दी जाती है। एफ. आर. एल. जिसे केंद्रीय जल आयोग द्वारा मंजूरी दी गई है, उस बांध पर एकत्र किए गए पानी के दुष्प्रभाव से महाराष्ट्र राज्य के कई गाँवों के डूबने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह तर्क न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं उठाया गया था क्योंकि न्यायाधिकरण ने नहीं उठाया था

अलमट्टी बांध की किसी भी ऊँचाई को हटाने के सवाल पर विचार किया गया। लेकिन वर्तमान मुकदमा दायर करने के बाद, आगे की जांच और उसके द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर, यह देखा जाता है कि इस तरह के डूबने की संभावना है। अब जहाँ तक इस शिकायत का संबंध है, महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रस्तुत संकलन एम. ए. एच.-2 में पैरा 1.8 और 1.9 में निम्नलिखित प्रासंगिक अभिकथन किए गए हैं:

" 1.8 . चूंकि 1997 के वाद संख्या 2 में विवाद का विषय रहे अलमट्टी की ऊँचाई बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए महाराष्ट्र राज्य एक संवेदनशील मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था।

बड़े परिणाम।

1.9 . जुलाई 1998 में, महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक राज्य और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय और संबंधित केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ महाराष्ट्र क्षेत्र के संभावित जलमग्न होने का सवाल उठाया। उस समय तक, महाराष्ट्र राज्य अपने प्रारंभिक सर्वेक्षण में ऐसा करने में सक्षम था जिससे पता चला कि अल्माटी एफआरएल/एमडब्ल्यूएल आरएल 524.256 एम के साथ। महाराष्ट्र का क्षेत्र 5 से 6 मीटर गहराई (16 से 20 फीट गहराई) तक डूब जाएगा। बाढ़ के दौरान यह जलमग्नता और बढ़ जाएगी। इसलिए, महाराष्ट्र राज्य ने अपने दिनांकित पत्र 27.7.1998 के माध्यम से कर्नाटक से अनुरोध किया कि वह अलमट्टी बांध पर आगे के सभी निर्माण और विशेष रूप से फाटकों की स्थापना और फाटकों के सामने किसी भी भंडारण को तत्काल रोक दे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाराष्ट्र का कोई भी क्षेत्र नहीं है।
 डूबा हुआ था। इसने कर्नाटक राज्य से एक लिखित गारंटी के लिए भी कहा कि वह अलमट्टी में रेडियल गेट नहीं लगाएगा और/या पानी का भंडारण नहीं करेगा जब तक कि पानी के डूबने और संभावित नुकसान के मामले न हों।

महाराष्ट्र के क्षेत्र में संरचनाओं पर चर्चा की गई और बसाया गया [2000] 3 एस. सी. आर.

422

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महाराष्ट्र राज्य को अपनी पूरी संतुष्टि के साथ। राज्य का कर्नाटक को यह भी सूचित किया गया कि रसीद न मिलने की स्थिति में लिखित आश्वासन, महाराष्ट्र राज्य को मजबूर किया जाएगा

माननीय उच्चतम न्यायालय से संपर्क करें और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करें

अलमट्टी बांध पर सभी निर्माण कार्यों को पूरी तरह से रोकने के लिए और शिखर स्तर आरएल 509.00 मीटर से ऊपर पानी के भंडारण को रोकें।

पृष्ठ 73 पर पैरा 1.13 में महाराष्ट्र राज्य का रुख इस प्रकार बताया गया है -

पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से खुलासा किया गया:

" (क) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के पास कृष्णा नदी का स्तर

आरएल 519.00 एम से कम है। 524.256 m के FRL RL की तुलना में। में

अलमट्टी और एफआरएल आरएल 524.87 एम। हिप्परगी में, परिणाम के साथ वहाँ होगा

महाराष्ट्र में 5 से 6 मीटर तक जलमग्न होना।

महाराष्ट्र में जलमग्नता की मात्रा और विस्तार का आकलन करना।
कर्नाटक ने अब कहा है कि इस तरह के सर्वेक्षण किए जाएंगे

कर्नाटक केवल अप्रैल 1999 से।

महाराष्ट्र में अलमट्टी बांध के कारण जलमग्न होने के पहलू की जांच की गई
एफआरएल आरएल 524.256 एम के साथ।

(घ) अलमट्टी बांध के लिए, शिखर स्तर आरएल 509.016 और एफआरएल
आरआई के साथ
524.256 , अधिकतम डिजाइन बाढ़ जैसे तकनीकी पहलुओं में से कोई भी नहीं

स्पिलवे पर्याप्तता, गेट की संख्या और आकार, गाद और इसके प्रभाव
महाराष्ट्र में ऊपर की ओर, बाढ़ मार्ग, जलाशय संचालन कार्यक्रम

केंद्रीय जल आयोग द्वारा। ये सभी पहलू भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं।
और महाराष्ट्र में जलमग्नता की सीमा को प्रभावित करता है।

पृष्ठ 75 पर पृष्ठ 1.14 पर इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

" अब यह पता चला है कि कर्नाटक राज्य अब वेल्डिंग का प्रस्ताव रखता है।

रेडियल गेट के फ्रेम वर्क पर त्वचा की प्लेटें। यह अब पूरा हो जाएगा।

फाटकों का निर्माण और अलमट्टी बांध की ऊँचाई को बढ़ाने के लिए

एफआरएल आरएल 524.256 एम। एफ. आर. एल. आर. 1 को 524.256 एम तक बढ़ाना। बांध का

महाराष्ट्र के क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा। कर्नाटक राज्य ने
द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्रों को जलमग्न करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण।”

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [मजमुदार, जे.] 423

जब हम अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने के लिए अनुमति देने के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर 1999 की आई. ए. संख्या 8 की ओर मुड़ते हैं, तो हम पैरा 1.2 पर पृष्ठ 6 पर निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियाँ पाते हैं। वही नीचे पढ़ा गया है:

" अपना लिखित वक्तव्य दाखिल करने के बाद, महाराष्ट्र द्वारा दस्तावेजों, अभिलेखों, परियोजना रिपोर्टों और अंतःविषय जवाबों का एक विस्तृत अध्ययन किया गया।

एफआरएल आरएल 524.256 मीटर के साथ अलमट्टी बांध का निर्माण करके महाराष्ट्र राज्य के कर्नाटक राज्य द्वारा जलमग्न होने की संभावना थी। और एफ. आर. एल. आर. एल. 524.87 एम. के साथ हिप्परगी बैराज। और इसके परिणामस्वरूप कई गाँवों और कुछ कस्बों से आबादी का विस्थापन होगा महाराष्ट्र। जैसा कि इसके बाद कहा गया है, पुरातात्विक संरचनाओं और तीर्थ स्थलों सहित निजी और सार्वजनिक संपत्तियों और कार्यों और संरचनाओं को भारी नुकसान होने की भी संभावना है।

नीचे पैरा 5 में। अवसादन और मौजूदा नदी चैनलों की क्षमता में कमी, तल ढाल के समतल होने, दोनों राज्यों की सीमा के पास पहले से ही नाजुक नदी व्यवस्था में बदलाव और बाढ़ की गहराई में वृद्धि के कारण हर साल बाढ़ के दौरान संचार में व्यवधान, बढ़ी हुई परेशानी और नुकसान होगा।

हर साल अवधि और परिणामी संकट।

एक साधारण दीवानी अदालत के समक्ष एक मुकदमे के सख्त मापदंड के रूप में, हमें अलमट्टी बांध की ऊँचाई के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई वास्तविक शिकायत की सराहना करनी होगी। यह 524.256 मीटर की ऊँचाई के आसपास केंद्रित है। इससे परे कोई भी ऊँचाई। 519 एम. और 524.256 m पर जा रहे हैं।, महाराष्ट्र राज्य के अनुसार, [2000] 3 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके गाँवों को जलमग्न करने की संभावना है, हालांकि यह एक संभावना है और एक वास्तविक निश्चितता नहीं है। जहां तक इस शिकायत का संबंध है, इसलिए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 3 की शिकायत वास्तव में इसके गाँवों के डूबने की एक दूरस्थ और अनिश्चित संभावना तक सीमित है यदि अलमट्टी बांध की ऊँचाई 519 मीटर से अधिक थी। और 524.256 m तक पहुँचता है। 524.256 मीटर की ऊँचाई के बारे में शिकायत। वादी-आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा भी आवाज उठाई गई है, हालांकि अलग-अलग कारणों से। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, अलमट्टी बांध की ऊँचाई यदि 519 मीटर तक की अनुमति दी जाए। वादी के लिए कोई वास्तविक समस्या पैदा नहीं करेगा-एक ओर राज्य या प्रतिवादी के लिए नंबर 3 राज्य दूसरी ओर और योजना "ए" के बाध्यकारी निर्णय के आलोक में अलमट्टी बांध पर पर्याप्त पानी के भंडारण के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 राज्य की वर्तमान आवश्यकता को भी पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में, 519 मीटर की ऊँचाई। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णा नदी बेसिन में स्थित तीनों तटवर्ती राज्यों के बीच गंभीर विवाद नहीं है और यदि इस ऊँचाई को अलमट्टी बांध पर बनाए रखने की अनुमति दी जाती है तो यह एक ओर केंद्रीय जल आयोग की राय और चार प्रमुखों की विशेषज्ञ समिति की राय के खिलाफ नहीं जाएगा।

दूसरी ओर मंत्री।

लेकिन महाराष्ट्र राज्य की शिकायत के इस पहलू को एक तरफ रखते हुए,

यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 3 महाराष्ट्र राज्य द्वारा उठाया जाने वाला विवाद प्रतिवादी संख्या 1 राज्य, अर्थात् कर्नाटक राज्य के खिलाफ है, जो 519 मीटर से अधिक अलमट्टी बांध की ऊँचाई में किसी भी वृद्धि के संबंध में है। या उस मामले के लिए 512 मीटर से अधिक। महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंधारुजिना के अनुसार, यह अनुमेय ऊँचाई हो सकती है और जिसका महाराष्ट्र क्षेत्र में जलमग्न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, हालाँकि, इस विवाद को वर्तमान कार्यवाही में इस सरल कारण से हल नहीं किया जा सकता है कि यह एक 'जल विवाद' की प्रकृति ग्रहण करेगा जैसा कि हम वर्तमान में देखेंगे। 'जल विवाद' जैसा कि अनुच्छेद 262 द्वारा विचार किया गया है

जिसे विवाद अधिनियम की धारा 2 (सी) द्वारा परिभाषित किया गया है, जैसा कि पहले निकाला गया था। इसका अर्थ है दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद।

कर्नाटक राज्य को कृष्णा नदी के जल को नियंत्रित करने का अधिकार देता है जो एक अंतर-राज्यीय नदी है और यदि प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा कृष्णा जल के इस प्रकार के नियंत्रण

से महाराष्ट्र राज्य के गाँवों के डूबने की संभावना है, जो एक ऊपरी नदी तटीय राज्य है, तो यह स्पष्ट रूप से परिभाषा के अंतर्गत आएगा। धारा 2 (सी) (आई) में पाए जाने वाले 'जल विवाद' का। यह तुरंत धारा 3 (ए) को आकर्षित करेगा जो जल विवादों के बारे में राज्य सरकारों की शिकायतों से संबंधित है। इसमें कहा गया है:

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [जे. जे. मजमुदार]

425

" 3. जल विवादों के बारे में राज्य सरकार द्वारा शिकायतें। यदि किसी राज्य की सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी अन्य राज्य की सरकार के साथ जल विवाद इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है कि किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल में राज्य या उसके निवासियों में से किसी के हित निम्न द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं या होने की संभावना है -

(क) की गई या पारित की गई कोई कार्यकारी कार्यवाई या विधान, या प्रस्तावित

दूसरे राज्य द्वारा लिया या पारित किया जाना; या

XXXX "

XXXX

XXXX

यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र राज्य, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3, आशंका व्यक्त करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 राज्य की कार्यकारी कार्यवाई के कारण 524.256 M. पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर विचार करने के कारण, प्रतिवादी संख्या 3 राज्य या उसके निवासियों के अपने गाँवों और वहाँ के निवासियों द्वारा कब्जा की गई भूमि के जलमग्न होने से पूर्वाग्रह होने की संभावना है। इस प्रकार विवाद अधिनियम की धारा 2 (सी) (आई) और धारा 3 (ए) के संयुक्त पठन पर प्रतिवादी संख्या 3 राज्य द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ की गई ऐसी शिकायत परिणामस्वरूप अनुच्छेद 262 के तहत विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विवाद अधिनियम के अग्र-कोणों में आएगी। एक बार जब यह निष्कर्ष निकल जाता है तो परिणाम स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार की शिकायत और विवाद पर हम अनुच्छेद 131 के तहत निर्णय नहीं ले सकते हैं और यह महाराष्ट्र राज्य के लिए है यदि इस तरह की सलाह दी जाती है कि वह केंद्र सरकार के समक्ष विवाद अधिनियम की धारा 3 के तहत एक उचित अनुपालन दायर करके ऐसा

विवाद उठाए जो पहले उसने नहीं उठाया था और एक बार ऐसा होने पर अधिनियम की धारा 4 स्वतः ही आकर्षित हो जाएगी। यह निम्नानुसार प्रदान करता है:

" 4. न्यायाधिकरण का गठन-(1) जब किसी राज्य सरकार से किसी जल विवाद के संबंध में धारा 3 के तहत कोई अनुरोध प्राप्त होता है और केंद्र सरकार की राय होती है कि जल विवाद वार्ता द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक जल विवाद का गठन करेगी।

जल विवाद के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण।

(2) (न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा।
ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के नामांकन के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं

न्यायालय या उच्च न्यायालय:)

426

[

2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) न्यायाधिकरण दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकता है -

उससे पहले की कार्यवाही में उसे सलाह दें।

इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3, राज्य द्वारा जलमग्न होने के बारे में की गई शिकायत प्रतिवादी संख्या 3 राज्य और प्रतिवादी संख्या 1 राज्य के बीच 'जल विवाद' के दायरे में आती है। इसके संकल्प के लिए, द्वारा निर्णय

न्यायाधिकरण ही एकमात्र रास्ता है। यह पक्षों के बीच विवाद में नहीं है कि इस तरह के जल विवाद पर के. डब्ल्यू. डी. टी. द्वारा कभी निर्णय नहीं लिया गया था। दूसरे शब्दों में, यह एक खुला विवाद बना हुआ है जो इसके निर्णय की मांग करता है। हम अनुच्छेद 131 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते हैं, वास्तव में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष महाराष्ट्र राज्य

प्रतिवादी संख्या 3 के मामले के बयान में, जिसे एमआरके-I के रूप में संलग्न किया गया है, महाराष्ट्र राज्य ने स्वयं ऐसी शिकायत को 'जल विवाद' का एक हिस्सा माना है। पैरा (के) में महाराष्ट्र राज्य द्वारा जल न्यायाधिकरण से मांगी गई राहत निम्नानुसार प्रस्तुत की गई थी:

" (के) कि इस निर्णय को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से माननीय न्यायाधिकरण को सभी निर्देश दिए जा सकते हैं और आदेश पारित किए जा सकते हैं

नदी जल विवाद जिसमें एक निर्देश भी शामिल है कि पानी नहीं होगा किसी भी परियोजना में उपयोग किया जाता है जिसका जलमग्न होने का प्रभाव होगा

की पूर्व सहमति के अलावा किसी अन्य राज्य का क्षेत्र

नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजे पर समझौता

संबंधित राज्य यदि उसने अपने क्षेत्र के किसी हिस्से के लिए सहमति दी है

डूबा हुआ "।

यह निश्चित रूप से सच है कि हालांकि प्रतिवादी संख्या 3 राज्य ने माना न्यायाधिकरण द्वारा हल किए जाने वाले 'जल विवाद' के एक भाग के रूप में जलमग्न होने के प्रश्न पर, न्यायाधिकरण ने अलमट्टी बांध की ऊंचाई के कारण प्रतिवादी संख्या 3 राज्य के क्षेत्र में गाँवों के जलमग्न होने के प्रश्न पर विचार नहीं किया। इसलिए, यह प्रतिवादी संख्या 3 राज्य और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच एक गर्म विवाद बना हुआ है। इसलिए, इसे एक सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने की आवश्यकता है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। यह स्वयंसिद्ध है कि महत्वपूर्ण प्रश्न

विवाद अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धारण यह है कि क्या महाराष्ट्र राज्य या कृष्णा नदी घाटी में इसके किसी भी निवासी का हित किसी अन्य नदी तटीय राज्य की कार्यकारी कार्यवाही से प्रभावित होगा, जैसे कि प्रतिवादी संख्या 1। राज्य एक अभिन्न इकाई है और इसके हित में नदी बेसिन के बाहर के क्षेत्रों सहित इसके क्षेत्र के भीतर इसके निवासियों की भलाई शामिल है। इसलिए, अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत कर्नाटक और ओ. आर. एस. राज्य।

प्रासंगिक विचार समग्र रूप से राज्य और उसके सभी निवासियों का हित है, न कि केवल राज्य के बेसिन क्षेत्रों का हित। नतीजतन, यह माना जाना चाहिए कि कर्नाटक राज्य द्वारा अलमट्टी बांध की ऊंचाई 519 मीटर से अधिक बढ़ाने से महाराष्ट्र राज्य के गांवों के जलमग्न होने के बारे में विवाद। एक अनसुलझा जल विवाद है जिस पर हम अनुच्छेद 131 के तहत विचार नहीं कर सकते हैं और हमें करना होगा

प्रत्यर्थी संख्या 3 राज्य को केंद्र सरकार के समक्ष विवाद अधिनियम की धारा 3 के तहत एक उचित शिकायत दर्ज करने के लिए, यदि इस तरह की सलाह दी जाती है, यदि इस बीच में प्रतिवादी संख्या 3 राज्य और प्रतिवादी संख्या 1 राज्य के बीच विवाद का कोई सौहार्दपूर्ण समझौता या निपटान नहीं हुआ है।

अब, हम स्थिति का जायजा लेते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 519 मीटर की ऊंचाई तक तीनों राज्यों के बीच कोई वास्तविक विवाद नहीं है। अलमट्टी बांध। इसलिए, हम प्रश्न संख्या का उत्तर देते हुए ऐसा कर सकते हैं। 9 (क) और (ख) सुरक्षित रूप से यह ठहराते हैं कि, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है और जैसा कि साक्ष्य है, कर्नाटक राज्य द्वारा निष्पादित और प्रगति पर और विचार की गई अन्य सभी परियोजनाओं के साथ एक एफ. आर. एल. 524.256 के साथ अलमट्टी बांध के निर्माण को मंजूरी नहीं दी जा सकती है और न ही कर्नाटक राज्य को अन्य सभी नदी तटीय राज्यों की सहमति के साथ-साथ केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना उस ऊंचाई तक निर्माण करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, यह शर्त लागू होगी कि कर्नाटक राज्य के प्रतिवादी संख्या 1 को 519 मीटर की ऊंचाई तक अलमट्टी बांध के निर्माण की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जिसके लिए, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, पक्षों के बीच कोई वास्तविक विवाद नहीं है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 राज्य को दी गई इतनी छूट भी निम्नलिखित सुरक्षा उपायों और सवारियों के अधीन होगी:

जबकि प्रतिवादी संख्या 1 राज्य ने एफआरएल 519 मीटर तक अलमट्टी बांध के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह अन्य सभी सक्षम लोगों द्वारा मंजूरी के अधीन होगा।

विभिन्न कानूनों के तहत कार्य करने वाले प्राधिकरण। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य द्वारा बांध की ऊंचाई को और भी ऊपर उठाने के लिए आवश्यक मंजूरी की आवश्यकता होगी।

\$19 मिलियन तक।

विशेष रूप से, इस तरह की मंजूरी एनवी रोन्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के तहत और वन और पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त करनी होगी

मेंट, सरकार। इस संबंध में भारत।

इसकी ऊँचाई 519 मीटर तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय जल आयोग से भी उचित मंजूरी लेनी होगी।

519 मीटर की ऊँचाई बढ़ाने के लिए उपरोक्त अनुमति/मंजूरी।

इस [2000] 3 एस. सी. आर. द्वारा

428

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेश भविष्य के किसी भी जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित विवादित राज्यों द्वारा प्राप्त किसी भी आगे के निर्देश, यदि कोई हो, के अधीन होगा, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य प्रतिवादी संख्या 3 सहित किसी भी विवादित राज्य द्वारा की गई शिकायत पर किया जा सकता है। वर्तमान की सुनवाई लंबित रहने तक इस न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत

वाद को इस प्रभाव से संशोधित किया जाएगा कि कर्नाटक राज्य,

अधिकारियों की उपरोक्त मंजूरी से अलमट्टी बांध की ऊँचाई 519 मीटर तक बढ़ सकती है।, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है।

अलमट्टी बांध की ऊँचाई को 519 मीटर से आगे बढ़ाना। करेंगे।

स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष तीन विवादित राज्यों में से किसी एक द्वारा उठाई गई शिकायतों पर और न्यायाधिकरण और अन्य सभी सक्षम अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने के बाद भी विवाद अधिनियम के तहत गठित उपयुक्त जल विवाद न्यायाधिकरण से भविष्य में प्राप्त निर्णय, यदि कोई हो, का पालन करें। अलमट्टी बांध की ऊँचाई को 519 मीटर से ऊपर उठाने का सवाल। के लिए भी गिर जाएगा 31 मई, 2000 के बाद न्यायाधिकरण का विचार, जब योजना "ए" समीक्षा के लिए आएगी, जैसा कि के. डब्ल्यू. डी. टी. ने अपनी रिपोर्ट पी. के.-आई. एंड. में पहले ही निर्देश दिया है।

पी. के.-II। इसे प्रस्तावित योजना "बी" के आलोक में भी विचार करना होगा जो उपयुक्त जल विवाद न्यायाधिकरण के विचार के लिए आ सकती है। भविष्य में यदि इस संबंध में किसी भी प्रतियोगी द्वारा शिकायतें उठाई जाती हैं

केंद्र सरकार के समक्ष राज्य।

मुद्दा संख्या। 9 (ए), (बी) और (सी) का उत्तर उपरोक्त के रूप में दिया गया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1997 का मूल मुकदमा संख्या 2 निपटाया जाएगा।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बनर्जी, जे. मुझे विस्तृत अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है।

इन दो मुकदमों (ओएस नंबर 1 और ओएस नंबर 2) के संबंध में भाई पटनायक द्वारा तैयार किए गए निर्णय और मैं इसके साथ अपनी सहमति दर्ज करता हूं। मेरे पास भी है

कुछ मुद्दों के संबंध में ओएस नंबर 2 में भाई मजूमदार द्वारा तैयार किए गए निर्णय को देखने का विशेषाधिकार है और मैं इसके साथ अपनी सहमति भी दर्ज करता हूं, लेकिन मैं दोनों मुकदमों के लिए एक सहमति वाले निर्णय के माध्यम से मुद्दे में मामलों में अपने तर्क के रूप में कुछ पृष्ठ जोड़ना चाहता हूं।

इन दो मुकदमों (ओएस नंबर 1 और ओएस) में विवाद के बिंदु

सं. 2/97) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बीच संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कृष्णा नदी के पानी के उपयोग और बंटवारे से संबंधित है। जबकि कर्नाटक ने 1997 का मूल मुकदमा संख्या 1 आंध्र प्रदेश राज्य के खिलाफ पहले प्रतिवादी और कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. के रूप में दायर किया है।

» . ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.] 429

दूसरे के रूप में महाराष्ट्र, 1997 का मूल मुकदमा संख्या 2 आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के खिलाफ स्थापित किया गया है। हालाँकि, भारत संघ को दोनों मुकदमों में एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है।

हालाँकि, उठाए गए विवादों के साथ आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान दिया जाए

देश में जल संसाधनों का वितरण विशिष्ट है जिसे समय तत्व के संबंध में अत्यधिक असमान नहीं माना जा सकता है। भारतीय नदियों में 80 से 90 प्रतिशत से अधिक बहाव वर्ष के चार महीनों में होता है और हानिकारक प्रचुरता और तीव्र कमी वाले क्षेत्र हैं। देश को काफी समय से देश के जल संसाधनों के मामले में कई महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटना पड़ता है। वर्ष 2050 तक देश की कुल पानी की आवश्यकता 973 से 1180 किलोमीटर होगी। पीने, बिजली परियोजनाओं और

अन्य उपयोगों सहित घरेलू उपयोग के बाद सबसे अधिक पानी की आवश्यकता के लिए सिंचाई प्रमुख क्षेत्र है। राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए एकीकृत जल संसाधन विकास: (सितम्बर, 1999) के अभिलेख:

" वर्ष 2050 में देश की कुल जल आवश्यकता अनुमानित उपयोग योग्य जल संसाधनों से मुश्किल से मेल खाती है। यह सर्वोपरि महत्वपूर्ण है कि हमें कम मांग वाले परिदृश्य में पानी की आवश्यकता को कम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक एकीकृत जल नीति तैयार करते समय तीन प्रमुख विचारों को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। पहला, आवश्यकता और उपलब्धता के बीच संतुलन तभी बनाया जा सकता है जब पानी के उपयोग में अत्यधिक दक्षता की शुरुआत की जाए। दूसरा, औसत राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता का मतलब यह नहीं है कि सभी बेसिन आंतरिक संसाधनों से अपनी पूरी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हैं। तीसरा, क्षेत्रों के बीच और आबादी के वर्गों के बीच पानी की पहुंच में समानता का मुद्दा अधिक महत्व रखता है, जिसे कुल उपलब्धता और आबादी के बीच एक नाजुक संतुलन के रूप में देखा जाता है।

जल की समग्र आवश्यकता "।

रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि हालांकि 1987 की राष्ट्रीय जल नीति एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति विकसित करने की दिशा में एक अच्छा पहला कदम था, लेकिन नए मुद्दों के उभरने के कारण, राष्ट्रीय जल नीति को संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता है। लेकिन तब तक कि इस नई पुनर्जीवित नीति को इसका वास्तविक रूप और आकार दिया जा सके और उसके बाद इसे लागू किया जा सके।

वास्तविक भौतिक तरीकों और साधनों में समान, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण, इंटर [2000] 3 एस. सी. आर.

430

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य नदी विवाद जारी हैं और ये असामान्य से अधिक आम हो गए हैं: हालांकि, यह केवल इस देश के लिए प्रतिबंधात्मक नहीं है, बल्कि इसने राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लिया है। कान्सास बनाम के मामले में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ। कोलोराडो 51 लॉ Ed.U.S. (203-

206) 967 वर्तमान संदर्भ में काफी उपयुक्त प्रतीत होता है। बेंच की ओर से बोलते हुए ब्रेवर, जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" इस वाद में सीमा या सीमा का कोई प्रश्न शामिल नहीं है।
क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। अन्य और अमूर्त अधिकारों का दावा किया जाता है

संबंधित वादी। राज्यों के बीच विवाद बढ़ रहे हैं

जीवन और व्यवसाय की तेजी से बदलती स्थितियों में,
और भी अधिक होने की संभावना है। जैसे वे करते हैं, अधिकारों को शामिल करना

राजनीतिक समुदाय जो कई मायनों में संप्रभु हैं और
स्वतंत्र, वे कभी-कभी दूरगामी प्रश्न प्रस्तुत नहीं करते हैं

आयात और अत्यधिक कठिनाई "।

हालाँकि, संविधान के निर्माता स्थिति के प्रति जीवित थे

ऐसे विवादों के समाधान के संबंध में कानून। बाद का कानून जैसा कि संविधि पुस्तक में
प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 संविधान के अनुच्छेद
262 के तहत एक ऐसा विधान है और इसकी धारा 11 में सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायालयों
की अधिकारिता शामिल नहीं है।

जल विवाद के संबंध में न्यायालय। हालाँकि, धारा 11 के वास्तविक प्रभाव पर जल्द ही विचार
किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने से पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां अनुच्छेद 262
सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को हटाने से संबंधित है, वहीं अनुच्छेद 131 सर्वोच्च
न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने से संबंधित है और इस संदर्भ में, अनुच्छेद 262 के
प्रभाव की संविधान के अनुच्छेद 131 की तुलना में भी सराहना की जानी चाहिए।

यहाँ यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय संविधान संघीय रूप में है।

और चरित्र, राज्यों और संघ के बीच अधिकार के स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्रों के साथ केंद्र
और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का मौजूदा विभाजन है, हालांकि, कुछ आवश्यकताओं को
छोड़कर, जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है। सातवीं अनुसूची के तहत तीन सूचियाँ हमारे ज्ञान
को प्रदर्शित करती हैं। दोहरी राजनीति बनाए रखने के मामले में संविधान निर्माता।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाता है ताकि कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. के
बीच के मुद्दों को निर्धारित किया जा सके।

बी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.] 431

संघ और राज्यों के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच और इस परिप्रेक्ष्य में, संविधान का अनुच्छेद 131 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल न्यायशास्त्र प्रदान करता है जिसमें संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक तरफ संघ और किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों के संबंध में किसी अन्य न्यायालय को बाहर रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 262 और 131 की तुलना में बहुत ही विद्वान और विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गई हैं, लेकिन विस्तृत चर्चा शुरू करने से पहले, इस मुद्दे के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर ध्यान देना सुविधाजनक होगा।

पृष्ठभूमि तथ्य:

कृष्णा नदी के पानी का उपयोग मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के लिए विवादास्पद है। हालाँकि, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को मामले के अभिलेखों से मुक्त कर दिया गया था और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए विस्तृत कारण दर्ज करना समीचीन है, सिवाय इसके कि ऊपर उल्लेख किया गया है। अपने मामलों के बयानों में, महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश ने मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं के लिए कृष्णा नदी के पानी के उपयोग के अपने दावों पर जोर दिया: जहाँ महाराष्ट्र ने सकल उपयोग के लिए 820.70TMC का दावा किया, मैसूर ने 1430.00 टीएमसी का दावा किया और आंध्र प्रदेश ने उनके सकल उपयोग के संबंध में 1888.10 टीएमसी का दावा किया। उपरोक्त के अलावा, महाराष्ट्र ने पुनः उत्पन्न प्रवाह के लिए 32.5 टी. एम. सी. और औद्योगिक उपयोग और घरेलू जल आपूर्ति के लिए 70-80 टी. एम. सी. का दावा किया। आंध्र प्रदेश ने भी महाराष्ट्र की तरह घरेलू जल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए अतिरिक्त 120 टी. एम. सी. का दावा किया और मैसूर राज्य ने 1430 टी. एम. सी. की मांग की, लेकिन पानी की अपनी जरूरतों को शामिल नहीं किया।

घरेलू और औद्योगिक उपयोग। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कृष्णा नदी प्रणाली में कुल उपलब्ध पानी, उठाई गई या दावा की गई मांगों के बराबर नहीं है।

संयोग से, कृष्णा भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाटों की महादेव श्रृंखला में उगता है और

मैसूर और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और विभिन्न सहायक नदियों, नालियों और धाराओं से जल संचय सहायता प्राप्त करती है और अंत में मिलती है।

बंगाल की खाड़ी। महाराष्ट्र के भीतर 186 मील की दौड़ में, बिस्तर गिर जाता है [2000] 3 एस. सी. आर.

432

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14.06 ft है। प्रति मील, 85 मील तक का झरना 22.1 फीट की दर से अधिक ऊँचा है। प्रति मील। मैसूर के भीतर 300 मील की दौड़ में, बिस्तर झरना 2.12 फीट है। प्रति मील और आंध्र प्रदेश के भीतर 358 मील की दौड़ में, बिस्तर झरना 3 फीट है। प्रति मील। यह ध्यान दिया जाए कि भीमा और तुंगभद्रा नदियाँ कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन वे स्वयं प्रमुख अंतरराज्यीय नदियाँ हैं।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का पता लगाते हुए, यह भी प्रतीत होता है कि वास्तव में,

केवल मल्लापुरम के ऊपर तुंगभद्रा के पानी के बंटवारे के संबंध में मदरास और मैसूर के बीच एक समझौता। जुलाई, 1944 के इस समझौते ने केवल तुंगभद्रा के पानी में मदरास और मैसूर का हिस्सा तय किया और यह नदी को बांधने के लिए बाध्य नहीं किया। अन्य नदी तटीय राज्य। हालांकि यह सच है कि जुलाई, 1944 के समझौते ने मैसूर के मौजूदा उपयोग को संरक्षित किया है, इसने मैसूर के अन्य मात्रा में पानी का उपयोग करने के अधिकार को भी स्थापित किया है। स्वतंत्रता और भारत में हैदराबाद राज्य के विलय के औपचारिक होने के बाद, योजना आयोग ने 31 जुलाई, 1951 को बॉम्बे, मदरास और हैदराबाद की सरकारों को चर्चा और समझौते के ज्ञापन के संक्षिप्त रिकॉर्ड की प्रतियां संलग्न करते हुए लिखा और उनसे समझौते की पुष्टि करने के लिए कहा। मदरास सरकार द्वारा 17 अगस्त, 1951 को, हैदराबाद सरकार द्वारा 23 अगस्त, 1951 को और बॉम्बे सरकार द्वारा 30 अगस्त, 1951 को अनुसमर्थन पत्र भेजे गए थे। हालांकि, मैसूर ने आवश्यकता के अनुसार समझौते की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। वास्तव में, 24 सितंबर, 1951 को, जैसा कि अभिलेखों से पता चलता है, मैसूर सरकार ने योजना आयोग को एक नोट भेजा जिसमें लिखा था कि मसौदा समझौते में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि मैसूर को पानी के उपयोग के अधिकार की अनुमति दी जा सके और अनुसमर्थन के प्रश्न पर उपरोक्त सीमा तक संशोधन के बाद ही विचार किया जाएगा। यह तथ्यात्मक पीछे हटना ही है जिसने न्यायाधिकरण को ऊपर उल्लिखित 1951 के समझौते की निर्णायकता के संबंध में पहले मुद्दे का जवाब नकारात्मक में देने के लिए प्रेरित किया है। न्यायाधिकरण इस विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुँचा कि चूंकि मैसूर ने समझौते की पुष्टि नहीं की है, इसलिए पक्षों के बीच कोई परिचालन और निष्कर्षित समझौता नहीं है और अन्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थन पूरी तरह से अप्रभावी था।

न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया गया अगला मुद्दा इस आशय का था। 'क्या?

कृष्णा नदी और नदी घाटी के पानी का लाभकारी उपयोग'। हालाँकि, उपरोक्त मुख्य मुद्दे पर निम्नलिखित उप मुद्दे भी उठाए गए थे: उप-मुद्दे

(1) उपलब्ध जल का निर्धारण किस आधार पर किया जाना चाहिए?

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.]

433

(2) न्यायसंगत विभाजन कैसे और किस आधार पर होना चाहिए?

बनाया गया?

(3) कौन सी परियोजनाएं और कार्य चल रहे हैं या निर्माणाधीन हैं, यदि

क्या किसी को संरक्षित और/या अनुमति दी जानी चाहिए? यदि हाँ, तो किस हद तक?

(4) जल को बाहर की ओर मोड़ना या आगे मोड़ना चाहिए

कृष्णा जल निकासी बेसिन को संरक्षित किया जाए और/या अनुमति दी जाए? यदि ऐसा है तो

किस हद तक और किन सुरक्षा उपायों के साथ? जल निकासी कैसे होती है?

बेसिन को परिभाषित किया जाना है?

(5) क्या सिंचाई को कोई प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

बिजली का उत्पादन?

(6) क्या किसी राज्य के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का कोई वैकल्पिक साधन है? अगर

तो, किस प्रभाव के साथ?

(7) क्या किसी राज्य का वैध हित प्रभावित है या होने की संभावना है

समग्र उपयोग और आवश्यकता से प्रतिकूल रूप से प्रभावित

किसी अन्य राज्य के बारे में?

(8) उपलब्ध कराने के लिए कौन सी मशीनरी, यदि कोई हो, स्थापित की जानी चाहिए और

संबंधित राज्यों को जल के आवंटन, यदि कोई हो, को विनियमित करना।
या अन्यथा न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए?

संयोग से, कृष्णा जल विवादों की जांच ट्रिब्यूनल द्वारा की गई थी

अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत अपनी सर्वसम्मति रिपोर्ट और निर्णय 24 दिसंबर, 1973 को भारत सरकार को भेज दिया गया। हालाँकि, न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकारों ने 1956 के अधिनियम की धारा 5 (3) के प्रावधानों का सहारा लेते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण के लिए चार अलग-अलग संदर्भ दायर किए, और न्यायाधिकरण ने बाद में 27 मई, 1976 को संबंधित प्रस्तुतियों को सुनने के बाद अपनी आगे की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत केंद्र सरकार को जो, हालाँकि, बाद में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित संदर्भों में प्रकाशित किया गया था:

1956 के अधिनियम की धारा 6 न्यायाधिकरण के निर्णय के रूप में।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम आदेश में

इन तीनों राज्यों में से प्रत्येक के लिए जल वितरण के लिए योजनाएं। महत्वपूर्ण रूप से, हालाँकि, योजनाएं के संबंध में, न्यायाधिकरण ने बिना किसी अनिश्चितता के [2000] 3 एस. सी. आर. का अवलोकन किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

434

कि 25 साल की अवधि के बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इस तरह के समावेशन के प्रभाव को कुछ सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए; लेकिन ऐसा करने से पहले न्यायाधिकरण

द्वारा पहले वर्ष 1973 में और अंत में वर्ष 1976 में पारित आदेश की बुनियादी विशेषताओं पर ध्यान देना सुविधाजनक होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायाधिकरण ने कृष्णा नदी के पानी के वितरण के लिए योजना 'ए' का निर्देश देते हुए एक अन्य योजना (योजना 'बी' के रूप में स्वीकार की गई) भी तैयार की है, जिसका विवरण इस निर्णय में आगे दिखाई देगा। काफी है, हालाँकि, वर्तमान में यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायाधिकरण ने स्वयं सोचा कि इसे लागू करने योग्य निर्णय के रूप में नहीं लेना उचित है।

1973 में पारित आदेश की बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) 75 प्रतिशत पर उपयोग करने योग्य विश्वसनीय प्रवाह का बड़े पैमाने पर आवंटन और

पानी का प्रवाह, पानी का कुल प्रवाह 2060 टी. एम. सी. होगा जिनमें से 1693.36 टी. एम. सी. तीन राज्यों को आवंटित किया जाना चाहिए।

संरक्षित उपयोगों के लिए और शेष 366.64 TC (2060 TC)

1693.36 टी. एम. सी.) निम्नलिखित तरीके से:

टीएमसी

1 . महाराष्ट्र राज्य

125.35

2 . मैसूर राज्य

190.45

3 . आंध्र प्रदेश राज्य

50.84

366.64

कुल

इस प्रकार, 2060 टी. एम. सी. के विश्वसनीय प्रवाह में से प्रत्येक राज्य का हिस्सा इस प्रकार है:

टीएमसी

565.00

1. महाराष्ट्र राज्य

695.00

2. मैसूर राज्य

800.00

3. आंध्र प्रदेश राज्य

कुल

2060.00 कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.] 435

(ख) जल की मात्रा का निर्धारण जो होगा

कृष्णा नदी के 75 प्रतिशत विश्वसनीय प्रवाह में जोड़ा गया

वापसी प्रवाह के कारण विजयवाड़ा।

(ग) एक पूरी तस्वीर देने के लिए, न्यायाधिकरण ने इस पर विचार किया

विषय पर कुछ प्रावधानों को शामिल करने के लिए उपयुक्त और उचित

महाराष्ट्र के बीच कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे का,

मैसूर और आंध्र प्रदेश अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार हैं।

(क) आदेश का खंड III भरोसेमंद प्रवाह और वृद्धि से संबंधित है।

प्रतिगमन के कारण भरोसेमंद प्रवाह में परिवर्तन। बहती है।

(ख) खंड IV और V में पानी के बंटवारे की योजना शामिल है।

तीन राज्यों महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी। खंड 5 में महाराष्ट्र और मैसूर राज्य के संबंध में कहा गया है कि उनमें से प्रत्येक किसी भी जल वर्ष में उसमें निर्दिष्ट पानी की एक विशेष मात्रा से अधिक का उपयोग नहीं करेगा। यह जरूरी है कि

इसका तात्पर्य यह था कि ये दोनों राज्य किसी भी जल वर्ष में, न्यायाधिकरण द्वारा लगाई गई शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन और पानी की उपलब्धता के अधीन, उस खंड में निर्दिष्ट मात्रा तक कृष्णा नदी के पानी का उपयोग कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि तीनों राज्यों में से प्रत्येक को पानी आवंटित किया गया है और शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, प्रत्येक राज्य को आवंटित पानी का किसी भी तरह से लाभकारी उपयोग करने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे। यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक राज्य को आवंटित जल घरेलू और औद्योगिक उपयोग सहित सभी लाभकारी उद्देश्यों के लिए है और

ऐसे उपयोगों के लिए अलग से आवंटन किया जाता है।

(ग) खंड IX कृष्णा बेसिन में पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।

तीन राज्यों में। महाराष्ट्र राज्य पर प्रतिबंध कि वह घाटप्रभा उप-बेसिन (के 3) से किसी भी जल वर्ष में 7 टी. एम. सी. से अधिक का उपयोग नहीं करेगा, अन्यथा उस उप-बेसिन में परियोजनाओं के लिए मैसूर राज्य की आवश्यकताओं को नुकसान हो सकता है। आंध्र प्रदेश राज्य पर प्रतिबंध है कि वह आंध्र प्रदेश राज्य में कागना नदी के जलग्रहण क्षेत्र से 6 टी. एम. सी. से अधिक का उपयोग नहीं करेगा ताकि उस नदी का पानी भीमा नदी की मुख्य धारा तक पहुंच सके। राज्य द्वारा बताई गई मात्रा से अधिक पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए, न्यायाधिकरण ने एक ऊपरी सीमा निर्धारित की जो उस राज्य की कुल आवश्यकता से थोड़ी अधिक है जैसा कि उन मांगों से मूल्यांकन किया गया है जिन्हें या तो संरक्षित किया गया है या जिन्हें योग्य माना गया है विचार करें।

1 1 436

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(घ) खंड X महाराष्ट्र राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित है।

पश्चिम की ओर मोड़ पर।

(ङ) खंड बारहवीं और तेरहवीं में निहित प्रावधान आवश्यक हैं -

वे प्रत्येक राज्य द्वारा प्रत्येक जल वर्ष में कितने पानी का उपयोग किया जाता है, यह निर्धारित करने के लिए तंत्र प्रस्तुत करेंगे। वे मूल्यवान आंकड़े भी प्रस्तुत करेंगे जो भविष्य में काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

(च) खंड XIV न्यायाधिकरण के आदेश की समीक्षा से संबंधित है -

31 मई, 2000 के बाद सक्षम प्राधिकारी या न्यायाधिकरण।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, न्यायाधिकरण ने स्वयं अभिलिखित किया है कि आदेश को

उचित अवधि बीतने के बाद समीक्षा की जानी चाहिए। हालाँकि, इस तरह के निष्कर्ष का कारण स्पष्ट और स्पष्ट है और न्यायाधिकरण के शब्दों में, कारण नीचे दिए गए हैं:

" सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमारी राय है कि आदेश

31 मई, 2000 के बाद किसी भी समय न्यायाधिकरण की समीक्षा की जा सकती है।

इस अवधि को हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित मानते हैं कि

बीच की अवधि के दौरान बढ़ती मांग होगी

कृष्णा बेसिन में सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी

नए आंकड़ों के आलोक में जांच करनी पड़ सकती है जो हो सकता है

उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि तीनों राज्यों की मांगें

उस समय तक यह बहुत अधिक यथार्थवादी रूप ले लेगा। इसके अलावा, के रूप में

कंजर्वे के मामले में प्रौद्योगिकी में अद्भुत प्रगति

जल की स्थिति और इसके उपयोग और अन्य कारणों से भी यह हो सकता है

के बाद पानी के विभाजन के विषय की जांच करना आवश्यक है
 31 सेंट मई, 2000। हालाँकि, हमने यह प्रावधान किया है कि प्राधिकरण या
 न्यायाधिकरण जो इस न्यायाधिकरण के आदेश की समीक्षा करेगा,
 जहाँ तक संभव हो, किसी भी उपयोग को बाधित करें जो किया जा सकता है
 द्वारा किए गए आवंटन की सीमाओं के भीतर किसी भी राज्य द्वारा
 न्यायाधिकरण। 1925 के नील आयोग ने इसी तरह की सिफारिश की थी।
 इस आशय का प्रावधान कि -

" आयोग का मानना है कि यह समय-समय पर आवश्यक होगा।

इस रिपोर्ट में चर्चा किए गए प्रश्न की समीक्षा करने का समय है। इसे
 माना जाता है।

यह आवश्यक है कि सभी स्थापित सिंचाई का सम्मान किया जाए

प्रश्न की कोई भी भविष्य की समीक्षा।

यदि मध्यवर्ती अवधि के दौरान वृद्धि होती है

कृष्णा नदी के पानी के मोड़ से

कोई अन्य

1 437

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य (बनर्जी, जे.)

नदी, किसी भी राज्य को उपरोक्त से पहले दावा करने से प्रतिबंधित नहीं किया
 जाएगा।

प्राधिकरण या न्यायाधिकरण की समीक्षा करना कि वह अधिक हिस्से का हकदार है इस तरह की वृद्धि के कारण कृष्णा का पानी और नहीं बढ़ेगा।

किसी भी राज्य को इस तरह के दावे पर विवाद करने से प्रतिबंधित किया जाए।

यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि पानी प्रकृति का वरदान और सामाजिक है।

लाभार्थी को इस तरह से आवंटित किया जाना चाहिए ताकि सभी संबंधित लोगों द्वारा इसका लाभकारी उपयोग किया जा सके। 'लाभकारी उपयोग' शब्द का अर्थ और तात्पर्य पानी का उपयोग है जो समाज की भलाई के लिए अनुकूल है-यह सिंचाई के लिए हो सकता है: घरेलू उपयोग के लिए: औद्योगिक उद्देश्यों के लिए: वन्यजीव संरक्षण के लिए: मत्स्य पालन के लिए-'लाभकारी' अभिव्यक्ति के दायरे में सभी कारकों को समझना संभव नहीं है, लेकिन स्थिति की समग्रता में, मुझे लगता है, कोई भी इस प्रभाव को एक अर्थ दे सकता है कि लाभकारी उपयोग का अर्थ है

'समाज का लाभकारी उपयोग, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। मान लीजिए, इस देश में पानी की कमी है, इसलिए इसका उपयोग भी सख्त नियमों के अनुसार होना चाहिए।

आवश्यकता है और समान नहीं है। न्यायाधिकरण ने तीनों राज्यों को कृष्णा नदी के पानी के आवंटन के मामले में विभिन्न कारकों पर विचार किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, जो नदी के तटों का अंतिम मालिक है और फिर समुद्र में गिरती है। इसलिए कोई भी अतिरिक्त जल, जिसका उपयोग इन तीनों राज्यों में से किसी एक द्वारा नहीं किया जाता है, समुद्र में गिर जाता है। न्यायाधिकरण ने इस प्रकार आवंटन के मामले में पाँच कारकों पर विचार किया।

1 .

कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियों के पानी का आवंटन

पूरी तरह से एक या दूसरे राज्य को और शेष जल को विभाजित करना।

न्यायसंगत आधार पर।

किसी निचले राज्य को पानी की गारंटीकृत आपूर्ति की अनुमति देना

2 .

ऊपरी राज्य और शेष जल के उपयोग की अनुमति देना

ऊपरी राज्य किसी भी प्रतिबंध के साथ या उसके बिना।

3 .

किसी ऊपरी राज्य द्वारा अपने हिस्से के लिए डायवर्जन को प्रतिबंधित करना निर्धारित किया गया

एक न्यायसंगत आधार पर शेष पानी को कम उपयोग के लिए छोड़ दें राज्य।

4 .

तीन राज्यों को कृष्णा नदी का पानी आवंटित करना न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रतिशत।

5 .

तीनों राज्यों को कृष्णा नदी के पानी का बड़े पैमाने पर आवंटन एक निश्चित सीमा तक यह प्रावधान करते हुए कि पक्षों को [2000] 3 एस. सी. आर. साझा करना है।

438

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कुछ प्रतिशत में पानी अधिशेष के साथ-साथ घाटे के वर्ष।

इस मुद्दे से निपटने और इसके लिए योजना 'ए' प्रदान करने के बाद

हालांकि, न्यायाधिकरण ने स्वयं कहा कि "यह बेहतर होगा कि हम महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी के विभाजन के लिए दो योजनाएं तैयार करें। इन योजनाओं को योजना ए और बी कहा जाएगा। योजना ए अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत आधिकारिक राजपत्र में इस न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। योजना बी को उस स्थिति में लागू किया जा सकता है जब महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्य एक अंतर-राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन करते हैं जिसे उनके बीच समझौते द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ऐसे प्राधिकरण का गठन किए जाने की स्थिति में कृष्णा घाटी प्राधिकरण कहा जा सकता है। यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं

है कि योजना 'ए' समझौते पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। पक्षकार और न्यायाधिकरण के आदेश के आधार पर कार्य में आता है। यह योजना बी से पूरी तरह से स्वतंत्र है। हालांकि, न्यायाधिकरण अपने विवेक में यह स्पष्ट करता है कि योजना बी पार्टियों की सर्वसम्मति सहमति और अनुमोदन के बिना या संसद द्वारा कानून के अधिनियमन के बिना अमल में नहीं आ सकती है, लेकिन उसने योजना बी के तौर-तरीकों पर विस्तार से ध्यान दिया। इस आधार पर न्यायाधिकरण ने नीचे लिखे अनुसार अभिलिखित किया है:

" अब हम इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि कृष्णा नदी का पानी कैसे आता है।

योजना 'बी' के तहत पक्षों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। द.

इस योजना में आवश्यक तत्व यह है कि महाराष्ट्र राज्य,

मैसूर और आंध्र प्रदेश नदी के उपयोग योग्य जल को साझा करते हैं।

प्रत्येक जल वर्ष में निर्दिष्ट अनुपात में कृष्णा
उस वर्ष में पानी की उपलब्धता, अर्थात् यदि इसमें कोई कमी है।

न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित उनके शेयरों के अनुसार लाभ। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पानी के पूर्ण उपयोग का प्रावधान करता है।

पक्षों को अतिरिक्त निर्माण की अनुमति देकर कृष्णा नदी का

बहने वाले पानी को रोकने के लिए अपने क्षेत्रों में भंडारण
उस में उपयोग किए जाने वाले किसी भी जल वर्ष में भरोसेमंद प्रवाह से अधिक

बहुत जल वर्ष या बाद के जल वर्षों में। हम पहले से ही

इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की योजना को व्यावहारिक बनाने के लिए, एक
अंतर राज्य
प्रशासनिक प्राधिकरण, जिसे कृष्णा घाटी कहा जा सकता है

प्राधिकरण, पक्षों के बीच समझौते द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए

और कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा पक्षों के बीच इस तरह के समझौते में विफल होना।

वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.] 439

संसद की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 56 सूची I के तहत संविधान।

कृष्णा नदी के पानी के पूर्ण उपयोग के लिए हमारी राय है कि इस तरह के प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए

पर्यवेक्षण और विनियमन, यदि आवश्यक हो, कि पानी उपलब्ध है

प्रत्येक वर्ष कृष्णा नदी का उपयोग तीनों राज्यों द्वारा साझा किया जाना चाहिए। जिन कारणों का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, हम अपने आदेश के तहत ऐसा प्राधिकरण स्थापित नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा प्राधिकरण या तो पक्षों के बीच समझौते से या कानून के तहत स्थापित किया जाता है

हम अपने विचारों को अभिलेख पर रखना उचित समझते हैं कि उस स्थिति में कृष्णा नदी के पानी को महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाना चाहिए। अंततः यह पक्षों के लिए या उनके द्वारा बनाए गए कानून के लिए है।

संसद एक अंतिम योजना तैयार करेगी और हमारे विचार इसके अधीन हैं -

दोनों मामलों में संशोधन "।

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों ने कृष्णा घाटी प्राधिकरण को शक्तियाँ प्रदान करने के मामले में आपत्ति जताई थी।

विभिन्न कारणों से निचले राज्य के जलाशय से पानी स्थानांतरित करना। लेकिन न्यायाधिकरण ने इस टिप्पणी के साथ इसे नकार दिया था कि स्पष्ट रूप से कृष्णा घाटी प्राधिकरण (के. वी. ए.) उच्च श्रेणी के इंजीनियरों से बना होगा, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में पानी के हस्तांतरण के मामले में अपने विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे। हालाँकि, ठीक है, न्यायाधिकरण ने यह दर्ज करते हुए निष्कर्ष निकाला कि जहां तक योजना बी का संबंध है, ऐसी योजना को लागू करने का सवाल "दलों की अच्छी समझ या संसद के विवेक के लिए" छोड़ दिया गया है।

हालाँकि, दलों के मन में अभी तक "समझदारी" नहीं आई है और न ही संसद के विवेक ने उन्हें इस आधार पर कानून बनाने के लिए प्रेरित किया है और इस प्रकार, निचले नदी तटीय राज्य और दो ऊपरी नदी तटीय राज्यों के बीच विवादों के समाधान के मामले में योजना बी की शुरुआत। - ए-अर्थात्

न्यायाधिकरण के अपने दृष्टिकोण के अनुसार कृष्णा नदी से संबंधित जल विवाद उत्पन्न नहीं होता है और न ही हो सकता है और न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष के कारण, मैं योजना 'बी' के तौर-तरीकों का विवरण देने से खुद को रोकता हूँ।

इस प्रकार, इस स्तर पर उस मामले पर ध्यान देना सुविधाजनक होगा जिसके साथ पक्षकार अनुच्छेद 131 के आह्वान पर इस न्यायालय में आए हैं। संविधान से। लेकिन ऐसा करने से पहले, एक छोटा लेकिन दिलचस्प सवाल

संविधान [2000] 3 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 262 की व्याख्या के संबंध में विचार किया जाना चाहिए।

440

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और जैसा कि भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने यह तर्क देते हुए उठाया कि दोनों मुकदमों (ओएस नंबर 1 और ओएस नंबर 2) को अनुच्छेद 262 के तहत वर्जित किया जा रहा है, जिसमें उपयोग की जाने वाली भाषा का उचित सम्मान किया गया है। सुविधा के लिए, अनुच्छेद 262 नीचे दिया गया है।

" 262. अंतर-राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय या नदी घाटियाँ।

(1) संसद कानून द्वारा किसी के निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है

उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में शिकायत का विवाद किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल का।

(2) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, संसद कानून द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय

ऐसे किसी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। जैसा कि खंड (1) में संदर्भित है।

संयोग से, जबकि अनुच्छेद 262 विधायी अधिनियमों से संबंधित है

जिसमें उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का निष्कासन शामिल है: अनुच्छेद 131 दो राज्यों के बीच या एक या एक से अधिक राज्यों के बीच और दूसरी ओर या भारत संघ और अन्य राज्यों के बीच कोई विवाद होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता प्रदान करने से संबंधित है। हालाँकि, आइए हम अनुच्छेद 262 के तहत अधिकार क्षेत्र को हटाने के मुद्दे का विश्लेषण करें, जैसा कि भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री साल्वे ने तर्क दिया था। अनुच्छेद 262 का शीर्षक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे "जल से संबंधित विवादों" के रूप में पढ़ा जाता है और अनुच्छेद के मुख्य भाग में यह प्रावधान किया गया है कि कोई विवाद होने की स्थिति में, संसद किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद के निर्णय के लिए कानून द्वारा प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 262 इस संबंध में विशिष्ट है।

जल से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन जबकि अनुच्छेद 131 दो राज्यों आदि के बीच कोई विवाद होने की स्थिति में एक सामान्य शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता प्रदान करने का प्रावधान करता है। न तो अनुच्छेद 262 और अनुच्छेद 131 के बीच कोई टकराव है और न ही, इस प्रकार, इसमें शामिल क्षेत्र एक-दूसरे को ओवरलैप करते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा एक विशिष्ट बहिष्करण के बारे में सोचा गया है और संविधान में इसका प्रावधान किया गया है।

हालाँकि, वर्तमान में यह मुद्दा थोड़ा अलग है कि क्या

वर्तमान मुकदमा अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित अनुच्छेद 262 के तहत वर्जित है।

1956 का। यह अब तय हो गया है और मुझे इस आधार पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है कि कर्नाटक और ओ. आर. एस. का अंतर-राज्य राज्य।

» . ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.] 441

जल विवाद अधिनियम, 1956 को अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा संविधि पुस्तक में अधिनियमित किया गया है। की धारा 11

1956 का अधिनियम इस प्रकार है:

" 11. उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों की अधिकारिता का अवरोध किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय और किसी भी जल विवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करेगा जिसे संदर्भित किया जा सकता है

इस अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण।

इसलिए, सभी न्यायालयों की अधिकारिता को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इस संदर्भ में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है।

ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 522 (कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के मामले में) में जिसमें इस न्यायालय ने अनुच्छेद 262 और जल विवाद अधिनियम, 1956 का विश्लेषण करते हुए कहा:

" अनुच्छेद के विश्लेषण से पता चलता है कि संसद को ऐसे विवादों के निर्णय के लिए एक कानून बनाने की विशेष शक्ति दी गई है। जिन विवादों या शिकायतों के लिए निर्णय दिया जा सकता है, वे किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के "उपयोग, वितरण या नियंत्रण" से संबंधित हैं। "उपयोग", "डिस्ट्री ब्यूशन" और "नियंत्रण" शब्द व्यापक महत्व के हैं और इसमें उक्त जल का विनियमन और विकास शामिल हो सकता है। प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्णय के दायरे के विस्तार को इंगित करते हैं क्योंकि यह उक्त जल के उपयोग की सीमा और तरीके के निर्धारण और संबंध में निर्देश देने की शक्ति को अपने दायरे में लेगा।

उसी से। अनुच्छेद की भाषा को प्रविष्टि 56 और प्रविष्टि 17 से अलग किया जाना है। जहां अनुच्छेद 262 (1) किसी भी विवाद या शिकायत के निर्णय की बात करता है और वह भी किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में, प्रविष्टि 56 विनियमन और

अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विकास। इस प्रकार अनुच्छेद 262 और प्रविष्टि 56 के बीच अंतर यह है कि जहां पूर्व किसी भी अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवादों के निर्णय की बात करता है, प्रविष्टि 56 बताती है

अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास (जोर दिया गया)। प्रविष्टि 17 इसी तरह पानी की बात करती है, अर्थात्, जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन जल भंडारण और जल शक्ति।

[2000] 3

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह विवादों के निर्णय या किसी अंतर-राज्य की बात नहीं करता है।

वास्तव में यह पूरी तरह से नदी नहीं हो सकती, क्योंकि एक राज्य केवल इससे निपट सकता है।

अपने क्षेत्र के भीतर पानी। इन बातों का रखना होगा ध्यान अनुच्छेद 262, प्रविष्टि 56 और प्रविष्टि 17 के बीच अंतर

अध्यादेश की वैधता पर तर्क और प्रतिवाद

उन पर असर डालें।

हम पहले ही अनुच्छेद के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा कर चुके हैं।

262, अर्थात्।, अनुच्छेद के खंड (2) में प्रावधान है कि किसी भी संविधान में अन्य प्रावधान, संसद कानून द्वारा बहिष्कृत कर सकती है

संबंध में उच्चतम न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय की अधिकारिता

किसी विवाद या शिकायत के बारे में जिसके निर्णय के लिए -

ऐसे कानून में प्रावधान किया गया है। हमने यह भी नोट किया है कि धारा 11

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया है।

उक्त अधिनियम, जैसा कि इसकी प्रस्तावना से पता चलता है, इसके लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है

नदी घाटियाँ"। अधिनियम की धारा 2 का खंड (सी) "विवादों" को परिभाषित करता है। इस प्रकार है:

" 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

(अ)

(ख)

(ग) "जल विवाद" का अर्थ है दो या दो के बीच कोई विवाद या अंतर। के संबंध में अधिक राज्य सरकारें

(i) किसी भी क्षेत्र के जल का उपयोग, वितरण या नियंत्रण।

राज्य नदी या नदी घाटी;

((ii) संबंधित किसी भी समझौते की शर्तों की व्याख्या

ऐसे जल का उपयोग, वितरण या नियंत्रण या कार्यान्वयन

ऐसे समझौते का; या

((ग) निषेध के उल्लंघन में किसी भी जल दर का अधिरोपण।

धारा 7 में निहित है।

अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि यदि यह सरकार को किसी भी मामले में दिखाई देता है कर्नाटक और ओ. आर. एस. की प्रकृति के दूसरे राज्य की सरकार के साथ जल विवाद पर।

वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.]

443

उसमें कहा गया है कि उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, राज्य सरकार केंद्र सरकार से जल विवाद को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को भेजने का अनुरोध कर सकती है। अधिनियम की धारा 4 में विवाद को न्यायाधिकरण को भेजने के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है और केंद्र सरकार की राय है कि जल विवाद को बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 5 में न्यायाधिकरण से यह अपेक्षा की गई है कि वह उसे भेजे गए मामले की जांच करे और केंद्र सरकार को उसकी रिपोर्ट भेजे। निष्कर्ष और उसका निर्णय। केंद्र सरकार को तब अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्णय को प्रकाशित करना होता है जो निर्णय अंतिम और विवाद के पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और उन्हें उनके द्वारा प्रभावी बनाया जाना होता है। अधिनियम के ये प्रमुख प्रावधान, अन्य बातों के अलावा, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अधिनियम अपने शीर्षक के अलावा, संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 262 के प्रावधानों के अनुसार विशेष रूप से नदी तटीय राज्यों के बीच जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवादों के निर्णय के लिए बनाया गया है।

अंतर-राज्यीय नदियाँ या नदी घाटियाँ। यह अधिनियम प्रविष्टि 56 से संबंधित नहीं है और इसलिए, प्रविष्टि 56 या प्रविष्टि 17 द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को शामिल नहीं करता है। चूंकि उक्त विवादों के निर्णय के विषय का ध्यान रखा जाता है विशेष रूप से और विशेष रूप से अनुच्छेद 262 द्वारा, आवश्यक निहितार्थ द्वारा

प्रविष्टि 56 और 17 द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से विषय को बाहर रखा गया है। इसलिए, प्रविष्टि 56 के तहत संसद या प्रविष्टि 17 के तहत किसी राज्य विधानमंडल के लिए यह अनुमति नहीं है कि वह उक्त विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने वाला कानून बनाए या अनुच्छेद 262 के तहत विधि द्वारा स्थापित न्यायनिर्णयन या न्यायनिर्णयन प्रक्रिया या न्यायनिर्णयन के लिए तंत्र को किसी भी तरह से प्रभावित या हस्तक्षेप करे। यह इस तथ्य के अलावा है कि राज्य विधानमंडल अन्यथा अपने क्षेत्र से परे अंतर-राज्यीय नदी जल के संबंध में या ऐसे जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित अपने और किसी अन्य राज्य के बीच विवादों के संबंध में निर्णय लेने या किसी भी तरह से निर्णय लेने की प्रक्रिया या निर्णय को प्रभावित करने में अक्षम होगा। उसकी ओर से ऐसा कोई भी कार्य प्रकृति में अतिरिक्त-क्षेत्रीय होगा और इसलिए, इसकी क्षमता से परे होगा।

इसलिए, आइए हम ओ. एस. सं. की शिकायत में की गई प्रार्थनाओं का विश्लेषण करें। 1 और 2

श्री साल्वे द्वारा उठाए गए अधिकारिता प्रतिबंध के प्रश्न से निपटने के लिए। 1997 के ओएस नंबर 1 में प्रार्थना (कर्नाटक राज्य बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य) यहाँ नीचे दिए गए हैं और वे पढ़ते हैं:

" (क) आदेश और घोषणा करता है कि कृष्णा नदी में अधिशेष जल अर्थात्,

2060 टी. एम. सी. से अधिक 75 प्रतिशत निर्भरता पर, इसमें साझा किया जाना चाहिए

न्यायाधिकरण के निर्धारण और निर्देशों के अनुसार, [2000] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसकी रिपोर्ट (1973) और आगे की रिपोर्ट (1976) में निहित है।

(ख) आदेश और घोषणा करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 आंध्र राज्य

प्रदेश को अतिरिक्त जल के उपयोग के अपने अधिकार पर जोर देने का अधिकार नहीं है

अर्थात् 2060 टी. एम. सी. से अधिक 75 प्रतिशत निर्भरता पर, जब तक कि योजना

न्यायाधिकरण द्वारा बनाए गए बी को विधिवत और पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है

योजना को अधिसूचित करने के लिए अनिवार्य, डिक्री, आदेश और निषेधाज्ञा सहित
बी न्यायाधिकरण द्वारा तैयार किया गया और एक की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया

कृष्णा घाटी प्राधिकरण और के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए

न्यायाधिकरण ने रिपोर्ट (1973) और आगे की रिपोर्ट (1976) में, अंतर-राज्य जल
विवाद अधिनियम के Sec.6A के तहत विचार किया गया,

1956 .

(घ) प्रतिवादी को रोकने वाले स्थायी आदेश और निषेधाज्ञा के लिए

सं. 1 निम्नलिखित परियोजनाओं को जारी रखने से।, तेलुगु

गंगा, श्रीशैलम दाहिने किनारे की नहर, सिरीसैलम बाएं किनारे की नहर, भीम
लिफ्ट सिंचाई और पुलीचिंतला परियोजनाएं योजना बी तक

न्यायाधिकरण द्वारा तैयार किया गया कार्य विधिवत और प्रभावी रूप से लागू किया जाता है
और

लागू किया गया। (ई) मुकदमे की सुनवाई और अंतिम निपटान लंबित होने पर,
प्रतिवादी

योजना ए में आंध्र प्रदेश की परिकल्पना नहीं की गई है। (च) मुकदमे की सुनवाई
और अंतिम निपटान तक, प्रतिवादी

आंध्र प्रदेश राज्य को इसके आदेश और निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाए।

माननीय न्यायालय, अतिरिक्त जल के किसी भी हिस्से का उपयोग करने से

गंगा, श्रीशैलम दाहिने किनारे की नहर, सिरीसैलम बाएं किनारे की नहर, भीमा
लिफ्ट सिंचाई और पुलीचिंतला परियोजनाएं लागू होने तक

न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई योजना बी।

(छ) ऐसे अन्य राहों के लिए जो मामले की प्रकृति की आवश्यकता होती है।

वर्तमान मुकदमा (1997 का ओ. एस. नंबर 1) इस प्रकार एक घोषणा के लिए एक मुकदमा है
कि

इसके अलावा नदी में 2060 टी. एम. सी. से अधिक का पानी 75 प्रतिशत निर्भरता पर सभी के निर्धारण और घोषणा के अनुसार साझा किया जाता है। दूसरी प्रार्थना इस घोषणा से भी संबंधित है कि कर्नाटक राज्य और ओआरएस।

वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.] 445

आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त जल के उपयोग के अपने अधिकार पर जोर देने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, वाद संख्या 1 में मुख्य प्रार्थना न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई योजना बी को अधिसूचित करने और जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 6 ए के तहत कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना है। हालाँकि, उपरोक्त तीन प्रार्थनाएँ,

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कर्नाटक के वादी राज्य ने इस न्यायालय का रुख किया है 1973 और 1976 की रिपोर्टों में निहित न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार किसी अधिकार की पुष्टि के लिए। यह किसी भी जल विवाद से संबंधित नहीं है, न ही शिकायत में किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा होने का दावा किया जा सकता है। तथापि, भारत संघ की ओर से उपस्थित श्री साल्वे ने अनुच्छेद 262 के तहत गैर-रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे की शुरुआत करते हुए तर्क दिया कि 1956 के अधिनियम की धारा 2 (सी) 'जल विवाद' शब्दों की परिभाषा के कारण व्यापक संभव विस्तार की है। 'जल विवाद' को 1956 के अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

" 2.ए एंड बी

(ग) "जल विवाद" से दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच (i) किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में कोई विवाद या अंतर अभिप्रेत है; या (ii) ऐसे जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी समझौते की शर्तों की व्याख्या या

ऐसा समझौता; या (iii) उल्लंघन में किसी भी जल-दर का शुल्क

धारा 7 में निहित निषेध।

हालाँकि, धारा 11 के अधीन होने के लिए पानी से संबंधित विवाद का संबंध उपयोग, वितरण और नियंत्रण से होना चाहिए।

परिभाषा खंड स्वयं, क्योंकि उसी ने विशेष रूप से 'किसी भी नदी में पानी का उपयोग, वितरण और नियंत्रण' अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। यदि यह 'उपयोग, वितरण या नियंत्रण' अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आता है, तो धारा 11 किसी भी जल विवाद के संबंध में सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है। जिसे अन्यथा न्यायाधिकरण को भेजा जाना है, उसके आवेदन का कोई तरीका नहीं होगा। इस प्रकार किसी न्यायालय में किसी राज्य द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाई की स्थिरता की कसौटी यह होगी कि क्या उसमें उठाए गए मुद्दे निर्णय के लिए किसी न्यायाधिकरण को भेजे जाने में सक्षम हैं। विचाराधीन मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, किसी भी जल विवाद के निर्णय का प्रश्न

धारा 2 (सी) का अर्थ उत्पन्न नहीं होगा। मुकदमा कार्यान्वयन से संबंधित है,

लेकिन [2000] 3 एस. सी. आर. के बीच जल अधिकारों के किसी और निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

446

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्यों। इस न्यायालय के दो निर्णयों का संदर्भ एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम. निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य।, [1952] एस. सी. आर. 218 और मोहिंदर सिंह गिल और अन्र। वी. मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य।, [1978] 2 प्रासंगिक तथ्यों में एस. सी. आर. 272 की बहुत अधिक प्रासंगिकता नहीं हो सकती है; इस प्रकार, हमें इससे निपटने में खुद को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 329 (बी) की पूर्ण शक्ति, जो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की प्रक्रिया को परिणामों की औपचारिक घोषणा में उसकी पराकाष्ठा तक ले जाने के लिए उठाए गए चुनावी कदमों को कानूनी चुनौती देने पर पूर्ण प्रतिबंध है, सिद्धांतों पर टिकी हुई है।

मोहिंदर सिंह गिल के मामले में अधिक विस्तृत। लेकिन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रासंगिक तथ्य किसी भी विस्तृत चर्चा की गारंटी नहीं देते हैं और इसलिए मैं टालता हूं। इस संबंध में ऐसा करने से। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि जहां जल विवाद का निर्णय अनुच्छेद 262 के साथ पठित 1956 के अधिनियम की धारा 11 में निहित शक्ति के कारण पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन मामले के तथ्यात्मक पहलू के कारण और निर्णय के बजाय पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए प्रार्थना के कारण, धारा 11 के अधिवक्ता की शरारत का कोई भी आवेदन नहीं होगा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए श्री साल्वे द्वारा उठाए गए प्रारंभिक मुद्दे को

स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बहिष्करण का प्रावधान विचाराधीन मामले की परिस्थितियों के तथ्यों में लागू है। इसलिए, मुकदमा अन्यथा बनाए रखने योग्य है।

जहाँ तक दूसरे मुकदमे के संबंध में 1997 का ओ. एस. संख्या 2 (आंध्र राज्य) है।

प्रदेश बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य) और उसमें प्रार्थनाओं के अवलोकन से संकेत मिलता है कि वाद की मात्रा के उपयोग के संबंध में एक घोषणा के लिए है

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों द्वारा अनुमत जल। और उन्हीं कारणों से श्री साल्वे द्वारा उठाया गया प्रारंभिक मुद्दा और 1997 का दूसरा मुकदमा O.S.No.2 भी विफल हो जाता है।

इस मुद्दे में मामले के गुण-दोष की ओर ध्यान देना, चाहे इस पर ध्यान दिया जाए

कि पक्षों के कहने पर, धारा 11 के साथ पठित अनुच्छेद 262 के तहत मुकदमों की गैर-रखरखाव के प्रारंभिक मुद्दे के अलावा दोनों मुकदमों में कुल 34 मुद्दे उठाए गए हैं। हम पक्षों की ओर से कई दिनों से किए गए सबसे विद्वान निर्देशात्मक और स्पष्ट प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं। लेकिन मेरे विचार में विवाद का क्षेत्र सीमित है और इसका दायरा प्रतिबंधात्मक है और इसलिए मुझे उपरोक्त मुकदमों में उठाए गए सभी मुद्दों को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, निश्चित रूप से, यदि मैं यह नोट कर सकता हूँ कि हमारे समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ सबसे अधिक ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद रही हैं, तो यह आकलन करने के लिए कि मामले का मूल न्यायिक दृष्टिकोण के बुनियादी तत्वों में से एक है और यह इस संदर्भ में है, मुझे यह दर्ज करना समीचीन लगता है कि 1997 के ओ. एस. नंबर 1 में, एकमात्र प्रश्न जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है वह कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. के बारे में है।

वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.] 447

क्या कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा सुझाए गए योजना 'बी' को 1956 के अधिनियम की धारा 6 के अर्थ के भीतर एक निर्णय कहा जाए। जहाँ तक दूसरे मुकदमे का संबंध है, जहाँ आंध्र प्रदेश राज्य ने 1997 की ओ. एस. संख्या 2 होने के कारण न्यायालय में कार्रवाई शुरू की थी, अल्माटी में बांध की ऊंचाई विचार का केंद्र बिंदु है और इसी आधार पर इस न्यायालय ने निर्णय के लिए मुद्दा संख्या 9 (ए) और (बी) रखने पर प्रसन्नता व्यक्त की है, जो नीचे दिया गया है:

\$

" 9. (क) क्या अन्य सभी परियोजनाओं के साथ 524.256 मीटर के एफआरएल के साथ अलमट्टी बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

और कर्नाटक द्वारा विचार किए जाने से यह अधिक पानी का उपयोग करने में सक्षम होगा।

न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित की तुलना में?

(ख) क्या कर्नाटक को अन्य नदी तटीय राज्यों की सहमति के बिना इस तरह के बांध के निर्माण के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है, और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना?

यहाँ यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि विद्वान प्रस्तुतियाँ ओ. एस. नंबर 1 और ओ. एस. नंबर 2 होने वाले दो मुकदमों में इन दो मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं और जिन्होंने वास्तव में इस पीठ के समक्ष 25 से अधिक सुनवाई की है।

हालाँकि, इस मोड़ पर यह ध्यान रखना सुविधाजनक होगा कि योजना बी से संबंधित मुद्दा-चाहे निर्णय हो या नहीं, सबसे अधिक प्रासंगिक है और सभी महत्वपूर्ण मुद्दे। लेकिन तथ्यात्मक पहलुओं पर उससे निपटने से पहले,

1956 के अधिनियम में उपयोग किए गए 'निर्णय' शब्द के सटीक अर्थ का जल्दबाजी में उल्लेख किया जाना चाहिए। आम अंग्रेजी स्वीकृति में हम

" "निर्णय" का अर्थ और तात्पर्य समाधान निष्कर्ष है: औपचारिक निर्णय: हल किया गया (संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, नया सातवां संस्करण)। हालाँकि, हमारी स्थिति इस मायने में थोड़ी आसान है कि कानून (1956 का अधिनियम) की भाषा अपेक्षाकृत सरल और स्पष्ट है। अधिनियम की धारा 5 (2) विशेष रूप से प्रदान करती है कि जब एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है

धारा 4, न्यायाधिकरण उसे भेजे गए मामलों की जांच करेगा और केंद्र सरकार को उसके द्वारा पाए गए तथ्यों को प्रस्तुत करने वाली एक रिपोर्ट भेजेगा और

उसे निर्दिष्ट मामलों का निर्णय देते हुए और धारा 5 (3) में यह प्रावधान है कि यदि न्यायाधिकरण के निर्णय पर विचार करने पर, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की राय है कि उसमें निहित किसी भी चीज़ के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार या राज्य

सरकार निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर, फिर से संदर्भित करती है

न्यायाधिकरण को विचार के लिए विषय और न्यायाधिकरण का निर्णय [2000] 3 एस. सी. आर.

448

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तदनुसार संशोधित स्थिति।

संयोग से, प्रासंगिक तथ्यों में न्यायाधिकरण का निर्णय था

न्यायाधिकरण ने 1973 में घोषित किया, लेकिन 1956 के अधिनियम की धारा 5 (3) के संदर्भ में आवेदनों के कारण, वर्ष 1976 में एक और रिपोर्ट प्रकाशित की। यह ध्यान दिया जाए कि धारा 5 के संदर्भ में निर्णय द्वारा प्रकाशित किया जाना आवश्यक है

केंद्र सरकार और सरकारी राजपत्र में इस तरह के प्रकाशन पर 1956 के अधिनियम की धारा 6 की शर्तों के अनुसार, न्यायाधिकरण का निर्णय विवाद के पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और उनके द्वारा प्रभावी किया जाएगा। न्यायाधिकरण का निर्णय, इस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

न्यायाधिकरण द्वारा जल विवाद के निर्णय का मामला। अवधारणात्मक रूप से-एक आदर्श स्थिति: संविधान निर्माता अपनी महान विचारशीलता में और

भाषा और रीति-रिवाजों के विचलन का कारण यह है कि सभी अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान इसके लिए गठित न्यायाधिकरण के निर्णय से करना होगा। तत्काल मामले में वास्तव में एक ऐसा न्यायाधिकरण था जो तीनों राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी के आवंटन के मुद्दे पर गया जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू किया जाना है और यह है

एक सांविधिक आवश्यकता, इसलिए, और परिणामस्वरूप निर्णय आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के तुरंत बाद इसकी निर्णायकता और इसकी बाध्यकारी प्रकृति ग्रहण करेगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुद्दा संख्या 2, जैसा कि इससे पहले उठाया गया था,

न्यायाधिकरण और यहाँ पहले नोटिस किया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा योजनाएं, न्यायाधिकरण द्वारा सुझाए गए विस्तृत योजना के माध्यम से अंतिम आदेश में ही जवाब दिया

गया है। हालांकि, योजना बी को अंतिम क्रम में जगह नहीं मिलती है। मान लीजिए, न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे को कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना द्वारा विवादों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक योजना के रूप में देखा और यह योजना है-यह दूसरी योजना है जिसे कर्नाटक राज्य के वादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरीमन ने तर्क दिया कि इस योजना को स्वयं न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश और निर्णय के एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए और इस तरह इसे लागू किया जाना चाहिए।

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस अधिकार की बात की गई है (कृष्णा घाटी)

प्राधिकरण) न्यायाधिकरण के आदेश के संदर्भ में स्वयं को या तो पक्षों के बीच समझौते द्वारा या संविधान की दूसरी अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा स्थापित किया जाना है। न्यायाधिकरण ने किसी भी अनिश्चित शर्तों में कहा कि औचित्य इस तरह के प्राधिकरण के गठन को अधिकृत नहीं करेगा। यदि मैं न्यायाधिकरण को पूरे सम्मान के साथ बता सकता हूँ कि कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. में मामले में शामिल किसी भी औचित्य का कोई सवाल ही नहीं है।

» . ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.] 449

चूंकि न्यायाधिकरण कानून का एक हिस्सा होने के नाते किसी भी बोर्ड या प्राधिकरण का गठन करने के लिए कोई अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं था-इसलिए उसे कार्य करना पड़ता है

कानून के तहत निर्धारित मापदंडों के भीतर और ऐसे प्राधिकरण के अभाव में, किसी भी औचित्य का सवाल नहीं उठता है और न ही उठ सकता है। कानून में प्रावधान है कि न्यायाधिकरण के निर्णय का, इस तरह के निर्णय के प्रकाशन पर, जल विवाद के पक्षों पर एक बाध्यकारी बल होगा। सबसे अच्छा, योजना बी और कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव से संबंधित टिप्पणियां केवल अनुशंसित प्रकृति की हो सकती हैं क्योंकि योजना बी स्वीकार्य रूप से न्यायाधिकरण के निर्णय का हिस्सा नहीं है जिसे केंद्र सरकार द्वारा कानून के प्रावधानों के संदर्भ में प्रकाशित किया गया है।

हालांकि, यह उपरोक्त के कारण है कि मुझे आश्चर्य है कि न्यायाधिकरण ने स्वीकार किए जाने पर एक वैकल्पिक योजना तैयार करने का बीड़ा उठाया है।

इसके पास कृष्णा घाटी प्राधिकरण का गठन करने की कोई शक्ति, अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिसे "योजना बी का केंद्र" माना जाता है। न्यायाधिकरण को इस संबंध में कानून बनाने

के लिए या तो पक्षों की अच्छी अंतरात्मा या विधायिका की विधायी इच्छा पर भरोसा करना पड़ा है।

न्यायाधिकरण के प्रति उचित सम्मान के साथ मैं फिर कहता हूँ कि मैं योजना 'बी' के रूप में दूसरी योजना का प्रस्ताव करने की आवश्यकता की सराहना नहीं कर पाया हूँ जब

न्यायाधिकरण ने स्वयं कहा:

" पानी के हस्तांतरण का निर्देश देते समय, कृष्णा घाटी

आई.

प्राधिकरण राज्य द्वारा इस प्रकार हस्तांतरित किए गए पानी का उपयोग करने के तरीके के बारे में उचित निर्देश दे सकता है।
पानी लेते हैं। "

" यदि यह जल वर्ष के अंत में अंतिम लेखांकन पर पाया जाता है

II.

कि किसी भी राज्य द्वारा जल वर्ष में उपयोग किया जाने वाला पानी पैराग्राफ 2 के तहत उसके हिस्से से अधिक या कम है, उक्त प्राधिकरण -

पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन, ऐसे कदम उठाएं जो दोनों पक्षों द्वारा किए जाने वाले पानी के उपयोग की सीमा को विनियमित करके पक्षकारों के जल खातों को समायोजित करने के लिए आवश्यक हों।

आने वाले वर्षों में बताएँ "।

III "। कृष्णा घाटी प्राधिकरण अस्थायी रूप से निर्धारित करेगा

सभी राज्यों के शेयर।

" कृष्णा घाटी प्राधिकरण देने की स्थिति में होगा

IV.

पक्षों को अपने उपयोग को इस तरह से समायोजित करने का निर्देश 450

[2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि एक जल वर्ष के अंत में प्रत्येक राज्य द्वारा किया गया उपयोग है जहाँ तक संभव हो "।

" कृष्णा घाटी प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पक्ष प्राप्त करें

वी.

उनके हिस्से के अनुपात में पानी। इस उद्देश्य के लिए ले सकते हैं कोई भी कदम जो उसे किसी भी समय उचित लगे।

VI "। कृष्णा घाटी प्राधिकरण हस्तांतरण का निर्देश भी दे सकता है

परियोजना से ऊपरी राज्य से निचले राज्य की परियोजना तक पानी समय-समय पर बताएँ "।

VII "। हम मानते हैं कि कृष्णा घाटी प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

उच्च श्रेणी के इंजीनियर जिनका उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है एक राज्य से दूसरे राज्य को जल अंतरण के मामले में विवेकाधिकार

एक और विवेकपूर्ण तरीके से "।

VIII "। एक अत्यधिक सक्षम निकाय जैसे कि कृष्णा घाटी प्राधिकरण

जिसमें न केवल राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे

लेकिन भारत सरकार भी उचित ध्यान रखेगी जबकि

एक राज्य से दूसरे राज्य में जल अंतरण का निर्देश देना। ए के रूप में अधिक सुरक्षा, यह प्रदान किया जा सकता है कि निर्देश

एक राज्य से दूसरे राज्य में जल का अंतरण -

एक बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सभी उपलब्ध

भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य उपस्थित हैं।

ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट से ऊपर दिए गए उद्धरण से एक

स्पष्ट निष्कर्ष कि न्यायाधिकरण कृष्णा घाटी प्राधिकरण को कुछ दिशानिर्देश प्रदान करना चाहता था जब भी इसका गठन किया जाता है और विशेष रूप से, न्यायाधिकरण ने स्वयं इसे पक्षकारों की अच्छी समझ और बेहतर सराहना या ऐसे प्राधिकरण के गठन के लिए विधायी इरादे पर छोड़ दिया है-यह वह जगह है जहाँ मैं सम्मानपूर्वक इस मुद्दे में शामिल होता हूँ: यहां तक कि आज तक वैचारिक रूप से प्राधिकरण का जन्म नहीं हुआ है और इस प्रकार भ्रूण अवस्था में भी नहीं है।

इसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में श्री परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए और श्री साल्वे, सॉलिसिटर जनरल

भारत संघ की ओर से पेश हुए और श्री अंधारुजिना, वरिष्ठ अधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश होते हुए समान स्वर में तर्क दिया गया कि वाद (1997 का ओ. एस. संख्या 1) में दो योजनाओं का समामेलन होने के कारण किसी भी राहत के अनुदान का सवाल ही नहीं उठेगा। वास्तव में, कर्नाटक और ओ. आर. एस. का विद्वान राज्य।

वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.] 451

भारत संघ के सॉलिसिटर जनरल ने अपने आदेश में न्यायाधिकरण के निम्नलिखित बयानों की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित किया:

" इस मामले पर गहराई से विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बेहतर होगा कि हम महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी के विभाजन के लिए दो योजनाएं तैयार करें। इन योजनाओं को योजना ए और बी कहा जाएगा। योजना ए इस न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत राजपत्र। योजना बी को राज्यों के मामले में लागू किया जा सकता है -

महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश एक अंतर-राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन करते हैं जिसे उनके बीच समझौते से या संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ऐसे प्राधिकरण का गठन किए जाने की स्थिति में कृष्णा घाटी प्राधिकरण कहा जा सकता है। योजना 'क' पक्षकारों की सहमति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है और न्यायाधिकरण के आदेश के आधार पर लागू होती है। यह पूरी तरह से योजना बी से स्वतंत्र है।

" अंत में जहां तक योजना बी का संबंध है, हम इस तरह की योजना को लागू करने का सवाल दलों की सद्भावना या संसद के विवेक पर छोड़ते हैं।

न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त रूप में दर्ज किए गए बयानों के मद्देनजर, मुझे न्यायाधिकरण के निर्णय के रूप में योजना बी को जोड़ने का कोई कारण नहीं दिखता है।

1956 के अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशन या अधिसूचना की आवश्यकता।

1956 के अधिनियम की धारा 6 न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन का प्रावधान करती है और इसकी भाषा में और इसके विश्लेषण पर विशिष्ट है

ऐसा प्रतीत होता है कि 1956 के अधिनियम के अर्थ के भीतर जल विवाद से संबंधित न्यायाधिकरण द्वारा केंद्र सरकार को एक निर्णय सूचित किए जाने की स्थिति में, प्रकाशित करने के लिए एक वैधानिक और अनिवार्य आवश्यकता मौजूद है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, न्यायाधिकरण ने स्वयं अनिश्चित शब्दों में अभिलिखित किया कि जहां तक योजना बी का संबंध है, उसके प्रवर्तन का प्रश्न पक्षों की अच्छी समझ या संसद के विवेक पर निर्भर करेगा। इस प्रकार यह 1956 के अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में एक निर्णय नहीं है ताकि जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, इसके प्रकाशन के लिए एक दायित्व पैदा किया जा सके। न्यायाधिकरण ने स्वयं इसके साथ अलग व्यवहार किया है और बिना किसी अनिश्चित शब्दों में दर्ज किया है कि जबकि योजना ए को लागू किया जाना चाहिए [2000] 3 एस. सी. आर.

452

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तत्काल, योजना बी का प्रवर्तन दोनों आकस्मिकताओं में से किसी एक के घटित होने पर प्रभावी होगा जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

एक लाभप्रद विशेषता जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, ठीक है, यह सच है कि इसके बावजूद

अनुच्छेद 262 और वर्तमान वाद (1997 का ओ. एस. संख्या 1 और 2) के तथ्य के बावजूद अनुच्छेद 262 द्वारा प्रभावित नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह न्यायालय को एक ऐसे मुद्दे पर निर्णय देने के लिए तैयार नहीं करता है जिसे न्यायाधिकरण ने स्वयं खुला रखना उचित समझा

था। आदेश में योजना बी के मुद्दे से निपटने के लिए न्यायाधिकरण की ओर से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग पूरी तरह से इसके दायरे से बाहर है

न्यायाधिकरण और जैसा कि ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक तथ्यों में, किसी भी खंड में कोई कार्यान्वयन योग्य योजना बी नहीं है और न ही इसे तीनों के बीच कृष्णा घाटी जल विवाद से संबंधित न्यायाधिकरण का निर्णय कहा जा सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य। संक्षेप में, एक कार्यान्वयन योग्य निर्णय होना चाहिए और जब न्यायाधिकरण ने स्वयं अपने गैर-निर्णय को दर्ज किया है।

कार्यान्वयन क्षमता, केंद्र को मंडमस का आदेश जारी करना

इस न्यायालय द्वारा सरकार अनुच्छेद 131 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्पन्न नहीं होती है और न ही हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थना के संबंध में एक और आलोचना हुई है

विद्वान महान्यायवादी द्वारा योजना बी की अधिसूचना के लिए। उनके अनुसार, न्यायाधिकरण का निर्णय वर्ष 1973 में सुनाया गया था और धारा 5 (3) की कार्यवाही के बाद आगे की रिपोर्ट वर्ष 1976 में आई और योजना बी को सबसे अच्छी तरह से एक सिफारिश होने के नाते वर्ष 1997 में निर्णय नहीं माना जा सकता है और मैं निश्चित रूप से श्री के साथ सहमत हूं।

सॉलिसिटर ने कहा कि एक न्यायाधिकरण एक ऐसा निर्णय नहीं सुना सकता है जिसके कार्यान्वयन के लिए संसद द्वारा या पक्षों की सहमति से अधिनियमित एक कानून की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि केंद्र सरकार विवाद में एक पक्ष नहीं है और न्यायाधिकरण के पास अन्यथा कोई निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और इसके विपरीत, केंद्र सरकार के पास किसी भी निर्देश को लागू करने के लिए सहमत होने का कोई दायित्व नहीं होगा।

योजना बी को वैकल्पिक के अधीन स्पष्ट रूप से अनुशंसित किया गया है।

आकस्मिकताएँ-(I) पक्षों के बीच एक समझौता या (II) 453 द्वारा एक विधान

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.]

संसद और यह इस अंतराल के दौरान भी दोनों में से किसी भी घटना को पूरा न करने के कारण, योजना बी के निर्णय के रूप में अधिसूचित होने में सक्षम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। संक्षेप में योजना बी,

यह एक निर्णय नहीं होगा। जिस कृष्णा घाटी प्राधिकरण के बारे में पहले कहा गया था और जो इस योजना का केंद्र है, उसे केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाना चाहिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र

सरकार ने अभी तक ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं बनाया है, योजना बी को लागू करने का सवाल, क्योंकि न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं आता है और न ही हो सकता है। यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि संभवतः कोई बाध्यकारी निर्देश भी नहीं हो सकता है और वास्तव में, कृष्णा घाटी प्राधिकरण जैसे प्राधिकरण के गठन के मामले में कुछ भी नहीं हुआ है-इसे केवल दलों की सहमति और विधायिका के विधायी इरादे पर छोड़ दिया गया है।

हालाँकि, आइए हम इस स्तर पर जल्द ही रिकॉर्ड करें कि पार्टियों के पास क्या है

न्यायाधिकरण की रिपोर्ट बनाम योजना बी और कृष्णा घाटी प्राधिकरण के गठन पर विचार किया गया। हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य, वादी (कर्नाटक राज्य) की योजना बी को लागू करने या कृष्णा घाटी प्राधिकरण के गठन की इच्छा को भी नकारते हैं।

1989 में भारत सरकार के सचिव,

जल संसाधन ने 2 मई, 1989 को कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को संबोधित एक पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित जानकारी दी:

यह याद किया जा सकता है कि कृष्णा बेसिन के संबंध में कृष्णा नदी प्राधिकरण की अवधारणा का वर्णन पहले ही किया जा चुका है।

योजना "बी" के संदर्भ में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण

कृष्णा जल के पूर्ण उपयोग का प्रावधान।

इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर उद्धृत घटनाक्रमों और कर्नाटक सरकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के मुद्दे पर विचार किया जाए ताकि उचित कदम उठाए जा सकें।

ले जाया जाए "।

कर्नाटक राज्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण, आगे के पत्र लिखे गए और अंततः 17 अगस्त, 1992 को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट आई।

[2000] 3 एस सी आर ।

454

कर्नाटक सरकार के सचिव, सिंचाई विभाग ने भारत सरकार के सचिव, जल संसाधन मंत्रालय (Ex.P.K.93) को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ एक पत्र संबोधित किया:

" मैं ऊपर दिए गए पत्र के संदर्भ को आमंत्रित करने और सूचित करने के लिए लिख रहा हूँ

आप इस प्रकार हैं:

(क) कर्नाटक राज्य इस विषय की गहराई से जाँच कर रहा है -

द्वारा तैयार किए गए आवंटन की योजना "बी" को लागू करने के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ।

अल ।

(ख) इस विषय पर कर्नाटक के विचारों को सूचित किया जाएगा ।

जैसे ही इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाता है ।

कृष्णा में राज्यों के हितों पर दूरगामी प्रभाव बेसिन " ।

इसके बाद, कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में,

कर्नाटक सरकार के अवर सचिव, सिंचाई विभाग

भारत सरकार के सचिव को 30.8.93 दिनांकित एक पत्र संबोधित करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय निम्नलिखित प्रभाव से:

" मुझे 17.8.92 दिनांकित सरकारी पत्र का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है ।

कर्नाटक की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ और संप्रेषण करना ।
कृष्णा घाटी की स्थापना पर

(क) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम निर्णय में विचार किया है।
आदेश, कार्यान्वयन के लिए केवल योजना "ए", अर्थात् 75 प्रतिशत का आवंटन

केवल भरोसेमंद प्रवाह। न्यायाधिकरण का आदेश समीक्षा के लिए आता है

आवंटन की योजना "ए" के अनुसार परियोजनाओं का कार्यान्वयन
न्यायाधिकरण द्वारा। न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम आदेश में इस पर विचार नहीं किया है

आवंटन की योजना "ए" के लिए स्थापित की जाने वाली कोई भी मशीनरी और

इसलिए इसे स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(जोर

दिया गया)

(ख) तंत्र के गठन पर केवल योजना के लिए विचार किया गया था।

" बी "जहाँ अधिशेष प्रवाह को भी आवंटित किया जाना था। लेकिन योजना "बी"

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. » . ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.] 455

न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं था और न ही पक्ष अभी तक योजना
"बी" के लिए सहमत हुए हैं। मशीन तभी आ सकती है जब

पार्टियां योजना "बी" का विकल्प चुनती हैं। (जोर दिया गया)

(ग) हालांकि, योजना "बी" के संदर्भ के बिना भी, अतिरिक्त पानी को पक्षों द्वारा
आपसी समझौते से साझा किया जा सकता है। बेसिन

वर्तमान में राज्य इस पर विचार कर रहे हैं।

(घ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक सरकार की दृढ़ राय है कि कृष्णा
घाटी प्राधिकरण की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

उपस्थित "। (जोर दिया गया)

19 सितंबर, 1995 के अंत तक के दस्तावेजी साक्ष्य इस मामले में कुछ सहायक होंगे, जैसा
कि पत्र में कहा गया है।

कर्नाटक सरकार के सचिव, सिंचाई विभाग से लेकर मुख्य अभियंता (पी. ए. ओ.), केंद्रीय जल आयोग, पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ

निम्नलिखित:

" कार्यवाही के पृष्ठ-3, पैरा-1 में आगे यह उल्लेख किया गया है कि

कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव पर सहमति हो सकती है -

अंतर-राज्य कृष्णा-घाटी प्राधिकरण का गठन। इस संदर्भ में, मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमत होने के बारे में नहीं कहा था, लेकिन

प्रस्ताव यह था कि केंद्रीय जल आयोग या ऐसा कोई

प्राधिकरण यू. के. पी. के तहत अलमट्टी बांध से नियमों की निगरानी कर सकता है

अलमट्टी बांध के एफ. एफ. एल. को 521 मीटर पर रखने का प्रस्ताव, और

योजना के अनुसार यू. के. पी. के तहत उपयोग 177 टी. एम. सी. तक सीमित है। कृष्णा जल पुरस्कार के आधार पर कर्नाटक राज्य द्वारा बनाया गया

विवाद न्यायाधिकरण। "

इसके तुरंत बाद, 20 नवंबर, 1995 को एक पत्र द्वारा श्री पी. बी.

भारत सरकार के जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रंगय्या नायडू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच. डी. देवेगौड़ा को एक पत्र संबोधित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें लिखी गई हैं:

" न्यायाधिकरण ने एक योजना 'बी' पर विचार किया था जिसकी परिकल्पना की गई थी

कृष्णा नदी में औसत प्रवाह का उपयोग। कार्यान्वयन के लिए

इस योजना के तहत एक कृष्णा घाटी स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी

प्राधिकरण। इसने नदी [2000] 3 एस. सी. आर. के पानी का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कृष्ण। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने अपनी योजना में योजना 'बी' को शामिल नहीं किया।

अंतिम आदेश।

राष्ट्रीय जल संसाधन द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति

सितंबर, 1987 में परिषद ने निर्धारित किया कि नदी बेसिन होना चाहिए

जल संसाधनों की योजना और विकास के लिए एक इकाई के रूप में लिया गया। के साथ नीति के प्रमुख घटकों को संचालित करने के लिए एक दृष्टिकोण, एक उप

जल मंत्रालय की सलाहकार समिति की समिति संसाधन तैयार किए गए। इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि

सभी प्रमुख अंतर-राज्यीय नदियों के लिए, नदी बेसिन संगठनों को

उपयुक्त कानून बनाकर स्थापित किया गया।

यदि आप सहमत हैं, तो मैं एक बैठक बुलाता हूँ।

कृष्ण की स्थापना के लिए संविधान और कार्य और तौर-तरीके घाटी प्राधिकरण "।

उक्त पत्र पी. के.-97 का उत्तर देने के लिए, दिनांकित 3.2.96 (P.K.98) का कुछ महत्व है और इसे नीचे दिया गया है:

" कृपया ऊपर दिए गए अपने डी. ओ. पत्र को देखें जिसमें एक प्रस्ताव दिया गया है।

कृष्णा बेसिन के सिंचाई मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए बनाया गया

संविधान और कार्य और तौर-तरीकों को तैयार करने के लिए राज्य कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के लिए।

इस संबंध में, मैं इस योजना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

बी जैसा कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा परिकल्पित है जो

नदी के पानी का पूर्ण और बेहतर उपयोग प्रदान करता है।

कृष्ण। केवल इस योजना के लागू होने पर, कृष्ण

घाटी प्राधिकरण की स्थापना करनी होगी।

अब तक मुख्यमंत्रियों के स्तर पर तीन अंतर-राज्यीय बैठकें हो चुकी हैं।

पहली बैठक तिरुपति में 21.4.1990 पर आयोजित की गई, दूसरी बैठक

मैसूर में 22.8.1990 पर और 22.5.1993 पर तीसरी बैठक

अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कृष्णा घाटी प्राधिकरण का संविधान पालन कर सकता है,

जब एक बार योजना बी पर आम सहमति बनती है।

टी 457

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. » . ए. पी. राज्य (बनर्जी, जे.)

इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से चित्रित करने के लिए प्रचुर हैं।

योजना बी के कार्यान्वयन या कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के बारे में वर्ष 1996 तक कर्नाटक राज्य का इरादा। वास्तव में, श्री परासरन के इस तर्क में कुछ औचित्य प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण की रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार करने पर योजना बी के कार्यान्वयन का सवाल ही नहीं उठेगा। योजना बी

यह केवल वैसा ही प्रभावी होगा जैसा कि दो आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर तर्क दिया गया था जैसा कि अधिक पूरी तरह से ऊपर उल्लेख किया गया है और चूंकि कोई भी आकस्मिकता नहीं हुई थी, इसलिए योजना बी के कार्यान्वयन का सवाल ही पैदा नहीं होगा और इसी आधार पर श्री परासरन ने इस मामले में प्रकट किए गए पत्राचार पर बहुत जोर दिया, जिसके बाद यह स्पष्ट है कि कर्नाटक कभी भी योजना बी को लागू नहीं करना चाहता था और न ही कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना करना चाहता था। यहाँ तक कि केंद्रीय जल आयोग की नदी तट मालिकों को दी गई एहतियाती सलाह का भी कोई परिणाम नहीं निकला और तथ्यों की स्थिति ऐसी थी कि कार्यवृत्त में भी एक चूक को गंभीरता से इंगित किया गया था ताकि किसी भी विपरीत राय को रिकॉर्ड में जगह न मिले और मामला था इन सभी वर्षों के लिए उस कार्यकाल और

जोश के साथ आगे बढ़े। वर्ष 1997 में, हालांकि, कर्नाटक राज्य ने योजना बी के कार्यान्वयन के लिए मुकदमा दायर करना विवेकपूर्ण समझा। मुझे यह बहुत गलत नहीं लगा जब आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की ओर से क्रमशः श्री परासरन और श्री अंधारुजिना दोनों ने तर्क दिया कि इस अचानक परिवर्तन के लिए तर्क के पूरे सरगम को विस्तार से जाने की आवश्यकता है और मामलों को निस्संदेह आगे देखने की आवश्यकता है। दोनों विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मई, 2000 में पूरी स्थिति की समीक्षा के संबंध में न्यायाधिकरण की रिपोर्ट को सेवा में लगाया है, जहां तक योजना 'ए' का संबंध है, अन्यथा नदी तटीय राज्यों के लोगों को अनुचित पीड़ा होगी। ऊपर देखे गए दस्तावेजी साक्ष्य आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के प्रस्तुतिकरण को विश्वास दिलाते हैं।

इस संदर्भ में मामले के समीक्षा पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अर्थात् न्यायाधिकरण की रिपोर्ट में निहित 25 वर्षों के बाद पानी के वितरण की समीक्षा और जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1956 के अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने दायित्व के संदर्भ में प्रकाशित किया गया है। न्यायाधिकरण ने स्वयं महसूस किया कि योजना बी अन्यथा फायदेमंद हो सकती है, लेकिन योजना बी को अंतिम आदेश या केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वयन की गारंटी देने वाले न्यायाधिकरण के निर्णय का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है।

इस मामले का तीसरा पहलू इक्विटी की अवधारणा के संबंध में है।

निस्संदेह, कुछ परियोजनाओं का निर्माण महाराष्ट्र और 458 दोनों ने किया है।

[

2000] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आंध्र प्रदेश द्वारा और स्थिति में कुछ बदलाव होने की स्थिति में, राष्ट्रीय खजाने को बहुत गंभीर रूप से नुकसान होगा क्योंकि परियोजना की लागत अन्यथा अभूतपूर्व है। न केवल राष्ट्रीय जल निकासी होगी

अर्थव्यवस्था लेकिन तदनुसार, इसका देश के पूरे सुपर स्ट्रक्चर पर उचित प्रभाव पड़ेगा। किसी भी स्थिति में, योजना ए स्वयं देय है

मई, 2000 के महीने में समीक्षा और स्पष्ट रूप से समीक्षा एक न्यायाधिकरण द्वारा की जानी चाहिए और न्यायाधिकरण के लिए इस मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए खुला होगा। संयोग से, भारत सरकार ने एक समय पर योजना बी के कार्यान्वयन के बारे में सोचा था और इस संबंध में उसके सभी प्रयासों को कर्नाटक राज्य द्वारा निरर्थक बना दिया गया है जैसा कि दस्तावेजी साक्ष्य के पुनरुत्पादन के माध्यम से पहले देखा गया है।

किसी भी मामले में, के कार्यान्वयन के लिए एक मुकदमे में कामतक का दावा

योजना 'बी' को सापेक्ष पीड़ा और उस समय को ध्यान में रखे बिना तार्किक सीमा तक नहीं दबाया जाना चाहिए जिसके दौरान कर्नाटक राज्य ने आंध्र प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य को बिना किसी शिकायत के योजना 'ए' के साथ आगे बढ़ने दिया है। किसी भी स्थिति में समानता प्रासंगिक तथ्यों में योजना 'बी' को लागू करने की अनुमति नहीं देगी। विस्कॉन्सिन राज्य बनाम इलिनोइस राज्य में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ (74 एल. एड। 799) उपरोक्त को समर्थन दें।

निस्संदेह, लंबे समय के अंतराल के कारण पूरे मुद्दे की आवश्यकता है

और मुझे विश्वास है कि तटवर्ती राज्यों में से एक पूर्ववर्ती न्यायाधिकरण की इच्छाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में आवश्यक कदम उठाएगा, जिसने स्वयं मई, 2000 के महीने में पूरी योजना पर पुनर्विचार दर्ज किया है।

के खिलाफ मंडमस के अनुदान से संबंधित मुद्दे के संबंध में

केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 6 ए के तहत एक योजना बनाएगी और जैसा कि श्री नरीमन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह ध्यान दिया जाए कि 1956 का अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और न्यायाधिकरण के निर्णय को निष्पादित करने के लिए कोई एजेंसी नहीं बनाता है। अधिनियम यह प्रावधान करने के लिए पर्याप्त विशिष्ट है कि न्यायाधिकरण के निर्णय को राज्य द्वारा लागू किया जा सकता है क्योंकि जहां तक राज्यों का संबंध है, यह बाध्यकारी प्रकृति का है और केंद्र सरकार के किसी भी तरह से बाध्य नहीं होने से पहले इसे अधिक पूरी तरह से निपटा जा सकता है।

हालाँकि, इस मुद्दे पर श्री साल्वे का जोर चार पहलुओं पर था: - प्रथम गणना पर श्री सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि "का निर्णय

न्यायाधिकरण, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, केंद्र सरकार को बाध्य नहीं करता है।

यदि धारा कर्नाटक और ओ. आर. एस. का राज्य है। वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.]

459

6 क को एक कर्तव्य के साथ एक शक्ति के रूप में माना जाता है, इसे अनिवार्य रूप से इस बात का पालन करना चाहिए कि इसकी घोषणा पर न्यायाधिकरण का निर्णय संघ (जो इस तरह के निर्णय का एक पक्ष भी नहीं है) को इस हद तक बाध्य करता है कि वह संघ को वह सब करने के लिए मजबूर करता है जो इस तरह के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, कार्यान्वयन में स्वयं संघ पर दायित्व शामिल हो सकते हैं जो नहीं कर सकते हैं

उस पर एक ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा अधिरोपित किया जाए जिसका अधिकार क्षेत्र जल विवाद के पक्षों तक ही सीमित हो। दूसरी गणना पर उन्होंने तर्क दिया कि धारा 6 और धारा 6 ए विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं-धारा 6 ए सशर्त रूप से संघ को ऐसे कदम उठाने का अधिकार देती है जिन्हें वह न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए उचित समझ सकता है। संघ की यह शक्ति राज्यों द्वारा किसी भी अवज्ञा पर सशर्त नहीं है, और न ही यह उन स्थितियों तक सीमित है जहां न्यायाधिकरण

एक प्राधिकरण के गठन का निर्देश देता है: तीसरी गणना पर उन्होंने तर्क दिया कि "कर्तव्य के साथ शक्ति" का सिद्धांत इसलिए इन पर लागू नहीं होता है। इस तथ्य के कारण कि न्यायाधिकरण का निर्णय अधिनियम की धारा 6 के तहत संघ के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसे इसलिए भी लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 6 ए के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति स्पष्ट रूप से विधायी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अनुचित है।

प्रदत्त शक्ति की प्रकृति।

ए.

विनियमों को तैयार करने की शक्ति, जो ओवरराइडिंग होगी

बी.

प्रभाव पड़ता है।

संसदीय नियंत्रण की प्रकृति।

सी.

डी.

धारा 6 ए (6) में प्रदत्त अधिनिर्णय की शक्ति।

चौथे मामले में श्री सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि प्रावधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि संसद यह तय कर सकती है कि परिस्थितियों में किसी भी योजना की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पहली बार में, इसके प्रतिनिधि-केंद्र सरकार को यह तय करना होगा कि कोई योजना है या नहीं।

आवश्यक है। यह सुझाव देना कानून की योजना के साथ पूरी तरह से असंगत होगा कि केंद्र सरकार एक योजना तैयार करने के कर्तव्य के तहत है, लेकिन

संसदीय नियंत्रण का प्रयोग करते हुए, योजना की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उन कारकों में से एक के रूप में संदर्भित किया जाता है जिन पर विचार किया जा सकता है।

प्रस्तुतियाँ कुल परिप्रेक्ष्य पर की गई हैं

स्थिति और आगे बढ़े बिना मैं इसके साथ अपनी सहमति दर्ज करता हूँ। अनिवार्य आदेश या रिट जारी करने के संबंध में कानून शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण के साथ-साथ कार्य की प्रकृति और [2000] 3 एस. सी. आर. पर निर्भर करता है।

460

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनसे उत्पन्न होने वाले दायित्व। यह तय किया गया कानून है कि ऐसा निर्देश संभवतः नहीं दिया जा सकता है ताकि किसी प्राधिकरण को ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया जा सके जिसमें विवेक का एक महत्वपूर्ण तत्व हो। किसी भी स्थिति में विधायी चरित्र की शक्ति का प्रयोग करने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है और मैं पूरी तरह से हूँ। इस पर भी श्री सॉलिसिटर जनरल की प्रस्तुति के साथ समझौता। कम से कम यह केवल सुशासन का मुद्दा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि केंद्र सरकार के पास राज्य पर समझौता करने के लिए भी कार्यकारी शक्ति है।

इस मामले के उस दृष्टिकोण में मुकदमा 1997 का O.S.No.1 है।

अन्यथा बनाए रखने योग्य लेकिन किसी भी योग्यता से रहित है और जिन राहतों के लिए अनुरोध किया गया है वे प्रासंगिक तथ्यों में पूरी तरह से अनुचित हैं और इस तरह लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दिए गए हैं।

जैसा कि 1997 के O.S.No.2 में विवाद के प्रमुख बिंदु के ऊपर देखा गया है।

यह अलमट्टी बांध की ऊँचाई से संबंधित है। मेरे सम्मानित भाई पटनायक ने मुख्य निर्णय में इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से विचार किया है और भाई मजमुदार ने भी अपने समवर्ती निर्णय में ऐसा ही किया है। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के साथ अपनी सहमति दर्ज करते समय, मैं इसके लिए अपने स्वयं के तर्क दर्ज करना चाहूँगा, हालाँकि, बहुत विशिष्ट मुद्दों तक ही सीमित है जैसा कि यहाँ नीचे उल्लेख किया गया है क्योंकि मैं विवादों के अन्य क्षेत्रों के संबंध में उपरोक्त दो निर्णयों में दर्ज किए गए तर्कों को अपनाता हूँ।

हालाँकि, मामले को आगे बढ़ाने से पहले, एक महत्वपूर्ण विकास

इस वाद के विचारण के दौरान ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पक्षों ने इस न्यायालय को विस्तार से संबोधित किया है। 30 सितंबर, 1997 की कार्यवाही के रिकॉर्ड में कर्नाटक राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एफ. एस. नरीमन की ओर से एक रियायत दर्ज की गई है, जो प्रतिवादी संख्या 1 (<आईडी2) हैं और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल श्री टी. आर. अंधारुजिना, जो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर 1997 के O.S.No.2 में वाद में याचिका को स्वीकार करने के मामले में महाराष्ट्र राज्य की ओर से प्रतिवादी संख्या 3 (<आईडी2) हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के वादी राज्य ने एक घोषणा के लिए अनुरोध किया है कि रिपोर्ट/निर्णय दिनांक 24.12.1973 और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की 27 मई, 1976 की अगली रिपोर्ट/निर्णय उनकी संपूर्णता पर बाध्यकारी हैं। 30 सितंबर, 1997 के इस न्यायालय के आदेश में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लिखा गया है कि इस तरह की रियायत के कारण, न्यायाधिकरण के दिनांक 461 के निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति के संबंध में कोई विवाद होने का सवाल है।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.]

24 दिसंबर, 1973 और जैसा कि अगली रिपोर्ट और निर्णय दिनांक 27 मई, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, तीनों नदी तटीय राज्यों के बीच उत्पन्न नहीं होगा। तथापि, आदेश में अभिलिखित किया गया है कि भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी मामले में निर्देशों की कमी के कारण अन्यथा कोई बयान देने में असमर्थ थे, लेकिन इस न्यायालय को यह दर्ज करने में खुशी हुई कि प्रतिवादी संख्या की रियायत या स्वीकारोक्ति के आधार पर इस हद तक एक आंशिक डिक्री। 1 और 3 (क्रमशः कर्नाटक और महाराष्ट्र) को पारित किया जा

सकता है और इस प्रकार वाद में इस प्रार्थना को शामिल करने के लिए आगे कोई मुद्दा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नरीमन ने इसी आदेश का सहारा लिया है।

वादी (आंध्र प्रदेश राज्य) के मामले में न्यायाधिकरण के निर्णय को पूरी तरह से लागू करने के संबंध में, विशेष रूप से इसके कारण से तथ्य यह है कि न्यायाधिकरण के आदेश में स्वयं योजना बी के रूप में दूसरी योजना शामिल है, इस मुद्दे पर कुछ समय खर्च किया गया है और पहली बार में यह भी आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन पक्षों की प्रस्तुतियों की बारीकी से जांच करने पर और इससे भी अधिक कि श्री गांगुली ने कर्नाटक राज्य द्वारा दायर लिखित बयान को प्रस्तुत किया है, जिसमें वादी आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा मामले की अपनी समझ दर्ज की गई है, जैसा कि उठाया गया मुद्दा सुविधा के लिए बिल्कुल भी कायम नहीं किया जा सकता है, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर याचिका में किए गए कथनों के संबंध में कर्नाटक राज्य की समझ के प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिए गए हैं:

" 3 . आंध्र राज्य की मुख्य सामग्री

प्रदेश

3.1 आंध्र प्रदेश राज्य का तर्क है कि पूरी रिपोर्ट और

न्यायाधिकरण की आगे की रिपोर्ट होनी चाहिए थी और होनी चाहिए थी

राजपत्रित और यदि राजपत्रित किया जाता है, तो यह पता चलता है कि कर्नाटक

सिंचाई के लिए 155 टी. एम. सी. तक सीमित उपयोग। ऊपरी कृष्ण में परियोजना और उस उद्देश्य के लिए बांध की ऊँचाई नहीं हो सकी

519.6 m से अधिक। (ध्यान दें: यह आंध्र प्रदेश द्वारा विवादित नहीं है।

कि अलमट्टी बांध के निर्माण का वर्तमान चरण [2000] 3 एस. सी. आर. तक है।

केवल 509.0 m.) .

3.2 कि यदि रिपोर्ट और आगे की रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाता है, तो यह यह स्पष्ट होगा कि ऊपरी के तहत सिंचित किया जाने वाला क्षेत्र कृष्णा परियोजना 14.20 लाख एकड़ के क्रम की होगी। - और कर्नाटक ने एकतरफा रूप से क्षेत्र बढ़ाने की योजना बनाई है 23.77 लाख एकड़ तक सिंचित जो निर्णय के विपरीत है न्यायाधिकरण का।

3.3 कि अगर कर्नाटक को वृद्धि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए आरएल 519.60 मीटर से परे अलमट्टी बांध, यह अधिक के भंडारण को सक्षम बनाता है 200.00 टीएमसी की तुलना में। और लगभग 400 टी. एम. सी का उपयोग। इसलिए, आंध्र प्रदेश के अनुसार डाउनस्ट्रीम प्रवाह होगा गंभीर रूप से प्रभावित और परिणामस्वरूप बिजली और सिंचाई आवश्यकताएँ प्रभावित होंगी।

*

*

लिखित में दर्ज उपरोक्त समझ के मद्देनजर

बयान में, आंध्र प्रदेश राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गांगुली ने 1997 के ओएस नंबर 2 में वादी होने के नाते तर्क दिया कि

वाद में की गई प्रार्थना की प्रशंसा स्वयं वाद में किए गए कथनों और उनके द्वारा की गई प्रशंसा के संदर्भ में की जानी चाहिए। प्रतिवादी और समान नहीं। उपरोक्त कथन का अवलोकन कर्नाटक राज्य की विशिष्ट समझ को स्पष्ट रूप से दर्शाता है -

मुकदमे में दिए गए कथनों के संबंध में और यह अपने आप में श्री नरीमन के कथन को नकारता है। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद, मुझे श्री गांगुली की दलीलों के दूसरे भाग पर अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

इस तथ्य के बारे में कि भाई पटनायक ने इसे बहुत स्पष्टता के साथ निपटाया है।

इस मुद्दे के संबंध में श्री गांगुली की प्रमुख दलीलों में से एक

अलमट्टी बांध की ऊँचाई कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के रूप में योजना ए की स्वीकृति का तथ्य है। श्री गांगुली ने तर्क दिया कि वैधानिक आवश्यकता के संदर्भ में प्रकाशित किए गए निर्णय का एक बाध्यकारी प्रभाव है। श्री गांगुली ने तर्क दिया कि सहमत 75 प्रतिशत निर्भरता पर पार्टी राज्यों के बीच वितरण के लिए 2060 टी. एम. सी. के कुल उपलब्ध पानी में से न्यायाधिकरण ने तीन नदी तटीय राज्यों को संरक्षित उपयोग के रूप में टी. एम. सी. आवंटित किया और टी. एम. सी. की शेष मात्रा को तीन राज्यों के बीच निम्नानुसार विभाजित किया जाए:

463

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. वी. ए. पी. राज्य [बनर्जी, जे.]

आई.

महाराष्ट्र राज्य

125.35 टीएमसी

मैसूर राज्य

190.45 टीएमसी

II.

50.84 टीएमसी

III

आंध्र प्रदेश राज्य

न्यायाधिकरण ने स्पष्टीकरण No.XXI में, जैसा कि प्रदर्शनी P.K.II से दिखाई देता है, निम्नलिखित दर्ज किया:

" एम. आर. नोट No.30, एम. वाई. नोट No.17 और ए. पी. नोट No.14 में राज्यों ने

महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी संरक्षित उपयोगों के प्रावधान के बाद बचे हुए पानी से पानी के आवंटन के लिए अपने संशोधित दावे प्रस्तुत किए। हमने तीनों राज्यों की संशोधित मांगों पर विचार करने के बाद उनकी जरूरतों का आकलन किया। हमने महाराष्ट्र की गुडावले लिफ्ट योजना और कोयना-कृष्णा लिफ्ट सिंचाई योजना और लिफ्ट की मांगों को भी मंजूरी दे दी है

रिपोर्ट के खंड II के पृष्ठों 638-643, 674-675 और 731-733 पर दिए गए कारणों के लिए मलप्रभा परियोजना के तहत सिंचाई। भीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की मांग की अनुमति नहीं देने के कारण रिपोर्ट के Vol.II के पृष्ठ 737-738 पर दिए गए हैं। हमने पृष्ठों पर ऊपरी कृष्णा परियोजना पर विचार किया है

714-719 रिपोर्ट के Vol.II का। दोनों पक्षों ने परियोजना के लिए 103 टी. एम. सी. के उपयोग की रक्षा करने पर सहमति व्यक्त की। हमने उपलब्ध जल आपूर्ति और अन्य राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में उल्लिखित सीमा तक इस परियोजना के लिए अतिरिक्त मांग की अनुमति दी। ऊपरी कृष्णा परियोजना के संबंध में इस रिपोर्ट में कहीं और की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम आगे स्पष्टीकरण के लिए कोई आधार नहीं देखते हैं।

हालाँकि, हम यह जोड़ सकते हैं कि इस परियोजना को चरणों में निष्पादित किया जाना है और अगर यह भविष्य में पाया जाता है कि वितरण के लिए अधिक पानी उपलब्ध है

तीन राज्यों के बीच, अधिक आवंटन के लिए कर्नाटक का दावा इस परियोजना के लिए पानी पर अनुकूल विचार किया जा सकता है न्यायाधिकरण या मामले की समीक्षा करने वाले प्राधिकरण के हाथ। अलमट्टी बांध निर्माणाधीन है और कैरी-ओवर जलाशय (एम्फा) के रूप में काम कर सकता है सि आपूर्ति की गई।

स्पष्ट रूप से सिंचाई उद्देश्यों के लिए केवल एक कैरी-ओवर जलाशय के रूप में उपयोग किया जाता है और इसी आधार पर श्री गांगुली ने तर्क दिया कि तीन नदी तटीय राज्य न्यायाधिकरण के आदेश से बाध्य होना, जैसा कि उसके निर्णय में निहित है, [2000] 3 एस. सी. आर.

1956 के अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में अधिसूचित संभवतः न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकता है। मान लीजिए, अलमट्टी की ऊँचाई एफ. आर. एल. 509 थी। अंतिम निर्णय या न्यायाधिकरण के निर्णय के तहत, ऊपरी कृष्णा परियोजना i.e. Hippargi, अलमट्टी और नारायणपुर के तीनों घटकों के तहत अनुमति प्राप्त कुल उपयोग $155 + 5 = 160$ टी. एम. सी. था और कोई सिंचाई नहीं की गई थी।

अलमट्टी नहर के तहत अनुमति दी गई क्योंकि न्यायाधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य के स्पष्टीकरण के जवाब में प्रदर्शनी P.K.II में स्पष्ट रूप से कहा: “हम यह भी बता सकते हैं कि हमने अलमट्टी नहर के संबंध में पानी की किसी भी मांग की अनुमति नहीं दी। उच्च कृष्णा परियोजना के लिए कर्नाटक राज्य की आगे की मांग को भी न्यायाधिकरण द्वारा यह दर्ज करने पर अस्वीकार कर दिया गया है कि भविष्य में तीनों राज्यों के बीच वितरण के लिए पानी की उपलब्धता की स्थिति में, कर्नाटक के दावे पर इस मामले की समीक्षा करते समय विचार किया जाना चाहिए जैसा कि इस निर्णय में पहले देखा गया था। श्री गांगुली ने इस बात पर जोर दिया है कि अलमट्टी बांध के एक कैरी-ओवर जलाशय होने के कारण इसकी ऊंचाई में और वृद्धि की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उपलब्ध पानी को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पदार्थ है। संयोग से, यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने कार्यवाही के शुरुआती चरण में अलमट्टी बांध की ऊंचाई के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, हालांकि, किनारे के खंभों के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन बिना किसी द्वार के, ताकि पानी के प्रवाह में बाधा न आए। तथ्यों से पता चलता है कि किनारे के खंभे पहले ही खड़े किए जा चुके हैं और क्या है

उस द्वार को स्थापित करना आवश्यक है जिसे बिना अधिक समय गंवाए प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में श्री गांगुली ने तर्क दिया कि

कानून का उचित प्राधिकरण रखने वाले न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिए जाने वाले पक्षों को किसी अन्य नदी तटीय राज्य के हितों के खिलाफ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने का प्रयास होने की स्थिति में, इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य को अलमट्टी बांध की ऊंचाई को एफआरएल 524 एमटी तक बढ़ाने से रोकने के लिए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा देना चाहिए। मौजूदा एफआरएल 509 एमटी की तुलना में। जबकि यह सच है कि पक्षों के अधिकारों का निर्णय उचित रूप से गठित पक्ष द्वारा किया गया है।

1956 के अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में सांविधिक न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण के निर्णय का एक बाध्यकारी प्रभाव है, लेकिन यह मुद्दा उठता है कि क्या इस तरह का कोई अधिकार मौजूद है, जहां तक वादी का संबंध निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने के मामले में है- उसके अधिकार (आंध्र प्रदेश राज्य) का उल्लंघन क्या है। मान लीजिए, योजना 'क' के लिए मई, 2000 तक न्यायाधिकरण के आदेश के संदर्भ में समीक्षा की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को यदि 1997 के ओ. एस. (1) में ऊपर दिए गए निर्णय के साथ पढ़ा जाए, तो नदी तट के मालिकों के अधिकारों को तय और पुष्टि किए जाने के बजाय अभी भी तरलता के चरण में कहा जा सकता है और

इस स्तर पर निषेधाज्ञा का आदेश देना प्रासंगिक तथ्यों में न तो उचित होगा और न ही उचित-हालांकि श्री गांगुली की दलीलें अतार्किक नहीं लगती हैं, लेकिन वर्तमान प्रासंगिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं निषेधाज्ञा देने के पक्ष में दलीलों से सहमत होने में असमर्थ हूँ-अनुदान के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, न ही उचित है।

इस समय अनुदान की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर, हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निषेधाज्ञा देने के मुद्दे को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि क्या निषेधाज्ञा से इनकार करने पर, वादी को पक्षों के मामले की ताकत को ध्यान में रखते हुए क्षति का अपूरणीय नुकसान होगा। सुविधा या असुविधा का संतुलन भी एक अन्य आवश्यकता है लेकिन निषेधाज्ञा देने के मामले में कोई निश्चित नियम या धारणा नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर राहत हमेशा लचीली होनी चाहिए। स्थिति का न्याय मार्गदर्शक कारक होना चाहिए (कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार। हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, [1999] 7 एस. सी. सी. पी. 1: स्वयं निर्णय में एक पक्ष होने के नाते)। इसलिए, प्रासंगिक तथ्यों में, मेरे विचार में निषेधाज्ञा के किसी भी आदेश को देने का सवाल ही नहीं उठेगा।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, 1997 के O.S.No.2 में अलमट्टी बांध की ऊंचाई प्रमुख मुद्दा है: अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वादी के मामले को स्वीकार न करने का अर्थ एफ. आर. एल. 524 मीटर की ऊंचाई पर अलमट्टी बांध बनाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 की प्रार्थना को स्वीकार करना होगा और इसका अर्थ होगा-इसका उत्तर हालांकि, नकारात्मक नहीं हो सकता है; विशेष रूप से आसपास की परिस्थितियों के कारण। दो नदी तटीय मालिकों की दलीलें और संविधान के अनुच्छेद 131 की विशिष्ट भाषा और कर्नाटक राज्य के पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करने के अपने अधिकार के दावे को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव में हस्तक्षेप न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में आगे बढ़ने से पहले, कर्नाटक राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों में से एक का उल्लेख करना उपयोगी होगा। भारत संघ (1978 (2) एस. सी. आर. 1) जिसमें न्यायमूर्ति भगवती ने कहा:

" हम अनुच्छेद 131 को उन मामलों तक सीमित नहीं समझ सकते हैं जहां विवाद राज्य के कानूनी अधिकार के अस्तित्व या विस्तार से संबंधित है।

वादी, ऐसा करने के लिए, लेख में उन शब्दों को पढ़ना होगा जो वहां नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवाद लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के नियमों के भाग III में प्रदान की गई कार्यवाही का तरीका एक मुकदमा है, कि हम अनजाने में 'कार्रवाई के कारण' की धारणा को आयात करने के लिए प्रभावित हैं, जो जर्मन [2000] 3 एस. सी. आर. है।

एक मुकदमे में, अनुच्छेद 131 की व्याख्या में और इस लेख को पढ़ने के लिए इसका उल्लंघन किया गया और इसके परिणामस्वरूप, इसके खिलाफ 'कार्रवाई का कारण' है प्रतिवादी। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इसका कोई संदर्भ नहीं है

अनुच्छेद 131 में एक मुकदमा या 'कार्रवाई का कारण' और वह अनुच्छेद प्रदान करता है के चरित्र के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता विवाद जिसे न्यायनिर्णयन के लिए उसके समक्ष लाया जा सकता है। द. 'कार्रवाई के कारण' की आवश्यकता, जो एक मुकदमे में इतनी आवश्यक है, इसलिए, दायरे और दायरे को समझते हुए आयात नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 131। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे द्वारा दिया गया निर्णय सही है। वादी का उल्लंघन किया गया है, लेकिन इस पर कोई उचित चर्चा नहीं हुई उस मामले में तर्कों के दौरान और पूर्ण रूप से प्रश्न

अधिकार "निर्भर करता है, भले ही कानूनी अधिकार किसी के द्वारा दावा किया गया हो। पक्ष या अन्य और यह आवश्यक नहीं है कि कुछ कानूनी अधिकार इसके तहत मुकदमा दायर करने से पहले वादी का उल्लंघन किया जाना चाहिए। लेख। वादी को निश्चित रूप से विवाद का एक पक्ष होना चाहिए और जाहिर है कि यह विवाद का एक पक्ष नहीं हो सकता है जब तक कि यह प्रभावित न हो यह "। चंद्रचूड़, जे. ने भी उसी निर्णय में और उसी नस में देखा गया:

" मेरा मानना है कि संविधान ने इसे उद्देश्यपूर्ण रूप से प्रदान किया है। न्यायालय एक ऐसा अधिकार क्षेत्र है जो उन विचारों से अप्रभावित है जो पहली बार के न्यायालय की अधिकारिता को बाधित करना, जो और एक नागरिक प्रकृति के सूट की कोशिश करता है। उत्पन्न होने वाले विवादों की प्रकृति अनुच्छेद 131 के तहत रूप और सार दोनों में अलग है दावों की प्रकृति जिसके लिए सामान्य मुकदमों में निर्णय की आवश्यकता होती है। मेरी राय में, ऊपर व्यक्त किया गया दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 का अर्थ और तात्पर्य। यह एक संवैधानिक है

कुछ निर्दिष्ट मामलों के संबंध में अधिकारिता प्रदान करना जो कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. की प्रकृति के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाने की आवश्यकता है।

मतभेद और विवाद। यह अधिकारिता प्रदान करना विशेष परिस्थितियों में और विशेष कारणों से है, जिसमें संविधान में इस तरह के अनुच्छेद को शामिल करने के पीछे न्याय की अवधारणा प्रमुख कारक है।

इस तरह के विशेष मामलों में सामान्य नियम या प्रक्रिया लागू नहीं की जा सकती है।

परिस्थितियाँ। उपरोक्त के मद्देनजर और इस न्यायालय के पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के निर्णय के कारण, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त

शक्तियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में इस न्यायालय के पास कोई भी आदेश पारित करने या कोई भी निर्देश जारी करने की शक्ति, अधिकार और अधिकार क्षेत्र है जो न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक पाया जा सकता है और मुझे उस पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कानून उस मुद्दे पर अच्छी तरह से तय है। हालाँकि इस परिप्रेक्ष्य में और इस मोड़ पर कुछ तथ्यात्मक घटनाओं को नोट करना उपयोगी होगा।

भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर, चार मुख्यमंत्रियों से हस्तक्षेप करने और कर्नाटक राज्य के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया था

अलमट्टी बांध को एफ. आर. एल. 524 मीटर की ऊँचाई तक ले जाना। हालाँकि, चारों मुख्यमंत्रियों को एक-दूसरे की सहमति से नियुक्त किया गया, एक विशेषज्ञ समिति ने देखा कि ऊँचाई को एफआरएल 524 मीटर तक बढ़ाने का सवाल उठाया जा रहा है। इस स्तर पर बांध की ऊँचाई वास्तव में एफआरएल 519 मीटर तक नहीं होगी। अन्यथा किसी को भी आहत किए बिना अनुकूल होगा

स्थिति की वास्तविकताएँ। मान लीजिए, अलमट्टी भंडारण उद्देश्यों के लिए है और चूँकि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, आवंटन सीमित और प्रतिबंधित हैं, इसलिए आगे भंडारण का सवाल ही नहीं उठेगा। इस मामले का यह पहलू रहा है भाई पटनायक और भाई मजमुदार ने भी अपने समवर्ती निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला है कि मुझे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि श्री अंधारुजिना ने अलमट्टी बांध की ऊँचाई बढ़ने या बढ़ने की स्थिति में क्षेत्र में बाढ़ आने की आशंका व्यक्त की है, विशेषज्ञों द्वारा इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। की आशंका

आंध्र प्रदेश के वादी राज्य के समर्थन में उपस्थित श्री गांगुली ने भी बहुत दृढ़ता से तर्क दिया कि बांध की ऊँचाई में वृद्धि की स्थिति में, खरिफ फसल को उठाने के लिए कोई पानी उपलब्ध नहीं होगा, कर्नाटक राज्य के स्पष्ट रुख के कारण भी कुछ सार है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में पानी की आपूर्ति की कमी को तुरंत पूरा किया जा सकता है। यह स्वीकार किया गया मामला है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में पानी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में खरिफ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी: नागार्जुन सागर, श्री सैलेम और कालाहस्ती में भंडारण सुविधा वास्तव में स्थिति को कम नहीं करेगी। इससे पहले इस फैसले में मैंने कहा था कि इस देश की नदियों की विशेषताएँ हैं -

जबकि एक बाढ़ से भारी नुकसान हो रहा है, 468

दूसरा पूरी तरह से सूखा है जिससे समान मात्रा में सूखे अकाल का मौसम होता है और उपरोक्त के मद्देनजर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएँ निराधार नहीं लगती हैं और इसलिए संबंधित प्राधिकरण या प्राधिकरणों द्वारा योजना 'ए' पर पुनर्विचार

के समय ओ. एस. में हमारे निर्णय के संदर्भ में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
1997 का नंबर 1।

इस मामले के उस दृष्टिकोण में मैं निष्कर्षों के साथ अपनी सहमति दर्ज करता हूँ

भाई पटनायक ने कहा कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के कारण, अलमती बांध और इसकी ऊपरी सीमा को एफआरएल 519 पर रखा जा सकता है, हालांकि, कानून के तहत आवश्यक उचित प्राधिकरण या अधिकारियों से मंजूरी के लिए। मैं भाई पटनायक से भी सहमत हूँ कि अलमट्टी में अंतिम ऊंचाई बढ़ाने के सवाल पर न्यायाधिकरण द्वारा नदी तटीय राज्यों द्वारा रखी गई स्थिति के आकलन और जलमग्न होने की आशंका और खरिफ फसल के नुकसान की आशंका के आकलन पर भी विचार किया जा सकता है। न्यायाधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि समय के लंबे अंतराल और आधुनिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण पहले के न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण द्वारा की गई टिप्पणियों से पूरी तरह से अप्रभावित कृष्णा नदी बेसिन में पानी के आवंटन के संबंध में यदि और जब भी अवसर आता है, तो इस मामले को देखे। मुकदमे (1997 का ओ. एस. 2) का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

सेठी, जे. भाई पटनायक के मुख्य निर्णयों से सहमत होते हुए, जे. मूल सूट संख्या में। 1 और 1997 का 2 और पूरक सहमति

1997 के मूल वाद संख्या 2 में भाई मजमुदार, जे. का निर्णय। इसके अलावा मैं अपनी कुछ टिप्पणियों को दर्ज करने के लिए राजी हूँ, जो कृष्णा नदी बेसिन के तटवर्ती राज्यों द्वारा समय-समय पर स्थानीय दबावों और राजनीतिक परिस्थितियों में अपनाए गए अनुचित, अवास्तविक, प्रेरित और विरोधाभासी दृष्टिकोण के कारण आवश्यक हो गए हैं।

संघ, भारत संघ के संविधानकों ने निर्णय में हमारी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए। जल प्रकृति का एक अनूठा उपहार है जिसने पृथ्वी ग्रह को रहने योग्य बना दिया है। जल के बिना जीवन नहीं चल सकता। 1987 में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय जल नीति में यह घोषित किया गया था कि जल 469 है।

यह एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, एक बुनियादी मानव आवश्यकता और एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति है। पानी, हवा की तरह, मानव अस्तित्व का सार है। जल का इतिहास उपलब्धता और इसका उपयोगकर्ता सभी सभ्यताओं में जैविक रूप से विकास के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन की शुरुआत न केवल पानी से हुई है, बल्कि पानी ही जीवन है। लेफ्टिनेंट मानव जाति, पशुओं, पर्यावरण, वनस्पतियों और जीवों के लिए आवश्यक है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि प्राचीन काल में जल ने पूरी दुनिया में सभ्यता की उत्पत्ति, विकास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देशों के आर्थिक विकास में जल एक महत्वपूर्ण कारक है जो अंततः निवासियों के बीच सामाजिक और मानवीय संबंधों को

प्रभावित करता है। नियोजित विकास और जल संसाधनों का उचित उपयोग किसी राष्ट्र की समृद्धि के कारण और प्रभाव दोनों के रूप में काम कर सकता है। पृथ्वी पर पानी जमी हुई बर्फ, नदियों, झीलों, झरनों, जलमार्गों, जलप्रपातों और जलमार्गों आदि के रूप में उपलब्ध है।

इस आकाशगंगा और पृथ्वी के आसपास के वातावरण में, इसकी जलधारा

गोल खंड में ज्यादातर महासागरों के आकार का पानी होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से 97.3% जल ऐसा है जिसका उपयोग मानवता के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है। केवल 2.07% पानी खपत के लिए उपलब्ध है।

और मानव जाति का उपयोग। इस उपभोग्य जल में से 30 प्रतिशत का उपयोग सिंचाई के लिए, 7 प्रतिशत का उपयोग घरेलू और 12 प्रतिशत का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। शेष पानी कुप्रबंधन और बेहतर उपयोग की सुविधाओं की कमी के कारण पानी जाता है। जबकि पानी दुर्लभ और सीमित है, इसके उपयोगकर्ता कई हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर में विकास के साथ, पानी की खपत हर दिन बढ़ रही है और इसकी कुल उपलब्धता में इसी तरह की वृद्धि नहीं हो रही है। वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के एक अनुमान के अनुसार, औसतन एक व्यक्ति को लगभग 60,600 लीटर की आवश्यकता होती है। अपने जीवनकाल में और यू. एस. ए. जैसे औद्योगिक देशों में प्रत्येक व्यक्ति को पानी

वर्तमान में लगभग 260 लीटर का उपयोग किया जा रहा है। हर दिन पानी। हालाँकि हमारे देश में खपत बहुत कम है। में प्रगति के कारण प्रौद्योगिकी और सभ्यता की जल की आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं। आरामदायक जीवन की अपनी खोज में, लोगों को अधिक से अधिक पानी चाहिए। ऐसी जैसी सुविधाएँ, कचरा निपटान, स्वचालित वाशर और आधुनिक स्नानघर, जिन्हें पहले विलासिता के रूप में माना जाता था, अब एक बड़ी मानव आबादी के जीवन की आवश्यकताओं के रूप में माने जाते हैं।

भारत ईर्ष्यापूर्ण संपत्ति से संपन्न सबसे भाग्यशाली देशों में से एक है जल संसाधन। इस देश में औसत वार्षिक वर्षा दक्षिण को छोड़कर दुनिया के किसी भी अन्य महाद्वीप की तुलना में अधिक है।

अमेरिका। हालाँकि, अल्प संसाधनों और विकासात्मक [2000] 3 एस. सी. आर. की कमी के कारण।

सुविधाओं के अनुसार, भारत सालाना प्राप्त होने वाली वर्षा का केवल 10 वां हिस्सा उपयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप शेष पानी समुद्र में बर्बाद हो जाता है। इस देश में पानी के स्रोत या तो जमी हुई बर्फ है जो गर्मियों में पिघलती है या मानसून के मौसम में बांधों में जमा पानी है

जिसका उपयोग उस मौसम में किया जाता है। उचित जल स्रोत प्रबंधन के अभाव में, बड़ी आबादी बाढ़ या सूखे के कारण हर साल कई लोग पीड़ित होते हैं। भौगोलिक रूप से, भारत में 20 से अधिक प्रमुख नदी बेसिन हैं। उनमें से कुछ, जैसे कि सिंधु, चिनाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता, हालांकि भारत से उत्पन्न होती हैं और बहती हैं, फिर भी प्रभावी और सार में, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं क्योंकि वे अन्य संप्रभु राज्यों के क्षेत्रों से गुजरती हैं।

आधी सदी से अधिक समय से स्वतंत्रता के बावजूद देश ने ऐसा नहीं किया है

3000 से अधिक बड़े और छोटे बांधों का निर्माण करने की स्थिति में है जिसके परिणामस्वरूप देश में अन्यथा उपलब्ध अधिकांश पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। दुनिया के लगभग सभी देशों में भूमि संसाधनों के उपयोगकर्ता के साथ-साथ जल संसाधनों के उपयोगकर्ता को विनियमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल प्रबंधन को भूमि प्रबंधन के आलोक में देखने की आवश्यकता है।

मन में। जल अधिकारों से संबंधित कानून में पूरी दुनिया में भारी बदलाव आया है। जल के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-राज्य विवाद हैं -

"युद्ध या कूटनीति द्वारा" पुराने सिद्धांत या बसने वालों के स्थान पर कानून की प्रक्रिया का सहारा लेकर निपटाने की कोशिश की गई। पानी सभी प्रचलित कानून की प्रणालियों को जनता की संपत्ति घोषित किया गया है और उनके उपयोग के लिए समर्पित किया गया है, जो विनियोग और सीमाओं के अधीन है जो कानून के तहत या निपटान द्वारा या निर्णय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। जल प्रबंधन, इसके विकास और इसके वितरण से संबंधित विवादों पर कठोर तकनीकी या कानूनी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि पूर्व-विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि जल संपदा सभी देशों के लोगों की सामाजिक आर्थिक प्रगति और कल्याण के जैविक सार और सहायता के लिए एक केंद्र बिंदु और आधार है। जल के विकास, प्रबंधन और वितरण से संबंधित विवादों के समाधान में लंबे समय तक उपयोग, रीति-रिवाजों, प्रचलित प्रथाओं, नियमों, विनियमन अधिनियमों और न्यायिक निर्णयों पर निर्भरता रखी जानी चाहिए। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हमारे देश में संवैधानिक योजना के तहत पानी का अधिकार जीवन का अधिकार है और इस प्रकार यह एक मौलिक अधिकार है। भारत में संविधान के तहत पानी के महत्व को मान्यता दी गई है जैसा कि अनुच्छेद 252, 7 वीं अनुसूची सूची II प्रविष्टि 17, सूची I, प्रविष्टि 56 और अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 जैसे कानूनों से स्पष्ट है।

वी. ए. पी. राज्य [सेठी, जे.] 471

महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के पानी के उपयोग के संबंध में हैं जो देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।

प्रायद्वीपीय भारत। नदी की कुल लंबाई 870 मील है जो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और उपरोक्त तीन राज्यों के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। कृष्णा नदी बेसिन का क्षेत्रफल लगभग एक लाख वर्ग किलोमीटर है। जो तीनों राज्यों के लगभग 39 मिलियन निवासियों को सीधे प्रभावित करता है। इस नदी का पानी डेढ़ सदी से अधिक समय से तटवर्ती राज्यों के बीच विवाद का कारण रहा है। यह केवल 1955 में था जब इस नदी के पानी के उपयोगकर्ता को ठीक से विनियमित करने के लिए कृष्णा डेल्टा नहर प्रणाली शुरू की गई थी। नवंबर, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद केंद्रीय जल और विद्युत आयोग ने राज्यों के पुनः आवंटन के लिए योजना तैयार की।

कृष्णा जल जिसे संबंधित राज्यों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर, 1960 में एक अंतर-राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया था, लेकिन क्योंकि कोई समझौता नहीं हो सका था, इसलिए मामला अंततः न्यायाधिकरण को भेजा गया था।

न्यायनिर्णयन, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, पी. के. 1 और पी. के. 2 को प्रदर्शित करता है, जिन पर मुख्य निर्णय में विस्तार से चर्चा की गई है।

अप्रैल, 1969 से, अनिर्धारित विशाल जल के साथ, राष्ट्रीय संपत्ति जो सार्वजनिक धन है, नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में बह गई है। लंबित मुकदमेबाजी के कारण। भारी खर्च होने के बावजूद और

न्यायाधिकरण द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य, संबंधित राज्यों द्वारा स्वीकार नहीं किए गए पानी के वितरण के संबंध में सबसे स्वीकार्य समाधान बहाने पर और तकनीकीताओं के झगड़ों के तहत। यहां तक कि शुरू में न्यायाधिकरण की रिपोर्टों को स्वीकार करने वाले राज्य भी अपने रुख को बदल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के बावजूद मामले को जीवित रखा गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से संबंधित राज्यों की सुविधा के लिए जो मुख्य रूप से राजनीतिक विचारों और परिवर्तनों से प्रेरित है, लेकिन जाहिर तौर पर अपने निवासियों के घोषित हितों के लिए है।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों द्वारा दायर मुकदमों को खारिज करना और उनका निपटारा करना और महाराष्ट्र द्वारा दायर याचिका को खारिज करना।

अतिरिक्त लिखित बयान से विवाद का समाधान नहीं होगा या समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से राज्यों के बीच नए मुकदमे का आधार बन जाएगा, जिससे निश्चित रूप से उनके निवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप कृष्णा के पानी की

बर्बादी होगी जो अन्यथा बहुतायत में पाई गई है। यह आशा की जाती है कि जब और जब हमारे निर्णय पर कार्रवाई शुरू की जाती है, तो न्यायाधिकरण या उसके परिणामस्वरूप नियुक्त प्राधिकारी,

उद्देश्य मामले में तेजी लाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सबसे कीमती उपहार प्रकृति का पानी और जनता का पैसा अनावश्यक [2000] 3 एस. सी. आर. में बर्बाद नहीं होता है।

बंधन। यह विवादित नहीं है कि जलाशय की अनुपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तैयार किए गए चीम बी, बहुत सारा पानी

बंगाल की खाड़ी में डूबने की अनुमति दी गई। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों पर प्रबलनिवासियों के लाभ के लिए इसके पानी का उपयोग

असिन।

मुकदमा सं. 1/97 खारिज कर दिया गया और

मुकदमा सं. 2/97 निपटाया गया।